

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 510]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936

No. 510]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

[रक्षोपाय महानिदेशालय (सीमाशुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद कर)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

विषय: बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच अंतिम जांच परिणाम

सा.का.नि: **७०२(अ).**—दिनांक 29 सितम्बर, 2014, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 को ध्यान में रखते हए;

1. प्रक्रिया

- सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5 के अंतर्गत मेरे समक्ष एक आवेदनपत्र मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट संख्या 10, इंडिस्ट्रियल एरिया, लोधी माजरा, बद्दी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) द्वारा भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए दायर किया गया है जिसमें कि भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न से संवर्धित आयातों द्वारा बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट के घरेलू उत्पादकों को कारित गंभीर क्षति/गंभीर क्षति की चुनौती से रक्षा की जा सके।
- 2. उपर्युक्त रक्षोपाय नियमावली के नियम 5 के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का घरेलू उत्पादकों के संयंत्रों का दौरा करके आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया। इस सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय पाठ को सार्वजनिक फाइल में रखा गया। इस बात से संतुष्ट होकर कि उक्त नियम 5 की सभी जरूरत पूरी हो गई है, भारत में आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच प्रारंभ करने के लिए रक्षोपाय जांच श्रूजात को नोटिस सीमाशुल्क प्रशुल्क

3923 GI/2014 (1)

(रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6 के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2014 को जारी किया गया और उसे उसी दिन भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

3. घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदनपत्र के अगोपनीय पाठ की एक प्रति के साथ दिनांक 28 फरवरी, 2014 के जांच शुरूआत नोटिस की एक प्रति को सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 6(2) और 6(3) के अनुसार केंद्रीय सरकार के वाणिज्य मंत्रालय तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों, प्रमुख निर्यातक देशों की सरकारों को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जिरए और निम्नलिखित सूचीबद्ध हितबद्ध पक्षकारों को अग्रेषित की गई:

(i) घरेलू उत्पादक

मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, प्लाट संख्या 10, इंडस्ट्रियल एरिया, लोधी माजरा, बद्दी, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश)

(ii) विदेशी राष्ट्र/प्रतिनिधिमंडल/राजदूतावास

- क. चीन जनवादी गणराज्य का राजदूतावास, 50 डी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
- ख. कोरिया गणराज्य का राजदूतावास, 9 चन्द्रगुप्त मार्ग, चाणक्यपुरी विस्तार, नई दिल्ली-21
- ग. भारत में ताईवान ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र का राजदूतावास, 34, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057
- घ. वियतनाम का राजदूतावास, 17, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
- ङ. सिंगापुर गणराज्य का उच्चयोग, ई-6, चन्द्रगुप्त, नई दिल्ली-21
- च. शाही थाई राजदूतावास, डी-1/3, वसंत विहार, नई दिल्ली

(iii) आयातकर्ता/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन

- क. इंडियन स्पिनर्स एसोसिएशन (आईएसए) सीआईओ दि मिलओनर्स एसोसिएशन, धुरू बिल्डिंग, चौथा तल, गोखले रोड नार्थ, दादर पश्चिम, मुंबई-400028
- ख. इंडियन वूलेन मिल्स फेडरेशन, सातवां तल, चर्चगेट चैम्बसै, 5, न्यू मरीन लाइन्स, मुंबई-400002
- ग. फेडरेशन आफ इंडियन आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री, तृतीय तल, सस्मीरा, सस्मीरा मार्ग, वर्ली, मुंबई-400025
- घ. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर्स परिसंघ (फिक्की), फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली
- ङ. भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ब्लाक संख्या 3, दक्षिण मार्ग, 31ए, सेक्टर 31, चंडीगढ़
- च. नार्थ इंडिया सेक्सन आफ दि टैक्सटाइल इंस्टीट्यूट (निस्टी) मेगाटेक (ओवरसीज) इंडिया लिमिटेड, 317, एम जे शापिंग सेंटर 3, वीर सावरकर ब्लाक, शकरपुर दिल्ली-110092
- छ. दि टैक्सटाइल एसोसिएशन (टी ए आई), 401, गगनदीप, 12, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
- ज. सिंथेटिक एंड रेयान टैक्सटाइल्स निर्यात संवर्धन परिषद (एस आर टी ई पी सी), रेशम भवन, 78, वीर नरीमन रोड, मुंबई-400020
- झ. बद्दी बडौतीवाला नालागढ़, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बी बी एन आई ए) आफिस आफ दि सिंगल विंडो क्लीयरेंस एजेंसी, इंडस्ट्रियल एरिया, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) -173205
- ञ. दि साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, फ्लैट संख्या 113 'ए' ब्लाक राहेजा सेंटर, 1073 एवं 1074, अविनाशी रोड, कोयम्बटर, तमिलनाड़-641018
- ट. एसोसिएशन आफ मैनमेड फाइबर इंडस्ट्री आफ इंडिया, रेशम भवन 78, वीर नरीमन रोड, मुंबई-400020
- ठ. दि सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशसन (सीमा) 41, रेसकोर्स, कोयम्बटूर-641018
- ड. दि क्लोथिंग मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (सी एम ए आई) 902, महालक्ष्मी चैम्बर्स, 22, भूलाभाई देसाई रोड, मुंबई-400026

- ढ. संगम (इंडिया) लिमिटेड (एसपीजी यूनिट-I) पोसट बॉक्स संख्या 126, बिलिया कलां, चित्तौड़गढ़ रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान
- ण. संगत (इंडिया) लिमिटेड, एसपीजी (यूनिट-II), 91 किमी स्टोन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79, सारेरी, भीलवाड़ा, राजस्थान
- त. बीएसटी टैक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट संख्या 09, सेक्टर 09, आईआईई, सिदकुल, पंतनगर, उद्यम सिंह नगर, रूद्रपुर, उत्तराखंड
- थ. आरती इंटरनेशनल लिमिटेड VIII उछी मंगली, पोस्ट आफिस रामगढ़ चुंगी चौकी के बाहर, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना
- द. एसआरबी सिंथेटिक्स, सर्वे नम्बर 259/12, पार्श्वनाथ इंडस्ट्रियल एस्टेट, ग्राम दादरा एवं नागर हवेली (युटी) सिल्वासा
- ध. जिंदल डेनिम्स इंक, (ए डिवीजन आफ जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड) 206, सैजपुर गोपालपुर पीपलाज, पिराना रोड, चिकुवाडी, अहमदाबाद
- न. सुनहरी टेक्सक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्लांट संख्या 92, सेक्टर 29 पार्ट-II, हुडा, पानीपत, हरियाणा
- प सचिनम फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड ,1-37, 28, ।-जोन, जीआईडीसी सचिन, सचिन, गुजरात
- फ इंडोरामा सिंथेटिक्स (इंडिया) लिमिटेड, ए-31, एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया, ब्टीबोरी, नागपुर, महाराष्ट्र
- ब दीपक इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, सैजपुर, गोपालपुर, पिराना रोड, पिपलाज अहमदाबाद, गुजरात 382405
- भ नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड, युनिट-॥,ग्राम जलालपुर, चंडीगढ़, अम्बाला रोड, ललस, पंजाब

(iv) विदेशी उत्पादक/निर्यातक

- क. ह्योसंग कारपोरेशन कोंगडक बिल्डिंग, 450, गोंगडिओक डांग, मायोगु, सियोल दक्षिण कोरिया-125-720
- ख. इन्विस्टा (कोरिया) इंक, 19एफ, कुर्नकांग टावर 889-13 डाइची डांग, गंगनम-गृ, सियोल 125-280 कोरिया
- ग. टीकवैंग इंडस्ट्रियल कंपनी, टीकवैंग बी/डी, 162-1 चांगचुंग-डांग 2-जीए जंग-गु सियोल 100-000 कोरिया
- घ. टी. के. कैमिकल्स, सिन्सांग सेंटर बीडी 25-12, योइडोडांग यंगडंगपो-गृ सियोल, कोरिया
- ङ. ह्योसंग वियतनाम कंपनी एन2, स्ट्रीट नोहान टैक 5 इंडस्ट्रियल पार्क नोहान टैक, डांगनाई वियतनाम
- च. यान्वाई आरएम 1206 10-15/एफ किली मैनसन 80 छायोयांग स्ट्रीट, यांताइ, चीन
- छ. इन्वेस्टा, एनविस्टा ट्रेनिंग (शंघाई) कंपनी लिमिटेड, 17 एफ, हांगकांग, न्यू वर्ल्ड टावर, संख्या 300, हुआइहाइ रोड (एम) शंघाई 200021 चीन
- ज. इन्वेस्टा, सकारा मैन्यूफैक्चरिंग वर्क्स 1 सकरा एवेन्यू सिंगापुर
- झ. असाही, संख्या 336 झोंग्झेंग थर्ड स्ट्रीट, यांगकांग सिटी ताइनान काउंटी 71081, ताइवान
- 4. ज्ञात निर्यातकों भारत में ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नाविलयां इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि वे इस जांच शुरूआत नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूपा में अवगत करा दें।
- 5. निम्नलिखित पक्षकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुआ कि उन्हें हितबद्ध पक्षकारों के रूप में माना जाए और उनके इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

(i) विदेशी राष्ट्र/प्रतिनिधिमंडल/राजदुतावास

- क. मलेशिया का उच्चायोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय 50एम, सत्य मार्ग चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
- ख. भारत में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल, 65 गोल्फ लिंक नई दिल्ली-110003
- ग. जापान का राजदूतावास, 50-जी, शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
- घ. अरब गणराज्य मिस्र का राजदूतावास, कामर्शियल ब्यूरो, 1/50 एम, नीति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21
- ङ. चाइन चैम्बर आफ कामर्स फार इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ टैक्साइटल्स, एफ 1, सातवां संख्या 12, पंजिआयुआन नानली छाओयांग जिला बीजिंग-10021, चीन

च. रूसी परिसंघ का राजदूतावास

(ii) आयातक/प्रयोक्ता/प्रयोक्ता एसोसिएशन

- क. आल इंडिया स्पानडेक्स यार्न इम्पोर्टर्स एसोसिएशन, कृष्णा टावर प्रथम तल, 35 गजलक्ष्मी थियेटर रोड, तिरपुर-641604
- ख. मैसर्स नैरो इलास्टिक मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन एक्सीलैंट प्यूटरियल्स के पीछे, पुर्तगाली चर्च के निकट धुरू बिल्डिंग, चौथा तल, गोखले रोड (नार्थ) दादर (पश्चिम) मुंबई-400028
- ग. भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ, 1508, मेकर चैम्बर्स, नरीमन प्वाइंट, मुंबई-400021
- घ. तिरूपुर एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, 62, अपाची नगर मेन रोड, पोस्ट बॉक्स संख्या 508, कोन्गु नगर, तिरूपुर 641607
- ङ. एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री डी-15, एफ-18-19, एनडीएसई पार्ट-॥, नई दिल्ली-110049
- च. हौजरी मैन्य्फैक्चरर्स एसोसिएशन दिल्ली 5126/2, हरफूल सिंह बिल्डिंग, क्लाक टावर, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007
- ज. मैसर्स माराल ओवरसीज लिमिटेड, डाकघर माराल सरोवर, गांव खालबुजुर्ग-451660, तहसील कसरावाड़ जिला खारगौन (मध्य प्रदेश)
- झ. सीताराम स्पिनर्स प्राइवेट लिमिटेड "रामा टावर्स" 5-4-83, द्वितीय तल, टीएसके चैम्बर्स, रानीगंज बस डिपो के पीछे, एमजी रोड, सिकन्दराबाद-500003 (आंध्र प्रदेश)
- ञ. मैसर्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड, 4/15, आरबीएन कम्पाउंड पीछमपलायम पुडुर, पी एन रोड, तिरप्र-641603
- ट. कोहिनुर इलास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 50-51, 60-61 पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एस्टेट इंदौर-452015 (मध्य प्रदेश)
- ठ. गिमाटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 202, द्वितीय तल, रामजी हाउस 30, जाम्बुलवाड़ी, काल्बादेवी रोड, मुंबई-400002
- ड. लायन टेप्स प्राइवेट लिमिटेड 283/ख, जीआईडीसी, चित्रा एस्टेट, भावनगर गुजरात
- ढ. स्ट्रेच बैंड्स (गुजरात) प्राइवेट लिमिटेड 283/ए, जीआईडीसी चित्रा एस्टेट, भावनगर गुजरात
- ण. चिरिपल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (फाइबर डिवीजन) सर्वे सं. 199/200 सैजपुर, गोपालपुर, पिराना रोड, पिपलाज, अहदाबाद, 382405
- त. जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, प्रथम तल "सूर्यरथ' पंचवटी प्रथम लेन, अम्बावाड़ी, अहमदाबाद-38004, गुजरात
- थ. हेमस्पन इंडस्ट्रीज एलएलपी 6, पंचरत्न इंडस्ट्रियल एस्टेट, सरखेज बावला हाइवे चंगोदर, अहमदाबाद
- द. हेमलान सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, 6 पंचरत्न इंडस्ट्रियल एस्टेट सरखेज बावला हाइवे चंगोदर, अहमदाबाद
- ध. मैसर्स सनहरी टेक्सक्राफ्टस प्राइवेट लिमिटेड, 30 पश्चिम एन्क्लेव, रोहतक रोड, दिल्ली-110087
- न. एसोसिएटेड कैमिकल कारपोरेशन, 275/277, सैमुअल स्ट्रीट, मस्जिद बंदर, मुंबई, महाराष्ट्र
- प. यूनीफ्लाई रबड़ यार्न लिमिटेड, 403, शिवदत्त रेड्डी, टोपीवाला लेन गोरेगांव पश्चिम, मुंबई-400062
- फ. लोटस निट प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट संख्या सी-471, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, एमआईडीसी पवनी, नवी मुंबई-400705
- ब. मैसर्स गोपालजी फेबिक्स, एफ 306, सेक्टर 63, नोएडा-201301
- भ. अनादि विनकाय प्राइवेट लिमिटेड, "डापमंड आर्केड" यूनिट 413, 68, जेस्सौर रोड, कोलकाता-700055
- म. पायनियर अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-156, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नौयण
- य. गिन्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 11, क्वाइवरो, चौथा तल, रोड नम्बर 1/ए/ए, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001
- कक. मैसर्स एलीगेन्ट ओवरसीज 38वां माइलस्टोन, जयपुर राजमार्ग, बेहरामपुर रोड, गुड़गांव
- खख. मैसर्स नेशनल सिंथेटिक्स 4/15-6, आरबीएन कम्पाउंड, पिचमपालयम पुडूर, पी एन रोड तिरपूर-641603
- गग. स्पाइका इलास्टिक प्राइवेट लिमिटेड, 22/2, हदपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट, पुणे -411013, भारत
- घघ. काटन कन्सेप्ट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, डी-66, सेक्टर-63 नोएडा, 201301 (उत्तर प्रदेश)
- ङङ. वर्धमान टैक्सटाइल्स लिमिटेड, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना, (पंजाब) पिन 141010
- चच. राज एक्सपोर्टस, बी/एच, स्वास्तिक बंशीधर इंजीनियर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8, नारोल, अहमदाबाद-382405

- छछ. विष्णु टैक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, बी-121, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर 18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078
- जज. मैसर्स सिल्वर सैंड एजेंसीज, 14, प्रथम गली, मुथुनगर, कोंगु मैन रोड, तिरपुर-641607
- झझ. मैसर्स जित्णुन सिंथेटिक्स, 2/625 मैसर्स प्रोसिडेंट क्लारिंग कंपनी, 15 पहली गली, मुथुनगर कोंगु मैन रोड, तिरपुर-641607
- टट. मैसर्स लायल टैक्सटाइलस 83, आर ए प्रम, प्रथम मुख्य सड़क, चेन्नई 600028, भारत
- ठठ. बीएनटी इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, 11क, कथसप्रम तीसरी गली पीएन पालायम रोड, तिरूप्र 641607
- डड. जिओन इंटरनेशनल 167, यूनियन मिल रोड, संगीता थियेटर (के सामने) तिरूपुर, भारत 641601
- ढढ. मैसर्स एल्बियन 26/ख 222, लायकराम काम्प्लेक्स, बदरपुर, नई दिल्ली
- णण. जेनिथ फाइब्रेस, 16/44, अंदावर ब्लीचिंग कम्पाउंड, अलनगाडु अरूवमपलायम तिरूपुर/तमिलनाडु पिन 641604
- तत. मैसर्स शिवालिक प्रिंट्स लिमिटेड, प्लाट संख्या 7, सेक्टर 6, फरीदाबाद (हरियाणा) पिन-121006
- थथ. एनफील्ड ए प्रल्स लिमिटेड, "परिधान गारमेंट पार्क" मोडयूल 301-302, 19, केनाल साउथ रोड, एमडीएफ-1/ए, कोलकाता, भारत
- दद. पी. के. पी. एन. स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सं.6, बाई-पास रोड, पल्लीपलायम इरोड-638 006
- धध. किरण टेक्स्प्रो प्राइवेट लिमिटेड, शेड सं. 20, 21,22, साईं लीला इंडस्ट्रियल एस्टेट, पुराने पेट्रोल पम्प के समीप, उधाना, सूरत, गुजरात- 394210
- नन. कोनिका इंडस्ट्रीज, ए/12/22, रोड नम्बर 6, उधाना, सूरत, गुजरात
- पप. आर वी डेनिम्स एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड, 191, शाहवाडी, पुराने चुंगी चौक के निकट, नारोल, सरखेज हाइवे, नारोल, अहमदाबाद-382 405
- फफ. भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट सं. 15-16 सेक्टर डी, औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप-462406
- बब. मैसर्स स्पेंडो इम्पेक्स, ई-105, वीना नगर सी एच एस एस , वी रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400 064
- भभ. गिंजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 501-ए, लोटस कारपोरेट पार्क, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे के सामने, गोरेगांव पूर्व, मुंबई-400 093
- मम. मफ्त लाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डेनिम प्रभाग, वेजलपुर रोड, नवसारी-396445
- यय. वेलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "वी" विंग, 9वां तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, लोअर परेल, मुंबई-400 013
- ककक. सोगो फेशन प्राइवेट लिमिटेड, प्लांट नम्बर डी-1, डी-2, साइट-बी, यूपीएसआई डीसी औद्योगिक क्षेत्र, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश -201307
- खखख. जे एम कमोडिटीज लिमिटेड, 701, तुल्सियानी चेम्बर, नारीमन प्वाइंट, मुंबई-40021
- गगग. आर के ब्रदर्स, ई-105, वीना नगर सीएचएसएस, वी रेड मलाड (पश्चिम), बंबई-400 064
- घघघ. अरूणाचला गोअंडर टेक्सटाइल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सं. 05, बाई-पास रोड, पल्लीपलायम, इगेट-638 006, तमिलनाड
- ङङङ. राजस्थान इंटरनेशनल, 1402, अग्रवाल कारपोरेट हाइट्स, ए-7, नेताजी सुभाव प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034
- चचच. मैसर्स मोसकोट एक्सपोर्टस, कपूर डेंटल क्लीनिक के ऊपर, शिवपुरी रोड, लुधियाना, पंजाब-141007
- छछछ. अरविंद लिमिटेड, नरोडा रोड, अहमदाबाद, गुजरात, पिन -380 025
- जजज. बिरला सेंचुरी, 826, जीआईडीसी जगाधिया, मरूच, गुजरात
- झझझ. ओसवाल वृलन मिल्स लिमिटेड, जीटी रोड, शेरप्र, लुधियाना
- অঅঅ. रेमंड्स यूसीओ डेनिम प्राइवेटल लिमिटेड, जेकीग्राम, पोरवरन रोड नम्बर 1, थाणे (पश्चिम), मुंबई
- टटट. डेनिस मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, 40-41, कम्यूनिटी सेंटर, न्यू फेंड्स कालोनी, नई दिल्ली
- ठठठ. गीमा मेन्य्फैक्चरिंग एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड, राम मंदिर, वार्ड हिंगनघाट, जिला वर्धा (एमएस)
- डडड. टेक्सप्रोकिल, 5वां तल, 9 मेथ्यू रोड, मुंबई
- ढढढ. यूनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा तल सं. 222, 244, 246 और 247, सेट्रम प्लाजा बिल्डिंग, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 53, गुड़गांव-122002

णणण. नंदन डेनिम लिमिटेड, सर्वे नम्बर 198/1 और 203 साइजपुर – गोपालगुपर,

(iii) विदेशी उत्पादक/निर्यातक

- क. टी के केमिकल कार्य, 3 एफ, यिओनु बिल्डिंग, 416-8, चिमसन डोंग, बुक –डु, दाएगु 702-713, कोरिया
- ख. इनाविसटिआ सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड, 39, टुअस क्रीसेंट, सिंगापुर-638726
- ग. हायोसंग स्पेंडेक्स (जिआक्साइंग) कंपनी लिमिटेड, बीआई हाय रोड, जिआक्सिंग इकनामिक डेवलपमेंट जोन, जिआंग प्रोविन्स, चीन-314001
- घ. थाई अशाइ केसी स्पेंडेक्स कंपनी लिमिटेड, 919 मृ, "तामबोल नोंगखाम, अमफुर श्रीराचा, चोनबुरी 20230, थाईलैंड
- ङ. टोरे ओप्लेनोटेक्स कंपनी लिमिटेड, 3-3-23, नकानोशिमा, किता-कु, ओसाका, जापान -530 8205
- च. अशाइकेसी फाइबर कारपोरेशन, 3-3-23, नकानोशिमा, किता-कु, ओसाका, जापान -530 8205
- छ. कोरिया फेडरेशन आफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (कोफोटी), टेक्सटाइल सेंटर 16 एफ, डायची 3-डोंग, गंगनम-गु, सियोल कोरिया
- ज. वियतनाम कॉटन एंड स्पिनिंग एसोसिएशन (वकोसा), आईओएफआई, विनाटेक्स ताइ न्गुयेन बिल्डिंग, 10 न्गुयेन हयु स्ट्रीट, बेन नगीह वार्ड, जिला ।, होची मिन्ह सिटी, वियतनाम
- झ. टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, डोनगो-रो. जंग-गु, सियोल -100855, कोरिया
- ञ. टेकवांग सिंथेटिक फाइबर (चेंगश्) कंपनी लिमिटेड, ब्लाक डी, टोंगगैंग इंडस्ट्रिल पार्क, चेंगश्, तिआंगस्, चीन
- ट. अशाइ केसी स्पेंडेक्स यूरोप जीएमवीएच, जर्मनी
- 6. निम्नलिखित पक्षों से अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ, जिनको अनुमति दी गई:
 - क. मैसर्स हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया
 - ख. हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन
 - ग. हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
 - घ. टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया
 - ङ. चीन चेम्बर आफ कामर्स फार इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आफ टेक्सटाइल
- 7. निम्नलिखित इच्छुक पक्षों ने प्रश्नावली के उत्तर दाखिल किए/प्रवर्तन के नोटिस के उत्तर में
- (i) घरेलू उद्योग मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
- (ii) आयातक/उपयोगकर्ता/उपयोगकर्ता संघ
 - क. यूनीफाई रबड़ यार्न लिमिटेड
 - ख मराल ओवरसीज लिमिटेड
 - ग. जिनजुन सिंथेटिक
 - घ. सिल्वरसैंड एजेंसिस
 - ङ. प्रेजीडेंट क्लोथिंग कंपनी
 - च. भारतीय वस्त्रोद्योग संघ (सी आई टी आई)
 - छ. दि सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
 - ज. तिरूपुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन
 - झ. बी बी एन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
 - ञ. दि सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन

- ट. एसोसिएडिड केमिकल कारपोरेशन
- ठ. पी के पी एन स्पिनिंग मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड
- ड. गिंजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ढ. सचमाम फेब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ण. अरविंद लिमिटेड
- त. ए जी टी मिल्स
- थ. जीनोन इंटरनेशनल
- द. नेगे इलास्टिक मैन्यूफैक्चर एसोसिएशन
- ध. नेशनल सिंथेटिक
- न. इंटरनेशनल बिजनेस एंड ट्रेड
- प. आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन
- फ. सीताराम स्पिन्स प्राइवेट लिमिटेड
- ब. इनविस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- भ. विष्णु टेक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
- म वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- य. जेनिथ फाइबर
- कक. चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- खख. किरण टेक्सप्रो प्राइवेट लिमिटेड
- गग. जीमाटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- घघ. बी एन टी इनोवेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
- ङङ. एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री
- चच. आर वी डेनिम्स एंड एक्सपोर्टस
- छछ. भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
- जज. जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड
- झझ. मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
- ञञ. वेलस्पन सिंथेक्स लिमिटेड
- टट. बिरला सेंचुरी
- ठठ. ओसवाल वुलन मिल्स लिमिटेड
- डड. रेमंड युको डेनिम प्राइवेट लिमिटेड
- ढढ. गीमा मैन्यूफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
- णण. टेक्सप्रोसिल
- तत. डेनिम मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
- थथ. यूनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- दद. कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री
- धध वर्धमान

(iii) विदेशी राष्ट्र/प्रतिनिधि/दूतावास

- क. भारत में ताइपेई इकानामिक एंड कल्चरल सेंटर
- ख मिस्र अरब गणराज्य का दतावास
- ग. रूसी संघ का दूतावास

(iv) विदेशी उत्पादक/निर्यातक

- क. अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन, जापान
- ख. थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड
- ग. टीके केमिकल कारपोरेशन, कोरिया
- घ. टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया
- ड. टेकवांग सिंथेटिक फाइबर (चेंगश्) कंपनी लिमिटेड, चीन
- च. हयोसुंग स्पेंडेक्स (जीएक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन
- छ. हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया
- ज. इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड
- झ. अशाई केसी स्पेंडेक्स यूरोप जीएमबीएच, जर्मनी
- 8. इच्छुक पक्षों द्वारा व्यक्त सभी विचारों को उचित निर्धारण करने में ध्यान में रखा गया है । प्राप्त या उपार्जित गैर-गोपनीय सूचना को सार्वजनिक फाइल में रखा गया है ।

II. हितबद्ध पक्षकारों के विचार (जांच पश्चात नोटिस के पश्चात)

क. रूसी संघ का उद्योग और व्यापार मंत्रालय

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 2012 से 2013 की जांच की अवधि के दौरान सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के उप-शीर्ष 54024400 और 54041100 के तहत आने वाले माल का आयात और रूसी संघ से भारत को आयात करना तीन प्रतिशत नहीं बढ़ा है। अत: सुरक्षा पर डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 9 और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (धारा 8ख) के तहत सुरक्षा प्रावधान के अनुसार सुरक्षा उपाय को रूसी संघ निर्यात से निकाल दिया जाना चाहिए।

ख. भारत में तेपेई इकनामिक एंड कल्चरल सेंटर

- क. आयात का बाजार हिस्सा पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ता।
- ख. भारत के महानिदेशक सुरक्षा द्वारा प्रकाशित सुरक्षा के आरंभण के नोटिस पर घरेलू उत्पादन की मात्रा के प्रति आयात की मात्रा का प्रतिशत लगातार उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति नहीं दिखाती । इसलिए जांच के अधीन आयात सुरक्षा के करार के अनुच्छेद 2.1 के तहत आयातों की मात्रा में वृद्धि के लिए अपेक्षा को पूरा नहीं करती ।
- ग. हाल के वर्षों में जांच के अधीन विषय उत्पादों के लिए घरेलू मांग घरेलू उत्पादन से बढ़ गई है । यदि सुरक्षा उपाय नहीं अपनराए जाते हैं तो यह भारतीय उत्पादकों को विषय उत्पादों को प्राप्त करने से प्रतिबंधित करेगा जोकि अधिक प्रतिस्पर्धी होगा और इसके फलस्वरूप भारत के समग्र आर्थिक विकास को प्रतिकृल रूप से प्रभावित करेगा ।

ग. मिस्र अरब गणराज्य

भारतीय सांख्यिकी के अनुसार जांच की अवधि के दौरान भारत को संबंधित उत्पाद का कोई मिस्री निर्यात नहीं है, अत: सुरक्षा संबंधी करार के अनुच्छेद 9.1 के अनुसार मिस्री निर्यात को सुरक्षा उपाय से निकाल दिया जाना चाहिए ।

- घ. मैसर्स डीजीएस अधिवक्ताओं ने मैसर्स हयोसुंग कारपोरेशन (कोरिया), टीके केमिकल कारपोरेशन (टीकेसी), कोरिया, टेक्वांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया, हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड , वियतनाम, हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन और टेकवांग सिंथेटिक फाइबर (चांगशु) कंपनी लिमिटेड, चीन की ओर से निवेदन दाखिल किए हैं।
 - क. मौजूदा जांच में आवेदक ने घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली दाखिल नहीं की है, अत: वह जांच प्राधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग करने में असमर्थ रहा है।

- ख. मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग ने अन्पेक्षित घटनाक्रम का दावा करने के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत नहीं किया है।
- ग. घरेलू उत्पादक अवश्य यह प्रमाणित करे कि आयातों में वृद्धि हुई है और घरेलू उत्पादक को ऐसे बढ़े हुए उत्पादों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा की स्थिति का मुकाबला करने के लिए स्वयं को तैयार करने के लिए समय और योजना की जरूरत है।
- घ. घरेलू उद्योग का दावा है कि विषयक वस्तुओं के आयातों का मूल्य नहीं बढ़ा है पूर्ण रूप से गलत और भ्रांतिपूर्ण है और तथ्यों पर आधारित नहीं है । घरेलू उद्योग ने उतरने के मूल्य का परिकलन उतरने के प्रभारों और सीमा शुल्क पर शिक्षा उपकर के प्रभाव पर विचार करते हुए नहीं किया है ।
- ङ. मूल्य में कोई कटौती/कम मूल्य पर बिक्री नहीं हुई है।
- च. विषयक माल के आयातों में वृद्धि पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त उल्लेखनीय नहीं है और विषयक माल के आयातों में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई है जिससे सुरक्षा शुल्क को लगाना आवश्यक हो ।
- छ. शिकायकर्ता द्वारा उठाई गई कथित क्षति न तो डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत अपेक्षाओं को पूरा करती है और न ही सुरक्षा उपायों को न्यायोचित ठहराती है, इसलिए आयातों में यदि कोई वृद्धि नहीं है उसने भारतीय घरेलू उद्योग कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई है जिसके लिए सुरक्षा शुल्क लगाना आवश्यक हो। डीजी (सुरक्षा) को प्रस्तुत निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट करेंगे कि घरेलू उद्योग को आयात द्वारा कोई क्षति नहीं हुई है।
 - (i) क्षमता को 500 एमटी के स्तर पर लगातार बनाए रखा गया है।
 - (ii) जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है। अधिक विशेष रूप से उत्पादन जो वर्ष 2012-13 में 2365.9 एमटी था बढ़कर 2013-14 (वार्षिक रूप से) में 4,797.0 एमटी हो गया है इसमें 103 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 - (iii) वर्ष 2012-13 और 2013-14 (सितम्बर तक) के बीच क्षमता का उपयोग दुगना हो गया है।
 - (iv) घरेलू बिक्री जो वर्ष 2012-13 में 1,679 थी बढ़कर 2013-14 में (वार्षिक रूप से) बढ़कर 3,646 हो गई है इसमें 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 - (v) कुल घरेलू खपत में भी वर्ष 2012-13 में 11,020 की तुलना में वर्ष 2013- |4| (वार्षिक रूप से) में 13,632 हो गई है इसमें 23.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 - (vi) घरेलू बाजार हिस्से को तिमाही आधार पर विश्लेषित करना उचित नहीं है क्योंकि यह बहुत कठोर संकेतक है, इसलिए यह बाजार की प्रवृत्ति को दर्शाने में पर्याप्त नहीं है। इसलिए घरेलू बाजार के हिस्से की वार्षिक विश्लेषण के आधार पर जांच की जानी चाहिए, घरेलू बाजार का हिस्सा वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत से 2013-14 में 25 प्रतिशत तक बड़ा है, दूसरी ओर आयात में बाजार हिस्सा वर्ष 2012-13 में 85 प्रतिशत से 2013-14 में 75 प्रतिशत तक कम हआ है।
 - (vii) जांच की अवधि के दौरान औसत रोजगार में वृद्धि हुई है।
 - (viii) जांच की अवधि के दौरान मालसूची में वृद्धि हुई है। परंतु मालसूची के प्रति उत्पादन संतुलन में 2012-13 (क्यू 4) में नाटकीय कमी हुई है। इसलिए मालसूची की वृद्धि भारत के घरेलू उत्पादन में वृद्धि का परिणाम है।
 - (ix) संभावत: यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता की वित्तीय स्थिति को क्षति उठाना पड़ी है । परंतु अधिक हाल में, लाभ/हानि और शिकायतकर्ता की संबंधित वित्तीय स्थिति बेहतर हो रही है ।
- ज. उपर्युक्त साक्ष्य के अनुसार घरेलू उत्पादकों की स्थिति में समग्र रूप से कोई उल्लेखनीय क्षति नहीं हुई है, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई कथित क्षति न तो डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत अपेक्षाओं को पूरा करती है और न ही सुरक्षा उपायों के प्रयोग को औचित्यपूर्ण ठहराती है।
- झ. घरेलू उद्योग सकारात्मक आकस्मिक संपर्क स्थापित करने में असमर्थ रहा है कि बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुंचाई है। इसके साथ-साथ, वे यह प्रमाणित करने में भी असमर्थ रहे हैं कि अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

(ड.) मैसर्स जे. सागर एसोसिएट ने इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड और इनविस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की ओर से निवेदन दाखिल किया है।

क. पीओआई के दौरान विषय देशों से पीयूसी के आयातों में वृद्धि के कारण इंडोरामा को कोई गंभीर क्षति नहीं हो रही है ।

ख. घरेलू उत्पादन:

- (i) आवेदन के अनुबंध 5क में प्रदान किया गया डाटा प्रावधान करता है कि वर्ष 2011-12 से सितम्बर, 2013 तक क्षमता के 5,000 एमटी पर रहने के बावजूद उत्पाद ने वर्ष 2011-12 में 18.1 एमटी से सितम्बर, 2013 तक 2398.5 एमटी की कई गणा वृद्धि दर्शायी है।
- (ii) घरेलू उद्योग ने विषय वस्तुओं का पीओआई के दौरान भारत से बाहर निर्यात भी किया है, जो फालतू उत्पादन के परिदश्य को दर्शाता है न कि कमी को।

ग. क्षमता का उपयोग

- (i) पूरे पीओआई के दौरान प्रत्येक तिमाही के लिए संस्थापित क्षमता वही रहने अर्थात 1250 एमटी के बावजूद क्षमता का उपयोग 2013-14 की पहली तिमाही में बढ़कर 99.8 प्रतिशत हो गया और उसकी तीसरी तिमाही में मामूली का कम होकर 90.2 प्रतिशत रह गया।
- (ii) घरेलू उद्योग नए संयंत्र के उत्पादन शुरू करने के दो वर्ष से कम समय पर 94 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर पहुंचने से उसकी गंभीर क्षति या आशंका का दावा नहीं कर सकता।
- घ. घरेलू बिक्री: आवेदन के भाग 4 के पैरा 5 में तालिका के अनुसार पीओआई के दौरान घरेलू बिक्री में, जो 2012-13 में 1866.5 एमटी से 2013-14 (सितम्बर, 2013 तक) तक छह महीनों में 2249 एमटी तक बढ़ी है, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो गंभीर क्षति के दावे विपरीत घरेलू उद्योग के घातांकी विकास का स्पष्ट संकेतक है जो आवेदन में स्वयं उल्लिखित तथ्यों से परे है।
- ङ. **मालसूची :** पूरे पीओआई के दौरान मालसूची में कोई प्रबल वृद्धि नहीं हुई है, जो कि इंडोरामा के नए संयंत्र के उत्पादन और क्षमता के उपयोग में वृद्धि के अनुरूप है । वर्ष 2012-13 (क्यू 1) में मालसूची (एमटी) 477 थी और 2013-14 (क्यू 3) में यह 601 पर है जो कि प्रमुख परिवर्तन नहीं है । इसके अलावा 2013-14 में भी क्यू 1 से क्यू 3 में मालसूची 646 से कम होकर 601 हो गई है ।
- च. उत्पादकता और रोजगार : पीओआई के दौरान औसत रोजगार, जो वर्ष 2012-13 (क्यू 1) में 221 था 2013-14 (क्यू 3) में 256 हो गया, का स्तर बढ़ा है । इसके अलावा, अति कर्मचारी उत्पादकता, जैसाकि आरंभण अधिसूचना में भी बताई गई है, 2012-13 क्यू 1 में 3.0 से बढ़कर 2013-14 क्यू 3 में 4.4 हो गई है ।
- **छ.** आयात और बाजार का हिस्सा: घरेलू उद्योग ने मार्च, 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया और दो वर्ष से कम में अर्थात सितम्बर, 2013 तक सर्वसम्मित से क्षमता उपयोग का 94 प्रतिशत प्राप्त किया है और देशी बाजार में बाजार हिस्से का लगभग 30 प्रतिशत ग्रहण किया है। इंडोरामा के डाटा और निवेदनों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि पीओआई के दौरान कुल आयातों में यद्यपि मामूली वृद्धि हुई फिर भी उन्होंने स्थानीय मांग में वृद्धि की दर की तुलना में नकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाई है। इस प्रकार आयातों में ऐसी कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो।
- ज. अतिरिक्त क्षमता में निवेश : आवेदन के अनुबंध 6 में घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक समायोजन करने के उद्देश्य से इंडोरामा अपने संयंत्र की क्षमता वर्तमान के 5,000 एमटी से मार्च, 2015 में 10,000 एमटी तक बढ़ा रहा है। इस प्रकार यह आश्चर्य चिकत करने वाला है कि एक ओर घरेलू उद्योग दावा करता है कि निर्यातकों द्वारा स्थापित अतिरिक्त क्षमता घरेलू मूल्यों पर दबाव डाल रही है, अत: उससे गंभीर क्षति या आंशका पैदा हो रही है और घरेलू उद्योग के विकास को बाधित कर रही है और दूसरी ओर इंडोरामा स्वयं ही अपने संयंत्र की मौजूदा क्षमता को दुगुना करने के लिए और निवेश करने की दृष्टि कर रहा है।
- **झ. मूल्य में कटौती:** घरेलू उद्योग के आवेदन में पृष्ठ 13 में आयातित पीयूसी के मूल्यों को दर्शाने वाली तालिका को देखते हुए यह स्पष्ट है कि आयातित पीयूसी के मूल्य में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है और मूल्य में कोई कटौती नहीं हुई है जैसाकि आवेदन में दावा किया गया है।
- ञ. सीमा शुल्क टैरिफ की धारा 8ख के अनुसार घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के कारण कोई क्षति नहीं हुई है, पहले क्योंकि पीयूसी के आयातों में अचानक वृद्धि नहीं हुई है जिससे कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो ।
- ट. **संपूर्ण कार्यवाही की प्रतिस्पर्धा रोधी है:** घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धारोधी इच्छा आवेदन के पृष्ठ 16 (पैरा च) में यथा उल्लिखित पीयूसी के मूल्य में वृद्धि न कर पाने में उनकी शिकायत से स्पष्ट है।

(च) यूनीफ्लाई रबड़ यार्न ने निम्नानुसार प्रस्तुतिकरण किया है:

- क. उक्त कंपनी द्वारा उत्पादित यार्न की गुणवत्त कोरियाई और जापानी के नानकों के साथ मेल नहीं खाता और कोई भी कंपनी अपने तैयार उत्पादों में समझौता करने की इच्छुक नहीं होगी ।
- ख. चूंकि यह एकमात्र कंपनी है जो भारत में स्पेंडेक्स यार्न का विनिर्माण करती है, इसलिए यह अन्य सभी कंपनियों को भविष्य में इस पर निर्भर होने के लिए बाध्य करेंसी जो दरों को बिना किसी कारण के पर्याप्त रूप से बढ़ा देगा।
- (छ) मराल ओवरसीज लिमिटेड: ने निवेदन किया कि वे लायक्रा स्पेंडेक्स के साथ बुने हुए काटन फेब्रिक का निर्माण कर रहे हैं। वे इयोसंग, वियतनाम सिंगापुर से और क्रिओग स्पेंडेक्स से लायक्रा स्पेंडेक्स एंड इलास्पेन स्पेंडेक्स (इनविस्टा) का आयात कर रहे हैं। लायक्रा स्पेंडेक्स की उनकी मासिक खपत लगभग 10 एमटी है। पहले उन्होंने इंडोरामा की इनविया स्पेंडेक्स का प्रयोग किया तथा ओर उनकी गुणवत्ता की समस्या हुई थी।
- (ज) जिंगुन मिंथेटिक, सिल्वरसैंड एजेंसिस एंड प्रेजीडेंस क्लोथिंग कंपनी: वे टेफेलोन कोरियाई ब्रांड स्पेंडेक्स के आयातक हैं और वे विभिन्न निर्यातकों, फेब्रिक निर्माताओं और जॉब कामगारों के स्पेंडेक्स यार्न बेच रहे हैं। इंडोरामा सिंथेटिक का विनिर्माण क्षमता भारतीय बाजार की कुल आवश्यकता का लगभग 30 प्रतिशत है, अत: पूरे बाजार को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त है। यदि स्पेंडेक्स यार्न के मूल्य बढ़ते हैं तो यह तैयार परिधान की लागत पर बोझ डालेगी जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय परिधान उद्योग की प्रस्पर्धात्मकता कम हो जाएगी।

(झ) भारतीय वस्त्रोद्योग संघ, मैसर्स अरविंद लिमिटेड और वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने पूछताछ निवेदन को अपने अधिवक्ता मैसर्स लक्ष्मी कुमारन और श्रीष्ठरण के माध्यम से दाखिल किया है:

- क. आवेदक ने इस मामले में अनपेक्षित घटनाक्रमों के अस्तित्व को दर्शाने के लिए कोई विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नहीं किया है।
- ख. आवेदक ने कहा है कि वह हिमाचल प्रदेश में प्रचालन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कुछ घटनाक्रमों को देखने में असमर्थ था । आवेदक द्वारा पहचान किए गए घटना क्रम वार्ताकारों की बजाए उस आवेदक के घटनाक्रम से संबंधित थे वह पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ था । इसके अलावा, कथित घटनाक्रम मार्च, 2012 में भी अनपेक्षित थे जब आवेदक ने वर्ष 1995 की बजाए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया जब वार्ताकारों ने संबद्ध रियायतें लीं थी । इसलिए कानून की दृष्टि से आवेदक का निवेदन अयुक्तियुक्त है ।
- ग. आवेदक का दावा है कि वह पिछड़े क्षेत्र का लाभ लेने में असमर्थ था जिसकी उसने आशा की थी । आवेदक ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किए हैं कि वह ऐसा लाभ लेने में असमर्थ क्यों था । इसके लिए कोई संभव कारण हो सकते हैं । आवेदक ने या तो सरकार द्वारा तय की गई कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है या सरकार ने अपनी नीति को बदल दिया है ।
- घ. जिस सीमा तक आवेदक सरकार द्वारा तय की गई कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा है, आवेदक को यह पूर्वानुमान लगाने में समर्थ होना चाहिए था कि यदि वह संबद्ध अपेक्षाओं को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे उक्त लाभ नहीं दिए जाएंगे।
- ङ. इसके अलावा, कारक जैसे कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के परिवहन और पहाड़ी क्षेत्र में लाजिस्टिक्स की ऊंची लागतें उस आवेदक के लिए पूर्णत: स्पष्ट होनी चाहिएं जो हिमाचल प्रदेश में यूनिट की स्थापना कर रहा था।
- च. महत्वपूर्ण दायित्व यह है कि मुद्दे में अनपेक्षित घटनाक्रम बढ़े हुए आयातों में परिणत हुए होंगे। वर्ष 2012-13 में आयात जब आवेदक ने उत्पादन शुरू किया 9341 थे जबिक इसकी तुलना में 2013-14 में 9986 (वार्षिक रूप से) थे, इसमें 645 यूनिट की मामूली वृद्धि हुई। वास्तव में यह वृद्धि केवल भारत में बढ़ी हुई बाजार मांग के कारण थी और आयात मांग के संबंध में वर्ष 2013-14 में कम हुए। यद्यपि आयात में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी मांग वास्तव में 24 प्रतिशत तक बढ़ी। इसलिए आवेदक भारत में बढ़ी हुई मांग का सबसे बड़ा लाभभोगी था। ऐसी परिस्थिति में यह सुझाव देना अत्यधिक कपटपूर्ण है कि घटनाक्रम जिन्हें हिमाचल प्रदेश में इसने प्रचालन स्थापित करने के समय नहीं देख सका बढ़े हुए आयातों में परिणत हुए।
- छ. जब आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया तो सीमा शुल्क की दर 5 प्रतिशत थी । चूंकि आवेदक ने प्रचालन मार्च, 2012 में शुरू किया था, इसलिए वह पहले सीमा शुल्क की दर की जानकारी रखता है । इसलिए वह संभवत: यह तर्क नहीं दे सकता है कि वह यह पूर्वानुमान नहीं लगा सका कि आयात शुल्क 5 प्रतिशत रहेगा क्योंकि शुल्क पहले ही 5 प्रतिशत था जब उसने प्रचालन शुरू किया ।
- ज. मौजूदा मामले में आयता हाल के, अचानक, तेज और उल्लेखनीय नहीं हैं जिसके कारण से प्रारंभिक कानूनी पाठों में विनिर्दिष्ट पद्धति को पूरा नहीं किया गया।

- झ. डीजी, सुरक्षा मानेंगे कि एलएबी मामले के विपरीत, जिसमें आयातों का बाजार हिस्सा बिल्कुल हाल के वर्ष तक बढ़ता रहा, मौजूदा मामले में घरेलू मांग में आयातों का हिस्सा वास्तव में कम हुआ है। इसलिए निष्कर्ष निकालने का अधिक कारण भी है कि आयातों की वृद्धि अचानक नहीं हुई थी। तेज वृद्धि की बजाए मांग के संबंध में आयातों में तेजी से कमी हुई है। इसलिए आयातों में अचानक, हाल में, तीव्र और उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है।
- ज. घरेलू उद्योग की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और उनका बाजार हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसलिए मौजूदा प्रवृद्धि बढ़ हुए आयातों को निर्दिष्ट नहीं करती परंतु वास्तव में दर्शाती है कि आयात लगातार कम हो रहे हैं। इस कारण से डब्ल्यूटीओ सुरक्षा करार के अनुच्छेद 2.1 और जीएटीटी के अनुच्छेद-XIX के साथ पठित धारा 8ख(1) के अर्थ के भीतर आयात में कोई बढ़ी हुई मात्राएं नहीं हैं।
- ट. प्रारंभिक अधिसूचना निर्दिष्ट करती है कि डीजी सुरक्षा वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में घरेलू बिक्री में कमी द्वारा प्रभावित प्रतीत होता है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आवेदन के पृष्ठ 29 के अनुसार तीसरी तिमाही में कुल बिक्री (निर्यात + घरेलू) पिछली तीन तिमाहियों में उच्चतम थी। घरेलू बाजार निम्न बिक्री का एकमात्र कारण यह था कि आवेदक ने पूर्ववर्ती तिमाहियों की तुलना में अधिक निर्यात किया।
- ठ. भारत में अंत्य उपयोगकर्ताओं को दोष देना काफी अनुचित है क्योंकि आवेदक का यह स्वयं का निर्णय था कि घरेलू बाजार की बाजाए अपने संसाधनों को निर्यातों को दे।
- ड. वर्ष 2013-14 में और अधिक प्रमुख रूप से वर्ष 2013-14 की तीसरी तिमाही में रुपया संयुक्त राज्य डालर के विरूद्ध उल्लेखनीय रूप से मूल्यह्रासित हुआ । इसके फलस्वरूप विदेशी वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) पर निर्भर उद्योगों के लिए उधार की लागत भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी थी । आवेदक इस मुद्दे पर खामोश है । क्षति, यदि कोई हो, आवेदक के उद्योग की अद्वितीय वित्तीय ढांचे के कारण हो सकती है ।
- ढ. आवेदक ने कोई समयबद्ध समयोजन योजना प्रस्तुत नहीं की थी परंतु क्षमता के विस्तार के केवल निराधार दावों को प्रस्तुत करते हैं।

(অ) सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

- क. मानव निर्मित मिश्रित फेब्रिक के निर्माण में "बेअर इलास्टो मेरिक फिलामेंट यार्न" का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है जिसके भारत से निर्यात पिछले वर्षों के दौरान बढ़ रहे हैं । इस मद का केवल एक भारतीय निर्माता मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज है ।
- ख. घरेलू विनिर्माण मद का मूल्य आयात सममूल्यता मूल्य के आधार पर रखेगा । जिसमें सुरक्षा शुल्क शामिल है । यह "बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" को और अधिक महंगा बना देगा । निर्यात उत्पाद की लागत सुरक्षा शुल्क तक बढ़ जाएगी । मानव निर्मित फेब्रिक के अधिकांश निर्यातक प्रति अदायगी रूट का प्रयोग करते हैं और वह सुरक्षा शुल्क को निष्प्रभावी नहीं करता है । इस प्रकार निर्यातक कम प्रतिस्पर्धी हो जाएगा ।
- ग. सरक्षा जांच को भारतीय वस्त्रोद्योग और निर्यातों के समग्र हित में समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

(ट) सिंथेटिक फाइबर उद्योग संघ

- क. स्पेंडेक्स यार्न घरेलू परिधान और फेब्रिक उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण यार्न है और यह चीन और कोरिया में प्रति स्पर्धी मूल्यों पर उपलब्ध है ।
- ख. आयात भारत से फेब्रिक और परिधानों के निर्यातों से संबद्ध हैं । इस किस्म से यार्न पर कोई शुल्क निर्यातों और घरेलू उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा ।
- ग. घरेलू उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अपने निर्यात मूल्य के परिकलन के लिए शुल्क प्रति अदायगी रूप पर कार्य करता है । सुरक्षा और एडीडी को शुल्क प्रति अदायगी परिकलनों में हिसाब में नहीं लिया गया है ।
- घ. घरेलू उद्योग ने पहले वस्त्र मंत्रालय को इस यार्न पर आयात शुल्क बढ़ाने के लिए संपर्क किया था ताकि एकाधिकारियों उत्पादक होने के कारण यह भारी लाभ अर्जित कर सके क्योंकि यह इस यार्न को भारत में आयात के बराबर बेचता है।
- ङ. यदि घरेलू उद्योग को आयातों से कोई क्षति उठानी पड़ती है तो इसे सुरक्षा शुल्क लगातार पूरे विश्व भर में संपूर्ण आयातों को अवरूद्ध करने की बजाय विशेष उपचार के लिए डीजीएडी को संपर्क करना चाहिए।

(ठ) तिरुपुर निर्यातक संघ

- क. तिरुपुर से निटवियर निर्यातक यूनिटें भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिल्लामेंट यार्न की कुल खपत लगभग 25 प्रतिशत की खपत करते है।
- ख. परिधान निर्यातक प्रतिस्पर्धात्मक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तभी बने रह सकते हैं जब वे मूल्य के अलावा वांछित गुणवत्ता वाले परिधानों की आपूर्ति करते हैं और यहां तक कि गुणवत्ता में थोड़ा परिवर्तन जागरूक खरीददारों को अन्य प्रतिस्पर्धी देशों से लेने के लिए प्रेरित करेगा।
- ग. मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का क्षमता का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है और यह एक वर्ष में 2012-13 (पहली तिमाही) में 54.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 (पहली तिमाही) में 99;8 प्रतिशत हो गया, जो संकेत करता है कि परिधान उद्योग घरेलू बाजार में उनके यार्न को खरीद रहा था और वे घरेलू उत्पाद से यार्न लेने को भी तरजीह दे रहे हैं।
- घ. घरेलू निर्माता का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में केवल 9 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012-13 (चौथी तिमाही) में, नौ महीनों में 39 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2013-14 (पहली तिमाही) में कमोबेश 38 प्रतिशत बना रहा। कमी केवल वर्ष 2013-14 (दूसरी तिमाही और क्यू 3) तिमाहियों में देखी गई है।
- ङ. सुरक्षा उपायों को लगाना निटवियर परिधान के निर्यातकर्ता यूनिट की घरेलू खपत को बढ़ाने में किसी भी तरह से सहायक नहीं होगा और इसके अलावा सिलसिलेवार प्रतिक्रिया के रूप में लगाया गया शुल्क तिरुपुर के हिस्सेधारों और उनमें नियोजित लोगों को प्रभावित करेगा।

(ड) बीबीएन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

- क. मैसर्स इंडोरामा के संयंत्र की क्षमता 5000 एमटी/वर्ष है और यह पिछले एक वर्ष से (इसकी संस्थापना के एक वर्ष के अंदर) 90 प्रतिशत से अधिक उपयोगिता पर प्रचालन कर रहा है।
- ख. मैसर्स इंडोरामा इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न की केवल सीमित उत्पाद श्रृंखला का उत्पादन कर रहा है और अपनी कुछ वस्तुओं का निर्यात कर रहा है।
- ग. घरेलू निर्माता की क्षमता मौजूदा खपत की दर पर घरेलू मांग का केवल 30 प्रतिशत है और मांग तेजी से बढ़ रही है।
- घ. इसके बहुत से उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों को मौजूदा उत्पाद श्रृंखला में गुणवत्ता की समस्या है । यदि निर्माण गुणवत्ता समस्या को संबोधित कर सकता है तो वे लाभ की इच्छी राशि के साथ उत्पादों को बेचने में समर्थ हो सकेंगे ।

(ढ) सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन

- क. संघ (एस आई एम ए) 80 वर्ष पुराना है और यह एकल सबसे बड़ा नियोजक संगठन है जो देश में काटन अनुसंधान और विकास से लेकर परिधानों/बने बनाए/तकनीकी वस्त्रों तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है और वस्त्रोद्योग से संबंधित राज्य और केंद्र स्तर पर सभी नीति बनाने वाली समितियों में अग्रणी भूमिका निभाता है।
- ख. उनकी कुछ सदस्य मिलें बेअर इलास्टोमेरिक/स्पेंडेक्स यार्न का आयात करती हैं और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग को पूरा करने के लिए मूल्य वर्धित सामग्रियों जैसे मूल स्पन यार्न, स्ट्रेच फेब्रिक (डेनिम फेब्रिक सहित निटिड, बुने हुए) का उत्पादन करती है।
- ग. संघ ने स्पेंडेक्स यार्न पर किसी सुरक्षा शुल्क के लिए कड़ी आपत्ति की है जो ऐसे निर्माताओं के विकास को कम करेगी और विदेशी मुद्रा अर्जनों को भी कम करेगी।
- घ. मैसर्स इंडोरामा सिंथेटिक (भारत में एकाधिकारिक विनिर्माता) द्वारा विनिर्मित स्पेंडेक्म यार्न की गुणवत्ता बहुत से गुणवत्ता के पैरामीटरों में आयातित स्पेंडेक्स यार्न की तुला में कहीं घटिया है ।
- इ. घरेलू विनिर्माता को पहले ही 3 प्रतिशत बुनियादी सीमा शुल्क, 4 प्रतिशत विशेष अतिरिक्त शुल्क, 12 प्रतिशत प्रतिकारी शुल्क और प्रयोज्य शुल्क उपकर के द्वारा 19 से 20 प्रतिशत का लाभ ले रहा है, जबिक भारत के प्रतिस्पर्धी देश जैसे कि पाकिस्तान में कोई आयात शुल्क नहीं है और यहां तक कि देश जैसे इटली में स्पेंडेक्स यार्न पर केवल 4 प्रतिशत शुल्क है। चीन, विश्व में स्पेंडेक्स यार्न का सबसे बड़ा उत्पादक, में कोई आयात शुल्क नहीं है।
- च. मैसर्स इंडोरामा सिंथेटिक द्वारा उत्पादित मात्रा केवल उपयोगकर्ताओं के 20 प्रतिशत की जरूरतों को पूरा करती है और शेष को अनिवार्य रूप से इलास्टोमेरिक यार्न के आयातों पर निर्भर होना पड़ता है ।

(ण) एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन

- क. आवेदक ने अपनी बिक्री और उत्पादन डाटा में विशेष डेनियर और मात्रा के ब्यौरे प्रदान नहीं किए हैं, अत: यह उचित होगा कि मामले पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए डाटा पर विचार किया जाए । स्पेंडेक्स में बहुत सी किस्में और डेनियर हैं अत: मामले का उचित डाटा के साथ अध्ययन किया जाना आवश्यक है ।
- ख. बहुत सी किस्में और डेनियर हैं जिन्हें स्थानीय विनिर्माता द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता अत: समग्र उत्पाद लाइन पर कोई सुरक्षा शुल्क लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है । उत्पाद का मूल्य उत्पाद की गुणवत्ता और डेनियर पर निर्भर करता है, अत: यह अनप्रयोग उचित और सही नहीं है ।
- ग. भारत में केवल एक निर्माता है और उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क लगाने से इस क्षेत्र में विनिर्माता द्वारा एकाधिकार हो जाएगा । यह एमआरटीपी के भारतीय अधिनियम के भी विपरीत होगा ।
- घ. भारतीय वस्त्र निर्माता निर्यात और स्थानीय प्रीमियम ब्रांड के लिए स्पेंडेक्स निटिड/ बुने हुए/तंग फेब्रिक का निर्माण करता है, अधिकांशत: वे आयातित स्पेंडेक्स का प्रयोग करते हैं क्योंकि स्थानीय स्पेंडेक्स निर्माण की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानक के बराबर नहीं है और उनका स्पेंडेक्स निम्न बाजार के लिए लागत के लिए जागरूक वस्त्र निर्माता द्वारा प्रयोग की जा रही है। अत: उक्त उत्पाद के ग्राहक को या तो सीधे ही इसका आयात करके या इसे आयातकों के माध्यम से खरीदना पड़ता है।
- ङ. आवेदक द्वारा अनुबंध 5क में प्रस्तुत उत्पादन और बिक्री डाटा निर्दिष्ट करते हैं कि स्थानीय बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मानक उत्पादों के बिक्री मूल्य की तुलना में काफी कम है । प्रस्तुत किया गया निर्यात डाटा यह दर्शाता है कि स्थानीय आवेदक द्वारा प्राप्त बिक्री मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में काफी कम है ।
- च. काफी कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचना सुरक्षा शुल्क लगाने का पक्ष प्राप्त करने के कारण हो सकता है । आवेदक उत्पाद को घटिया गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार बेच नहीं सका ।
- छ. स्थानीय विनिर्माता के पास अपने समग्र उत्पादन से लगभग 40-50 प्रतिशत का निर्यात करने के पश्चात् भारतीय स्पेंडेक्स उपयोगकर्ता की जरूरत को पूरा करने के लिए लगभग 200 एमटी/महीना बच जाता है और इस समय स्पेंडेक्स के लिए भारतीय बाजार लगभग 1100 से 1200 एमटी/माह है, अत: भारतीय उपयोगकर्ता के पास स्पेंडेक्स के आयात को छोड़कर कोई विकल्प नहीं रहता है।
- ज. बेरोजगारी होगी जो आवेदक द्वारा दिए गए रोजगार की तुलना में कम से कम 20 प्रतिशत अधिक होगी । बेरोजगारी के अलावा, सुरक्षा शुल्क के कारण स्पेंडेक्स की ऊंची दरों का प्रयोग करके भारत में विनिर्मित उत्पादों के गैर-प्रतिस्पर्धी मूल्यों के कारण राजस्व की हानि होगी ।
- झ. उनके मुखिया द्वारा प्रस्तृत चालू आयात मृल्य आवेदक द्वारा बताए गए मृल्य से कहीं अधिक हैं।
- ञ. स्थानीय निर्माता द्वारा प्रस्तुत मूल्य बेचे जा रहे आयातित उत्पाद के मूल्य की तुलना में काफी कम है । कम मूल्य गुणवत्ता समस्या के कारण हो सकता है या सुरक्षा शुल्क के लिए आवेदक की तैयारी की योजना के कारण हो सकता है ।
- ट. स्थानीय निर्माता का आयातित मूल्य निर्धारण के बारे में दावा कुछ भेदभाव पूर्ण है और पूरी तरह नहीं बताया गया है क्योंकि स्पेंडेक्स यार्न के मूल्य डेनियर के अनुसार घटते-बढ़ते है । डेनिए जितना महीन होगा उतना मूल्य निर्धारण ऊंचा होगा, स्थानीय निर्माता ने डेनियर के अनुसार आयातित स्पेंडेक्स की स्पष्ट तस्वीर नहीं दी है ।
- ठ. आवेदक केवल 1 प्रतिशत सीएसटी (बिक्री कर) ले रहा है इसकी तुलना में वे 5 प्रतिशत वैट ले रहे हैं। आवेदक को बिक्री कर की रियायती दर दी जा रही है। आवेदक दावा करता है कि स्पेंडेक्स का आयात करना सस्ता है परंतु वास्तव में स्थानीय स्पेंडेक्स निर्माण की तुलना में यह महंगा है।
- ड. आवेदक के पास स्पेंडेक्स का विशेष उत्पाद नहीं है जैसाकि समुद्रपारीय स्पेंडेक्स निर्माता के पास है उदाहरण: काली स्पेंडेक्स/कम ताप पर स्थितर स्पेंडेक्स/क्लोरीन रोधी स्टेंडेक्स/डायपर अनुप्रयोग के लिए स्पेंडेक्स/ऍठन बुनाई के लिए प्रयोज्य स्पेंडेक्स आदि।
- ढ. आवेदन द्वारा दर्शाई गई हानि पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कम उत्पादन क्षमता और उत्पाद की ऊंची लागत के कारण है। सभी अंतर्राष्ट्रीय निर्माता अपने उत्पाद सुखद बाजार मूल्यों पर बेच रहे हैं और हानि नहीं दर्शा रहे है जैसाकि स्थानीय निर्माता द्वारा दावा किया गया है। कम मूल्य पर ब्रिकी ओर उत्पादन की ऊंची लागत के कारण हानि हुई है।
- ण. यदि सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है तो वस्त्र निर्माता जो गुणवत्ता वाली स्पेंडेक्स फेब्रिक का निर्माण कर रहे हैं अनावश्यक लागत वृद्धि के कारण मुसीबत में आ जाएंगे जो लागत वृद्धि से भारतीय निर्यातक बंगलादेश, पाकिस्तान, वियतनाम और चीन प्रतिस्पर्धियों आदि से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता।

(त) पीकेपीएन स्पेंडेक्स मिल्स (प्राइवेट) लिमिटेड और गीमाटेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड

- क. इंडोरामा स्पेंडेक्स निर्माण की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर को पूरा करने के लिए स्तर की नहीं है।
- ख. इंडोरामा स्पेंडेक्स निर्माता की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर को पूरा करने के लिए स्तर की नहीं है।
- ग. इंडोरामा अपनी स्पेंडेक्स आयातित स्पेंडेक्स की तुलना में घटिया गुणवत्ता की स्पेंडेक्स होने के कारण कम मूल्य पर बेच रहा है।
- घ. किसी वस्त्र या परिधान में स्पेंडेक्स लगभग 2-8 प्रतिशत होती है, अत: निर्माता को गुणवत्ता आश्वस्त स्पेंडेक्स का प्रयोग करना होता है क्योंकि किसी वस्त्र स्ट्रेच फेब्रिक में शामिल प्रमुख लागत अन्य वस्त्र फेब्रिक जैसे सूती/पालिएस्टर आदि की लागत शामिल होती है, स्पेंडेक्स लागत वस्त्र फेब्रिक या परिधान में प्रमुख नहीं होती । अत: स्पेंडेक्स की गुणवत्ता अत्याधिक महत्वपूर्ण है।
- ङ. इंडोरामा काली स्पेंडेक्स/कम ताप निश्चित स्पेंडेक्स/क्लोरीन रोधी स्पेंडेक्स का निर्माण नहीं कर रहा है।
- च. इंडोरामा का आयातित स्पेंडेक्स के मूल्य निर्धारण का दावा सही नहीं है, आयातित स्पेंडेक्स महंगी होती है क्योंकि आयतक को सीआईएफ मूल्य पर लगभग 19-20 प्रतिशत शुल्क अदा करना होता है ।
- छ. अच्छी किस्म के वस्त्र स्ट्रेच यार्न या फेब्रिक के भारत के निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय मानक की स्ट्रेच वस्त्र फेब्रिक का उत्पादन करने के लिए विनिर्माता के लिए गुणवत्ता वाली स्पेंडेक्स के निर्यात के कारण भारत अच्छा विदेशी राजस्व पैदा कर रहा है ।
- ज. यदि सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है तो वस्त्र निर्माता जो गुणवत्ता वाली स्पेंडेक्स फेब्रिक का निर्माण कर रहे हैं अनावश्यक लागत वृद्धि के कारण मुसीबत में आ जाएंगे, जो लागत में वृद्धि के कारण भारतीय वस्त्र निर्यात को और प्रभावित करेगा उस लागत वृद्धि से भारतीय निर्यातक बंगलादेश, पाकिस्तान, चीनी प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला नहीं कर सकता।

(थ) गिंजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- क. स्पेंडेक्स निर्माता की गुणवत्ता अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानक की नहीं है और इस स्थानीय स्पेंडेक्स का प्रयोग करके उत्पादित अंतिम फेब्रिक खरीददार द्वारा खारिज कर दी जाती है ।
- ख. स्थानीय निर्माता की स्पेंडेक्स निर्माण क्षमता लगभग 500 एमटी प्रति माह है परंतु वास्तव में वे केवल 350/450 एमटी/ माह का निर्माण कर रहे हैं। इस भाग का लगभग 40 प्रतिशत उनके द्वारा खराब गुणवत्ता के कारण अधोमुख सामग्री के रूप में निर्यात किया जा रहा है। अब लगभग 800 एमटी की भारतीय स्पेंडेक्स आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगभग 200 एमटी बचता है। इस प्रकार भारतीय उपभोगकर्ता के पास स्पेंडेक्स के आयात के सिवाए और विकल्प नहीं रहता।
- ग. स्थानीय स्पेंडेक्स निर्माता दावा करते हैं कि स्पेंडेक्स का आयात करना सस्ता है परंतु वास्तव में यह स्थानीय स्पेंडेक्स निर्माता की तुलना में महंगा है और वे उपयोगकर्ता के रूप में आयातित स्पेंडेक्स की गुणवत्ता के कारण, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक की है, आयातित स्पेंडेक्स के लिए ऊंची लागत अदा कर रहे है और गुणवत्ता वाले वस्त्र के अंतिम उत्पाद के निर्माण में उनको आश्वस्त करती है।

(द) सचमाम फेब्रिक प्राइवेट लिमिटेड

- क. उक्त इंडोरामा द्वारा विनिर्मित और आपूर्ति किए जा रहे उत्पाद की गुणवत्ता मानक वाली नहीं है।
- ख. वे स्वयं भी उत्पादों की नियमित और समय पर आपूर्ति करने में समर्थ नहीं हैं।
- ग. उक्त सामग्री का कुल बाजार आकार लगभग 1200 एमटी प्रति माह है जबिक इंडोरामा का वास्तविक उत्पादन एक चौथाई बाजार मांग को भी पुरा करने में समर्थ नहीं है।
- घ. भारत में केवल एक निर्माता है और उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क लगाने से इस क्षेत्र में एक निर्माता का एकाधिकार हो जाएगा।
- ङ. आयातित वस्तुओं की लागतें उक्त इंडोरामा द्वारा लिए जा रहे मूल्य की तुलना में अधिक हैं।
- च. भारत के पास केवल एक स्पेंडेक्स निर्माता है जिसकी क्षमता थोड़ी है और वह भारतीय स्पेंडेक्स की मांग, जो कि लगभग 1100 टन प्रति माह है, को पूरा करने में समर्थ नहीं है ।

(ध) एजीटी मिल्स और गीमा मैन्यूफेक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड

- च. इंडोरामा स्पेंडेक्स निर्माता की गुणवत्ता स्तर की नहीं है।
- छ. इंडोरामा की उत्पादन क्षमता पुरे भारतीय बाजार की जरूरत को पुरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- ज. इंडोरामा अपनी स्पेंडेक्स इसकी घटिया किस्म के कारण आयातित स्पेंडेक्स की तुलना में सस्ते मुल्य पर बेच रहा है।
- झ. इंडोरामा स्पेंडेक्स निर्माता की स्पेंडेक्स के उत्पादन की क्षमता थोड़ी है जो लाभ कमाने के लिए इसकी हानि रहित व्यापार करने की लागत के लिए एक कारण हो सकता है।
- ञ. इंडोरामा का आयातित स्पेंडेक्स के मूल्य निर्धारण के बारे में दावा सही नहीं है, आयातित स्पेंडेक्स महंगी है और आयातक को मूल्य पर लगभग 19.20 प्रतिशत शुल्क अदा करना होता है ।

(न) जिओन इंटरनेशनल

- क. **एकाधिकार का सृजन कर रहा है:** यदि सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है तो यह एकाधिकार जैसी स्थिति का सृजन करेगी जिसमें वस्त्र निर्माताओं के पास कोई विकल्प नहीं होगा परंतु स्पेंडेक्स यार्न इंडोरामा से खरीदना होगा, जो कि भारत में स्पेंडेक्स यार्न का एकमात्र निर्माता है।
- **ख. पर्याप्त क्षमता नहीं है :** जैसाकि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया है कि भारत में स्पेंडेक्स यार्न की वर्तमान मांग लगभग 3500 टन प्रति तिमाही है ।
- ग. **इंडोरामा का व्यवसाय फल-फूल रहा है:** अपने व्यवसाय को स्थानीय करने के दो वर्ष से कम समय में वे क्षमता उपयोग में 90-99 प्रतिशत से अधिक कुशलता प्राप्त करने में समर्थ हुए है और वर्ष 2013-14 की पिछली तीन तिमाहियों में अपने उत्पादन का 98 प्रतिशत बेचने में समर्थ रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि उनका कारोबार फल-फूल रहा है, आयातों से कोई आशंका नहीं है।
- घ. आयातों में ऐसी पर्याप्त वृद्धि नहीं है जो आशंका का संकेत करती हो: आरंभन के नोटिस का पैरा यह दर्शाता है कि आयातों में जो वर्ष 2012-13 के क्यू 1 में 2488 एमटी थे से वर्ष 2012-13 के क्यू 4 में कम होकर 2111 एमटी रह गए और केवल वर्ष 2013-14 के क्यू 3 में मामूली बढ़कर 1682 एमटी हो गए जो उत्पादन के संबंध में आयातों का 229 प्रतिशत से 238 प्रतिशत तक की वृद्धि है। स्थिर पद में यह केवल 3.9 प्रतिशत की वृद्धि है। एक एकल तिमाही में 4 प्रतिशत की वृद्धि निश्चित रूप से अधिक नहीं है। इसके अलावा, यह मौसमी कारकों, फैशन प्रवृत्ति आदि के कारण भी हो सकता है। इसी अर्थ में यदि वर्ष 2012-13 के क्यू 3 की वर्ष 2013-14 के क्यू 3 के साथ तुलना करनी हो तो आयातों का प्रतिशत (उत्पादन के संबंध में) 582 प्रतिशत से 238 प्रतिशत तक गिरा है, जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि आयातों में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है।
- **ङ**. **निम्न गुणवत्ता मानक :** स्पेंडेक्स के वस्त्रोद्योग में विभिन्न अनुप्रयोग हैं : मुख्य अनुप्रयोग हैं : सर्कुलर बुनाई, कोर स्पिनिंग, वायु कवरिंग और महीन फेब्रिक । इनमें से वायु कवरिंग केवल ऐसा अनुप्रयोग है जिसमें बहुत उच्च गुणवत्ता मानक वाली अपेक्षित नहीं होता और इन ग्राहकों द्वारा केवल मूल्य प्रतिस्पर्धी स्पेंडेक्स मांगी जाती है । इन खंडों में इंडोरामा का निष्पादन निम्नानुसार है :

ਰ.

बाजार खंड	कुल स्पेंडेक्स मांग का प्रतिशत	खंड में इंडोरामा के हिस्से का प्रतिशत	इंडोरामा की स्वीकार्यता
कोर स्पिनिंग	35	15	खराब
सर्कुलर निटिंग	30	15	खराब
एयर कवरिंग	20	60	अच्छी
महीन फेब्रिक	15	10	खराब

छ. घरेलू और निर्यात बाजारों में सस्ते मूल्य निर्धारण के कारण हानियां: वर्ष 2012-13 की पहली तीन तिमाहियें में इंडोरामा के लिए हानि 3.65 करोड़ रुपए है, जबकि वर्ष 2013-14 की उसी अवधि में हानि केवल 2.65 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2013-14 की अवधियों में भी आयातों में मामूली वृद्धि हुई जैसाकि इंडोरामा द्वारा दावा किया गया है । इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि उनकी हानि में 27 प्रतिशत की कमी हुई है, हालांकि उपर्युक्त अवधि में आयातों में वृद्धि हुई है ।

ज. निर्यात में वृद्धि के फलस्वरूप घरेलू बाजार का हिस्सा कम हो रहा है: कमी के लिए निर्यात मात्रा में क्यू 4 (2012-13) में 106 एमटी से क्यू 3 (2013-14) में 532 एमटी तक पर्याप्त वृद्धि मुख्य कारण है। यह स्पष्ट है कि घरेलू बाजार के हिस्से थोड़ी कमी केवल इंडोरामा द्वारा निर्यात में वृद्धि के कारण है और न कि आयातित स्पेंडेक्स यार्न की वृद्धि के कारण है।

(प) आरवी डेनिम एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड

- क. इंडोरामा द्वारा बनाई जा रही स्पेंडेक्स फिलामेंट की गुणवत्ता अब तक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार नहीं है।
- ख. आयातित स्पेंडेक्स यार्न का मूल्य मौजूदा आयात शुल्क के पश्चात 510 किलोग्राम बैठता है जबकि उत्पादित की जा रही भारतीय स्पेंडेक्स का मूल्य लगभग 500 किलोग्राम है, जिसका अर्थ है कि भारतीय स्पेंडेक्स का मूल्य उसकी खराब गुणवत्ता के कारण आयातित की तुलना में कम है।
- ग. इसके अलावा भारतीय निर्माता से आपूर्ति भारतीय कुल मांग की तुलना में काफी कम है।

(फ) आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन

- क. इंडोरामा के उत्पाद की गुणवत्ता इसके बाजार हिस्से को बढ़ने नहीं दे रही है।
- ख. इंडोरामा पूर्ण क्षमता पर, बशर्ते कि यह सामग्री निर्यात नहीं करता, बाजार आवश्यकता के केवल 30 प्रतिशत की आपूर्ति कर सकता है ।

(ब) मैसर्स इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड, तिरुपुर एंड मैसर्स नेशनल सिंथेटिक

- क. प्रस्तुत किया गया डाटा किसी भी ढंग से मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले का समर्थन नहीं करता क्योंकि बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों में असाधारण वृद्धि हुई है ।
- ख. मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड मार्च, 2012 में स्थापित हुई थी और पहले दिन से ही इसने उत्पादन शुरू किया, यह न केवल अपनी क्षमता का उपयोग का 99.8 प्रतिशत प्राप्त करने में समर्थ रही आपितु वर्ष 2013-14 के दौरान अपने उत्पादन का 98 प्रतिशत बेचने में समर्थ रही।
- ग. उत्पादन के साथ-साथ बिक्री दोनों में लगातार वृद्धि हुई है।
- घ. निर्यातों सहित बिक्री के आंकड़े बढ़कर 3453 एमटी हो गए हैं जो वर्ष 2013-14 (दिसम्बर, 2013 तक) के दौरान कुल उत्पादन का 98 प्रतिशत है।
- ङ. आयात वर्ष 2012-13 के क्यू 1 से 2488 एमटी से कम होकर वर्ष 2012-13 के क्यू 4 में 2111 एमटी रह गए हैं और आधार केवल जिस पर क्षिति हुई है वर्ष 2013-14 के क्यू 3 में आयातों में मामूली वृद्धि के कारण कही जा सकती है, जिसमें यह 229 प्रतिशत से बढ़कर 238 प्रतिशत हो गई जो चरम पद में 3.9 प्रतिशत है। केवल एक तिमाही में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि को आयातों में अचानक और तेल वृद्धि नहीं कहा जा सकता है विशेष रूप से तब वर्ष के दौरान आयातों पूर्ववर्ती तदनुरूपी वर्ष की तुलना में समग्र कमी हुई है।
- च. किसी उद्योग के लिए मांग और आपूर्ति को तिमाही से तिमाही के आधार पर नहीं मापा जा सकता है क्योंकि विभिन्न कारकों के कारण मौसमी घटबढ़ हो सकती है और केवल गहराई से अध्ययन ऐसे कारकों को बाहर का सकता है।
- छ. घरेलू निर्माताओं द्वारा अपेक्षित यार्न की गुणवत्ता मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विनिर्माण नहीं किया जा रहा था, इसलिए आयातों की मात्रा में कुछ वृद्धि हो सकती है ।
- ज. कारक जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, घरेलू मांग में बाजार का हिस्सा, बिक्री के स्तर में परिवर्तन, लाभ/हानि, उत्पादकता और नोटिस के पैरा 7 में बताया गया रोजगार मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के किसी क्षति या तो हो रही है या क्षति की कोई आशंका है के दावे का समर्थन नहीं करते है ।
- झ. किसी विशेष तिमाही में घरेलू मांग में 2.1 प्रतिशत की सांकेतिक कमी चिंता का कभी कारण नहीं हो सकता और यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू बाजार को क्षति पहुंचायी है।

- ञ. स्पेंडेक्स का उपयोग स्ट्रेज फेब्रिक में है । भारत में मुख्य बाजार खंड कोर स्पिनिंग, सर्कुलर बुनाई, एयर कवरिंग, महीन फेब्रिक, डायपर आदि हैं । इन खंडों में से मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पाद की स्वीकृति केवल मूल्य संवेदी एयर कवरिंग खंड में है ।
- ट. यहां तक कि यदि यह माना जाए कि आयातों में वृद्धि हुई, फिर भी हानियां अधिक होने की बजाए कम हो गई हैं। इस प्रकार हानि न केवल आयातों में वृद्धि के कारण है अपितु वाणिज्यिक कारणों जैसे लंबी सारगर्भ अवधि, जिसमें उत्पादन की लागत बिल्कुल पहले वर्ष के उत्पादन में वसूल नहीं की जा सकती, के कारण हो सकती है। यह प्रबंध के नियंत्रण, कुशलता नियोजित प्रौद्योगिकी और विभिन्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है।
- ठ. जहां तक उत्पादकता और रोजगार का संबंध है, प्रति कर्मचारी उत्पादन जो वर्ष 2012-13 में 2.6 प्रतिशत था वर्ष 2013-14 में बढ़कर 4.7 प्रतिशत हो गया है। इस प्रकार उत्पादकता और रोजगार के आधार पर घरेलू उद्योग को कोई क्षति होना नहीं कहा जा सकता है जहां तक मालसूची का संबंध है वह भी वर्ष 2012-13 में 94 दिनों से कम होकर 2013-14 में 49 दिन पर आ गई है, जो कि बहुत उल्लेखनीय सुधार है।
- ड. आयात मुल्य काफी बढ़ गया है जो मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के दावे की आयात मुल्य कम है के विपरीत है।
- ढ. आयातों के कारण मूल्यों में कोई कटौती नहीं की गई है कि या मूल्य पर दबाव के लिए कारण है और इसके विपरीत अंतर बढ़ रहा था । फिर भी वर्ष 2013-14 क्यू 2 में घरेलू बिक्री में कमी हुई थी जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन में आकस्मिक संपर्क है ।
- ण. पूर्ण क्षमता के उपयोग से भी मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अधिक से अधिक बाजार आवश्यकता के केवल एक तिहाई को पूरा कर सकता है । अत: सुरक्षा शुल्क लोक हित में नहीं होगा ।
- त. इंडोरामा द्वारा बनाई जा रही स्पेंडेक्स फिलामेंट की गुणवत्ता उपयोगकर्ताओं की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है।
- थ. आवेदक ने किसी समायोजना योजना का प्रस्ताव नहीं किया है परंतु केवल एक विस्तार योजना का प्रस्ताव किया है।
- द. भारत में केवल एक निर्माता है और उत्पाद पर सरक्षा शल्क लगाने से इस क्षेत्र में निर्माता द्वारा एकाधिकार हो जाएगा।

(भ) नैरो इलास्टिग मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन

- क. मौजूदा मामले में उत्पाद गुणवत्ता अभी निश्चित की जानी है। वास्तव में यह घटिया है।
- ख. आयात मांग और घरेलू उपलब्धता के बीच अंतर के कारण होती है।

(म) विष्णु टेक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड:

- ट. कोई भी ग्राहक इंडोरामा स्पेंडेक्स यार्न की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है।
- ठ. घरेलू उत्पाद आयातित स्पेंडेक्स की तुलना में सस्ता है।

(य) जीनथ फाइबर एंड जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड

- क. स्थानीय निर्माता की स्पेंडेक्स निर्माण की क्षमता लगभग 500 एमटी प्रति माह है और वे लगभग 350-400 एमटी/माह का निर्माण कर रहे है और इसमें से वे इसके गुणवत्ता स्तर के कारण निम्न मूल्य निर्धारण पर लगभग 40-45 प्रतिशत का निर्यात कर रहे हैं।
- ख. स्थानीय निर्माता के पास अपने समग्र उत्पादन से लगभग 40-45 प्रतिशत का निर्यात करने के पश्चात लगभग 200 एमटी/माह भारतीय स्पेंडेक्स के उपयोगकर्ता की जरूरतों को पूरा करने के लिए बच जाते हैं और इस समय भारतीय बाजार का आकार स्पेंडेक्स की खपत के लिए लगभग 1000 एमटी/माह है, अत: भारतीय उपयोगकर्ता के पास स्पेंडेक्स के आयात करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।
- ग. स्पेंडेक्स बुनियादी रूप से अन्य साथी वस्त्र फाइबर जैसे सूती/पालिएस्टर/नायलान आदि के साथ वस्त्र फेब्रिक या परिधान बनाने में प्रयोग किया जाता है और तैयार फेब्रिक अवस्था में स्पेंडेक्स का अंश अधिकांशत: लगभग 2-8 प्रतिशत होता है और शेष लगभग 90-98 प्रतिशत साथी अन्य वस्त्र फाइबर का होता है, अत: स्पेंडेक्स की गुणवत्ता वस्त्र फाइबर और परिधान के भविष्य का निर्णय करती है। यदि स्पेंडेक्स की गुणवत्ता खराब होती है तो उपयोगकर्ता या वस्त्र निर्माता को अन्य साथी वस्त्र फाइबर की बड़ी लागत के कारण भारी वित्तीय हानि हो सकती है।

- घ. स्थानीय स्पेंडेक्स निर्माता दावा करते हैं कि स्पेंडेक्स का आयात करना सस्ता है परंतु वास्तव में यह स्थानीय स्पेंडेक्स की तुलना में महंगा है।
- ङ. यदि सुरक्षा शुल्क लगाया जाता है तो मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एकाधिकारिक आपूर्तिकर्ता बन जाएगा और अधिक मूल्य लेगा जिससे फेब्रिक में मूल्य वृद्धि हो जाएगी जो प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी की जीवन निर्वाह की लागत को प्रभावित करेगी।

(कक) किरण टेक्सप्रो प्राइवेट लिमिटेड

- क. स्थानीय निर्माता की गुणवत्ता स्तर की नहीं है और इसमें बहुत सी समस्याएं जैसे अनवाइंडिग, स्टिककिंग, स्रिंकेल, स्ट्रेच आदि हैं।
- ख. इलास्टिक टेप में प्रयुक्त स्पेंडेक्स 13 प्रतिशत से 15 प्रतिशत है और नायलोन लगभग 85 प्रतिशत है । नायलोन यार्न भी महंगा यार्न है, इस प्रकार खराब गुणवत्ता वाली स्पेंडेक्स यार्न के प्रयोग से, तीन किस्म की हानियां हुईं (1) उत्पादन में हानि (2) अपशिष्ट और (3) व्यवसाय में हानि ।
- ग. क्षमता घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और भारत में केवल एक निर्माता है और उत्पाद पर सुरक्षा शुल्क लगाने से विनिर्माता का इस क्षेत्र में एकाधिकार हो जाएगा । यह एमआरटीपी के भारतीय अधिनियम के भी प्रतिकूल होगा ।
- (खख) मैसर्स टीपीएम परामर्शदाताओं ने इच्छुक पक्षों (1) एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (2) आरवी डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड (3) भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (4) जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड (5) मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और (6) वेलस्पन सिनटेक्स लिमिटेड (7) डेनिम मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (8) बिरला सेंचुरी (9) ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड (10) रेमंड यूको डेनिम प्राइवेट लिमिटेड
 - क. सुरक्षा महानिदेशक द्वारा जारी व्यापार नोटिस के अनुसार सूचना कम से कम तीन वर्षों के लिए अपेक्षित है और किसी लंबी अवधि पर विचार किया जा सकता है।
 - ख. याचिका को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण तथ्यों को महानिदेशक (सुरक्षा) से छिपाया है। याचिकाकर्ता ने याचिका डिम्पंग रोधी शुल्क लगाने के लिए दाखिल की है। तथापि नामित प्राधिकारी ने याचिका को इस कारण से खारिज किया है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि विचाराधीन उत्पाद के ''डम्प किए गए आयात'' भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना को धीमा कर रहे थे।
 - ग. याचिकाकर्ता उपर्युक्त 80 डीनियर के विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन नहीं करता, इसलिए 80 एमएम से ऊपर विचाराधीन उत्पाद को किसी सुरक्षा शुल्क से छोड़ दिया जाना चाहिए ।
 - घ. स्थानीय निर्माता के पास कोई बीमिंग सुविधा नहीं हैं। चूंकि घरेलू उद्योग बीम पर कोई याम का उत्पाद और आपूर्ति नहीं करती, इसलिए बीम पर याम को विचाराधीन उत्पाद को वर्तमान जांच और प्रस्तावित उपायों के कार्य क्षेत्र से छोड़ दिया जाना चाहिए।
 - ङ. आयातों ने ऐसी कोई अचानक, उल्लेखनीय, तीव्र और हाल की वृद्धि नहीं दर्शाई है कि सुरक्षा कानून के अर्थ के अंदर बढ़े हुए आयात बनते हों । आयात 2012-13 के क्यू 1 से 2012-13 के क्यू 2 तक बढ़े है और उसके पश्चात 2012-13 के क्यू 4 तक मामूली गिरे हैं ।
 - च. घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में आयातों का तिमाही विश्लेषण दर्शाता है कि उत्पादन के संबंध में आयातों में क्यू 1 की तुलना में 2012-13 के क्यू 2 में वृद्धि हुई है, तथापि इनमें हाल की अवधि में कमी हुई है।
 - छ. "अनपेक्षित घटनाक्रम" सुरक्षा उपाय लगाने के लिए आवश्यक कारक है और याचिकाकर्ता किसी अनपेक्षित घटनाक्रम पर अपना दावा करने में विफल रहा है । जिससे आयातों में कोई वृद्धि हुई हो ।
 - ज. याचिकाकर्ता के अनुसार भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग 3352 एमटी प्रति तिमाही (वर्ष 2013-14 के क्यू 3 के आधार पर) 1250 एमटी/तिमाही है अर्थात देश की कुल आवश्यकता का 37 प्रतिशत है । अत: देश की शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है परंतु कुल घरेलू मांग का लगभग 63 प्रतिशत का आयात करना है ।
 - झ. सुरक्षा करार का अनुच्छेद 4.1 (ख) शर्त लगाता है कि गंभीर क्षति का अर्थ घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र उल्लेखनीय क्षति है। तथापि, कारक यह निर्दिष्ट करते हैं कि घरेलू उद्योग याचिका में इसे प्रमाणित नहीं करता है। कंपनी का निष्पादन भी हाल की अविध में विभिन्न पैरामीटरों के संबंध में सुधरा है।

- ञ. याचिकाकर्ता ने यह दावा किया है कि आयात मूल्य घरेलू बिक्री मूल्य को दबा रहे हैं और याचिकाकर्ता को लागतें वसूल कर पाने के कारण गंभीर हानियां हो रही हैं। तथापि, वक्तव्य वास्तव में सही नहीं है। यह घरेलू उद्योग द्वारा दावा किए गए लाभों से प्रमाणित हो जाता है। इसके अलावा, तिमाही लाभप्रदता का पैटर्न भी इसे स्पष्ट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई हानियां पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 में उल्लेखनीय रूप से कम हुई हैं।
- ट. यह भी बताया गया है कि भारतीय उत्पादक के विचाराधीन उत्पाद को आयात मूल्य की तुलना में कम कीमत पर बेच रहा है क्योंकि भारतीय उत्पादक द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता अभी तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं हुई है।
- ठ. नियमों के तहत, घरेलू उद्योग द्वारा अन्य कारकों के कारण उठाई गई क्षति, यदि कोई हो, को बढ़ हुए आयातों के कारण नहीं माना जा सकता । मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता अन्य कारकों जैसे प्रचालनों को शुरू करने और याचिकाकर्ता द्वारा खर्च की लागत के कारण क्षति उठा रहा है।
- ड. याचिकाकर्ता के नए और एकमात्र उत्पादक होने के कारण शुल्कों को लगाने से घरेलू उत्पादक द्वारा एकाधिकार की स्थिति हो जाएगी।

(गग) टेक्सप्रोकिल ने निम्नानुसार निवेदन किया है:

- क. बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के लिए घरेलू मांग लगभग 3400 एमटी प्रतिवर्ष है जबिक आवेदक की उत्पादन क्षमता केवल लगभग 1130 एमटी प्रतिवर्ष है । इस प्रकार बेअर इलास्टोमेरिक यार्न की घरेलू मांग और घरेलू आपूर्ति में भारी अंतर है, इसलिए इस उत्पाद पर कोई सुरक्षा उपाय लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है ।
- ख. आवेदक के हिमाचल प्रदेश में स्पेंडेक्स यार्न निर्माण यूनिट को पहले ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है। यदि सुरक्षा शुल्क लगाए जाते हैं तो ये आयातों को महंगा कर देंगे जिसके फलस्वरूप घरेलू मूल्य में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि भारत में स्पेंडेक्स यार्न का एकाधिकारिक उत्पादन है। इसलिए यह घरेलू उद्योग और परिधान निर्यातकों के हित में नहीं है।
- ग. भारत में केवल एक विनिर्माण संयंत्र है जो एकाधिकारिक स्थिति में है । सुरक्षा शुल्क का लगाना इस यूनिट को और संरक्षण प्रदान करेगा, जिससे और एकाधिकारिक स्थिति का सृजन होगा ।

(घघ) यूनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

- क. यूनीचार्म बेबी डायपर और सेनेटरी नेपिकन का निर्माण करता है जिसके लिए प्रयोग की जाने वाली आयाितत कच्ची सामग्री पोलियुरेथेन से बनी इलास्टिक गुणों के साथ "स्ट्रिंग" है। ये स्ट्रिंग विशेष साइज और ग्रेड के तैयार उत्पाद है और मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद से भिन्न हैं जो परिधान उद्योग द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कच्चा रूप है, यद्यपि ये स्ट्रिंग उसी टैरिफ शीर्ष के तहत है जैसािक विचाराधीन उत्पाद है।
- ख. दिनांक 28.02.2014 के आरंभण नोटिस में जांच की अवधि के लिए पहचान की गई है और चयनित अवधि वर्ष 2012-13 से 2013-14 है। किसी विनिर्माण यूनिट के लिए शुरू के चरण के दो से तीन वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं और इसे उत्पादन और लाभप्रदता के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने में समय लगता है। ये निम्न हो सकते हैं:
 - (i) श्रम समायोजन और प्रशिक्षण
 - (ii) कच्ची सामग्री की श्रृंखला का निपटान
 - (iii) अंतिम उत्पाद की आपूर्ति और विवरण श्रृंखला को पुरा करना
 - (iv) कच्ची सामग्री की आरंभिक गुणवत्ता और तैयार उत्पाद की गुणवत्ता
 - (v) आश्वासन आदि
- ग. वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही से आगे आवेदन के उत्पादन और बिक्री में नाटकीय वृद्धि हुई और यह लगभग उत्पादन के इष्टतम स्तर अर्थात 1250 एमटी को प्राप्त कर गया। आवेदक के विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में नया होने के कारण वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए वर्तमान जांच और कार्यवाही अपरिपक्व है और केवल इस आधार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
- घ. यदि घरेलू उद्योग (आवेदक) उत्पादन का इष्टतम स्तर प्राप्त कर लेता है या अपना उत्पादन दुगना करके 2500 एमटी कर लेता है तो भारत में विचाराधीन उत्पाद की कुल मांग को पूरा नहीं कर सकता।

- ङ. यह देखा जा सकता है कि विचाराधीन उत्पाद के घरेलू उत्पादन में वृद्धि लगभग कुल आयातों और भारत में उक्त उत्पाद की कुल मांग के अनुपात में हुई है। इसलिए आयातों में वृद्धि ने उक्त उत्पाद के घरेलू उत्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया है।
- च. दिलचस्प बात यह है कि घरेलू उद्योग और आयात मिलकर भी भारत में विचाराधीन उत्पाद की शत-प्रतिशत मांग को पूरा नहीं कर पाए हैं। इसलिए विचाराधीन उत्पाद के आयात के विरुद्ध कोई सुरक्षा उपाय देश में परिधान उद्योग को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेंगे जो निर्यात आय में वृद्धि करने और देश के लिए विदेशी मुद्रा को पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- छ. वर्ष 2012-13 और 2013-14 (क्यू 1 से क्यू 3) के दौरान औसत क्षमता का उपयोग 47.32 प्रतिशत से 94 प्रतिशत तक बढ़ा था जो एक वर्ष की अवधि में बिल्कुल दुगना है। यहां तक कि घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा एक वर्ष में 15 प्रतिशत से 26 प्रतिशत तक बढ़ा है।
- ज. आवेदक ने हानियों के लिए विभिन्न अन्य कारणों जैसे कि कच्ची सामग्री के उतरने के मूल्य में वृद्धि, रुपए का मूल्यहास, मालसूची आदि का उल्लेख किया है जो भारत में मिलते-जुलते उत्पाद के आयातों के कारण नहीं हो सकते।

(ड.ड.) मैसर्स नंदन डेनिम लिमिटेड, मैसर्स चिरपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मैसर्स दीपक इम्पेक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

- क. "घरेलू उद्योग" शब्द सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6)(ख) में भी परिभाषित किया गया है जिसमें प्रावधान है कि "घरेलू उद्योग" का अर्थ उत्पादन (i) मिलती-जुलती वस्तु के पूरे के रूप में या भारत में सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु; या (ii) जिसका सामूहिक उत्पादन, भारत में मिलते-जुलते वस्तु या सीधे प्रतिस्पर्धी वस्तु का भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का बड़ा हिस्सा गठित करता है। इस प्रकार, प्रावधान "घरेलू उद्योग" को "उत्पादकों" के रूप में एक वचन उत्पादक का उल्लेख करता है परंतु स्वरूप में बहु वचन है और यह एक से अधिक ऐसे उत्पादक का जिक्र करता है। तथापि, वर्तमान आवेदक नामत: मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दावा किया है कि वे भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का उत्पादन करने वाला भारत में एकमात्र उत्पादक है अत: कुल घरेलू उत्पादन का शत-प्रतिशत के लिए हिसाब में लेते हैं और इसलिए एकल कंपनी होने के कारण वर्तमान याचिका विषय में दाखिल करने का ऐसा कोई आधार नहीं है।
- ख. आवेदक भारतीय बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं है, यहां तक कि यदि वे शत-प्रतिशत उत्पादन क्षमता का उपयोग करने में भी समर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह जांच अन्य आयातकों के लिए न्याय के हित में अनावश्यक है।
- ग. आवेदक ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उनके मामले में उनको सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(घ) में यथा व्याख्या की गई ऐसी "गंभीर क्षति की आशंका" का कोई खतरा है।
- घ. आवेदक का बाजार हिस्सा बढ़ा है और उसी अवधि में आयात का बाजार हिस्सा कम हुआ है । आवेदक द्वारा यथा प्रस्तावित सुरक्षा उपायों को लगाने का कोई औचित्य नहीं है ।
- ड. आवेदक की बिक्री वर्ष 2013-14 के क्यू1 तक बढ़ी है, यह वर्ष 2013-14 के क्यू 1 में 931 एमटी से वर्ष 2013-14 के क्यू 3 में 670 एमटी तक कम हुई है। ये आंकड़े यह नहीं दर्शाते। प्रमाणित करते हैं कि आवेदक को हाल ही विगत में बिक्रियों में गंभीर हानि हुई है या इसने कोई गंभीर क्षति या ऐसी किसी गंभीर क्षति की आशंका पैदा की है।

(चच) जे. एम. कमोडिटीज: मैसर्स जे. एम. कमोडिटीज ने अपने 16.6.2014 के पत्र द्वारा निम्नान्सार निवेदन किया है:

- क. इंडोरामा (इनविया) का उत्पादन भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने में अपर्याप्त है।
- ख. यदि सुरक्षा को लागू किया जाता है तो इसके स्पेंडेक्स यार्न की भविष्य में एकाधिकारिक बिक्री होगी और वे अधिक मूल्य लेंगे और ग्राहकों को प्रीमियम उत्पाद के रूप में बेचेंगे ।
- ग. इनविया की गुणवत्ता स्तर की नहीं है या आयातित स्पेंडेक्स के समकक्ष नहीं है।

III. सार्वजनिक सुनवाई

9. 19 जून, 2014 को सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की गई थी जिसके लिए नोटिस सभी इच्छुक पक्षों को 6 मई, 2014 को भेजा गया था । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान निम्नलिखित इच्छुक पक्षों ने अपने विचार प्रस्तुत किए :-

इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग) विवतनामी दुतावाम विवतनामी दुतावाम वार वार विवाद कर्मा हिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड एसोसिएशन आफ विवेदिक फाइबर इंडस्ट्री पास्तर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पास्तर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड विवत्य वर्ण्डवाइड लिमिटेड वर्ण्डवाच्याइड लिमिटेड वर्ण्वव्य क्रिया वर्ण्डवाच्याइड ल्ल्य्यंट लिमिटेड वर्ण्वव्य क्रिया वर्ण्डवच्याइड ल्ल्यंट लिमिटेड वर्ण्डवच्या वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्यवच्याचिल वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्यवच्याचिल वर्ण्यवच्याचिल वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्यवच्याचिल वर्ण्डवच्याचिल वर्ण्यवच्याचिल वर्ण्यवच्याच्याचच्याचच्याचच्याचच्याचच्याचचच्याचचच्याचचच्याचचचच्याचचचचचचचच		वजातक पुरावाद के बारान निर्माणावाद इंज्युक नवा ने जनने विवाद प्रस्तुत कर हुन ।
वियतनामी दुरावास आर वी डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री आग्न्कर इंडस्ट्रीज प्राइबेट लिमिटेड अग्न्कर इंडस्ट्रीज प्राइबेट लिमिटेड अग्न्कर इंडस्ट्रीज प्राइबेट लिमिटेड अग्न्कर संप्ता सिंप्शन सिंप्सेड अग्न्कर संपत्त स्वा सिंप्सेड अग्न्कर संपत्त सिंपसेड अग्न्कर संपत्त सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड सिंपसेड सिंपसेड अग्न्कर संपत्त सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड स्वय सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड स्वय सिंपसेड स्वय सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड स्वय सिंपसेड सिंपसेड अग्न्य सिंपसेड सि	1	इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
4 आर वी डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड 5 एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइवर इंडस्ट्री 6 मास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 7 जिंदल वल्डंबाइड लिमिटेड 8 मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9 बेलस्पन सिटेक्स लिमिटेड 10 डेनिम मैन्यूफैक्स एसोसिएशन 11 बिरला सेंचुपी 12 ओसाल बुलन गिल्स लिमिटेड 13 रेमंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड 15 नंदन डेनिम लिमिटेड 16 आल इंडिया स्पेडेक्स वार्न इस्पोर्ट एसोसिएशन 17 अशाई केनी फाइवर कारगोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेडेक्स कंपनी 18 एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइवर इस्ट्री (एएसएफआई) 19 अरविंद लिमिटेड 20 वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 21 करफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 22 एसोसिएटिङ केमिकल कारपोरेशन 23 एनफील्ड एप्रल लिमिटेड 24 इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया 25 इयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम 26 इयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम 27 इंक केमिकल कारपोरेशन, कोरिया 28 इंक्योम क	2	जापानी दूतावास
5 एसोसिएशन आफ सिथेटिक फाइबर इंडस्ट्री 6 मास्कर इंडस्ट्रीज प्राइबेट लिमिटेड 7 जिंदल वर्ल्डबाइड लिमिटेड 8 मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 10 इनिम मैन्यूफेक्क्स एसोसिएशन 11 बिरला सेंचुरी 12 श्रीसवाल बूलन मिल्स लिमिटेड 13 रिमंड यूसीओ डेनिम प्राइबेट लिमिटेड 14 चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 15 नंदन हेनिम लिमिटेड 16 आल इंडिया स्पेंडक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन 17 अशाई केनी फाइबर कारयोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडक्स कंपनी 18 एसोसिएशन आफ सिथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) 19 अरविंव लिमिटेड 20 बर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 21 कमफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 22 एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन 23 एनफील्ड एफल लिमिटेड 24 इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया 25 इयोसुंग स्थेटेक्स (जिआविंसन) कंपनी लिमिटेड, चीन 26 इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया 28 टेक्बांग जीन पीआर 29 टेक्बांग कीरिया 26 इयोसुंग कीरिया	3	वियतनामी दूतावास
6 भास्तर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड 7 जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड 8 मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9 वेलस्पन सिटेबस लिमिटेड 10 इनिम मैन्यूफैक्क से एसोसिएशन 11 विस्ता संयुग्धे 12 श्रीसवाल बूलन फिल्स लिमिटेड 13 रिमंड यूगीओ इंतिम प्राइकेट लिमिटेड 14 विस्तिम लिमिटेड 15 नंदन डेनिम लिमिटेड 16 आल इंडिया स्पेडेक्स वार्न इस्पोर्टर एसोसिएशन 17 अशाई केनी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केनी स्पेडेक्स कंपनी 18 एसोसिएशन आफ सियेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) 19 अरविंद लिमिटेड 20 वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 21 क्रमेकेडश्न आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 22 एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन 23 एनफील्ड एफल लिमिटेड 24 इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया 25 इयोसुंग स्वेल्कल कारपोरेशन, कोरिया 26 इयोसुंग सेल्कल कारपोरेशन, कोरिया 27 टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया 28 टेक्नांग कीरिया 29 टेक्नांग कीरिया	4	आर वी डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
7 जिंदल वर्ण्डवाइड लिमिटेड 8 मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9 वैलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड 10 डेनिम मैन्युफैक्चर्स एमोसिएशन 11 विराण संदुरी 12 ओसवाल बूलन मिल्स लिमिटेड 13 रेमंड बूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड 14 चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 15 नंदन डेनिम लिमिटेड 16 आल इंडिया स्पॅडेक्स यार्न इस्पोर्टर एसोसिएशन 17 अशाई केसी फाइवर कारपोरेश एसोसिएशन 18 एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइवर इंडस्ट्री (एएसएफआई) 19 अरविंद लिमिटेड 20 वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 21 कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 22 एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन 23 एनफील्ड एप्रल लिमिटेड 24 इयोसुंग करपेडक्स (जिआविंसग) कंपनी लिमिटेड, चीन 25 इयोसुंग क्वतामा कंपनी लिमिटेड, विवतामा 26 इयोसुंग किपापुर का का पोरेशन, कोरिया 28 देक्कोग की पापुर एंड सर्विंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इनिक्टा सिंगापुर फाइवर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोमिल 33 विवेटिक	5	एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री
मफतलाल इंडर्ट्रीज लिमिटेड विलस्पत सिंटेबस लिमिटेड विलस्पत सिंटेबस लिमिटेड विलस्पत सिंटेबस लिमिटेड विराण सेंचुरी विराण सेंचुरी विराण सेंचुरी विराण सेंचुरी विराण सेंचुरी विराण सेंचुरी विराण इंडर्ट्रीज लिमिटेड विराण इंडर्ट्रीज लिमिटेड विराण इंडर्ट्रीज लिमिटेड विराण इंडर्ट्रीज लिमिटेड विलस्पत सिंटेड विलस्पत सिंटेड काइबर इंडर्ट्री (एएसएफआई) अरविंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड एसोसिएटड केमिकल कारपोरेशन वर्षाच स्थान सिंटेड इयोसुंग सप्टेंडक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन इयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन टेक्चयां चीन पीआर टेक्चयां चीन पीआर टेक्चयां चीन पीआर टेक्चयां कोरिया टेक्चयां कोरिया टेक्चयां कीरिटा सिंपापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड टेक्मप्रोमिल टेक्सप्रोमिल टेक्सप्रमाल स्थाप्टेंड टेक्सप्रमाल स्थाप्य स्थाप्टेंड टेक्सप्टेंड टेक	6	भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
श्री वित्यम तिरिदेश तिमिटेड श्री वित्यम मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन श्री वित्यम मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन श्री वित्यम मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन श्री वित्यम मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन श्री वित्यम प्रेडेंट्स किमिटेड श्री वित्यम प्रेडेंट्स यार्न इस्प्रोटर एसोसिएशन श्री वित्यम प्रेडेंट्स यार्न इस्प्री (एएसएफआई) श्री वित्यम प्रेडेंट्स किमिटेड श्री वित्यम प्रेडेंट्स किमिटेड श्री वित्यम प्रेडेंट्स किमिटेड श्री वित्यम प्रेडेंट्स किमिटेड श्री वित्यम प्रेडेंट्स (जिआविसम) कंपनी विमिटेड, चीन श्री वित्यम प्रेडेंट्स (जिआविसम) कंपनी विमिटेड, चीन श्री के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया श्री के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया श्री वित्यम एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री वित्यम एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड श्री वित्यम एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउँसिल	7	जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड
शिवास मैन्यूफैक्क्वर्स एसोसिएशन शिवास मैन्यूफैक्क्वर्स एसोसिएशन शिवास मैन्यूफैक्क्वर्स एसोसिएशन शिवास मैन्यूफैक्क्वर्स एसोसिएशन शिवास में इंट्रिय स्थादेव लिमिटेड शिवास में इंट्रिय स्थादेव लिमिटेड शिवास में इंट्रिय स्थादेव स	8	मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
विरला सेंचुरी विरला सेंचुरी विरला सेंचुरी विरला सेंचुरी विरला सेंचुरी विरला सेंचुरी विरिणाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरिणाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरला सेंचेडस्म यार्च इम्पोर्टर एसोसिएशन अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडक्स कंपनी अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडक्स कंपनी एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरविंद लिमिटेड इक्षेमान टेक्सटाइल लिमिटेड कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया ट्विक्स केमिकल कारपोरेशन कोरिया ट्विक्स केमिकल कारपोरेशन कारपोरेड विम्मेड केसिल केसिटेड ट्विक्स केमिकल कारपोरेड प्रोमोशन कार्जिल कराइक क्षाइक क्षाइक कारपोरेड प्रोमोशन कार्जिल	9	वेलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड
श्रीसवाल बूलन मिल्स लिमिटेड रेसंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड तंदन डेनिम लिमिटेड श्री हेकसी पांड इस्प्रीटर एसोसिएशन श्री हेकसी पांड इस कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइवर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरविंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया टेक केमिकल कारपोरेशन, केमिकल कारपोरेशन, कारपोरेशन, कारपोरेक टेक केमिकल कारपोरेशन, कार	10	डेनिम मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
13 रेमंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड 14 चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड 15 नंदन डेनिम लिमिटेड 16 आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन 17 अशाई केसी फाइवर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी 18 एसोसिएशन आफ सिथेटिक फाइवर इंडस्ट्री (एएसएफआई) 19 अरविंद लिमिटेड 20 वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 21 कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 22 एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन 23 एनफील्ड एप्रल लिमिटेड 24 हथोगुंग कारपोरेशन, कोरिया 25 हथोगुंग कारपोरेशन, कोरिया 26 हथोगुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम 27 टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया 28 टेक्बांग कीरिया 30 इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इनविस्टा सेंगापुर फाइवर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउँसिल	11	बिरला सेंचुरी
चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नंदन डेनिम लिमिटेड नंदन डेनिम लिमिटेड आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्ग इस्पोर्टर एसोसिएशन अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरिबंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेक्चगंग चीन पीआर टेक्गंग चीन पीआर टेक्चगंग चीन पीआर टेक्चगंग चीन पीआर टेक्चगंग चीन पीआर टेक्गंग चीन पीआर टेक्चगंग चीन पीआर टेक्गंग चीन पीआर	12	ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
नंदन डेनिम लिमिटेड आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरिवंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन हियोसुंग कारपोरेशन इयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हियोसुंग किमिटेड, वियतनाम विमिटेड, वियतनाम विमिटेड, वियतनाम विमिटेड, विवतनाम विमिटेड टेक्सवंग चीन पीआर टेक्कवंग चीन पीआर टेक्कवंग कोरिया इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्टवंग केसिटा संगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्टवंग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	13	रेमंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड
अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी श्रि एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरिवंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टि के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेक्कबांग चीन पीआर टेक्कबांग कोरिया इनिकस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनिकस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल	14	चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरविंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एसीलड एप्रल लिमिटेड हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआिक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेकवांग चीन पीआर टेकवांग कोरिया वेकवांग केपनी लिमिटेड वेकवांग कोरिया वेकवांग कोरिया वेकवांग कोरिया वेकवांग कोरिया वेकवांग कोरिया वेकवांग कोरिया वेकवांग केपनी लिमिटेड वेकवांग कोरिया	15	नंदन डेनिम लिमिटेड
एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई) अरविंद लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड एसोसंग कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वीन हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेक्वांग चीन पीआर टेक्वांग चीन पीआर टेक्वांग कोरिया इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्टर रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	16	आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन
19 अरविंद लिमिटेड 20 वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 21 कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 22 एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन 23 एनफील्ड एप्रल लिमिटेड 24 हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया 25 हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआिवंसग) कंपनी लिमिटेड, चीन 26 हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम 27 टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया 28 टेकवांग चीन पीआर 29 टेकवांग कोरिया 30 इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इनिवस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	17	अशाई केसी फाइबर कारपोरेशन एंड थाई अशाई केसी स्पेंडेक्स कंपनी
वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड वर्धमान टेक्सटाइल हंडस्ट्री वर्धमान टेक्सटाइल हंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन हयोसुंग हयेडक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेक्वांग चीन पीआर टेक्वांग चीन पीआर टेक्वांग कोरिया व्यत्वस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल सिथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	18	एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री (एएसएफआई)
कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड एनफील्ड एप्रल लिमिटेड ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया ह्योसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन ह्योसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेकवांग चीन पीआर टेकवांग चीन पीआर टेकवांग कोरिया इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनविस्टा सिंगापुर फाइवर प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टिक्सप्रोहिल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	19	अरविंद लिमिटेड
एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन एनफील्ड एप्रल लिमिटेड हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआर्क्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टिकवांग चीन पीआर टेकवांग कोरिया इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल दिक्सप्रोसिल सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	20	वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड
एनफील्ड एप्रल लिमिटेड ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया ह्योसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेकवांग चीन पीआर टेकवांग कोरिया इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोहिल एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल टेक्टर राज के टिक्सप्रोहिल टेक्सप्रोहिल टेक्टर राज के टिक्सप्रोहिल टेक्सप्रोहिल टेक्सप्राहिल टेक्सप्रोहिल टेक्सप्रोहिल	21	कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री
ह्योसुंग कारपोरेशन, कोरिया ह्योसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेकवांग चीन पीआर टेकवांग कोरिया टेकवांग कोरिया इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोडक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल टेक्टप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्टप्रोसिल टेक्टप्रेस टेक्टप्रोसिल टेक्टप्रेस टेक्टप्रोसिल टेक्टप्रेस टेक्टप्रेस	22	एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन
ह्योसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन ह्योसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया टेकवांग चीन पीआर टेकवांग कोरिया टेकवांग कोरिया डिनवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड डिनवस्टा सिंगापुर फाइवर प्राइवेट लिमिटेड टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोसिल टेक्सप्रोहिल एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल टिक्ट टेक्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल टिक्ट टेक्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल टिक्ट टेक्स टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल टिक्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमेशन काउंसिल टिक्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमेशन काउंसिल टिक्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रामेशन काउंसिल टिक्ट टेक्सटाइल एक्सटाइल एक्स	23	एनफील्ड एप्रल लिमिटेड
26 हियोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम 27 टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया 28 टेकवांग चीन पीआर 29 टेकवांग कोरिया 30 इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	24	हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया
27 टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया 28 टेकवांग चीन पीआर 29 टेकवांग कोरिया 30 इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	25	
28 टेकवांग चीन पीआर	26	हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
29 टेकवांग कोरिया 30 इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	27	टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया
30 इिनवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 31 इिनवस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	28	टेकवांग चीन पीआर
31 इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड 32 टेक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	29	टेकवांग कोरिया
32 टिक्सप्रोसिल 33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	30	इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
33 सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल	31	इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड
	32	टेक्सप्रोसिल
34 यूनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	33	सिंथेटिक एंड रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल
	34	यूनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

35	एलबिओन
36	विष्णु टेक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
37	किरण टेक्सप्रो प्राइवेट लिमिटेड
38	प्रेजिडेंट क्लोथिंग कंपनी
39	जीनथ फाइबर
40	जिओन इंटरनेशनल
41	नैरो इलास्टिक मैन्यूफैचर्स एसोसिएशन

10. सभी इच्छुक पक्षों, जिन्होंने सार्वजिनक सुनवाई में भाग लिया, के सीमाशुल्क (सुरक्षा शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियम, 1997 के नियम 6 के उप-नियम (6) के अनुसार मौखिक रूप से प्रस्तुत विचारों का लिखित निवेदन दाखिल करना अपेक्षित है। उसके पश्चात् किसी इच्छुक पक्ष द्वारा दाखिल लिखित निवेदनों की प्रति अन्य सभी इच्छुक पक्षों को उपलब्ध कराई जाती है। इच्छुक पक्षों को अन्य इच्छुक पक्षों के निवेदन के लिए लिखित उत्तर, यदि कोई हो, को दाखिल करने का अवसर भी दिया जाता है। निम्नलिखित पक्षों ने उपरोक्त कथित नियमों के अनुसार लिखित निवेदन प्रस्तुत किया।

1	इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
2	जापानी दूतावास
3	वियतनामी दूतावास
4	आर वी डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
5	एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री
6	भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
7	जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड
8	मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9	वेलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड
10	डेनिम मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
11	बिरला सेंचुरी
12	ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
13	रेमंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड
14	चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
15	नंदन डेनिम लिमिटेड
16	अरविंद लिमिटेड
17	वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड
18	कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री
19	एसोसिएटिड केमिकल कारपोरेशन
20	एनफील्ड एप्रल लिमिटेड
21	हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया
22	हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन
23	हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
24	टी के केमिकल कारपोरेशन, कोरिया

25	टेकवांग चीन पीआर
26	टेकवांग कोरिया
27	इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
28	इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड
29	यूनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
30	जिओन इंटरनेशनल
31	नैरो इलास्टिक मैन्यूफैचर्स एसोसिएशन

11. सार्वजनिक सुनवाई के पश्चात् विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा दाखिल लिखित निवेदनों का संक्षिप्त सारांश निम्नानुसार है :

क. मैसर्स एपीजे - एसएलजी विधि अधिकारियों ने मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू कंपनी) की ओर से लिखित निवेदन दाखिल किया।

- क. निम्नलिखित के सहित सभी उत्तर देने वाले संघों को नियम 2(6) के अनुसार इच्छुक पक्ष नहीं माना जा सकता :
 - (i) कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज (सी आई टी आई)
 - (ii) सिंथेटिक और रेयन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रामोशन काउंसिंल (एस आर टी ई पी सी)
 - (iii) एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (ए एस एफ आई)
 - (iv) त्रिचुर एक्सपोर्टर एसोसिएशन (टीईए)
 - (v) बी बी एन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (पंजीकृत)
 - (vi) सदर्न इंडिया मिलस एसोसिएशन
 - (vii) नैरो इलास्टिक मैन्यफेक्चर्स एसोसिएशन
 - (viii) आल इंडिया स्पेंडेक्स यार्न इम्पोर्टर एसोसिएशन
 - (ix) सीताराम स्पिनर एसोसिएशन
- ख. डेनिम मैन्यफैचर्स एसोसिएशन

इच्छुक पक्षों के रूप में उत्तर देने वाले संघों की स्थिति ऐसे पक्षों द्वारा कारण सहित उनके मामले के केवल उचित प्रस्तुतिकरण के पश्चात् पुष्ट किया जाना चाहिए ।

- ग. संघ नियम 6(5) या नियम 2(घ) के अनुसार इच्छुक पक्षों के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करता ।
- घ. कितपय पक्षों (यथा सूचीबद्ध) को उनके द्वारा यथा दावा किए गए उसी उत्पाद के लिए डीजीएडी से संपर्क करने के बारे में सूचना प्रदान करनी चाहिए।
- ङ. डीजी को उक्त पक्षों द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन करना चाहिए । डीजी को उनके निवेदनों के भ्रामक होने पर खारिज कर दिए जाने चाहिए ।
- च. यह दावा कि घरेलू उद्योग 31 मार्च, 2014 तक गुणवत्ता मुद्दे का सामना कर रहे हैं भ्रामक है।
- छ. डेनिम निर्माण संघ ने डीजी को चीन, वियतनाम, सिंगापुर के मूल्यों की तुलना करके भ्रमित किया, जिनका भारत के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं हैं।
- ज. वर्तमान मामला मंच की खरीददारी का मृद्दा नहीं है।
- झ. आवेदक घरेलू कंपनी होने का पात्र है। (सामान्य धारा अधिनियम की धारा 8ख(6) (ख)(1), धारा 13 के अर्थ से भिन्न 8ख (6) (ख)।
- ञ. विषयक माल का एकमात्र उत्पादक कानुनी रूप से और तर्क की दृष्टि से पात्र घरेलु उद्योग है नियम 5(1)।
- ट. घरेलू उद्योग डीजी के समक्ष आवेदन दाखिल करने का हकदार है। डीजी सुरक्षा पूर्ण जानकारी के साथ शुरू की गई है कि घरेलू उद्योग ने 25 मार्च, 2012 से वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर दिया है। इसमें ऐसा कुछ भी सुझाने के लिए नहीं है कि यह अपेक्षा है कि घरेलू उद्योग डीजी के समक्ष आवेदन दाखिल करने का पात्र नहीं है क्योंकि यह तीन वर्ष से कम अविध के लिए अस्तित्व में है। (व्यापार नोटिस एसजी/टीएम/1/97 दिनांक 06.09.1997, नियम 5, नियम 4)।
- ठ. जांच की अवधि के चयन के लिए कोई सामान्य या विशेष प्रावधान या दिशानिर्देश नहीं है। (सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, सुरक्षा नियम)। यह आयात करने वाले सदस्य के जांच प्राधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है। (यूएस में पैनल निष्कर्ष कोरिया के विरुद्ध लाइन पाइप मामला), (पी एक्स 13 के मामले में डीजी का अंतिम निष्कर्ष दिनांक 06.6.2011 और मिथाइल एसीटोसिरेट अंतिम निष्कर्ष दिनांक 08.10.2011)।

- ड. उद्योग की आय् आवेदन दाखिल करने के लिए इसकी पात्रता को प्रभावित नहीं करती है।
- ढ. डीजी ने पीएक्स 13 अंतिम निष्कर्ष दिनांक 6.6.2011 और मिथाइल एसीटोसीटेड अंतिम निष्कर्ष दिनांक 8.10.2011 के मामले में डब्ब्ल्यूटीओ जूरी के विवेक अर्थात यूएस कोरिया से सर्कुलर वेल्डिड कार्बन क्वालिटी लाइन पाइप के आधार पर निष्कर्ष दिया कि यह डीजी (सुरक्षा) के विवेक पर है कि "जांच की अविध की लंबाई" और इसके "विश्लेषण" पर निर्णय ले क्योंकि करार में जांच की अविध की लंबाई के संबंध में कोई विशेष नियम नहीं दिया गया है।
- ण. आयात जो वर्ष 2011-12 में 4006 एमटी के थे वर्ष 2013-14 में बढ़कर 9066 एमटी के हो गए, जो दो वर्ष की अविध में 5060 एमटी की वृद्धि है। यह वृद्धि 2.26 गुणा या आधार वर्ष पर 126 प्रतिशत से अधिक है।
- त. वर्ष 2010-11 से औसत तिमाही-वार आयात पिछले वर्ष की तिमाहियों की तुलना में जांच की अवधि की सभी तिमाहियों के लिए वृद्धिकारी प्रवृत्ति पर हैं।
- थ. घरेलू उद्योग के उत्पादन में अर्थात मार्च, 2012 के पश्चात्, इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न से औसत मासिक आयातों में तत्काल पिछले वर्ष और आधार वर्ष की तुलना में क्रमश: 224 एमटी प्रितमाह और 388 एमटी प्रतिमाह की वृद्धि हुई जो क्रमश: 42 प्रतिशत से अधिक और 99 प्रतिशत की वृद्धि है।
- द. डीजी सराहना करना चाहेंगे कि मौजूदा मामले में सभी क्षति पैरामीटर प्रथम दृष्टया सुधार दर्शाएंगे क्योंकि तुलना शून्य स्तर या ऐसी अवस्था से की जा रही है जब घरेलू उद्योग स्थापित ही हुआ था। कोई विश्लेषण यांत्रिक ढंग से आधार वर्ष के साथ विकृत आंकड़े प्रदान करेगा और भ्रांतिपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त होंगे। बुनियादी तथ्य जिसकी सराहना करनी चाहिए वह है उच्च क्षमता का उपयोग प्राप्त करने के बावजूद घरेलू उद्योग लगातार हानियां उठा रहा है।
- ध. घरेलू उद्योग केवल तीन वर्ष की अंतरिम अवधि के लिए संरक्षण की मांग कर रहा है ताकि वे मूल रूप से संस्थापित की जाने वाली पूर्ण क्षमता को संस्थापित कर सकें । यह घरेलू उद्योग को अपनी लागत को कम करने में सहायता करेगा ताकि वे मार्जिन प्राप्त कर सकें जो लागत को वसुल करने के लिए पर्याप्त होंगे और बाजार में बने रहने के लिए भी पर्याप्त होंगे ।
- न. क्षमता का मुद्दा और पुनर्गठन योजना को भी साथ-साथ विश्लेक्षित करने की जरूरत होगी । यह संयुक्त विश्लेषण महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू उद्योग अपनी क्षमता मूल अनुसूची के अनुसार पूर्ण रूप से क्रियान्वित करने में समर्थ नहीं था जो घरेलू उद्योग के नियंत्रण में परिस्थितियों न होने के कारण था । इस संदर्भ में घरेलू उद्योग निम्नानुसार निवेदन करता है :
 - (i) संयंत्र भारत में बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए 15000 एमटी की वार्षिकी क्षमता के साथ स्थापित किया गया है जिसे 5000 एमटी प्रत्येक के तीन चरणों में संस्थापित किया जाना है।
 - (ii) घरेलू उद्योग की योजनाएं ठोस योजना है जिससे उद्योग की पुनर्संरचना होगी । मूल परियोजना योजना के अनुसार 5000 एमटी का दूसरे चरण का विस्तार *** में शुरू होना था और तक पूरा किया जाना था । तथापि, यह अनपेक्षित परिस्थितियों से इसमें देरी हो गई और आयातों आदि में वृद्धि हो गई।
 - (iii) 5000 एमटी की अतिरिक्त क्षमता *** तक प्रचालनात्मक हो जाएंगी बशर्ते कि उद्योग की तीन वर्ष की छोटी अविध के लिए सुरक्षा शुल्क के द्वारा आवश्यक समर्थन दिया जाता है।
 - (iv) कारण क्या है कि घरेलू उद्योग अपनी आरंभिक योजनाओं के अनुसार विस्तार करने में समर्थ क्यों नहीं हो सका, अत्यधिक आयात है ।
 - (v) घरेलू उद्योग की सीमित क्षमता के मुद्दे को एक बार घरेलू उद्योग के अपनी पूर्ण क्षमता की संस्थापना पर उपयुक्त रूप से संबोधित किया जाएगा।
- त. कितपय इच्छुक पक्षों द्वारा दिया गया वक्तव्य कि घरेलू उद्योग अपने उत्पादों को आयातों के उतरने के मूल्य से नीचे बेच रहा है सही नहीं है मानो यदि डीनियर से डीनियर और मास-दर-मास के आधार पर उचित विश्लेषण किया जाता है ।
- प. निम्नलिखित अनपेक्षित परिस्थितियां है जिसे वर्ष 2008 में परियोजना की कल्पना करते समय या इंडो-एएसईएएन एफटीए के वार्ताकारों द्वारा पूर्वानमान नहीं लगाया जा सका।
 - (i) घरेलू उद्योग यह प्रत्याशा नहीं कर सका और न ही भविष्यवाणी कर सका कि विषयक माल की कीमतें कच्ची सामग्री की कीमतों में विश्वव्यापी वृद्धि के बावजूद उल्लेखनीय रूप से कम होंगी इसके अलावा, विषयक माल की इस कीमत कटौती ने घरेलू उद्योग की ग्राहकों के साथ बेहतर मूल्य के लिए बातचीत की क्षमता को भी कम किया है।

(ii) घरेलू उद्योग ने परियोजना की संकल्पना करते समय इंडो-एएसईएएन एफटीए के तहत शुल्कों में कमी की प्रत्याशा नहीं की होगी। किसी उद्योग के लिए यह व्यवहार्य नहीं है कि अपनी योजनाओं को वापस ले यदि क्रियान्वयन की अवस्था के दौरान अनपेक्षित घटनाएं होती हैं।

फ. गुणवत्ता संबंधी मुद्दे

- (i) गुणवत्ता किसी सुरक्षा या डिम्पिंग रोधी जांच में पारस्परिक मुद्दा नहीं है। वाणिज्यिक उत्पादन के पश्चात् शुरू की अविध में कुछ प्रारंभिक समस्याएं थी परंतु उनका नवम्बर, 2012 तक पूर्ण समाधान कर लिया गया था। तथापि, यह समान रूप से नोट करना महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण मात्रा जो कथित रूप से गुणवत्ता में कम थी को भी अन्य ग्राहकों द्वारा खरीदा गया था जो उपयुक्त समायोजनों के साथ अपनी मशीनरी में प्रयोग कर सकते थे।
- (ii) घरेलू उद्योग वर्तमान में डेनिम मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन, एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री आदि के आधारभूत सदस्यों सहित लगभग 850 ग्राहकों को आपूर्ति कर रहा है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से विपक्षी पक्षों के इस तर्क को समाप्त करती है कि वे वर्तमान में गुणवत्ता मुद्दों के कारण घरेलु उद्योग से सामग्री नहीं खरीद रहे हैं।
- (iii) यह रिकार्ड का विषय है कि नवम्बर, 2012 और मार्च, 2014 के बीच प्रतिफल कुल बिक्री का 3 प्रतिशत था, जो कि उद्योग का मानदंड है। वित्त वर्ष 2013-14 के लिए प्रतिशतता कम होकर केवल 1.9 प्रतिशत रह गई जो जनवरी-मार्च, 2014 के दौरान और गिरकर मात्र लगभग 1 प्रतिशत और गिर गई।
- ब. घरेलू उद्योग अपना उत्पादन पूरे भारत में ग्राहकों, सहकारी घरानों से लेकर छोटे बुनकरों को बेच रहा है । वर्तमान में घरेलू उद्योग भारत में 850 ग्राहकों से अधिक की सेवा कर रहा है । नीचे स्पष्ट किए गए कारणों से प्रस्तावित सुरक्षा शुल्क लगाना लोक हित में होगा ।
 - (i) उत्पादकों का हित : विषयक माल के आयातों पर सुरक्षा शुल्क को लगाना विषयक माल के घरेलू उद्योग के हित में होगा । उपाय और क्षति को रोकेगा और अपनी क्षमताओं को संस्थापित करने के लिए समय देगा जो कि बढ़े हुए आयातों के कारण हानियों की वजह से पूरा नहीं हो सकी ।
 - (ii) उपभोक्ताओं का हित : विषयक माल के घरेलू उपभोक्ताओं के हित में यह होगा कि विदेशी उत्पादकों के साथ स्पर्धा करने के लिए सक्षम भारतीय घरेलू उद्योग हो । यह तभी संभव होगा जब घरेलू उद्योग अचानक आयातों में वृद्धि के कारण उठाई गई क्षति से संभलने में समर्थ हो ।
 - (iii) समग्र रूप से जनता का हित: यह समग्र रूप से जनता के हित में है कि सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी भारतीय घरेलू उद्योग हो। यह संभव नहीं होगा यदि बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की अनुमति देना जारी रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, समग्र रूप से जनता पर शुल्कों का प्रभाव नगणय है। इसे नीचे की तालिका से देखा जा सकता है।

विवरण		मोजे	स्ट्रेच डेनिम	शूटिंग के लिए	महिलाओं के बैसियर	टी-शर्ट	जीन्स	लेगिग्ज
ब्रैंडेड उत्पाद की थोक कीमत		रु.100 प्रति/जोड1	200/-प्रति लाइनियर मीटर	250/-प्रति लाइनियर मीटर	रु. 250 प्रति नग	रु. 800 प्रति नग	रु. 1000 प्रति नग	रु. 500 प्रति नग
कुल वजन	ग्राम/यू ओ एम	40	520	375	50	300	600	300
उत्पाद में स्पानडेक्स की लागत	रुपए/नग	1.05	6.93	5	2.21	7.91	7.99	6.62
औसत खुदरा मूल्य	न्यूनतम रुपए	100	200	250	250	800	1,000	500
कुल कीमत का स्पानडेक्स आयात का %	कीमत का %	1.10%	3.50%	2.00%	0.90%	1.00%	0.80%	1.30%
रक्षोपाय शुल्क पर संभावित संदेय कीमत	@25.00%	658	555	555	550	658	555	550

उत्पाद में स्पानडेक्स	रुपए/नग	1.32	8.66	6.24	2.75	9.87	9.99	8.25
की संभावित लागत	कीमत का %	1.30%	4.30%	2.50%	1.10%	1.20%	1.00%	1.70%
	रुपए/नग	0.26	1.73	1.25	0.55	1.97	2	1.64
स्पानडेक्स शुल्क वृद्धि का प्रभाव	कीमत का %	0.26%	0.87%	0.50%	0.22%	0.25%	0.20%	0.33%

ख. जापान के राजदूतावास द्वारा लिखित प्रस्तुतिकरण

क. शामिल उत्पाद

- जापानी कंपनी, यूनीकार्म इंडिया लिमिटेड, पालीयूरीथीन से इलास्टिक अभिलक्षण सिंहत आयातित कच्चे माल का प्रयोग करके बेबी डायमर्स और सैनिटरी नैपिकन्स के विनिर्माता। यह सामग्री भी वर्तमान जांच के अंतर्गत आने वाले उत्पाद की तरह की उसी प्रशुल्क शीर्षक के अंतर्गत आता है, परंतु उत्पाद प्रयोग का प्रयोजन बिल्कुल भिन्न है और यह बेबी डायपर्स एवं सैनिटरी नैपिकन्स के विनिर्माण तक सीमित है और यह सामग्री वर्तमान जांच के अंतर्गत आने वाले उत्पद से बिल्कुल भिन्न प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाता है।
- घरेलू उद्योग बेबी डायपर्स और सैनिटरी नैपिकन्स के लिए यह सामग्री या समान उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता है।
- आवेदक ने इलास्टोमैरिक फिलामेंट यार्न का वाणिज्यिक उत्पादन करना मार्च, 2012 में केवल दो वर्ष पहले ही प्रारंभ किया था
 ि किसी भी विनिर्माण इकाई को संवर्धित आयातों के अलावा जिनमें श्रमिक प्रशिक्षण, आपूर्ति श्रृंखला का सैटलमेंट, क्वालिटी में सुधार तथा अन्य कारणों से उत्पादक एवं लाभप्रदता का इष्टतम स्तर प्राप्त करने के लिए कुछ समय लगता है।
 - ख. जांच की अवधि (पीओआई): आवेदक को शुरूआती स्तर (वर्ष 2012-13 की प्रथम तिमाही से तृतीय तिमाही तक) पर अपने उत्पाद का उत्पादन और बिक्री की इष्टतम मात्रा प्राप्त करने के लिए कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा; परंतु इस स्थिति में नाटकीय ढंग से सुधार हुआ और यह वर्ष 2012-13 की चौथी तिमाही से लगभग इष्टतम स्तर पर पहुंच गया। इसलिए वर्ष 2012-13 और वर्ष 2013-14 तक की दो वर्षों की जांच अवधि कम है।
 - ग. संवर्धित आयात : वर्ष 2012-13 की आंकड़ों की तुलना वर्ष 2013-14 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक के आंकड़ों की तुलना में 2013-14 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक के आंकड़ों से करने पर यह स्पष्टत: देखा जा सकता है कि कुछ मांग में 25.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यद्यपि कुल आयात में केवल 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह घरेलू बिक्री लगभग तीन गुनी हो गई और समस्त घरेलू उत्पादन दो गुने से ज्यादा हो गया। इसका आशय यह है कि आयातों में वृद्धि से उक्त उत्पाद के घरेलू उत्पादन को कोई क्षति नहीं हुई।
 - घ. घरेलू उद्योग को क्षति : आयातों में वृद्धि और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । आवेदक ने इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का उत्पादन केवल 2 वर्ष पहले वर्ष मार्च, 2012 में शुरू किया था और यह प्राकृतिक है कि घरेलू उद्योग को क्षति के लिए विभिन्न अन्य कारक उत्तरदायी हैं जैसे प्रचालनात्मक अस्थिरता, जो किसी भी अवस्थापन/कंपनी के शुरूआती चरण में जरूरी सा है और बाह्य अस्थिरता जैसे बेशी उत्पादन क्षमता, खासकर चीन के कारण इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न की आपूर्ति और मांग में परिवर्तन ।

ग. वियतनाम के राजदूतावास द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण

क. वियतनाम ने संबद्ध उत्पाद का भारत को निर्यात सीएन कोड 54041100 के अंतर्गत नहीं किया । इसलिए, वियतनाम यह अनुरोध करता है कि महानिदेशक रक्षोपाय सीएन कोड संख्या 54041100 के अंतर्गत आने वाले उत्पादक के संबंध में वियतनाम का अपवर्जन कर दें।

- ख. जांच शुरूआत का नोटिस जांच की अवधि के दौरान संबद्ध उत्पाद के आयातों में भारी वृद्धि नहीं दर्शाता है।
- ग. घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण गंभीर क्षिति का स्पष्ट साक्ष्य नहीं दर्शाता है। अधिकांश संकेतक वर्ष 2012-13 के प्रारंभ (पहली तिमाही) की तुलना में वर्ष 2013-14 (पहली तिमाही) की शुरूआत में भारी सुधार तथा बाद में हल्की सी गिरावट दर्शाता है।

इस तर्क के संबंध में निम्नलिखित कारक हैं :

- घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई
- क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई
- आयातों के बाजार हिस्से में कमी आई जब कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई
- उत्पादकता में वृद्धि हुई
- घ. कारणात्मक संबंध : डब्ल्यूटीओ को अधिसूचना तथा जांच शुरूआत अधिसूचना में संवर्धित आयातों तथा कारणात्मक संबंध के बीच कोई स्पष्टीकरण नहीं है ।
- ड. अप्रत्याशित विकास : यह अधिसूचना किसी ऐसे विकास की कोई सूचना नहीं देता है जिससे बाजार में किसी अप्रत्याशित घटना के कारण आयातों में वृद्धि हुई हो ।
- च. पुनर्गठन योजना : वियतनाम की सरकार को उपलब्ध दस्तावेजों में ऐसी कोई पुनर्गठन योजना नहीं मिली ।
- छ. जनहित: चूंकि याचिकाकार्त घरेलू बाजार में एकमात्र उत्पादक है इसलिए इस बात की अत्यधिक संभावना है कि इससे बाजार पर आधिपत्य हो जाएगा और यह बाजार प्रविष्टि में अवरोध उत्पन्न करेगी जो भारत में इस उद्योग के स्वस्थ विकास एवं प्रतिस्पर्धी माहौल के लिए नुकसानदायक है। इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय साधन (यदि कोई) का अधिरोपण अनावश्यक रूप से संबद्ध उत्पाद की नियमित आपूर्ति कट जाएगी और इससे भारत के जनहित पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।
- घ. मैसर्स डीजीएस अधिवक्ताओं ने मैसर्स हयोसुंग कारपोरेशन (कोरिया), टी के केमिकल कारपोरेशन (टी के सी), कोरिया, टेकवांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड, कोरिया, हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड वियतनाम, हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआर्क्सिग) कंपनी लिमिटेड, चीन और टेक्वांग सिंथेटिक फाइबर (चांगशु) कंपनी लिमिटेड, चीन की ओर से लिखित निवेदन किया है।

क. जांच को शुरू करने में वास्तविक आधारों की कमी है

- (i) माननीय प्राधिकारी आवेदन में प्रदान किए गए साक्ष्य की शुद्धता और पर्याप्तता और स्वयं को संतुष्ट करने पर कि बढ़े हुए आयातों; गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आंशका और बढ़े हुए आयातों और कथित क्षति या गंभीर क्षति की आशंका की जांच किए बिना उप-नियम (1) के तहत किसी आवेदन के अनुसरण में जांच शुरू नहीं कर सकता । पूर्ण साक्ष्य की कमी, "पर्याप्त साक्ष्य" छोड़ दिया जाए, तो घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत आवेदन में स्पर्श गोचर है और शुद्धता या पर्याप्तता का प्रश्न ही नहीं उठता है।
- (ii) घरेलू उद्योग व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 06.09.1997 की सुस्पष्ट अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहा है, जो सुरक्षा नियमों के नियम 5(2) के अनुसरण में जारी किया गया है। व्यापार नोटिस के लिए आवेदक को बिल्कुल हाल के तीन वर्षों (या लंबी अविध) के लिए सूचना प्रस्तुत करना अपेक्षित है। ट्रेड नोटिस में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो तीन वर्ष से कम अविध के लिए सूचना प्रस्तुत करने की अनुमित देता है। मौजूदा मामले में, घरेलू उद्योग के मार्च, 2012 में अस्तित्व में आने से इस अपेक्षा को पूरा करने में असमर्थ है। इसको देखते हुए आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाना चाहिए।

- ख. आवेदक ने माननीय प्राधिकारी के साथ पूरी तरह सहयोग नहीं किया है आवेदक घरेलू उत्पादकों के लिए प्रश्नावली को विनिर्धारित फार्मेट में दाखिल करने में असमर्थ रहा है । आवेदक व्यवहार्य समायोजन योजना प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है ।
- ग. आवेदक ने वाणिज्यिक उत्पादन केवल मार्च, 2012 में शुरू किया है परंतु दावा करता है कि घरेलू उद्योग को वर्ष 2010 से हानि हो रही है । इसका कोई अर्थ नहीं निकलता कि आवेदक सहित घरेलू उत्पादक आयात उत्पादों द्वारा हुई भारतीय उद्योग को गंभीर क्षति के कारण उत्पादन नहीं कर सकते ।
- घ. आवेदक अनपेक्षित घटनाक्रमों के अस्तित्व को दर्शाने में असमर्थ रहा है जिनसे आयातों में वृद्धि हुई है।
 - (i) अर्जेन्टीना में फुट वियर ईसी 2, अपीलीय निकाय ने "अनपेक्षित घटनाक्रमों के फलस्वरूप" वाक्य के अर्थ की घोषण की और माना कि घटनाक्रम जिनके कारण उत्पाद इतनी बढ़ी हुई मात्रा में आयात किए जा रहे है ऐसी स्थितियों के तहत जिनसे घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होती है या आशंका होती है अवश्य ही "अप्रत्याशित" रह होंगे।
 - (ii) आवेदक दावा करता है कि इसका संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पिछड़े क्षेत्र का लाभ लेने की आशा से, जो यह लेने में असमर्थ है और दूसरी ओर उसे बहुत से कारकों जैसे कच्ची सामग्री और तैयार उत्पादों के परिवहन और पहाड़ी क्षेत्र में लाजिस्टिक्स की ऊंची लागत के कारण अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ा । यह आगे दावा करता है कि 5402.44.00 और 54.4.11.00 के तहत आने वाले इलास्टोमेरिक (स्पेंडेक्स) फिलामेंट यार्न पर आया शुल्क वर्तमान में 5 प्रतिशत होने से वैश्विक रूप से निम्नतम है।
 - (iii) आवेदक के अपना संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित करने प्राथमिक कारण है: (1) स्थिर विद्युत आपूर्ति; और (2) कर लाभ (5 वर्ष के लिए कर से छूट और उसके बाद 30 वर्ष के लिए आयकर में 30 प्रतिशत की कटौती)। इसलिए आवेदक को पूरी जानकारी थी कि स्थान, जहां संयंत्र स्थापित किया गया है, अवनत क्षेत्र है और इसके बावजूद इसने कर लाभों का फायदा लेने के उद्देश्य से संयंत्र स्थापित किया। इस जागरूक व्यवसाय निर्णय को देखते हुए, यद्यपि अव्यावहारिक, आवेदक की सुनवाई यह तर्क देने के लिए नहीं हो सकती कि उपर्युक्त परिस्थिति "अनपेक्षित घटनाक्रम" है जैसाकि कानून में परिकल्पना की गई है।
 - (iv) आवेदक ने अनपेक्षित घटनाक्रमों का दावा करने के लिए कोई औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत नहीं किया है, विशेष रूप से क्योंकि जांच की अवधि के दौरान आयातों में कमी हुई है।

ड. विषयक माल के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है जिसके कारण सुरक्षा शुल्क लगाया जाए।

सुरक्षा नियमों के नियम 2 के अनुसार "बढ़ी हुई मात्रा" में आयातों में वृद्धि शामिल चाहे यह स्थिर पद या घरेलू उत्पादन के संबंध में हो ।

- (i) अर्जेंटीना फुटवियर के आयात पर सुरक्षा उपायों पर डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के विनिर्णय के अनुसार, सुरक्षा पर करार के अनुच्छेद 2.1 और 4.2 में अपीलीय निकाय ने स्पष्ट किया कि "बढ़े हुए आयात गंभीर क्षति करने या आशंका के लिए मात्रात्मक रूप से ओर गुणवत्ता की दृष्टि से पर्याप्त हाल के पर्याप्त अचानक, पर्याप्त तीव्र और पर्याप्त उल्लेखनीय होने चाहिएं।"
- (ii) आवेदक ने केवल स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि भारत में आयात अचानक, तेजी से और उल्लेखनीय रूप से बढ़ गए है, इसके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया है। आवेदक ने अपने विश्लेषण को सितम्बर, 2013 तक उपलब्ध आयात डाटा पर आधारित किया है। पूरे वर्ष 2013-14 के लिए आयात डाटा के मामले में वर्ष 2012-13 की तुलना में आयातों में कमी हुई है, अत: आयातों में वृद्धि का आवेदक का दावा गलत और आधारहीन है।
- (iii) मांग के साथ-साथ आवेदक की बिक्री में वृद्धि के बावजूद जांच की अविध के दौरान आयातों में कमी हुई है जो आवेदन को संभवत: गंभीर क्षति होने नहीं कहा जा सकता । यह नीचे दी गई तालिका से भी देखा जा सकता है कि हाल के समय में विषयक माल के आयात में वृद्धि नहीं हुई है ।

ता	लका	

वर्ष	घरेलू बिक्री	आयात	कुल घरेलू खपत	कुल खपत में घरेलू बिक्री का हिस्सा
2010-11	0	4683	4683	0%
2011-12	3	7186	7189	0.10%
2012-13	1679	9341	11020	15.20%
2013-14	3646	9294	12940	28.18%
वर्ष 2012-13 तथा वर्ष 2013- 14 के बीच तुलना		0.50%	17.43%	

च. यदि आयातों में वृद्धि हुई भी है तो यह आवेदक को गंभीर क्षति नहीं पहुंचा सकती जिसके लिए सुरक्षा शुल्क लगाने की आवश्यकता है।

- (i) आवेदक द्वारा उठाई गई कथित क्षति न तो डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत अपेक्षाओं को पूरा करती है और न ही सुरक्षा उपायों के प्रयोग को न्यायोचित ठहरती है क्योंकि निर्यात में वृद्धि, यदि कोई हो, ने आवेदक, जो भारतीय घरेलू उद्योग का एकमात्र संघटक है, को कोई गंभीर क्षति नहीं पहुंचाई है, जिसके लिए सुरक्षा शुल्क लगाना आवश्यक है।
- (ii) वर्ष 2010-11, 2011-12 की अवधि को छोड़कर डाटा की सावधानीपूर्वक जांच से निम्नलिखित प्रकट होता है :
 - क्षमता को 500 एमटी के स्थिर स्तर पर रखा गया है।
 - जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है।
 - वर्ष 2012-13 और 2013-14 (सितम्बर तक) क्षमता का उपयोग दुगना हो गया था।
 - घरेलू बिक्री में तेजी से वर्ष 2012-13 के 1,679 से वर्ष 2013-14 (वार्षिक रूप से) में 3,646 बढ़ी है 117 प्रतिशत की वृद्धि।
 - जैसािक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित आयात डाटा से देखा जा सकता है, वर्ष 2012-13 में 9,341 मात्रा से वर्ष 2013-14 में 9,294 तक कम हुई है, इस प्रकार आयात में वृद्धि नकारात्मक है। इसके विपरीत कुल खपत जो वर्ष 2012-13 में 11,020 थी, 2013-14 में बढ़कर 12940 हो गई, जो कुल घरेलू खपत में 28.18 प्रतिशत विकास की दर को दर्शाता है। भारतीय बाजार तेजी से बढ़ रहा है फिर भी आयात की वृद्धि की दर नकारात्मक है।
 - इसलिए कोई वृद्धि और गंभीर क्षति घरेलू उद्योग को प्रतिकूलत: प्रभावित नहीं कर रही है।
 - आवेदक का हिस्सा जो वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत था बढ़कर 2013-14 में 25 प्रतिशत तक बढ़ा है, जबिक आयात बाजार का हिस्सा जो वर्ष 2012-13 में 85 प्रतिशत था कम होकर 2013-14 में 75 प्रतिशत रह गया है
 - जांच की अवधि के दौरान औसत रोजगार बढ़ा है। सामान्यत: प्रति कर्मचारी उत्पादकता भी बढ़ी है।
 - आवेदक के तर्कों के विपरीत उत्पादन के प्रति मालसूची का शेष वर्ष 2012-13 (क्यू 4) से नाटकीय ढंग से कम हुआ है। इसलिए मालसूची में वृद्धि भारत के घरेलू उत्पाद में वृद्धि का परिणाम है।
 - लाभप्रदता दर्शाती है कि आवेदक की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई है । परंतु अधिक हाल में, आवेदक की लाभ/हानि और संबंधित वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है ।
 - जांच की अवधि के दौरान बिक्री से प्राप्ति की तुलना में उतरने का मूल्य लगभग 21 प्रतिशत अधिक है । यह दर्शाता है कि मूल्य पर दबाव/छिपाव और आयातों द्वारा मूल्य में कटौती नहीं हुई है ।
- (iii) उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आवेदक की स्थिति में कोई उल्लेखनीय, समग्र क्षति नहीं हुई है और आवेदक द्वारा उठाई गई कथित क्षति न तो डब्ल्यूटीओ के तहत अपेक्षाओं को पूरा करती है और न ही सुरक्षा उपायों के प्रयोग को न्यायोचित ठहराती है।

- छ. आयातों में कोई वृद्धि नहीं हुई है अत: बढ़े हुए आयात के कारण आवेदक को गंभीर क्षति की आशंका नहीं हो सकती जिसके लिए सुरक्षा शुल्क लगाना आवश्यक हो।
- ज. आयातों के कारण मूल्य में कोई कटौती या मूल्य पर दबाव का कोई कारण नहीं है और इसके विपरीत अंतर बढ़ रहा था । इसके अलावा, अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आवेदक के निष्पादन पर आयात का मूल्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था । इस प्रकार आयातों और आवेदक के निष्पादन के बीच को आकस्मिक संपर्क नहीं है ।

ड. मैसर्स एस.जे. एसोसिएट्स इनविस्टा फाइबर्स पीटीई लिमिटेड और इनविस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड की ओर से प्रस्तुतिकरण दायर किया।

- क. घरेलू उद्योग जिसका अधिकतम उत्पादन, अधिकतम बिक्री, अधिकतम क्षमता उपयोग है और जो संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपनी क्षमता में विस्तार करता रहा जैसा कि यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामले में भारी समग्र नुकसान हुआ है ।
- ख. जीएटीटी के अनुच्छेद XIX के आशय के अंतर्गत कोई अप्रत्याशित विकास नहीं हुआ।
- ग. जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का इन्बिस्टा इंडिया द्वारा संवर्धित मात्रा में निर्यात नहीं किए हैं।
- घ. घरेलू उद्योग ने मार्च, 2012 से 94 प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लिया है । तथापि यह स्वदेशी बाजार की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं है । अत: भारतीय बाजार में मांग एवं आपूर्ति के अंतराल को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है ।
- ङ. घरेल उद्योग को कोई "गंभीर क्षति" नहीं हुई है।
- च. भारत में इस विचाराधीन उत्पाद का केवल इंडोरामा ही एकमात्र उत्पादक हैं जिसका 30 प्रतिशत घरेलू बाजार पर कब्जा है।
- छ. घरेलू उद्योग ने अपने उत्पादन और निर्यात की मात्रा में निरंतर वृद्धि की है। इसलिए इस विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने का दावा करने के लिए कुछ भी नहीं है।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में उल्लिखित विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों में से उत्पादन, बिक्री बाजार हिस्सा, रोजगार, क्षमता उपयोग में निरंतर वृद्धि हुई है । आयातों में गिरावट आ रही है, जिससे सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है । घाटों में सकारात्मक प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।
- झ. घरेलू उद्योग को क्षति विचाराधीन उत्पाद का निर्यातकों द्वारा संवर्धित आयात या कीमत अधोरदन के कारण क्षति नहीं हुई है परंतु यह क्षति इंडोरामा द्वारा किए गए भारी निवेश और इसकी विदेश स्थित कंपनी से लिए गए भारी ऋण के कारण हुई है।
- ञ. विचाराधीन उत्पाद जैसे फाइबर का विनिर्माण पूंजी उन्मुखी उद्योग है। इस उत्पाद में अपने पैर जमाने के लिए समय की जरूरत पड़ती है। रासायनिक फार्मूलेशन उद्योग जैसे इंडोरामा को उत्पादन का उच्चतर या वांछित स्तर पाने में समय लगता है। इसलिए घरेलू उद्योग की ओर से यह सही नहीं है कि उत्पादन शुरू करने के अट्ठारह महीने के अंदर ही घाटे का दावा करने लगे।
- ट. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में तुलनात्मक आंकड़े नहीं दिए हैं जिनके सहबद्धता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंडोरामा के वित्तीय निष्पादन से की जा सके। इसलिए इंडोरामा को "गंभीर क्षति" नहीं हुई।
- ठ. जब अन्य कारकों से क्षिति की जा रही हो तो रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण नहीं किया जा सकता है। क्षिति के लिए इंडोरामा को ऐसे भूभागीय क्षेत्र में अवस्थित होने को उत्तरदायी कहा जा सकता है जहां कच्चे माल और परिष्कृत उत्पाद के आवागमन पर भारी संभारतंत्रीय व्यय करना पड़ता है। अन्य कारण यह हो सकता है कि घरेलू उद्योग अभी शैशव अवस्था में हैं, इसके अलावा अन्य कारण हो सकते हैं बाह्य वाणिज्यिक उधार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की न्यून गुणवत्ता।
- ड. इन्विस्टा द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता विभिन्न पेटेंटेड प्रौद्योगिकियों से विनिर्मित माल की गुणवत्ता से कही अधिक है। इन्विस्टा और घरेलू उद्योग बाजार के विभिन्न सेगमेंटों को आपूर्ति करता है, इन्विस्टा द्वारा इस विचाराधीन उत्पाद का आयात क्षति कारित नहीं कर रहा है और इसलिए जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा प्रारंभ की गई जांब को केवल इसी आधार पर समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

- च. मैसर्स टीपीएम परामर्शदाताओं ने (1) एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर उद्योग, (2) आरवी डेनिम और एक्सपोर्ट लिमिटेड, (3) भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, (4) जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड, (5) मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (6) वेलस्पन सिंथेक्स लिमिटेड, (7) डेनिम मैन्यूफैसचर्स एसोसिएशन (8) बिरला सेंचुरी((9) ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड(त्र10) रेमंड यूसीओ डेनिम प्रा. लि., (11) चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (12) नंदन डेनिम।
 - क. याचिकाकर्ता एकमात्र उत्पाद है । याचिकाकर्ता यह प्रमाणित नहीं कर सका कि आयात कैसे गंभीर क्षति कर रहे हैं ।
 - ख. भारतीय उपभोक्ता विचाराधीन उत्पाद के लिए बहुत ऊंची कीमतें अदा कर रहे है जब मूल्यों के चीन में मौजूद कीमतों की सिंगापुर और वियतनाम के मूल्यों से तुलना की जाती है।
 - ग. नए उद्योग को सुरक्षा कानून के तहत क्षति की जांच नहीं की जा सकती।
 - घ. याचिकाकर्ता ने डीजी सुरक्षा से महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है । इसने डिम्पिंग रोधी कानून के तहत याचिका दाखिल की है ।
 - ङ. उद्योग का अस्तित्व सुरक्षा शुल्क के औचित्य पर विचार के लिए बहुत कम है। (व्यापार नोटिस; डीजी सुरक्षा की पिछली बहुत सी जांच)।
 - च. याचिकाकर्ता भारत में एकमात्र उत्पादक हैं परंतु देश की कुल आवश्यकता का केवल 39 प्रतिशत पूरा कर सकता है। इस प्रकार, मांग और पूर्ति में अंतर है। क्षमताओं को बढ़ाने के पश्चात भी याचिकाकर्ता देश में उत्पाद की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। घरेलू उद्योग तब तक संरक्षण के लिए पात्र नहीं है जब तक कि घरेलू उद्योग देश में उत्पाद के लिए मांग को पूरा कर सकता हो। (6 पीपीडी रबड़ केमिकल मामला डीजी सूरक्षा)।
 - छ. याचिकाकर्ता के उत्पाद खराब गुणवत्ता के हैं और अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं।
 - ज. ऐसे सभी उत्पादों की किस्में जिनका आयात किया जा रहा है और जिनको घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित नहीं किया जा रहा है को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से निकाल दिया जाना चाहिए।
 - झ. आयातों ने ऐसी अचानक, उल्लेखनीय, तीव्र और हाल में वृद्धि नहीं दर्शाई है कि सुरक्षा कानून के अर्थ के अंदर बढ़े हुए आयाता माने जाएं।
 - ञ. उत्पादन और खपत के संबंध में आयात कम हुए है जैसाकि तिमाही विश्लेषण में दर्शाया गया है । आयात वार्षिक आधार पर कम हुए हैं ।
 - ट. अनेपक्षित घटनाक्रम प्रमाणित नहीं किए गए हैं। कम मूल्यों पर बढ़े हुए आयात अनपेक्षित घटनाक्रम नहीं है। (अर्जेंटीना ने आडू को परिरक्षित किया)। मौजूदा मामले में पिछले क्षेत्र के लाभ अनपेक्षित घटनाक्रम की श्रेणी में नहीं आ सकता (अर्जेंटीना फुटवियर मामला)। भारत एसियान संघि घरेलू उद्योग की स्थापना से काफी पहले की गई है, और इस प्रकार यह अनपेक्षित घटनाक्रम नहीं है।
 - ठ. घरेलू उद्योग के निष्पादन ने बहुत से पैरामीटरों में सुधार दर्शाया है। इस प्रकार, वास्तव में बढ़े हुए आयातों के फलस्वरूप कोई क्षति नहीं उठाई है। घरेलू उद्योग के उत्पादन का वार्षिक विश्लेषण और तिमाही विश्लेषण उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। बिक्री ने भी ऐसा व्यवहार दर्शाया है। घरेलू उद्योग अपने अस्तित्व के केवल दूसरे वर्ष में 95 प्रतिशत क्षमता का उपयोग प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। घरेलू उद्योग अपनी समिति क्षमता के साथ उल्लेखनीय 26.8 प्रतिशत बाजार हिस्सा ग्रहण करने में समर्थ रहा है। याचिकाकर्ता को कोई क्षति नहीं हुई है, वास्तव में याचिकाकर्ता के निष्पादन में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ है।
 - ड. घरेलू उद्योग को हुई क्षति बढ़े आयातों के कारण नहीं मानी जा सकती । यह याचिकाकर्ता की आयातों के तुल्य मूल्य प्राप्त करने की असमर्थता के कारण है, याचिकाकर्ता देश में उत्पाद को सभी मुख्य उपभोक्ताओं को उत्पाद बेचने में समर्थ नहीं है, याचिकाकर्ता अब तक अपने उत्पाद को प्रमाणित करने में समर्थ नहीं हुआ है और अभी विभिन्न कंपनियों के साथ परीक्षण की अवस्था में है या शुरू के प्रचालनों और याचिकाकर्ता द्वारा खर्च की गई लागत के कारण हानियां हो सकती हैं।
 - ढ. उत्पादक हित अकेले लोक हित गठित नहीं कर सकता।
 - ण. सुरक्षा शुल्क का उपभोक्ताओं पर उल्लेखनीय प्रतिकृल प्रभाव होगा।
 - त. घरेलू उद्योग द्वारा ठोस समायोजन योजना देना पूरा नहीं किया गया है।
 - थ. प्रभाव विश्लेषण और क्षति विश्लेषण पर विचार किए जाने के तर्क के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि इसे नकारा जाता है, डीजी दो भिन्न अवधियों और घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पर विचार नहीं कर सकता ।

- (संयुक्त राज्य के मामले में डब्ल्यूटीओ पैनल –सर्कुलर कोरिया से वेलडिड कार्बन क्वालिटी लाइन पाइप के आयातों पर निर्णायक सुरक्षा उपाय)।
- द. वर्ष 2012-13 में आयात बढ़ने के तर्क के संबंध में, यह निवेदन किया जाता है कि मौजूदा मामले में आयात में वृद्धि वर्ष 2012-13 और 2013-14 के बीच देखी जानी चाहिए।
- ध. नए उद्योग के मामले में क्षति विश्लेषण अलग ढंग से करने के बारे में उठाए गए तर्क के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि सुरक्षा नियम नए उद्योग द्वारा उठाई गई क्षति की परिकल्पना नहीं करते है, इस प्रकार यह महानिदेशक (सुरक्षा) के क्षेत्राधिकार से बाहर है।
- न. उल्लेखनीय क्षति के कारण कम विस्तार के संबंध में दावे को दृढ़ता से नकारा जाता है क्योंकि याचिकाकर्ता पहले ही 100 प्रतिशत क्षमता के उपयोग पर पहुंचा गया है, इसलिए कटौती का कोई प्रश्न ही नहीं है।

छ. मैं लक्ष्मी कुमारन और श्रीघरन ने कनफेडरेशन आफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैसर्स अरविंद लिमिटेड और मैसर्स वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से लिखित निवेदन दाखिल किए।

- क. सुरक्षा शुलक लगाने के कारण अंत्य उपयोगकर्ता को स्ट्रेच यार्न के कम उत्पादन और विषयक उत्पाद की बढ़ी हुई लागत के कारण अत्यधिक क्षति होगी। इसका यार्न की लागत पर प्रमुख प्रभाव, भारतीय घरेलू उद्योग और निर्यात बाजार की प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ख. यार्न के निर्यात कारोबार को होगी और देशों में बदलना पड़ेगा।
- ग. आवेदन में दो वर्ष से कम का डाटा है जो डीजी सुरक्षा द्वारा जारी व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 दिनांक 06.09.1997 के तहत अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है।
- घ. बार-बार अनुस्मारक के पश्चात की आवेदन को अद्यतन नहीं बनाया गया था और इच्छुक पक्षों को निम्नलिखित सूचना प्रदान नहीं की गई थी :
- (i) वर्ष 2013-14 की पूरी अवधि के लिए आयात आंकड़े;
- (ii) वर्ष 2013-14 की पूरी अवधि दर्शाने के लिए अद्यतन बनाए गए क्षति पैरामीटर;
- (iii) वर्ष 2013-14 और 2013-14 की अवधियों के लिए वार्षिक रिपोर्टे;
- (iv) वर्ष 2013-14 की पूरी अवधि के लिए मूल्य पर दबाव की सूचना;
- (v) वर्ष 2013-14 की पूरी अवधि के लिए मूल्य पर दबाव की सूचना;
- (vi) वर्ष 2013-14 की पूरी अवधि के लिए मृत्य वृद्धि सचना के निवारण पर सुचना; और
- (vii) मार्च, 2014 तक आवेदक की स्थिति दर्शाने के लिए संशोधित आवेदन।
- ड. अनुबंध-5क जो उत्पादन और बिक्री का डाटा देता है, मात्रा के लिए यूनिटों और पैरामीटरों के किसी मूल्य का उल्लेख नहीं करते।
- च. आवेदक ने अत्यधिक गोपनीयता का प्रयोग किया है। आवेदक ने अपने वार्षिक लेखापरीक्षित खातों की गोपनीयता का दावा किया है, न ही गोपनीयता का दावा करते हुए पैरामीटरों के लिए कोई सूचकांकित आंकड़े प्रदान किए हैं। लाभ तथा हानि के आंकड़ों को सूचकंकित नहीं किया गया है और बहुत से पैरामीटर जिन्हें सूचकांकित किया जा सकता था गोपनीय रखे गए हैं।
- छ. मौजूदा मामला अधिनियम की धारा 8ख (1) के तहत और एओएस के अनुच्छेद 2.1 के तहत बढ़े हुए आयातों की पद्धति को पूरा नहीं करता।
- ज. आयात डाटा ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में अचानक वृद्धि की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है जिससे गंभीर क्षति या उसकी आशंका हुई है ।
- झ. घरेलु उद्योग को कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है । आवेदक ने बहुत से कारकों पर महत्वपूर्ण क्षति सूचना को रोक लिया है ।
- ज. मात्रा पैरामीटरों के संबंध में पीओआई में आयात की मात्रा गिर रही है। आवेदक के क्षमता के उपयोग में सुधार हो रहा है, बिक्री उल्लेखनीय सुधार दर्शा रही है, मांग में आयातों का हिस्सा कम हो रहा है, उत्पादकता और रोजगार में सुधार हो रहा है।
- ट. कीमत पैरामीटरों के संबंध में न कीमत अधोरदन हुआ है, न कीमत निग्रहण, आयात कमीतों में वृद्धि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप ही हुई है । इसके अतिरिक्त, आवेदक की क्षतियों में समय के साथ-साथ गिरावट हो

रही है। यह क्षति वर्ष 2013-14 (तीसरी तिमाही) में, जब आयात अधिकतम थे, तब घाटा न्यूनतम रहा, जिसे घाटे और बढ़ते आयातों के बीच कारणात्मक संबंध भंग हो जाता है।

- ड. कथित संवर्धित आयातों और किसी गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। मात्रा पैरामीटर एवं कीमत पैरामीटर के संबंध में भी कोई क्षति नहीं हुई। आंतरिक कारकों के कारण आवेदक को हुई क्षति के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। पिछड़ा क्षेत्र लाभ और अन्य कर लाभ की अनुपलब्धता के कारण दावाकृत कोई क्षति जो इसके संभारतंत्र मुद्दों और आवेदक द्वारा लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।
- ढ. इस आवेदन में गाट के अनुच्छेद XIX (1)(क) के आशय के अंतर्गत कोई अप्रत्याशित विकास की पहचान नहीं की जा सकी जिसके कारण आयातों में अचानक वृद्धि हुई हो। (304 ग्रेड के स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर शुरू हुए चीन विशिष्ट रक्षोपाय; डीएस कोरिया डेयरी उत्पाद में एबी रिपोर्ट; डीएस 121 अर्जेन्टीना फुटवियर में एबी रिपोर्ट; डोमिनिकन रिपब्लिक पालीप्रोपायलीन बैग्स डीएस 415-418 में पैनल रिपोर्ट; अर्जेन्टीना परिरक्षिण पीच्स डी एस 238)।
- ण. कच्चे माल एवं परिष्कृत उत्पाद के परिवहन एवं उस भूभागीय क्षेत्र में संभारतंत्र की उच्च लागत जैसे कारक स्पष्ट होना चाहिए क्योंकि यह एक बुद्धिमत्ता का मामला था।
- त. अभिज्ञात अप्रत्याशित विकास और आयातों में प्रकल्पित वृद्धि के बीच कोई सह संबद्ध नहीं है।
- थ. अप्रत्याशित विकास की जांच में भारत की प्रतिबद्धता इंडिया आशियान करार से संगत नहीं है । पाटनरोधी शुल्क में कमी की दर को विशिष्टीकृत समय तालिका एक जनवरी, 2010 को इंडिया आशियान एफटीए के सम्पन्न होने के शीघ्र पश्चात सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने पर भी इस तर्क का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है ।
- द. इस आवेदन में गाट के अंतर्गत संबद्ध उत्पाद के लिए टैरिफ रियायत सहित भारत द्वारा की गई किसी प्रतिबद्धता का उल्लेख नहीं है जिसके कारण आयातों में अचानक वृद्धि हुई हो ।
- ध. समायोजन योजना समयबद्ध नहीं है, यह अत्यधिक जेनरिक और सकारात्मक समायोजन के लिए कोई ठोस उपाय नहीं दर्शाता है (डीजी रक्षोपाय जांच मिथाइल एसिटोएसिटेट अंतिम जांच परिणाम दिनांक 8 अक्तूबर, 2013) ।
- न. कोई रक्षोपाय शुल्क (क) भारी मांग आपूर्ति अंतराल होने पर इस मामले में जनहित में नहीं होगा। वस्त्र उद्योग कई कारणों से संबद्ध उत्पाद के आयातों पर निर्भर रहता है। यह भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए और भारत में स्ट्रेचेएबल फेब्रिक्स के उपभोक्ताओं के लिए अत्यधिक घातक हो जाएगी। (ख) इस परिष्कृत उत्पाद के भारतीय निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएंगे; (ग) आवेदक आयातों को रोकर और अपनी नई क्षमताओं के लिए मांग का सूजन करके भारतीय बाजार में अपनी एकाधिकारिता सूजन करना चाहता है।

ज. यूनीकार्म इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के लिखित प्रस्तुतिकरण

- क. इस जांच की शुरूआत दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस सं. एसजी/टीएन/1/97- के विपरीत है।
- ख. इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में कोई आयात नहीं हुआ और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, न ही कोई क्षति हुई है और न ही क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई है जिसके कारण रक्षोपाय प्रक्रिया प्रारंभ की जाए ।
- ग. यह एक गलत घोषणा है कि घरेलू उद्योग इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के सभी डेनियर्स और सभी वैरायटियों का विनिर्माण करती है।
- घ. आयातक उस उक्त उत्पाद का आयात करता है जो 67 डेसीटेक्स से अधिक है अर्थात यह वह वैरायटी है जिसका उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया जा रहा है ।
- ङ. यह आवेदन इस आधार पर नामंजूर कर दिया जाना चाहिए कि घरेलू उद्योग द्वारा 67 डेसीटेक्स से अधिक फिलामेंट/यार्न के आयातों के संबंध में किया गया दावा गलत एवं भ्रामक है ।

- च. 67 डेसीटेक्स से अधिक के सभी उत्पादों का विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अपवर्जन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि उनका उत्पाद 67 डेसीटेक्स से कम है।
- छ. इंडोरामा स्पानडेक्स, कम क्रीप अवरोध के कारण, का प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के लिए नहीं किया जा सकता (आर एंड डी प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट) ।
- ज. घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद की बाजार पर एकाधिकार हासिल करना चाहता है।
- झ. आयातक द्वारा आयातित उत्पाद का प्रयोग वस्त्र उद्योग द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका प्रयोग स्वास्थ्य विनिर्माणों के लिए किया जाता है। इसलिए आयातक द्वारा आयातित उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद के साथ समान/समरूप/एक जैसा/ अंतनिर्मेय नहीं है।
- ञ. घरेलू उद्योग अपनी विनिर्माण प्रक्रिया का प्रयोग वर्ष 2013-14 में अपनी इष्टतम क्षमता से कर रहा था । न तो कोई क्षति हुई है और न ही क्षति की कोई चुनौती है ।
- ट. कंपनी की घटी हुई लाभप्रदता सस्ते आयातों के कारण नहीं आई है बल्कि यह उच्च ब्याज लागत और उच्च मूल्यह्रास के कारण आई है जिसके कारण विनिर्माण लागत में वृद्धि हुई और लाभप्रदता में कमी आई।
- ठ. घरेलू उद्योग इष्टतम क्षमता उपयोग करके भी घरेलू जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया।
- ड. आयातों की प्रमात्रा स्थिर है जबकि घरेलु जरूरतें बढ़ रही हैं।
- ढ. भारत के बाहर के बड़े-बड़े विनिर्माताओं से तुलना स्वयं में ही भ्रामक है क्योंकि उस विनिर्माता की लागत, जिसकी क्षमता 5000 एमटी और उस विनिर्माता की लागत जिसकी क्षमता एक लाख एमटी है, की तुलना नहीं की जा सकती, छोटे विनिर्माता की लागत उच्चतर होती है और वे विनिर्माता भारी संख्या में निर्माण करते हैं।
- ण. यह कथन कि विनिर्मातागण भारतीय बाजार में बहुतायत से आने के लिए अपनी अधिकतम क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं, गलत है, घरेलू उद्योग भारतीय बाजार में एकाधिकारता स्थापित करने का प्रयास कर रहा है ।
- त. प्रारंभ की गई रक्षोपाय शुल्क कार्रवाई जनहित में नहीं है क्योंकि किसी भी तरह की विपरीत कार्रवाई से आपूरणीय क्षति होगी और युनीचार्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित घरेलू प्रयोक्ताओं को क्षति होगी।

झ. मैसर्स एसोसिएटिड कैमिकल कारपोरेशन का लिखित प्रस्तुतिकरण

- क. आवेदकों को रक्षोपाय शुल्क का आवेदन करने की अनुमित नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने विनिर्माण के तीन वर्ष भी परक नहीं किए हैं।
- ख. शुल्क का अधिरोपण करने से एकाधिकारिता की प्रवृत्ति बढ़ेगी।
- ग. आवेदक ने यह कह कर गलत बयानवाजी की है कि यह स्पानडेक्स की सभी वैरायटियों और सभी डेनियर्स का उत्पादन कर रहे हैं।
- घ. स्पानडेक्स के बनाए गए उपयोग की गलत एवं अधूरे हैं। सभी स्पाडेक्स पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण न्यायोचित नहीं है।
- ङ. इलेस्टोमेरिक यार्न पर पाकिस्तान में 0 प्रतिशत शुल्क और इटली में 4 प्रतिशत शुल्क का उल्लेख न करके आयात शुल्क के बारे में गलत तस्बीर प्रस्तुत की गई है ।
- च. स्पानडेक्स की आयात कीमतम बढ़ रही है।
- छ. आवेदकों के हिस्से में वृद्धि हुई और घरेलू उद्योग द्वारा बिक्री में अंशदान भी बहुत अच्छा है, इससे यह स्पष्ट है कि आयातों से घरेलू उद्योग को न क्षति हुई और न क्षति की कोई चुनौती उत्पन्न हुई है।
- ज. भारत के बाहर स्थित बड़े विनिर्माताओं के पास स्पानडेक्स की पर्याप्त मात्रा नहीं है और इसलिए उन्होंने बेशी क्षमताओं के लिए संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं।
- झ. आवेदन भारतीय उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है।
- ञ. कई तरह से स्पानडेक्स है जिनका विनिर्माण आवेदक द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसलिए समग्र स्पानडेक्स यार्न पर शुल्क अधिरोपित करना न्यायोचित नहीं होगा ।
- ट. अपने माल की भारतीय बाजार में बिक्री करने पर आवेदक को किसी तरह की क्षति/क्षति की चुनौती नहीं हुई है । उनको नुकसान होने का प्रमुख कारण उसकी गुणवत्ता कम होना है और अपेक्षित मात्रा में इलास्टोमेरिक यार्न का उत्पादन करना है, जिससे उन्हें अंतर्राट्टीय कीमतें मिल सकती हैं।
- ठ. कोई गंभीर क्षति नहीं हुई है। आवेदकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत पर बिक्री करने के लिए दबाव डाला गया।
- ड. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई।

- ढ. आवेदक के निष्पादन में सुधार हो रहा है क्योंकि इनका घाटा कम हो रहा है।
- ण. यह कि आयाति स्पानडेक्स यार्न की उतराई कीमत उनकी बिक्री कीमत की तुलना में बहुत कम है, गलत अभिकथन है।
- त. स्पानडेक्स के आयातों के कारण लाभप्रदता को कोई चुनौती नहीं है।
- थ. पाटनरोधी शुल्क के लिए आवेदनपत्र नामंजूर कर दिया गया है । अत:, यह संभव नहीं है कि स्पानडेक्स के आयातों के कारण आवेदक को गंभीर क्षति हुई हो ।

ञ. मैसर्स एनफील्ड अपैरल्स लिमिटेड द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

- क. धारा 8(ख) में घरेलू उद्योग को एक "उत्पादकों" के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका आशय यह है कि एक से अधिक उत्पादक/आवेदक बड़ी चतुराई से पृष्ठपार्श्व के लाभ प्राप्त करके एकाधिकारवादी स्थिति की स्थिति प्राप्त करना चाहता है जहां वे केवल इस आधार पर कीमतें बढ़ा सकें कि आयात अधिक महंगे हो रहे हैं।
- ख. आवेदक ने इलास्टोमेरिक यार्न को एक उत्पाद के रूप में सामान्यीकृत कर दिया है और बड़ी चतुराई से यह छिपा लिया है कि वे डैनियर्स के उन सभी प्रकारों का उत्पादन नहीं करते हैं जिनकी पेशकश विश्व बाजार में की जाती है। वे क्लोरीन प्रतिरोधी स्पानडेक्स की पेशकश नहीं करते हैं, डोप टाइप का स्पानडेक्स नहीं बनाते हैं, अन्य फाइबर वैरायटियों से रंगने योग्य की पेशकश नहीं करते हैं, हाइजीन उद्योग के लिए उनका कोई उत्पाद नहीं है, उनके पास न्यूनहीट सेटर स्पानडेक्स टाइप नहीं है जो पर्यावरण की रक्षा करता है और जिनका अधिकाशत: भविष्य में प्रयोग किया जाएगा, और सार्वजनिक सुनवाई में विद्वान अधिवक्ता ने यह घोषणा की कि वे उसकी मांग नहीं कर रहे है। जिसका वे विनिर्माण नहीं करते हैं।
- ग. घरेलू उत्पादकों ने अपना उत्पादन मार्च, 2012 में प्रारंभ किया और जहां तक उत्पादन का संबंध है अभी तक उनकी अवस्थिति केवल दे वर्ष की हुई और यह अविध स्पानडेक्स जैसे अति नाजुक उत्पाद की गुणवत्ता और उसके उत्पादन में स्थिरता लाने का अति आवश्यक साधन है। इसके अतिरिक्त, आयातों में किसी भी तरह की वृद्धि को न्यायोचित ठहराने, और उसकी जांच करने के संबंध में दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/91/97 में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक के समय के लिए आयातों की वर्षवार मात्रा एवं मूल्य के रूप में उक्त आयातों के संबंध में विस्तृत सूचना की अनिवार्यत: मांग की गई थी।
- घ. आयात आंकड़े जिन्हें सरकार की एजेंसियों से लिया जा सका है, वे जांच की अवधि के दौरान इलास्टोमेरिक यार्न के कुल आयातों में मामूली से कमी प्रदर्शित कर रहे हैं। यदि हम उन प्रकारों को हटा दें जिनका वे उपयोग नहीं कर रहे हैं और जिन पर वे रक्षोपाय शुल्क की मांग नहीं कर रहें, तो इससे उसमें और भी अधिक गिरावट आ जाएगी, वास्तव में यह वही केस होना चाहिए था, इसलिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण नहीं होना चाहिए।
- ङ. उनके पास रक्षोपाय के अंतर्गत राहत प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला नहींहै । आयात में वृद्धि का आशय क्षति नहीं है क्योंकि मांग में वृद्धि के कारण भी हो सकती है और ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग अधिक मात्रा में बिक्री करने ओर उच्चतर कीमतों पर बिक्री करने का लाभ प्राप्त कर सकता है । गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की प्रत्याशा के अतिरिक्त क्षति को सिद्ध करने में वे असमर्थ रहे हैं ।
- च. घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि घाटे में भारी कमी हुई है और क्षमता उपयोग में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है । यह एक अच्छा प्रतीक है और वे अगली युक्तियुक्त अवधि में लाभ कमा सकते हैं ।
- छ. घरेलू उद्योग का निर्यात दायित्व है तथा उसी उत्पाद को सस्ती दरों पर बेचने का दायित्व भी है।

ट. मैसर्स नैरो इलास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन का लिखित प्रस्तुतिकरण

- क. नैरो इलास्टिक्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन के सदस्य इलास्टिक टेप्स का निर्माण करते हैं जिनके लिए इलास्टोमेरिक यार्न एक अनिवार्य इनपुट है। इसलिए टेप्स की गुणवत्ता बेहतर क्वालिटी के इलास्टोमेरिक यार्न पर निर्भर करती है।
- ख. परिधानों की मांग और इस प्रकार टेप्स एवं इलास्टोमेरिक यार्न की मांग में वृद्धि हो रही है। इसका पूर्ण उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब इसकी गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के अनुरूप हो। टेप विनिर्माण याचिकाकर्ता के इलास्टोमेरिक यार्न उत्पाद की अल्प गुणवत्ता से हतास है।
- ग. त्रुटिपूर्ण स्पान्डेक्स यार्न की आपूर्ति न केवल नैरा इलास्टिक फाइबर विनिर्माताओं को क्षति कारित कर रही है बल्कि यह फेब्रिक्स और परिधानों के विनिर्माताओं को और अंतत: राष्ट्रीय हित को क्षति पहुंचा रहे हैं।
- घ. इलास्टोमेरिक यार्न के लिए भारतीय बाजार के आकार में वृद्धि हो रही है, परंतु इस मांग को पूरा करने के लिए याचिकाकर्ता के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है, यद्यपि इसकी एकाधिकारिता है ।

- ङ. रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से इलास्टोमेरिक यार्न महंगा हो जाएगा । इलास्टिक टेप्स के अधिकांश निर्यातक ड्राबैक मार्ग को वरीयता देते हैं, जो रक्षोपाय शुल्क को निष्क्रिय नहीं करता हैं । इस प्रकार निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता समाप्त हो जाएगी और टेप विनिर्माताओं का भारी भाग, जो लघु एवं मध्यम उद्योग में आता है, को क्षति होगी ।
- च. याचिकाकर्ता का यह अभिकथन है कि "कच्चे माल और समग्र लागत में हुई वृद्धि की तुलना में संबद्ध वस्तु के उतराई मूल्य में वृद्धि नहीं हुई है" बिना किसी औचित्य के है।
- छ. वर्ष 2010-11 के आंकड़ों पर विचार करना उचित नहीं है क्योंकि उस वर्ष याचिकाकर्ता इस वस्तु का विनिर्माता नहीं था। कीमत अधोरदन का दोषारोपण निराधार है। टेप विनिर्माताओं को आयातित माल के लिए रुपयों में भुगतान करना पड़ता है।
- ज. यदि याचिकाकर्ता ने इलास्टोमेरिक यार्न की बिक्री उतराई लागत पर की होती तो याचिकाकर्ता को लाभ हुआ होता । परंतु यह न्युन गुणवत्ता के कारण ऐसा नहीं कर सका ।
- झ. याचिकाकर्ता यह आरोप लगाते हैं कि निरंतर क्षति के कारण टेप विनिर्माता यूनिट के 400 कामगारों और अन्य कर्मचारियों की नौकरियां जा सकती हैं। तथापि, यदि रक्षोपाय शुल्क लगाया जाता है, तो टेप विनिर्माता इकाइयों के 4000 से अधिक कामगारों तथा स्टाफ की नौकरी चली जाएगी।

ठ. नेशनल सिंथेटिक्स के लिखित प्रस्तुतिकरण

- क. बेयर इलास्टोमेरिक यार्न के आयातों की असाधारण वृद्धि नहीं हुई है।
- ख. मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आयातों में वृद्धि के कारण न तो कोई क्षति हुई और न ही क्षति की कोई चुनौती हुई, जैसा कि प्रक्षेपित किया जा रहा है।
- ग. आयातों में अचानक और यकायक वृद्धि नहीं हुई है । उद्देश्यपरक अध्ययन के लिए यह देखने के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए कि क्या घरेलू विनिर्माता घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित विनिर्देशनों और गुणवत्ता के यार्न का विनिर्माण करने में सक्षम हैं या नहीं । यह मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्रदान कराए गए आंकड़ों में नहीं बताया गया है।
- घ. घरेलू उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और इसी तरह क्षमता उपयोग भी बढ़ रहा है । घरेलू बाजार में गिरावट कम बिक्री के कारण नहीं आई है बल्कि निर्यातों के कारण हुई है, जिसे रुपए के मूल्य में अवक्षयण होने के कारण घरेलू उद्योग द्वारा अधिक लाभप्रद पाया गया ।
- ङ. इंडोरामा गुणवत्ता के कई नाजुक सेक्टरों में गुणवत्ता विनिर्देशनों को पूरा नहीं करता है । उनकी बिक्री में गिरावट के लिए आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है । मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज घरेलू उपभोक्ताओं की कीमत पर स्पानडेक्स बाजार में एकाधिकारिता प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है ।
- च. यह घाटा अन्य कारणों से भी हो सकती है, वाणिज्यिक कारण जैसे लंबी अवधारणा अवधि जहां उत्पादन लागत की अधिप्राप्ति उत्पादन के प्रथम वर्ष में प्राप्त नहीं की जा सकती है । यह प्रबंधन, नियंत्रण, कार्यकुशलता, लगाई गई प्रौद्योगिकी और विभिन्न अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है ।
- छ. उत्पादकता और रोजगार के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । मालसूची भी असमान्य नहीं है ।
- ज. भारत में आयातित स्पान्डेक्स की डालर रूप में कीमत कमोबेश रूप से संपूर्ण 2012-13 में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है और यह वर्ष 2013-14 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अनुरूप हो गई। अत: आयात कीमत में पर्याप्त वृद्धि हुई।
- झ. मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज का व्यवसाय सभी तरह से फलभूत रहा है । तथापि, अपनी संपूर्ण क्षमता उपयोग करके भी मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना सर्वोत्तम प्रयास करके तीसरे देश की बाजार की जरूरतों की केवल तिहाई जरूरत को ही पूरा कर सका और किसी तरह का रक्षोपाय शुल्क घरेलू वस्त्र उद्योग के लिए दंडात्मक होगा । जिसके लिए स्पानडेक्स यार्न एक कच्चा माल है । अत: रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जनहित में नहीं होगा ।

ड. मैसर्स जेएसएल ने अखिल भारतीय स्पानडेक्स यार्न आयातक एसोसिएशन की ओर से लिखित प्रस्तुतिकरण दायर किया

- क. स्पानडेक्स यार्न के लिए कोई जांच नहीं हो सकती है क्योंकि स्पानडेक्स यार्न के लिए भारत में कोई घरेलू उद्योग नहीं है।
- ख. स्पानडेक्स यार्न के घरेलू उत्पादन के तीन वर्षों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
- ग. रिकार्ड में उपलब्ध डाटा से ऐसा प्रदर्शित नहीं होता है कि स्पानडेक्स के आयातों में वृद्धि हुई है।

- घ. महानिदेशक रक्षोपाय के आंकड़ों में कोई बाध्याकलन नहीं हो सकता है। डीजीएस ने वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही के आंकड़ों का बाह्याकलन किया है और उसे जांच की अवधि के लिए माना है।
- ङ. "गंभीर क्षति" अथवा "गंभीर क्षति की चुनौती" मौजूद नहीं है।
- च. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी तथा भारत में होने वाले स्पानडेक्स यार्न के आयातों के बीच कोई करणात्मक संबंध नहीं है।
- छ. "संवर्धित आयातों" तथा गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है।
- ज. यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो उससे जनहित पर प्रभाव पड़ेगा।
- झ. आवेदक द्वारा कीमत अधोरदन कर बार-बार उल्लेख किया जाना विधि विरूद्ध है।

ढ. मैसर्स जियान इंटरनेशनल द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरण :—

- क. इलास्टोमेरिक यार्न पर रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करना भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अनिष्टकर होगा।
- ख. इंडोरामा एकाधिकार सृजित करेगा और तद्वारा वह बाजार पर अपना आधिपत्य जमाएगा और अपने फायदे के लिए कीमतों का जोड़-तोड़ करेगा । इससे स्पानडेक्स से बने भारतीय वस्त्र वैश्विक बाजार में अप्रतिस्पर्धी हो जाएगा ।
- ग. देश के मांग को पूरा करने के लिए इंडोरामा के पास पर्याप्त क्षमता नहीं है । इसलिए, सीमा-शुल्क का उदग्रहण करने से उन देशों को सस्ति देना होगा जो अभी भी स्पानडेक्स यार्न का आयात करना चाहते हैं ।
- घ. इंडोरामा का व्यवसाय आयातों की चुनौती के बिना फलफूल रहा है।
- ङ. आयातों में इतनी वृद्धि नहीं हुई है जिससे चुनौती का संकेत मिलता हो।
- च. स्पानडेक्स के विविध प्रयोग हैं और इंडोरामा का न्यूनतर एवं सीमित गुणवत्ता मानक है।
- छ. इंडोरामा द्वारा उठाई गई क्षति घरेलू और निर्यात बाजार में सस्ती कीमत निर्धारण के कारण हुई है।
- ज. निर्यात में भारी वृद्धि के कारण घरेलू बाजार हिस्सा कम हो गया।
- झ. भारत में स्पानडेक्स की खपत प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के अनुरूप 15-20 प्रतिशत बढ़ रही है। इसलिए इस समय पर स्पानडेक्स यार्न पर अतिरिक्त शुल्क उदग्रहण करना भारत में मूल्यवर्धित वस्त्र उद्योग के शैशव काल में विकास के अनिष्टकर होगा और लंबे समय में भारत प्रतिस्पर्धा करने और मूल्यवर्धित वस्त्र विनिर्माण आधार के रूप में विकास करने के अक्षम हो जाएगा।

12. निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरणों का प्रति प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है।

1	इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग)
2	आर वी डेनिम एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड
3	एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री
4	भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
5	जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड
6	मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
7	वेलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड
8	डेनिम मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन
9	बिरला सेंचुरी
10	ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड
11	रेमंड यूसीओ डेनिम प्राइवेट लिमिटेड
12	चिरीपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
13	नंदन डेनिम लिमिटेड
14	अरविंद लिमिटेड

15	वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड
16	भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ
17	हयोसुंग कारपोरेशन, कोरिया
18	हयोसुंग स्पेंडेक्स (जिआर्क्सिग) कंपनी लिमिटेड, चीन
19	हयोसुंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड, वियतनाम
20	टी. के. केमिकल कारपोरेशन, कोरिया
21	टेकवांग चीन पीआर
22	टेकवांग कोरिया
23	इनिवस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
24	इनविस्टा सिंगापुर फाइबर प्राइवेट लिमिटेड

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतिकरणों के उपर्युकत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर प्रति प्रत्युत्तरों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं :—

क. मैसर्स एपीजे एसएलजी विधि अधिकारियों द्वारा मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (घरेलू उद्योग) की ओर से दायर किए गए प्रति प्रत्युत्तर का सारांश

- क. घरेलू उद्योग ने याचिका का अगोपनीय पाठ विधिवत प्रदान किया है।
- ख. टीपीएम कंसलटेन्ट्स को ऐसी सूचना पर भरोसा करने के बारे में असंतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है । जितनी बार आवेदन दिया गया है उनकी संख्या तथा उस आवेदनपत्र को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के आधार के संबंध में सूचना का स्नोत नहीं दिया गया है । विरोधकर्ता पक्षकारों को चाहिए कि वे इसका पुख्ता सबूत दें जिससे कि नियम एवं प्रक्रिया का साफ तौर पर अनुपालन नहीं किया गया।
- ग. किसी भी एसोसिएशन ने नियम 2(घ) में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया, इसीलिए महानिदेशक महोदय से अनुरोध है कि वह उनके द्वारा दायर प्रत्युत्तरों को नकार दे।
- घ. घरेलू उद्योग की परिभाषा उद्योग के उस दायरे को अपवर्जित नहीं करती है जो तीन वर्षों से कम अविध से अपस्थिति हैं। नियम 5(1) में यह निर्धारित नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास घरेलू उद्योग से संबंधित सूचना है उनमें से कौन आवेदनपत्र दायर कर सकता है। ऋणात्मक खंड में यह भी अधिदेशित नहीं है कि डीजी रक्षोपाय किसी जांच की शुरूआत तभी कर सकते हैं जब तीन वर्षों से अधिक समय तक गंभीर क्षति होने के साक्ष्य हों। विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार इस स्तर पर इस मुद्दों को उठाने के हकदार नहीं है।
- ङ. यह अनुमेय नहीं होना चाहिए कि उक्त व्यापार नोटिस को पढ़ा जाए कि केवल वे उत्पादक ही आवेदनपत्र दायर कर सकते हैं जिनकी अवस्थिति तीन वर्ष से अधिक समय तक ही है ।
- च. जांच की अवधि की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है।
- छ. वर्तमान मामले में जांच की अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि का मूल्यांकन विगत आंकड़ों के रूप में किया जाना चाहिए । यह बिल्कुल असंगत है कि क्या घरेलू उद्योग ने अपना वाणिज्यिक उत्पादन उस अवधि में शुरू किया था जिसका प्रयोग यह बेंचमार्किंग करने और यह जांच करने के लिए किया गया था कि क्या आयातों में वृद्धि हुई है या नहीं ।
- ज. जांच की अवधि में आयातों में भारी वृद्धि हुई है। यद्यपि आयातों ने मार्च 2014 में मामूली सी गिरावट प्रदर्शित की है तब भी आयातों की वृद्धि के बारे में डीजी के निष्कर्ष के संबंध में कोई निहितार्थ नहीं है। निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त प्रमाण है।
- झ. माननीय डीजी को केवल यह विश्लेषण करने ओर निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है कि क्या आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और यह उन आधारों में से एक आधार है जो घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित कर रहे हैं। तथापि, घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई क्षति आयातों में वृद्धि के कारण हुई है।
- ञ. घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है।
- ट. किसी रक्षोपाय विधि या रक्षोपाय करार में ऐसी कोई विशिष्ट अपेक्षा नहीं है जिसमें कीमत अधोरदन का प्रावधान हो । इसके अलावा आयातों से भारी कीमत अवमंदन हो रहा है ।

- ठ. घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु और भारत में आयातित वस्तु, जब उनकी तुलना डेनियर-वार तथा माह-दर-माह आधार पर की गई हो. के बीच कोई वास्तविक कीमत अंतर नहीं है।
- ड. कुछ हितबद्ध पक्षकारों का कतिपय उत्पादों का अपवर्जन करने का दावा गलत एवं भ्रामक है।
- ढ. घरेलू उद्योग को अपना उत्पादन 30 प्रतिशत से न्यूनतर कीमतों पर निर्यातक करने के लिए बाध्य किया गया।
- ण. इस संबद्ध वस्तु का क्षमता मुद्दा और पुनर्गठन योजना का एक साथ विश्लेषण करना जरूरी है । यह संयुक्त विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घरेलू उद्योग, उन परिस्थितियों के कारण जिन पर घरेलू उद्योग का कोई नियंत्रण नहीं था, मूल अनुसूची के अनुरूप अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका ।
- त. कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां थी जिनकी घरेलू उद्योग वर्ष 2008 में परियोजना की संकल्पना करते वक्त या इंडो आशियन एफटीए के वार्ताकारों द्वारा संकल्पना करते समय पहले से कल्पना नहीं कर सका।
- थ. गुणवत्ता संबंधी मुद्दा बोगी है।
- द. रक्षोपाय शुल्क लगाना जनहित में है । यदि घरेलू उद्योग के इस स्तर पर संरक्षण प्रदान नहीं कराया जाता है तो इस बात का खतरा है कि घरेलू उद्योग लंबे समय तक बनाए रख सकेगे और उसे प्रासंगिक रूप से यह निर्णय करना होगा कि प्रचालन को बंद कर दिया जाए या वर्तमान प्रचालन से विविधीकरण किया जाए । उस सुथिति में निर्यातक फिर अपनी कीमतें बढ़ा देते ।

ख. मैसर्स डीजीएस एडवोकेट्स मैसर्स ह्योसंग कारपोरशन (कोरिया) टी.के. कैमिकल्स कार्प (टीकेसी) कोरिया, टैक्वांग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड कोरिया, हयोसंग वियतनाम कंपनी लिमिटेड वियतनाम, हयोसंग स्पानडेक्स (जियाक्सिंग) कंपनी लिमिटेड, चीन और टैक्वांग सिंथेटिक फाइबर (छान्यसु) कंपनी लिमिटेड, चीन की ओर से प्रस्तुत संक्षिप्त प्रति प्रत्युत्तर

- क. घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के अनुबंध में ट्रेड एसोसिएशन तथा प्रयोक्ताओं से संबंधित के रूप में प्रत्युत्तर दाता एसोसिएशन के रूप में बताया है । इसलिए उन्हें सुविधानुसार अपना आधार बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।
- ख. भारत सरकार ने पहले ही यह स्थापित एवं सिद्ध कर दिया है कि कोई "वास्तविक क्षति" नहीं हुई । भारत सरकार अब यह निष्कर्ष न ही निकाल सकती है कि घरेलु उद्योग को "गंभीर क्षति" आयातों के कारण कारित हुई है ।
- ग. वर्ष 2012-13 से पहले के आयातों की प्रवृत्ति का कोई संदर्भ सही नहीं है।
- घ. घरेलू उद्योग का यह दावा है कि प्रवृत्ति विश्लेषण की अवधि की शुरूआत वर्ष 2010-11 से होनी चाहिए, सही नहीं है और उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । वर्तमान जांच में माननीय प्राधिकारी ने विशेष रूप से यह माना है कि क्षति अवधि 2012-13 और 2013-14 हैं, इसलिए क्षति का संपूर्ण विश्लेषण, आयातों की प्रवृत्ति सहित, जांच शुरूआत अधिसूचना में क्षति विशिष्ट अवधि तक सीमित होना चाहिए ।
- ङ. डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यदि आयातों के समर्पित वर्गीकरण के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है तब इन्हें सर्वाधिक प्राधिकृत माना जाता है ।
- च. आयातित संबद्ध वस्त् की कीमतों में गिरावट नहीं हुई।
- छ. कोई अप्रत्याशित विकास नहीं हुआ।
- ज. सैकड़ों अंतिम प्रयोक्ताओं का रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण तथा उल्लिखित विभिन्न मुद्दों का माननीय प्राधिकारी के विरूद्ध प्रतिभागिता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि वेयर इलास्टोमेरिक यार्न पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा उठाया गया कोई भी कदम जनहित में नहीं होगा ।
- ग. मैसर्स टीपीएम कंसर्ल्टेंट्स द्वारा (1) एसोसिएशन आफ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज (2) आरबी डेनिम्स एंड एक्सपोर्टस लिमिटेड, (3) भास्कर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, (4) जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड, (5) मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, (6) वेलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड, (7) डेनिम मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, (8) बिरला सेंचुरी (9) ओसवाल वूलेन मिल्स लिमिटेड, (10) रेमंड्स यूको डेनिम प्राइवेट लिमिटेड, (11) चिरिपाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और (12) नंदन डेनिम की ओर से दायर किए गए प्रति प्रत्युत्तर का सारांश
 - क. महानिदेशक को वर्तमान प्रयोजन तथा प्रस्तावित निर्धारण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विचार करना अपेक्षित है।
 - ख. विभिन्न एसोसिएशनों को हितबद्ध पक्षकार के रूप में मान जाने के संबंध में विचार किए जा रहे घरेलू उद्योग के प्रतिवाद पर विलंब हुआ डेनिम विनिर्माता एसोसिएशन ने अपनी स्थिति के बारे में जांच के प्रारंभ होने के समय बताया था और प्राधिकारी ने उसे हितबद्ध पक्षकार का दर्जा दिया था।

- ग. यह एसोसिएशन ने उन उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है जो इस उत्पाद के आयातक हैं और इस प्रकार जो हितबद्ध पक्षकार हैं।
- घ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदान कराई गई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर है । याचिकाकर्ता ने अति महत्वपूर्ण जानकारी को महानिदेशक से छुपाया है ।
- ङ. याचिकाकर्ता के उत्पाद को अभी तक सभी उपभोक्ताओं तथा आवेदकों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।
- च. चीन, वियतनाम, सिंगापुर आदि से आयात कीमतों की तुलना का इस मामले से सीधा संबंध है।
- छ. घरेलू उद्योग ने यह छुपाने का प्रयास किया है कि उसने एक पाटनरोधी आवेदनपत्र भी दायर किया है । इसके पश्चात उसने आवेदन प्रपत्र में याचिका दायर करने से संबंधित निहित प्रश्नावली के संगत भाग का विलोपन कर के आवेदन-पत्र में हेरफेर किया है ।
- ज. घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि एकल घरेलू उत्पादक एक नई कंपनी है जो अपने माल की बिक्री आयात कीमत से कम पर कर रही है और जिसका इतना लंबा इतिवृत्त नहीं है जिससे महानिदेशक (रक्षोपाय) संवर्धित आयातों एवं घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का निर्धारण कर सके।
- झ. महानिदेशक (रक्षोपाय) संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति के लिए विभिन्न अवधियों पर विचार नहीं कर सकते हैं । इसलिए तीन वर्षों का इतिवृत्त न्युन कम है ।
- ञ. संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए तीन वर्षों से अधिक की अवधि आवश्यक है।
- ट. ऐसे मामलों में संवर्धित आयातों तथा गंभीर क्षति का निर्धारण करने के लिए उद्योग की अवस्था अनिवार्य है।
- ठ. महानिदेशक (रक्षोपाय) संवर्धित आयातों के लिए दीर्घतर अविध तथा गंभीर क्षति के लिए अल्पतर अविध पर विचार नहीं कर सकते हैं।
- ड. आयातों में तो वृद्धि हुई भी नहीं है । आईबीआईएस आंकड़ों के बजाय डीजीसीआईएंडएस आंकड़ों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- ढ. आयातों में उत्पादन एवं खपत की तुलना में वास्तव में गिरावट आई है।
- ण. घरेलू उद्योग निश्चय ही अपनी कीमतों की बेंचमार्किंग आयातों की न्यूनतम कीमतों के अनुरूप करता होगा। घरेलू उद्योग द्वारा सहन की जा रही क्षति कंपनी के अपने आंतरिक कारणों से हो रही है। किसी कंपनी के आयात कीमतों से तुलनीय कीमत प्रभारित करने के लिए कौन रोकता है।
- त. याचिकाकर्ता की दिक्कत उसके उत्पाद की तकनीकी रूप से स्वीकार्यता एवं आयात कीमत की तुलना में कीमत प्रभारित करने में उसकी असफलता से संबंधित हैं।
- थ. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में बार-बार यह उल्लेख किया है कि उसे अपने माल की बिक्री आयात कीमतों से कम कीमतों पर करने के लिए मजबूर किया गया और उसे अपनी कीमत न्यूनतम आयात कीमत के अनुरूप निर्धारित करने के लिए मजबूर किया गया।
- द. याचिकाकर्ता द्वारा उल्लेख किए गए कारक अप्रत्याशित विकास नहीं है।
- ध. गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । याचिकाकर्ता के उत्पाद को भारी संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है । यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपभोक्तागण उसी माल का आयात उन कीमतों से उच्चतर कीमतों पर कर रहे हैं जिन कीमतों पर याचिकाकर्ता अपने उत्पाद की बाजार में बिक्री की पेशकश कर रहा है ।
- न. याचिकाकर्ता के उत्पाद की खरीद केवल वे उपभोक्ता ही कर रहे हैं जो अपने अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करते हैं।
- त. विदेशी उत्पादकों के मानक ओर उस मानक को पूरा करने के लिए जिसकी उपभोक्तागण अपेक्षा करते हैं, याचिकाकर्ता को भारी प्रयास करना पड़ेगा।

- प. उपभोक्तागण प्रासंगिक उत्पाद का निकृष्ट विनिर्देशनों युक्त उत्पादन करने के लिए न्यूनतर गुणवत्ता वालो विनिर्देशित उत्पादों का प्रयोग करते हैं।
- फ. प्रस्तावित रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य, घरेलू उद्योग की रक्षा किए बिना अपने उत्पाद की कीमत बढ़ाना है।

घ. भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ, मैसर्स अरविंद लिमिटेड और मैसर्स वर्धमान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से मैसर्स लक्ष्मी कुमारन एवं श्रीधरन द्वारा दायर किए गए प्रति-प्रत्युत्तर का सारांश

- क. याचिकाकर्ता का यह प्रस्तुतिकरण कि एसोसिएशनों हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत होने के लिए पात्र नहीं हैं। रक्षोपाय विधि एवं विभिन्न नियमों के मद्देनजर पूर्णतया अस्वीकार्य है।
- ख. आवेदक अब यह उल्लेख नहीं कर सकता है कि प्रतिवादी द्वारा प्रदान कराई गई उतराई कीमत संबंधी सूचना भ्रामक है। उतराई कीमत के संबंध में भ्रामक सूचना के संबंध में भी आवेदक का तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।
- ग. डीजी रक्षोपाय से अनुरोध है कि वह आवेदक की पात्रता एवं आधार के संबंध में जांच करें।
- घ. डीजी रक्षोपाय से आवेदन में तीन वर्षों की न्यूनतम अवधि के संबंध में आंकड़ों की अनुपलब्धता से संबंधित पहलुओं तथा इस विधिक अपेक्षा को पूरा करने में आवेदक की असफलता के संबंध में जांच करने का अनुरोध किया जाता है।
- ड. आवेदन पत्र के प्रस्तुतिकरणों में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया गया है जिससे कि वे याचिकाकर्ता की मार्च, 2014 तक की स्थिति बता पाते। इसके अतिरिक्त, कई पैरामीटरों को गोपनीयत रखा गया और आवेदक द्वारा उसका सार्थक सारांश सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान नहीं कराया गया है। इस प्रकार, आवेदक का यह निश्चय कि जांच की अवधि का चयन करने का रक्षोपाय महानिदेशक को अधिकार है, गलत है।
- च. यह एक गलत अभिकथन है कि क्षति विश्लेषण के लिए जांच की अवधि से पहले की आयात मात्रा पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- छ. महानिदेशालय रक्षोपाय को इस मामले में किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए दिनांक 22.04.2014 को पत्र की विषय वस्तु पर विचार नहीं करना चाहिए। आवेदक द्वारा पूर्णतया एक अलग स्रोत (आईबीआईएस) से प्रदान कराए गए आयात आंकड़ों पर विचार नहीं करना चाहिए।
- ज. वर्तमान जांच को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसे आवेदन-पत्र पर आधारित है जिसके आयात आंकड़े त्रुटिपूर्ण हैं, आंकड़े अपूर्ण एवं अपर्याप्त हैं तथा विधिक प्रक्रिया का त्रुटिपूर्ण उल्लेख किया गया है ।
- झ. पर्याप्त क्षमता और समायोजन/पुनर्संरचना योजना के संबंध में आवेदक के आकन को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए । आवेदक की समायोजन योजना अत्यधिक सामान्य है और वह प्रस्ताव की प्रकृति का है और उसमें ऐसा कोई ठोस कदम नहीं दर्शाया गया है जो सकारात्मक ढंग से समायोजन करने के लिए आवेदक द्वारा उठाया जाएगा ।
- ञ. अप्रत्याशित विकास के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि कच्चे माल की कीमतों में बढोतरी होने के बावजूद भी संबद्ध वस्तु की कीमतों में गिरावट होने का आवेदक का दावा गलत है और उसके समर्थन में आवेदन में कोई साक्ष्य भी नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, किसी एफटीए के अंतर्गत रियायतों पर गाट प्रावधानों के अंतर्गत अप्रत्याशित विकास के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- ट. आवेदक के उत्पाद की गुणवत्ता अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा नहीं करती है। आवेदक को होने वाली क्षति आयातों में कथित वृद्धि के कारण नहीं हुई है परंतु यह आवेदक की अपनी समस्याओं के कारण हुई है जिसमें उत्पादित माल की कम गुणवत्ता भी शामिल है।
- ठ. यदि वर्तमान आवेदन को तुरंत खारिज कर दिया जाता है तो उससे व्यापक जनहित होगा क्योंकि आवेदन पत्र तथा आवेदक के सभी उत्तरवर्ती प्रस्तुतिकरणों में दिए गए आंकड़े इस मामले में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने को वांछित नहीं ठहराते हैं।
- 14. मैसर्स एस. जे. सागर एसोसिएट्स ने मैसर्स इन्विस्टा सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स इन्विस्टा सेल्स एंड सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिनांक 14.07.2014 के पत्र के तहत यह प्रस्तुतिकरण किया कि स्पानडेक्स का विनिर्माण करने के लिए कच्चे माल

पर आधारभूत सीमा शुल्क दिनांक 11.7.2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-सीमाशुल्क के तहत यथा मूल्य 5 प्रतिशत से घटाकर शुन्य कर दी गई है । घरेलु उद्योग द्वारा विनिर्मित स्पानडेक्स की कीमत भी तदनसार ही प्रभावित होगी ।

IV. जांच एवं जांच परिणाम

- 15. मैंने इस मामले के रिकार्डों, घरेलू उत्पादक, प्रयोक्ता/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक राष्ट्रो द्वारा तैयार दायर किए गए प्रत्युत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की है। उनके द्वारा किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों तथा प्रति प्रत्युत्तरों पर भी समुचित विचार किया गया है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए प्रस्तुतिकरणों तथा उनसे उत्पन्न मुद्दों का इस अंतिम जांच परिणाम में निम्नलिखित समुचित स्थानों पर निराकरण कर दिया गया है:
- 16. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख में आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का उल्लेख है। इसकी उपधारा (1) में केंद्रीय सरकार द्वारा उन मदों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए जाने का प्रावधान है जिनका भारत में इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हो रही हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो रही हो।
- 17. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचाना एवं आकलन) नियमावली 1997 में जांच को शासित करने वाले ढंग एवं सिद्धांतों का प्रावधान है।
- 18. यह जांच उक्त नियमों के अनुसार आयोजित की गई तथा अंतिम जांच परिणाम इस अधिसूचना द्वारा रिकार्ड किया जा रहा है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

19. इस मामले में विचाराधीन उत्पाद (जिसे एतद्पश्चात पीयूसी कहा गया है) सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 54024400 और 54041100 के अंतर्गत वर्गीकृत "सभी डैनियर्स और वैरायिटयों का बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न" है। इस उत्पाद को सामान्यत: "स्पानडेक्स" या "इलास्टेन" के रूप में भी जाना जाता है। इलास्टोमोरिक फिलामेंट का निर्माण" पाली टेरा मिथायलीन ईथर ग्लायकोल और मोनो डायफिनायल मिथेन डाईसोसाइनेट" नामक कच्चे माल द्वारा किया जाता है और इसका प्रयोग डेनिम जीन्स, स्पोर्टवीयर, टी. शर्टस, सूटिंग स्टाक्स तथा अन्य परिधानों के लिए किया जाता है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि वे सभी उत्पाद प्रकार जिनका आयात किया जा रहा है जिनका घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन नहीं किया जा रहा है, उन्हें विचाराधीन उत्पादन के दायरे से अलग कर दिया जाना चाहिए। किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस दावे को सिद्ध करने और उत्पाद के दायरे से उसका अपवर्जन करने के लिए कोई भी वास्तविक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और इसलिए किए गए दावे एवं निकाल गए निष्कर्ष मुख्यत: कल्पना पर आधारित है और इसलिए उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अत: यह संपुष्टि की जाती है कि विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 54 के सीमाशुल्क उपशीर्षक संख्या 54024400 और 54041100 के अंतर्गत वर्गीकृत "सभी डैनियर्स और वैरायटियों का बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न आयातित जांचाधीन उत्पाद के सभी रूपों में समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु है और यह कि घरेलू रूप से उत्पादित सभी डेनियर्स और सभी वैरायटियों का बेयर इलेस्टोमेरिक फिलामेंट यार्न, सभी डैनियर्स एवं सभी वैरायटियों के आयातित बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 2(ड.) के आशय के अंतर्गत समान उत्पाद है।

ख. घरेलू उद्योग (डीआई)

20. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख (6) (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नवत परिभाषित किया गया है ।

"ख "घरेलु उद्योग" का आशय

(i) भारत में समान उत्पाद या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद के समग्र रूप से उत्पादकों; अथवा

- (ii) उन उत्पादकों से होता है जिनका समान उत्पाद अथवा भारत में प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है।"
- 21. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6) (ख) (ii) के अंतर्गत प्रावधान है कि "उत्पादक" एकल उत्पादक नहीं है परंतु वह प्रकृति में बहु वचनी है और इसका संबंध ऐसे एक से अधिक उत्पादकों से है और इसलिए मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एकमात्र निकाय होने के कारण, उसे यह याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। यह दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में जनरल क्लाजेज एक्ट, 1897 की धारा 13 निम्नवत पठित है:

"13 जेंडर एवं संख्या – सभी (केंद्रीय अधिनियमों) एवं विनियमों में – जब तक विषय या संदर्भ में कोई वस्तु असंगत न हो तब तक – फीमेल्स को शामिल करने के गैर-कुलिन जेंडर को आयातित करने वाले शब्द लिए जाएंगे और एक वचन में बहु वचन तथा इसके विपरीत शामिल होंगे।"

- 22. जनरल ग्लाजेज एक्ट, 1897 की धारा 13 में उल्लिखित भाषा के मद्देनजर सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख (6)(ख) में शब्द "उत्पादकों" का प्रयोग स्वत: इसके एक वचन वाले रूप "उत्पादक" में शामिल है और इसलिए मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात घरेलू उद्योग कहा गया है) विचाराधीन उत्पाद का एकल उत्पादक होने के कारण वर्तमान याचिका दायर करने की हकदार है।
- 23. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और चूंकि मैसर्स इंडोरामा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का उत्पादन भारत में बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के कुल उत्पादन का 100 प्रतिशत उत्पादन बनता है इसलिए आवेदक घरेलू उत्पादक है तथा यह धारित किया जाता है कि आवेदक घरेलू उत्पाद सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 8ख(6)(6)(ii) के आशय के अंतर्गत परिभाषित एवं अपेक्षित घरेलू उद्योग है ।
- 24. **नए उद्योग को होने वाली क्षति की जांच रक्षोपाय विधि के अंतर्गत नहीं की जा सकती है:** कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि नए उद्योग की क्षति की जांच रक्षोपाय विधि के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। यह तर्क सही नहीं है क्योंकि सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8(ख) के अंतर्गत, रक्षोपाय नियमावली और रक्षोपाय करार के अंतर्गत भी ऐसी स्थिति की परिकल्पना नहीं की गई है जिसमें रक्षोपाय विधि के अंतर्गत किसी नए उद्योग की जांच नहीं की जा सकती है। अत: हितबद्ध पक्षकारों का तर्क स्वीकार्य नहीं है।

ग. हितबद्ध पक्षकारों के रूप में एसोसिएशनों की स्थिति

25. घरेलू उद्योग का यह दावा कि प्रतिवादी एसोसिएशनों के सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 (घ) के अनुसार हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है, आवेदन पत्र में किए गए इसके प्रस्तुतिकरणों के विपरीत है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर किए गए आवेदन के अनुबंध 4 के अनुसार अधिकांश एसोसिएशनों को संबंधित व्यापार एसोसिएशन और प्रयोक्ता एसोसिएशन के रूप में दर्शाया गया है। अब घरेलू उद्योग का यह दावा कि वे एसोसिएशनों जिन्होंने इस जांच में प्रतिभागिता की है और संबद्ध वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण किए जाने का विरोध किया है, हितबद्ध पक्षकार नहीं है, अपने प्रस्तुतिकरणों के विपरीत है। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2(घ) में स्पष्टत: यह उल्लेख है कि हितबद्ध पक्षकार में व्यापार या बिजनेस एसोसिएशन शामिल होती हैं जिनके अधिकांश सदस्य भारत में समान वस्तु या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी वस्तु का उत्पादन या व्यापार करती हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह निश्चय किया गया है कि उन सभी एसोसिएशनों को हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना जाए जिन्होंने अपने प्रस्तुतिकरण दायर किए है।

घ. सूचना का स्रोत

26. जांचाधीन उत्पाद का भारत में अभाव सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की पहली अनुसूची के अध्याय 54 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्रशुल्क शीर्षक 54024400 और 54041100 के अंतर्गत किया जाता है। यह रक्षोपाय जांच डीजीसीआई एंड एस से अक्तूबर, 2013 तक के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर शुरू की गई थी। अन्य विभिन्न पैरामीटरों से संबंधित दिसम्बर, 2013 तक के आंकड़े घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदनपत्र में प्रस्तुत किए गए थे और इस निदेशालय द्वारा उनकी जांच यथासंभव सीमा तक केंद्रीय उत्पाद कर रिकार्डों के आधार पर कर ली गई थी। नवम्बर, 2013 से मार्च 2014 तक के आयात आंकड़े भी डीजीसीआईएंडएस कोलकाता के रिकार्डों से लिए

गए हैं । विभिन्न आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित जनवरी, 2014 से मार्च, 2014 तक के आंकड़े आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ततिकरणों या प्रति प्रत्युत्तरों से लिए गए हैं जिससे कि क्षति विश्लेषण के लिए तिमाही के साथ-साथ वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक रूप से समेकित आंकड़ों पर पहुंचा जा सके । सत्यापन रिपोर्ट का अगोपनीय पाठ सभी संबंधितों के लिए सार्वजनिक फाइल में रख दिया गया है ।

27. घरेलू उद्योग द्वारा पाटनरोधी आवेदनपत्र : कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने कुछ प्रमुख तथ्यों को महानिदेशक रक्षोपाय से छुपाया है क्योंकि उन्होंने पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करने के लिए एक याचिका दायर कर रखी है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनकी यह याचिका खारिज कर दी है । घरेलू उद्योग द्वारा किए गए इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि हितबद्ध पक्षकारों ने उस सूचना पर भरोसा करने और प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, और कोई भी हितबद्ध पक्षकार अपने दावे के समर्थन में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका ।

ड. जांच की अवधि (पीओआई)

28. न तो सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 में और न ही सीमा शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 में विशेष रूप से "जांच की अविध" को अथवा रक्षोपाय जांच के लिए विचारित कम से कम अविध को परिभाषित किया गया है। रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार जांच की अविध का चयन करने के लिए न तो कोई सामान्य या विशिष्ट प्रावधान है और न ही कोई दिशानिर्देश है। तथापि जांच की अविध से संबंधित मुद्दे का विस्तृत विवरण कोरिया के विरूद्ध यूएस लाइन पाइप मामले में (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201) उल्लेख किया गया है। इस मामले में पैनल ने यह निर्धारित किया है कि आयातक देश के जांचकर्ता प्राधिकारी को "जांच की अविध की दीर्घता" और इसके "भंग" होने का निर्धारण करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग करने का अधिकार है।

"हम नोट करते हैं कि इस करार में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है कि रक्षोपाय जांच में जांच की अविध कितनी लंबी होनी चाहिए, और न ही यह उल्लेख है कि विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भंग की अविध क्या होनी चाहिए। इस प्रकार जांच की अविध और इसके भंग होने की अविध जांचकर्ता प्राधिकारियों के विवेक पर छोड़ दी गई है। हमारे समक्ष उपस्थित मामले में आईटीसी द्वारा चीन की गई अविध पांच वर्ष और छह माह थी, यह अविध अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में अर्जेन्टीना की जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की गई जांच की अविध के समकक्ष है। तथापि, हम नोट करते हैं कि अपीलीय निकाय ने अपने जांच परिणाम में जांच की अविध की लंबाई के संबंध में तर्क देने के लिए कोरिया पर भरोसा किया है, उसमें न केवल अविध की लंबाई पर बल दिया गया है परंतु अभिनव आयातों पर फोकस होना चाहिए और न कि जांच की गई अविध पर। लाइन पाइप जांच में आईटीसी ने न केवल अंतिम बिन्दु की तुलना में या जांच की अविध की समग्र प्रवृत्ति की जांच की (जैसा कि अर्जेन्टीना ने अर्जेन्टीना फुटवीयर रक्षोपाय में जांच के लिए किया था)। इसने पूरे 5 वर्षों के लिए वर्ष-दरवर्ष आधार पर आयातों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह भी विचार किया कि क्या अंतरिम 1998 की तुलना में अंतरिम 1999 में वृद्धि हुई थी। हमारा विचार है कि एक ऐसी अविध का चयन करके जो 5 वर्ष छह माह की थी आईटीसी ने अनुच्छेद XIX और अनुच्छेद 2.1 से असंगत कार्य नहीं किया। यह निष्कर्ष निम्नलिखित विचारों पर आधारित है: प्रथम करार में ऐसा कोई विशिष्ट नियम नहीं है जिसमें जांच की अविध की लंबाई बताई गई हों; द्वितीय, आईटीसी द्वारा चयनित अविध अभिनव आयातों पर प्रकाश डालती है; और तृतीय, आईटीसी द्वारा चयनित अविध, संवर्धित आयातों की मौजूदगी के संबंध में निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त दीर्घ है।" (पैरा 7.196, 7.199 और 7.201)।

29. प्रवृत्ति विश्लेषण की अवधि की शुरूआत : घरेलू उद्योग यह तर्क देती है कि जांच की अवधि से पहले की आयात मात्रा पर भी प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए विचार किया जाना चाहिए । यह महसूस किया गया कि इस तरह का स्पष्टीकरण पूर्णतया अतार्किक है । सर्वप्रथम तो मार्च 2012 से पहले घरेलू उद्योग का आस्तित्व ही नहीं था । द्वितीयत: जांच की अवधि का चयन और जांच शुरूआत नोटिस की अधिसूचना इस बात पर विचार करते हुए पहले ही कर दी गई थी कि घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन मार्च, 2012 में ही शुरू किया था । तृतीय घरेलू उद्योग को क्षति का सुनिश्चय विचाराधीन उत्पाद का वाणिज्यिक उत्पादन होने से पहले नहीं किया जा सकता है क्योंकि विश्लेषण के लिए संगत घरेलू आंकड़े जैसे उत्पादन, बिक्री कीमत, उत्पादन लागत तथा आयात मात्रा और आयातों का उतराई मूल्य, उपलब्ध नहीं थे । तथापि प्रवृत्ति विश्लेषण के मुद्दे का विवरण कोरिया के विरूद्ध यूएस पाइप लाइन मामले के अंतिम जांच परिणाम में विस्तार से दिया है (पैरा 7.209) । इन मामले में पैनल ने यह निर्धारित किया कि संवर्धित आयात प्रवृत्ति की जांच करने के लिए अविध वही होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग को गंभीर स्थिति के मामले में मानी गई हो :

¹ डब्ल्यूटी/डीएस 202/आरडीटी दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइप लाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

"िकसी रक्षोपाय जांच में संवर्धित आयात प्रवृत्ति की जांच करने के लिए जांच की अविध वही होनी चाहिए जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति की जांच के लिए है। यह स्थिति किसी पाटनरोधी या प्रतिवलनकारी शुल्क की जांच के विपरीत है जहां पाटन या सब्सिडीकरण की ध्विन किसी वास्तविक क्षित जांच करने के लिए सामान्यत: माफी कम पड़ जाती है। हमारा विचार है कि इस अंतर के पीछे के कारणों में से एक कारण यह है कि अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय द्वारा यह पाया गया कि "यह निर्धारण कि क्या आयातों का "इतनी अधिक मात्रा में होने" की जरूरत पूरी हो जाती है यह केवल गणितीय या तकनीकी निर्धारण द्वारा पूरी नहीं होती है। "अपीलीय निकाय ने यह नोट किया कि जहां संवर्धित आयातों का निर्धारण करने का मामला आता है वहां "सक्षम प्राधिकारियों को जांच की अविध के दौरान आयातों की प्रवृत्ति की जांच करना अपेक्षित होता है। आयातों की प्रवृत्ति का मूल्यांकन, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित का निर्धारण करने के लिए संगत कारकों की प्रवृत्ति के मूल्यांकन के साथ केवल एक निश्चित अविध के लिए किया जा सकता है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि क्षिति निर्धारण के लिए संगत अविध के संबंध में जो विचार अपीलीय निकाय द्वारा व्यक्त किए गए हैं वहीं विचार संवर्धित आयातों का निर्धारण करने पर भी लागू होंगे (पैरा 7.209)2

- 30. डब्ल्यूटीओ पैनल के उपर्युक्त जांच परिणामों के मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि संवर्धित आयातों की जांच की अविध वही रहेगी जो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित की जांच करने के लिए है, इसिलए चयिनत जांच अविध से पहले ही किसी अविध पर विचार करना गलत होगा। इस पैनल ने पुन: उल्लेख किया है कि इस संबंध में पाटनरोधी/प्रतिवलनकारी शुल्क जांच में विधि की स्थिति भिन्न है। इसिलए इस प्रयोजनार्थ पाटनरोधी मामलों पर विचार करना भी सही नहीं है। इसके अतिरिक्त, पाटनरोधी एक अलग प्रकार का व्यापार उपचार है जो पूर्णतया भिन्न स्थिति में उपलब्ध होता है। इसिलए इस मामले में पाटनरोधी विधि के निर्णयों को लागू करना उपयुक्त नहीं होगा।
- 31. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह ऐतराज जताया है कि इस आवेदनपत्र में दो वर्षों से कम समय की अविध के आंकड़े दिए गए हैं जो यह निदेशक रक्षोपाय द्वारा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस सं. एसजी/टीएन/97 के अंतर्गत अपेक्षाओं से असंगत है। इस संबंध में यह प्रेक्षण किया जाता है कि दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/97 के पैरा 5 में यह विहित है कि आवेदक केवल वही सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है जो उस समय मौजूद है। पुन: यह महसूस किया जाता है कि व्यापार नोटिस कोई कानून नहीं होता है परंतु यह कार्यकारी अनुदेशों का सूजन होता है। इसमें महानिदेशक घरेलू उद्योग तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का ही प्रावधान होता है। किसी व्यापार नोटिस की विषयवस्तु से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है कि महानिदेशक एक निस्सहाय प्राणी हो जाए तथा वह अपने सांविधिक दायित्वों का निर्वहन न कर सकें। किसी विधि में रक्षोपाय शुल्क से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो महानिदेशक को घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर केवल इस आधार पर विचार करने से वंचित करता हो कि तीन वर्षों या उससे अधिक समय के उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। यह वर्तमान स्थिति में और भी अधिक संगत है क्योंकि उद्योग मार्च, 2012 में अवस्थिति में आया।
- 32. उपर्युक्त के मद्देनजर, इन तथ्यों तथा ऊपर उल्लिखित सूचना के स्रोतों पर विचार करते हुए वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ वर्ष 2012-13 से 2013-14 तक की अवधि के लिए आंकड़ों को अंगीकार करना उपयुक्त माना गया है । तुलना तथा उसके परिणामस्वरूप गंभीर क्षति का आकलन करने के प्रयोजनार्थ आंकड़ों को तिमाही आधार पर तोड़ना भी उपयुक्त माना गया है ।

च. प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता

- 33. रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.2 तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली,1997 के नियम 7 में कितपय सूचना को गोपनीय मानने का प्रावधान है। नियम में प्रावधान है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को ऐसी सूचना का प्रकटन वास्तविक आधार पर करना अपेक्षित नहीं है जो कंपनी की गोपनीय सूचना हो और जिसका प्रकटन करने उक्त पक्षकार के व्यापारिक हितों को गंभीर क्षित पहुंचने की पूर्वावधारणा हो, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध न हो और जिसका याचिकाकर्ता ने विगत में कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रकटन न किया हो।
- 34. घरेलू उद्योग ने कुछ सूचना गोपनीय आधार पर प्रदान कराई है और प्रस्तु सूचना/आंकड़ों की गोपनीयता का दावा किया है । घरेलू उद्योग ने रक्षोपाय नियमावली, 1997 तथा दिनांक 06.09.1997 के व्यापार नोटिस संख्या एसजी/टीएन/1/97 के प्रावधानों के अनुसार

² डब्ल्यूटी/डीएस 202/आर दिनांक 29.10.2001, यूएस पाइप लाइन मामले में पैनल रिपोर्ट

आवेदन-पत्र का अगोपनीय पाठ प्रदान किया । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आवेदन दायर करते समय गोपनीयता की मांग करने वाले कारणों का भी उल्लेख किया है जो तर्कसंगत प्रतीत होता है तथा उसे स्वीकार कर लिया है ।

छ. संवर्धित आयात:

- 35. सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने की केंद्रीय सरकार के अधिकारों का उल्लेख करता है और इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है :
 - "(1) यदि केंद्रीय सरकार, ऐसी जांच जिसे वह उचित समझे करने के पश्चात इस तथ्य से संतुष्ट है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो तो यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस वस्तु पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर सकती है।"
- 36. नियम में यह अधिदेशित है कि रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग करने के लिए संवर्धित आयात एक आधारभूत पूर्वापेक्षा है। अत:, यह निर्धारित करने के लिए संवर्धित शुल्क का अनुप्रयोग करने के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद के आयातों में "इतनी अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है" कि जिससे नियमों के अंतर्गत इन संवर्धित आयातों का विश्लेषण, घरेलू उत्पादों के संगत रूप में और समग्र रूप में करना आवश्यक हो गया है।
- 37. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 2 में "संवर्धित मात्रा" की निम्नलिखित परिभाषा दी गई है :
 - "(ग) संवर्धित मात्रा में आयातों में वृद्धि उत्पादन के समग्र या रूप में होना शामिल है।"

क) समग्र रूप से आयातों में वृद्धि:

38. बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों की प्रवृत्ति का विश्लेषण उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में किया गया । बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का भारत में आयात कई देशों से और प्राथमिकत: वियतनाम, कोरिया, चीन, सिंगापुर, ताईवान और थाईलैंड से किया जाता है। वर्ष 2012-13 से 2013-14 के दौरान बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयात की प्रमात्रा निम्नलिखित है:

अवधि	आयात (एमटी)	उत्पादन (एमटी)
2012-13 (पहली तिमाही)	2488	683
2012-13 (दूसरी तिमाही)	2628	400
2012-13 (तीसरी तिमाही)	2114	363
2012-13 (चौथी तिमाही)	2111	921
2012-13	9341	2367
2013-14 (पहली तिमाही)	2428	1247
2013-14 (दूसरी तिमाही)	2565	1152
2013-14 (तीसरी तिमाही)	2214	1127
2013-14 (चौथी तिमाही)	2086	1217
2013-14	9293	4743

39. उपर्युक्त तालिका में दिए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि समग्र रूप में आयातों में वृद्धि नहीं हुई। आयात जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में 2488 एमटी थे, घटकर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 2086 एमटी रह गए जो 16 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। इसके अतिरिक्त आयात जो वर्ष 2013 में 9341 एमटी थे घटकर वर्ष 2013-14 में 9293 एमटी रह गए जो 0.5 प्रतिशत की कमी है।

ख) उत्पादन के संबंध में आयात

40. भारत में इस विचाराधीन उत्पाद के आयातों में जांच की अवधि के दौरान आधार तिमाई/वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में कमी आई है। कुल उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में 364 प्रतिशत थे घटकर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 171 प्रतिशत रह गए। इसके अतिरिक्त, उत्पादन के संबंध में आयात जो वर्ष 2012-13 में 395 प्रतिशत थे घटकर वर्ष 2013-14 में 196 प्रतिशत रह गए।

अवधि	आयात (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	उत्पादन के संबंध में आयातों का प्रतिशत
2012-13 (पहली तिमाही)	2488	683	364
2012-13 (दूसरी तिमाही)	2628	400	657
2012-13 (तीसरी तिमाही)	2114	363	582
2012-13 (चौथी तिमाही)	2111	921	229
2012-13	9341	2367	395
2013-14 (पहली तिमाही)	2428	1247	195
2013-14 (दूसरी तिमाही)	2565	1152	223
2013-14 (तीसरी तिमाही)	2214	1127	196
2013-14 (चौथी तिमाही)	2086	1217	171
2013-14	9293	4743	196

41. उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में घरेलू उत्पादन के संगत रूप में या समग्र रूप में कोई वृद्धि नहीं हुई।

ज. गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण

42. सीमा-शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 8ख की उपधारा 6(ग) में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :

"गंभीर क्षति" का आशय उस क्षति से है जिससे घरेलू उद्योग की स्थिति में समग्र ह्वास होता हो।

43. गंभीर क्षति एवं गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण:

"गंभीर क्षति की चुनौती" से स्पष्ट एवं आसन्न खतरे से है।

44. सीमा-शुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैराग्राफ 1 में निम्नलिखित प्रावधान है : "यह निर्धारण करने में कि क्या संवर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति कारित की है अथवा गंभीर क्षिति कारित करने की चुनौती उत्पन्न कर दी है तो महानिदेशक उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिभाषात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करेंगे जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, इनमें संवर्धित वस्तु के आयातों में संगत एवं समग्र रूप से तीव्र की दर एवं राशि, संवर्धित आयातों द्वारा घरेलू बाजार पर किए गए कब्जे की हिस्सेदारी, बिक्री के स्रत में परिवर्तन, उत्पादन, उत्पादकता क्षमता आयोग, लाभ एवं हानि तथा रोजगार शामिल है।

- 45. तदनुसार, गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति का विश्लेषण करने के लिए उन सभी कारकों की जांच की गई जिनका उल्लेख नियमावली में किया गया है, इसके अलावा गंभीर क्षति कारित करने तथा गंभीर क्षति कारित करने की चुनौती को निर्धारित करने के लिए संगत पाए गए अन्य कारकों पर भी विचार किया गया। गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में किया गया जिनका घरेलू उद्योग पर प्रभाव पढ़ता है:
- **क. उत्पादन :** घरेलू उद्योग का उत्पादन जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में 6013 एमटी था, बढ़कर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 1217 एमटी हो गया । इसके अतिरिक्त, वार्षिक विश्लेषण में आवेदक का उत्पादन 2012-13 में 2367 एमटी से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 4743 एमटी हो गया ।

वित्त वर्ष/तिमाही	कुल आयात (एमटी)	उत्पादन (एमटी)	घरेलू बिक्री (एमटी)	कुल मांग (एमटी)	बाजार हिस्सा	
					Import	DI
2012-13 (पहली तिमाही)	2488	683	220	2708	92	8
2012-13 (दूसरी तिमाही)	2628	400	293	2921	90	10
2012-13 (तीसरी तिमाही)	2114	363	351	2465	86	14
2012-13 (चौथी तिमाही)	2111	921	815	2926	72	28
2012-13	9341	2367	1679	11020	85	15
2013-14 (पहली तिमाही)	2428	1247	931	3359	72	28
2013-14 (दूसरी तिमाही)	2565	1152	892	3457	74	26
2013-14 (तीसरी तिमाही)	2214	1127	670	2884	77	23
2013-14 (चौथी तिमाही)	2086	1217	918	3004	69	31
2013-14	9293	4743	3411	12704	73	27

- **ख. बिक्री के स्तर में परिवर्तन :** घरेलू उद्योग की बिक्री जो 2012-13 (पहली तिमाही) में 220 एमटी से बढ़कर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 918 एमटी हो गई । इसके अतिरिक्त वार्षिक विश्लेषण में भी बिक्री जो वर्ष 2012-13 में 1679 एमटी थी बढ़कर वर्ष 2013-14 में 3411 एमटी हो गई ।
- ग. बाजार हिस्सा: घरेलू उत्पादकों का बाजार हिस्सा आयातों की तुलना में बढ़ा है। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) के दौरान 8 प्रतिशत था, से बढ़कर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) के दौरान 31 प्रतिशत हो गया जबिक आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में 92 प्रतिशत था से कम होकर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 69 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त वार्षिक विश्लेषण करने पर घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2012-13 में 15 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 27 प्रतिशत हो गया और आयातों का बाजार हिस्सा जो वर्ष 2012-13 में 85 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 में 73 प्रतिशत रह गया।

घ. क्षमता उपयोग: घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2012-13 (प्रथम तिमाही) में 55 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) के दौरान 97 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, वार्षिक विश्लेषण में आवेदक का क्षमता उपयोग जो वर्ष 2012-13 में 47 प्रतिशत था बढ़कर वर्ष 2013-14 में 95 प्रतिशत हो गया। तथापि, घरेलू उद्योग की विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने की कुल क्षमता भारत में कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

वित्त वर्ष/तिमाही	अखिल भारतीय उत्पाद (एमटी)	संस्थापित क्षमता (एमटी)	क्षमता उपयोग
2012-13 (पहली तिमाही)	683	1250	55
2012-13 (दूसरी तिमाही)	400	1250	32
2012-13 (तीसरी तिमाही)	363	1250	29
2012-13 (चौथी तिमाही)	921	1250	74
2012-13	2367	5000	47
2013-14 (पहली तिमाही)	1247	1250	100
2013-14 (दूसरी तिमाही)	1152	1250	92
2013-14 (तीसरी तिमाही)	1127	1250	90
2013-14 (चौथी तिमाही)	1217	1250	97
2013-14	4743	5000	95

ड. रोजगार तथा उत्पादकता : क्षति अवधि के दौरान रोजगार एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष/तिमाही	उत्पादकता (एमटी/दिन)	रोजगार (संख्या)
2012-13 (पहली तिमाही)	8	221
2012-13 (दूसरी तिमाही)	4	230
2012-13 (तीसरी तिमाही)	4	227
2012-13 (चौथी तिमाही)	10	236
2012-13	26	229
2013-14 (पहली तिमाही)	14	249
2013-14 (दूसरी तिमाही)	13	252
2013-14 (तीसरी तिमाही)	13	256
2013-14 (चौथी तिमाही)	14	260
2013-14	53	255

ङ. **लाभ एवं हानि :** घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिलाभ में जांच की अवधि के दौरान सुधार हुआ है । यह निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है :

वित्तीय वर्ष	लाभप्रदता (लाख रुपए में) अनुक्रमित	लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ (%) (अनुक्रमित)	
2012-13	-100	-100	
2013-14	-76	-46	

छ. अन्य महत्वपूर्ण कारक:

(i) मांग के संबंध में आयात: अधोलिखित तालिका में यह नोटिस किया जाता है कि तिमाही वार विश्लेषण में मांग के संबंध में आयात जो वर्ष 2012-13 (प्रथम तिमाही) में 92 प्रतिशत था से घटकर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 69 प्रतिशत हो गया अर्थात इसमें 23 प्रतिशत की कमी आई। इसके अतिरिक्त, वार्षिक विश्लेषण में मांग के संबंध में आयात जो वर्ष 2012-13 में 85 प्रतिशत था घटकर वर्ष 2013-14 में 73 प्रतिशत हो गया अथार्त इसमें 14 प्रतिशत की कमी आई। इससे यह प्रदर्शित होता है कि घरेलू उद्योग स्थानीय बाजार में अपनी पकड़ बनानें में सक्षम है।

अवधि	आयात (एमटी)	मांग (एमटी)	मांग के संबंध में आयात %	मालसूची (एमटी)
2012-13 (पहली तिमाही)	2488	2708	92	477
2012-13 (दूसरी तिमाही)	2628	2921	90	584
2012-13 (तीसरी तिमाही)	2114	2465	86	521
2012-13 (चौथी तिमाही)	2111	2926	72	528
2012-13	9341	11020	85	528
2013-14 (पहली तिमाही)	2428	3359	72	646
2013-14 (दूसरी तिमाही)	2565	3457	74	675
2013-14 (तीसरी तिमाही)	2214	2884	77	601
2013-14 (चौथी तिमाही)	2086	3004	69	398
2013-14	9293	12704	73	398

- (ii) मालसूची: आयातों में कमी तथा घरेलू बिक्री में वृद्धि से घरेलू उद्योग को मालसूची का संग्रहण करने के लिए मजबूर नहीं किया गया। मालसूची जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में 477 एमटी थी, घटकर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 398 एमटी हो गई। वार्षिक विश्लेषण में भी मालसूची जो वर्ष 2012-13 में 528 एमटी थी घटकर वर्ष 2013-14 में 398 एमटी हो गई।
 - (ii) कीमत अधोरदन, निग्रहण/अवमंदन: यह देखा जाता है कि बेअर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न की सभी प्रजातियों के आयात की औसत उतराई कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से बहुत अधिक है। घरेलू एवं आयातित उत्पाद के बीच भारी कीमत अंतर है। आयातों की उतराई कीमत, उत्पादन लागत, बिक्री कीमत, निर्यात कीमत और कच्चे माल की कीमत निम्नवत है:

वित्तीय वर्ष	2012-13 (अनुक्रमित)	2013-14 (अनुक्रमित)
आयातों का उतराई मूल्य (रुपए/किग्रा)	100	118
उत्पादन लागत (रुपए/किग्रा)	100	83

बिक्री कीमत (रुपए/किग्रा)	100	113
निर्यात कीमत (रुपए/किग्रा)	100	114
कच्चे माल की कीमत (रुपए/किग्रा)	100	110
कीमत अधोरदन	-100	-148

46. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जाता है कि इस अवधि के दौरान उत्पादन लागत में कमी हुई तथा बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वर्ष 2012-13 की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान 13 प्रतिशत वृद्धि हुई, जो आयातों के उतराई मूल्य में हुई वृद्धि (18 प्रतिशत) की तुलना में बहुत कम थी जबिक उत्पादन लागत में (17 प्रतिशत) गिरावट आई। इस प्रकार आयात घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में निग्रहण नहीं कर रहे थे और आधोरदन भी नकारात्मक था। इसके अतिरिक्त, कीमत अवमंदन भी नहीं हुआ क्योंकि जांच की अवधि के दौरान बिक्री कीमत में वृद्धि हुई। यह देखा जाता है कि उक्त अवधि के दौरान कच्चे माल की कीमतों में (10 प्रतिशत तक) वृद्धि हुई परंतु उत्पादन लागत में कमी आई जिससे यह स्पष्ट होता है कि घरेलू उद्योग को अपनी कीमतें बढ़ाने से नहीं रोका गया। इसके अतिरिक्त, घटते हुए उत्पादन लागत का आशय यह है कि घरेलू उद्योग में सुधार हो रहा है और यह अधिक प्रतिस्पर्धी हो रही है।

47. **निर्यात**: अधोलिखित तालिका से यह नोट किया जाता है कि तिमाहीवार विश्लेषण में उत्पादन जो वर्ष 2012-13 (पहली तिमाही) में 0.06 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2013-14 (चौथी तिमाही) में 41 प्रतिशत हो गया अर्थात इसमें 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, वार्षिक विश्लेषण करने पर उत्पादन के संबंध में निर्यातों में वृद्धि जो वर्ष 2012-13 में 8 प्रतिशत थी बढ़कर 2013-14 में 31 प्रतिशत हो गई अर्थात इसमें 23 प्रतिशत की बढोतरी हुई। इसके अतिरिक्त, नियात बिक्री कीमत घरेलू बिक्री कीमत से कम है। अत: न्यूनतर कीमत पर अधिक निर्यात क्षति का एक कारण हो सकता है।

वित्तीय वर्ष/तिमाही	उत्पादन (एमटी)	निर्यात (एमटी)	उत्पादन के संबंध में निर्यात का प्रतिशत
2012-13 (पहली तिमाही)	683	0.39	0.06
2012-13 (दूसरी तिमाही)	400	10	3
2012-13 (तीसरी तिमाही)	363	70	19
2012-13 (चौथी तिमाही)	921	106	12
2012-13	2367	187	8
2013-14 (पहली तिमाही)	1247	200	16
2013-14 (दूसरी तिमाही)	1152	226	20
2013-14 (तीसरी तिमाही)	1127	532	47
2013-14 (चौथी तिमाही)	1217	501	41
2013-14	4743	1460	31

- 48. उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जाता है कि विचाराधीन उत्पाद के आयातों में भारत में उत्पादन के संगत रूप में और समग्र रूप में वृद्धि नहीं हुई। चूंकि घरेलू उद्योग के निष्पादन में कई पैरामीटरों में सुधार प्रदर्शित हुआ है, इससे यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण गंभीर क्षति सहन नहीं करनी पड़ी है। वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के निष्पादन में नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी क्षति पैरामीटरों में सुधार हुआ है जैसाकि ऊपर दर्शाया गया है। जांच के दौरान बाजार हिस्से, उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची में कमी आई है। इस संपूर्ण अवधि में कीमत अधोरदन ऋणात्मक था। इसके अतिरिक्त, आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में वृद्धि को लागत में वृद्धि के अनुपात में बढ़ने से रोक नहीं रहे हैं।
- 49. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को आयातों के कारण क्षति नहीं हुई है ओर इसलिए आयात एवं घरेलू उद्योग द्वारा सहन की गई कथित क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध नहीं है । घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि भारी क्षमता उपयोग के बावजूद उन्हें भारी घाटा हुआ । केवल क्षति या निरंतर क्षति का आशय गंभीर क्षति नहीं है । घरेलू उद्योग को निम्नलिखित सूचीबद्ध कई कारणों से क्षति हुई जिसमें

उच्च निर्धारित लागत शामिल है । मेरे विचार से वित्तीय घाटा हुआ है परंतु विधिक क्षति नहीं हुई । यदि कोई क्षति हुई है तो उसके लिए न्यून कीमत वाले आयातों के अलावा कई अन्य कारक उत्तरदायी है जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है और जिन्हें घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन/प्रस्तुतिकरण में स्वीकार किया गया है ।

- (क) यह संयंत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित था और यह उम्मीद की गई थी कि उन्हें पिछड़ा क्षेत्र का लाभ मिलेगा, जो नहीं मिल सका।
- (ख) उन्हें कई कारकों के कारण लागत सहन करनी पड़ी जैसे कच्चे माल एवं परिष्कृत उत्पाद की ढुलाई और भूभागीय क्षेत्र में भारी संभारतंत्रीय लागत। इसके कारण परिष्कृत उत्पाद पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त लागत के साथ-साथ ग्राहकों को की गई बिक्री पर 1 प्रतिशत सीएसटी भी लगा जो हिमाचल प्रदेश के बाहार अवस्थित थे।
- (ग) घरेलू उद्योग द्वारा आयात कीमत की तुलना में कीमत प्राप्त करने में अक्षमता।
- (घ) विश्लेषण से यह भी नोटिस किया जाता है कि इस विचाराधीन उत्पाद के कुल उत्पादन के 33 प्रतिशत का निर्यात घरेलू उद्योग द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान घरेलू बिक्री कीमत से कम कीमत पर किया गया जो क्षति के कारणों में से एक कारण हो सकता है।
- 50. अत:, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों को आलोक में करने पर, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, उनकी स्थिति में भारी सुधार प्रदर्शित हुआ। अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को जांच की अविध के दौरान न तो कोई गंभीर क्षति हुई और न ही गंभीर क्षति की चुनौती मौजूद थी।

झ. संवर्धित आयात और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध

51. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुसार महानिदेशक (रक्षोपाय), अन्य बातों के साथ-साथ, इन नियमों के अनुबंध में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती का निर्धारण करना होगा।" इसके अतिरिक्त अनुबंध का पैराग्राफ 2 कथित संवर्धित आयातकों तथा गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना भी अपेक्षित होता है। नियम 8 के अनुबंध में पैराग्राफ 2 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"पैराग्राफ (1) में उल्लिखित निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि, उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर, जांच से यह स्पष्ट नहीं होता है कि संवर्धित वस्तु के संवर्धित आयातों तथा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है। साथ ही, जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हो तो उस क्षति के लिए संवर्धित आयातों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।"

52. कोरिया डेयरी पैनल ने "कारणात्मकता" का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित आधारभूत अधिगम निर्धारित किया है।

''अपना कारणात्मक संबंध आकलन करने में हमारा विचार है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी को यह विश्लेषण करना और यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि क्या उद्योग में हुआ विकस, जिसे राष्ट्रीय प्राधिकारी ने गंभीर क्षिति का प्रदर्शन करने के लिए विचारा है, संवर्धित आयातों के कारण कारित किया गया है। अपने कारणात्मक आकलन में राष्ट्रीय प्राधिकारी को उन सभी संगत कारकों का उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति का मूल्यांकन करना होता है जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त, यदि राष्ट्रीय प्राधिकारी ने संवर्धित आयातों के अलावा कुछ अन्य ऐसे कारक अभिज्ञात कर लिए हों जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंची हो तो वह यह सुनिश्चित करेंगे कि इन कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए यह नहीं माना जाएगा कि वह क्षति संवर्धित आयातों द्वारा कारित की गई है।

एक कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए कोरिया को यह प्रदर्शित करना कि इसकी घरेलू उद्योग को क्षति संवर्धित आयातों के कारण हुई है । दूसरे शब्दों में, कोरिया को यह प्रदर्शित करना पड़ा कि एसएमपीपी के आयातों द्वारा दुग्ध पावडर और अपरिष्कृत दुग्ध का उत्पादन करने वाली घरेलू उद्योग को क्षति हुई है । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने के उपरांत कोरियाई प्राधिकारियों की यह प्रतिबद्धता थी कि वह अन्य कारकों द्वारा कारित क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी न ठहराएं।

³ कोरिया पर पैनल रिपोर्ट – डेयरी, पैरा 7.89-7.90

53. कारणात्मक का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ उद्देश्यपरक एवं परिमाणात्मक प्रकृति के उन सभी संगत कारकों का मूल्यांकन किया गया जिनका घरेलू उद्योग की प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो यह कि आयातों में कोई उद्रेक नहीं हुआ और जांच की अविध के दौरान उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता जैसे कारकों में सुधार हुआ। द्वितीयत:, जांच की अविध के दौरान आयातों की उत्पाई, कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है। इस प्रकार आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों का बाजार में निग्रहण नहीं हो रहा था और कीमत अधोरदन ऋणात्मक है। यह देखा जाता है कि जांच की अविध के दौरान विचाराधीन उत्पाद की उत्पादन लागत में कमी आई है और बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है। अत:, ऐसे संकेत हैं कि घरेलू उद्योग को आयात कीमत के कारण क्षति नहीं हो रही है। जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ है। जांच की अविध के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है और आयातों के बाजार हिस्से में कमी आई है। चूंकि आयात संविधित नहीं हुए और ऊपर के पैराग्राफ में किए गए उल्लेख के अनुसार आयातों द्वारा गंभीर क्षति कारित नहीं की गई है, इसलिए संविधित आयातों और गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की चुनौती के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करने के लिए मूल्यांकन करने की जरूरत नहीं है।

ञ. समायोजन योजना

- 54. सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 5(2)(ख) में "आयात प्रतिस्पर्धा के साथ सकारात्मक समायोजन करने के लिए बनाई गई योजना या किए जा रहे प्रयासों या दोनों" के संबंध में प्रस्तुतिकरण करना अपेक्षित होता है । इसके अतिरिक्त, रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 7.1 में प्रावधान है कि कोई सदस्य रक्षोपाय शुल्क का अनुप्रयोग समायोजन को सुलभ बनाने तथा गंभीर क्षति को रोकने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यकतानुसार कर सकता है।
- 55. निर्णयात्मक रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को एक सीमित समयावधि प्रदान करना है जिसके अंदर वे अपना इस तरह पुनर्गठन कर सकें जिससे कि वे आयातों के साथ कारगर ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकें । सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की धारा 8ख(4) तथा सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली 1997 के नियम 16(2) में ऐसे साधन का उपयोग करने का निषेध किया गया है तब ऐसे साक्ष्य हों कि घरेलू उद्योग समायोजन का प्रयास नहीं कर रहा है।
- 56. इस मामले में घरेलू उत्पादकों ने निम्नलिखित समायोजन योजना निर्धारित की है:
 - (i) घरेलू उद्योग अगले एक वर्ष में 300 करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी उत्पादन क्षमता में 5000 एमटी प्रति वर्ष विस्तार करने की प्रकल्पना कर रहा है।
 - (ii) और मार्च, 2017 तक 300 करोड़ रुपए का और निवेश करके अपनी क्षमता में 5000 एमटी प्रतिवर्ष अतिरिक्त क्षमता वृद्धि करेगा।
 - (iii) इससे निर्धारित लागत कम होगी और उत्पादन लागत में कमी आएगी जिससे लाभ बढ़ेगा।
- 57. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने समायोजन प्रक्रिया में दो बड़े प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं का चयन किया है और उन्होंने इन दो बड़े प्रौद्योगिकी आपूर्तिकर्ताओं से उनके कुटेशन तथा अनुमानित परियोजना लागत प्राप्त कर ली है। वे छह सिग्मा विधि से उच्च गुणवत्ता मानकों का क्रियान्वयन करने ओर निष्क्रिय पदार्थ का उपशमन करने की प्रक्रिया में हैं। उन्होंने पुन: यह प्रस्तुत किया कि आपूर्तिकर्ताओं के दल ने विस्तृत तकनीकी विश्लेषण के लिए स्थल दौरा किया है और 13 अगस्त को चर्चा की है। आवेदक को यह उम्मीद है कि इससे उसकी लागत में कमी जाएगी। तदनुसार, आवेदक ने रक्षोपाय शुल्क तीन वर्षों की अविध के लिए लगाने का अनुरोध किया है जिससे वह अपनी आयात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सके।
- 58. पुन: यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त समायोजन योजना के कारण कंपनी की स्थिति में (i) इसकी लागत में कमी होने के बेहतर मार्जिन मिलेगा और (ii) बिक्री प्रापण में वृद्धि होगी। उपर्युक्त के मद्देनजर ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक ने एक लाभप्रद समायोजन योजना प्रस्तुत की है।
- 59. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना काल्पनिक है और उसमें किसी ठोस प्रयास को नहीं दर्शाया गया है।

60. इस संबंध में यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग ने एक समायोजन योजना प्रस्तुत की है जो 2-3 वर्षों तक चलेगी। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार सकारात्मक समायोजन योजना के लिए कोई समयबद्ध ठोस योजना घरेलू उद्योग ने नहीं दी है। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 30.06.2014 के प्रस्तुतिकरण में यह स्वीकार किया है कि 5000 एमटी के विस्तार का दूसरा चरण जो जुलाई, 2013 में शुरू होना था कुछ अनपेक्षित घटनाओं के कारण उसमें विलंब हो गया। विस्तार के संबंध में घरेलू उद्योग ने कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। मेरे विचार से घरेलू उद्योग ने व्यवहार समायोजन योजना प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि वह आयातित विचाराधीन उत्पाद की चुनौती के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

ट. अनपेक्षित विकास

- 61. घरेलू उद्योग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि महानिदेशक रक्षोपाय पर कोई ऐसा अभिव्यक्त दायित्व/अपेक्षा नहीं है कि वे अनपेक्षित परिस्थितियों का विश्लेषण करें क्योंकि भारतीय विधि में अथवा जीएटीटी में अथवा रक्षोपाय संबंधी डब्ल्यूआओ करार में ऐसा कोई विशिष्ट मार्गदर्शन या क्रियापद्धित नहीं है जिसका अनुपालन अनपेक्षित विकास का विश्लेषण करते समय किया जाना चाहिए। इस संबंध में मैं पाता हूं कि गट, 94 के अनुच्छेद–XIX में प्रावधान किया गया है कि गंभीर क्षति अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप होनी चाहिए।
- 62. गाट 1994 के अनुच्छेद- XIX में निम्नलिखित उल्लेख है:
 - 1. (क) यदि अनपेक्षित विकास के परिणामस्वरूप और इस करार के अंतर्गत किसी संविदाकारी पक्षकार द्वारा प्रशुल्क रियायतों सिहत सौंपे गए किसी दायित्व के प्रभावीस्वरूप उस संविदाकारी पक्षकार के भूभाग से किसी उत्पाद का आयात इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में या ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाता है जिससे उस भूभाग के समान या प्रत्यक्षत: प्रतिस्पर्धी उत्पाद के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षिति कारित होती है अथवा गंभीर क्षिति की चुनौती उत्पन्न हो जाती है तो संविदाकारी पक्षकार ऐसे उत्पाद के संबंध में ऐसी सीमा तक अथवा ऐसे समय तक के लिए जो उस क्षित से बचने अथवा उसका उपचार करने के लिए आवश्यक हो, उस प्रतिबद्धता को समग्र रूप से या उसके किसी भाग को समाप्त करने अथवा रियायत को वापस लेने या उसमें कोई संशोधन करने के लिए स्वतंत्र होगा।"
- 63. अर्जेन्टीना फुटवियर (ई सी मामला) में अपीलीय निकाय ने धारित किया कि पदबंध अनपेक्षित विकास का आशय उस विकास से है जो अप्रत्याशित हो। "अनपेक्षित विकास" यह अपेक्षा करता है कि वह विकास जिसके कारण किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में निर्यात किया जा रहा हो कि घरेलू उत्पादकों को अप्रत्याशित गंभीर क्षति होने लगी हो या गंभीर क्षति की चुनौती उत्पन्न हो गई हो। कोरिया-डेयरी मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास वह विकास होता है जो अनपेक्षित न हो या किसी सदस्य द्वारा कोई दायित्व लिए जाने के समय प्रत्याशित न हो।
- 64. अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में अपीलीय निकाय ने यह धारित किया कि अनपेक्षित विकास की जरूरत रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने के लिए कोई पृथक "शर्त" स्थापित नहीं करता है, परंतु यह केवल परिस्थितियों के एक निश्चित "समृह" को वर्णित करता है ।
- 65. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनपेक्षित विकास प्रस्तुत किया है :
- क) कम कीमतों पर संवर्धित आयात : कम कीमत पर संवर्धित आयात अनपेक्षित विकास नहीं होता है । अर्जेंटीना प्रिणर्वु पीच मामले में पैनल ने जोर दिया कि आयातों की संवर्धित मात्रा को अनपेक्षित विकास के समान न माना जाए । इसमें न ही कुछ अनपेक्षित है और न ही कुछ विकास । अत: न्यून कीमत पर होने वाले आयातों को अनपेक्षित विकास नहीं कहा जा सकता है । सर्वोपिर, घरेलू उद्योग का यह दावा है कि आयात कम कीमत पर हुआ, गलत है, क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि आयात कीमतें घरेलू बिक्री कीमतों से उच्चतर हैं ।
- ख) पिछड़ा क्षेत्र लाभ: यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने पिछड़ा क्षेत्र लाभ की प्रकल्पना की थी परंतु वे लाभ उसे प्राप्त नहीं हुए, रक्षोपाय विधि के आशय के अंतर्गत अनपेक्षित विकास नहीं है। अनपेक्षित विकास से आशय उस विकास से होता है जिसके कारण इस उत्पाद की इतनी अधिक संवर्धित मात्रा में और ऐसी परिस्थितियों में आयात हुआ होता जिससे घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति अथवा क्षति की चुनौती "अनपेक्षित" हुई होती जैसा कि डब्ल्यूटीओ द्वारा अर्जेंटीना फुटवीयर मामले में धारित किया गया है। यह वह परिस्थिति है जिसकी अवस्थिति अनपेक्षित होती। हालांकि यह तथ्य गंभीर क्षति के लिए अनेपक्षित विकास

- हो सकता है परंतु यह संवर्धित आयातों के लिए अनपेक्षित विकास नहीं हो सकता है । उपर्युक्त के मद्देनजर, पिछड़ा क्षेत्र लाभ वर्तमान मामले में संगत अनपेक्षित विकास नहीं हो सकता है ।
- ग) **शुल्क मुक्त आयात की अनुमित देते हुए भारत आशियान संधि**: आशियान संधि अनपेक्षित विकास इस कारण से नहीं हो सकती है कि यह संधि घरेलू उद्योग की स्थापना होने से काफी पहले की गई थी। घरेलू उद्योग ने अपना उत्पादन मार्च, 2012 में प्रारंभ किया था वहीं यह संधि वर्ष 2010 में की गई थी। इसलिए घरेलू उद्योग विचाराधीन उत्पाद पर लगने वाले संभावित सीमाशुल्क के प्रति पूर्ण सतर्क होना चाहिए था। अत: इस विकास को अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता है।
- घ) अत: यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग ने आयातों में वृद्धि होने के जिन कारणों का उल्लेख किया है उन्हें "अनपेक्षित विकास" नहीं कहा जा सकता है। वास्तव में आयातों में उद्रेक को देखा नहीं गया।

ठ. जनहित

- 66. केवल घरेलू उत्पादकों के हित को ही जनहित नहीं कहा जा सकता है। यदि यह मान भी लिया जाए कि विचाराधीन उत्पाद पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करने से घरेलू उत्पादकों के हित संरक्षित होंगे तो भी उसे जनहित नहीं माना जा सकता है। इस विचाराधीन उत्पाद की भारत में मांग घरेलू उद्योग जो इस उत्पाद का भारत में एकमात्र उत्पादक है के कुल उत्पादन से 2.5 गुना अधिक है, और चूंकि अपनी क्षमता में वृद्धि करने के लिए दी गई समायोजन योजना एक प्रस्ताव से बढ़कर और कुछ नहीं है, इसलिए मांग आपूर्ति में यह अंतर अगले दो वर्षों में जब तक घरेलू उद्योग प्रस्तावित क्षमता विस्तार करता है और भी अधिक बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग अपने उत्पाद के 30 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करता है जो घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता को और भी अधिक कम कर देता है। भारी मांग आपूर्ति अंतर तथा घरेलू उद्योग द्वारा अपनी क्षमता में उस स्तर तक वृद्धि करने में अक्षमता के कारण, जिस स्तर पर वह अगले दो वर्षों में कुल भारतीय मांग को पूरा करने में सक्षम हो पाता, बल्कि इससे उपभोक्ता उद्योग के विधि सम्मत हित और अधिक प्रभावित होंगे। इसलिए इन परिस्थितियों में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण करना जनहित में नहीं होता।
- 67. **गुणवत्ता मुद्दा :** इस विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता उस अन्य फेब्रिक में लगने वाली लागत, जिसमें इसका प्रयोग होता है, को देखते हुए बहुत अधिक है । कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह प्रस्तुतिकरण किया है कि यदि घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान कराई जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता अच्छी हो तो अधोप्रवाही उद्योग अधिक का भुगतान करने के लिए तैयार है । इस संदर्भ में घरेलू उद्योग ने यह प्रस्तुत किया है कि घरेलू रूप से उत्पादित वस्तु तथा भारत में आयातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई वास्तविक अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग ने प्रस्तुतिकरण किया है कि गुणवत्ता वह अपेक्षित पैरामीटर नहीं है जिसका रक्षोपाय जांच में विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है । इस संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सीमाशुल्क प्रशुल्क (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं आकलन) नियमावली, 1997 के नियम 8 के अनुबंध के पैरा 2 में यह उल्लेख है कि "जब संवर्धित आयातों के अलावा अन्य कारण साथ ही साथ क्षति कारित कर हो हो तो उस क्षति के लिए संवर्धित आयातों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा ।" इस मामले में घरेलू उद्योग की वस्तु में गुणवत्ता का मुद्दा वह कारण है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग अपने उत्पाद के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार होने में ही अच्छी कीमत प्राप्त करने में अक्षम रहा । घरेलू उद्योग ने अपने प्रस्तुतिकरण में यह स्वीकार किया है कि नवम्बर 12 से मार्च 14 के बीच कुल बिक्री से होने वाला बिक्री प्रतिलाभ 3 प्रतिशत था और घरेलू उद्योग संदत्त कुल क्षतिपूर्ति 0.15 प्रतिशत के लगभग है । इसके अतिरिक्त, विश्लेषण करते वक्त यह नोटिस किया गया कि घरेलू उद्योग घरेलू वस्तु के लिए पेशकश की जा रही कीमत तथा निर्यात वस्तु की कीमत तथा निर्यातित माल एवं आयातित माल की कीमत में बहुत अंतर है।

ड. जांच की अवधि के पश्चात आंकडों की जांच:

68. इन परिस्थितियों में जांच की अवधि के पश्चात की अवधि अर्थात वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही के पश्चात की अवधि का विश्लेषण किया गया जिससे कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की संभावना के बारे में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सके। घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 14 अगस्त, 2014 के पत्र के तहत घरेलू उद्योग ने भारत में आयातित संबद्ध विचाराधीन उत्पाद के लिए कतिपय आर्थिक पैरामीटरों से संबंधित आंकड़े अधोलिखत हैं:

	2012-13			2013-14				2014-15	
	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही
कुल आयात (एमटी)	2488	2628	2114	2111	2428	2565	2214	2086	2543
उत्पादन (एमटी)	683	400	363	921	1247	1152	1127	1217	1204
घरेलू बिक्री (एमटी)	220	293	351	815	931	892	670	918	965
कुल मांग (एमटी)	2708	2921	2465	2926	3359	3457	2884	3004	3508
आयातों का बाजार हिस्सा (%)	92	90	86	72	72	74	77	69	72
घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा (%)	8	10	14	28	28	26	23	31	28
मालसूची (एमटी)	477	584	521	528	646	675	601	398	333
लाभप्रदता (लाख रुपए में) (अनुक्रमित)	-100	-127	-138	-96.3	-89.3	-122	-54		-45

69. उक्त आंकड़ों की संवीक्षा करने पर यह नोट किया गया कि जांच की अविध के पश्चात् की अविध की तिमाही के दौरान आयातों में इतनी अधिक वृद्धि हुई है कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में समसामियक अविध में आई 3 प्रतिशत की गिरावट की तुलना में आयातों के बाजार हिस्से में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यद्यपि विगत तिमाही की तुलना में जहां की अविध के पश्चात् की तिमाही में उत्पादन में लगभग 1 प्रतिशत की मामूली सी गिरावट आई फिर भी घरेलू बिक्री में 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मालसूची में 16 प्रतिशत की कमी आई । यद्यपि जांच की अविध के पश्चात् की तिमाही के दौरान आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति के साथ घरेलू उद्योग के लिए लाभप्रदता में वृद्धि हुई । इससे यह संकेत मिलता है कि जांच की अविध के पश्चात् की तिमाही में आयातों में वृद्धि हुई, परंतु यह घरेलू उद्योग को किसी क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं है । इसके अतिरिक्त, अभी भारत सरकार द्वारा बेयर अलास्टोमेरिक का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल पर सीमाशुल्क दिनांक 11/07/2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014 सीमाशुल्क के तहत 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करके उसे संरक्षण प्रदान किया गया । इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत कम हो जाएगी और लाभप्रदता में वृद्धि होगी ।

ढ. निष्कर्ष

- 70. विचाराधीन उत्पाद के आयातों में समग्र रूप से और भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में कमी आई । जांच की अवधि के दौरान बेयर अलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों की मात्रा में कमी आई । अत: यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों में समग्र रूप से तथा घरेलू उत्पादन के संबंध में कोई वृद्धि नहीं हुई ।
- 71. जांच की अवधि के दौरान बाजार हिस्सा, उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता उपयोग, उत्पादकता, लाभप्रदता और निवेश पर प्रतिलाभ में सुधार हुआ। संपूर्ण क्षति अविध के दौरान घरेलू उद्योग के मालसूची में कमी आई है। संपूर्ण अविध के दौरान कीमत अधोरदन नकारात्मक रहा। अत:, घरेलू उद्योग की समग्र स्थिति का मूल्यांकन उन सभी संगत कारकों के आलोक में करने पर, जिनका घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो, यह पाया गया कि घरेलू उद्योग की स्थिति में बाजार हिस्सा, उत्पादन, बिक्री, निर्यात, मालसूची और लाभप्रदता में सुधार हुआ। यहां तक कि आयातों में भी कमी आई। इस प्रकार जांच की अविध में घरेलू उद्योग को न तो कोई क्षति हुई और न ही क्षति की चुनौती उत्पन्न हुई।
- 72. यहां तक कि जांच की अवधि के पश्चात् के आंकड़े के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ कि संवर्धित आयात घरेलू उद्योग की क्षति का एक कारण नहीं है क्योंकि आयातों में वृद्धि के साथ-साथ बिक्री में वृद्धि हुई और घाटे में कमी आई। इससे यह संकेत मिलता है कि आयातों तथा

गंभीर क्षति के बीच किसी भी कारणात्मक संबंध का कोई साक्ष्य नहीं है । इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने आयातित विचाराधीन उत्पाद की चुनौती को पूरा करने के लिए प्रतिस्पर्धी होने के लिए अर्थक्षम समायोजन योजना उत्पन्न नहीं की ।

73. अंत:, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को कोई गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की कोई चुनौती नहीं थी और जांच की अवधि के पश्चात् (वर्ष 2014-15 की पहली तिमाही में) भी कोई संरक्षण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, अभी हाल ही में भारत सरकार ने बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न का विनिर्माण करने के लिए अपेक्षित कच्चे माल पर दिनांक 11/07/2014 की अधिसूचना संख्या 12/2014-सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से कम करके शून्य करके घरेलू उद्योग को पहले ही राहत दे दी गई है, जिससे उसकी स्थिति में और अधिक सुधार होगा।

थ सिफारिश

74. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि "सभी डेनियर्स और सभी वैरायटियों के बेयर इलास्टोमेरिक फिलामेंट यार्न के आयातों पर एतद्दारा रक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती है और इस संबंध में यह जांच समाप्त की जाती है।

> [फा. सं. डी.-22011/23/2013] आर. के. सिंगला, महानिदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

[DIRECTORATE GENERAL OF SAFEGUARDS (CUSTOMS & CENTRAL EXCISE)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

Subject:- Safeguard investigation concerning imports of Bare Elastomeric Filament Yarn

Final Findings

G.S.R. 702(E).—Dated 29th September, 2014, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 thereof;

I. Procedure

- 1. An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by M/s. Indorama Industries Ltd., Plot No.10, Industrial Area, Lodhi Majra, Baddi, Distt. Solan(H.P.) for imposition of Safeguard Duty on imports of Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties into India to protect the domestic producer of Bare Elastomeric Filament Yarn against serious injury/threat of serious injury caused by the increased imports of Bare Elastomeric Filament Yarn into India.
- 2. In order to satisfy the requirements under Rule 5 of the said Safeguard Rules, the information presented by the applicant was got verified by on-site visits to the plants of the domestic producers to the extent considered necessary. The non-confidential version of verification report is kept in the public file. On being satisfied that the requirements of the said Rule 5 were met, the Notice of Initiation of Safeguard investigation concerning imports of Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties into India was issued under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 on 28th February, 2014 and was published in the Gazette of India Extraordinary on the same day.

3. A copy of the Notice of Initiation dated 28th February, 2014 along with copy of non-confidential version of the application filed by the Domestic Industry were forwarded to the Central Government, in the Ministry of Commerce and other Ministries concerned, Governments of major exporting countries through their embassies in India, and the Interested Parties listed below, in accordance with Rule 6(2) and 6(3) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997:

(i) Domestic Producers

M/s. Indorama Industries Ltd., Plot No.10, Industrial Area, Lodhi Majra, Baddi, Distt. Solan(H.P.)

(ii) Foreign Nation/Delegation/Embassies

- a. The Embassy of People's Republic of China, 50-D, Shantipath, Chanakya Puri, New Delhi -21.
- b. The Embassy of Republic of Korea, 9. Chandragupta Marg,, Chanakya Puri Extension, New Delhi -21.
- c. The Embassy of TaiwanTaipei Economic and Cultural Center in India, 34, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057.
- d. The Embassy of Vietnam, 17, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110 021.
- e. The High Commission of The Republic of Singapore, E-6, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
- f. The Royal Thai Embassy, D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi-110057

(iii) Importers/Users/Users Association

- a. Indian Spinners Association (I S A), CIO The Millowners Association, Dhuru Bldg, 4th Floor, Gokhale Road North, Dadar West, Mumbai- 400028
- b. Indian Woollen Mills Federation, VII floor, Churchgate Chambers, 5, New Marine Lines, Mumbai-400002.
- c. Federation of Indian Art Silk Weaving Industry, 3rd Floor, SASMIRA, Sasmira Marg Worli, Mumbai- 400025.
- Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI), Federation House, Tansen Marg, New Delhi-110001
- e. The Confederation of Indian Industry (CII), Block No 3, Dakshin Marg, 31A, Sector 31, Chandigarh.
- f. The North India Section of the Textile Institute (NISTI), Megatech Overseas (India) Ltd., 317, MJ Shopping Centre 3, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
- g. The Texti1e-Association (TAI), 401, Gagan Deep, 12, Rajendra Place, New Delhi-110 008.
- Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council Mumbai (SRTEPC), Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Road, Mumbai-400020.
- Baddi Barotiwala Nalagarh Industries Association (BBNIA), Office of Single Window Clearance Agency, Industries Area, Baddi (H.P) 173205.
- j. The South India Spinners Association, Flat No. 103- 'A' Block, Raheja Centre, 1073 & 1074, Avinashi Road, Coimbatore, Tamil Nadu-641018
- k. Association of Man Made Fiber Industry of India, Resham Bhavan, 78, Veer Nariman Road, Mumbai-400020.
- 1. The Southern India Mills Association (SIMA),41, Race Course, Coimbtore-641018
- m. The Clothing Manufacturers Associations of India (CMAI), 902, Mahalakshmi Chambers 22, Bhulabhia Desai Road, Mumbai-400026
- n. Sangam (India) Limited,(SPG Unit-1), Post Box No 126, Biliya Kalan, Chittorgharh Road, Bhilwara, Rajasthan
- o. Sangam (India) Limited, SPG (UNIT-II), 91 K. M. Stone, N.H. No. 79, Sareri, Bhilwara, Rajasthan
- p. BST Textile Mills Pvt. Ltd., Plot No. 09, Sector 09, IIE SIDCUL Pantnagar, U.S. Nagar Rudrapur, Uttarakhand
- q. Aarti International Ltd., VIII Uchhi Mangli, P.O. Ramgarh outside Octroi Post, Chandigarh Road, Ludhiana
- r. SRV SYNTHETICS, Survey No. 259/12, Parshwanath Industrial Estate, Village Dadra & Nagar Haveli, (U.T.) Silvassa
- s. Jindal Denims Inc., (A division of Jindal World Wide Ltd.), 206, Saijpur-Gopalpur Piplaj-Pirana Road, Chikuwadi, Ahmedabad
- t. Sunheri Texcraft Pvt. Ltd., Plot No.-92, Sector-29, Part-II Huda, Panipat, Haryana
- u. Sachinam Fabrics Pvt Ltd., 1-37, 38, I-Zone, GIDC Sachin, Sachin, Gujarat

- v. Indo Rama Synthetics (India) Ltd., A-31, MIDC Industrial Area, Butibori, Nagpur, Maharashtra
- w. Deepak Impex Pvt. Ltd., Saijpur-Gopalpur, Pirana Road, Piplaj, Ahmedabad, Gujarat-382405
- x. Nahar Industrial Enterprises Limited, Unit II, Village Jalalpur, Chandigarh-Ambala Road, Lalru, Punjab

(iv) Foreign Producers/Exporters

- a. Hyosung Corporation, Kongduk Building, 450, Gongdeok Dong, Mapo Gu, Seoul, South Korea, 121-720
- b. Invista (Korea) Inc.19F, Kurnkang Tower 889-13 Daechi-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-280, Korea.
- c. Teakwang Industrial Company, Taekwang B/D, 162-1, Changchung-dong 2-ga Jung-gu Seoul 100-000 Korea;
- d. T.K.Chemicals, Sinsong Center B D 25-12, Yoido-Dong Youngdungpo-Gu Seoul, Korea.
- e. Hyosung Vietnam Co.N2 Street, NhonTrach, 5 Industrial Park, NhonTrach, Dong Nai, Viet Nam.
- f. Yantai, Rm,1206 10-15/F Qili Mansion 80 Chaoyang Street, Yantai, China.
- g. Investa, NVISTA Trading (Shanghai) Co. Ltd., 17 F, Hong Kong, New World Tower, No. 300, HuaiHai Road (M), Shanghai-200021, China.
- h. Investa, Sakra Manufacturing Works, 1 Sakra Avenue, Singapore-628225.
- i. Asahi, No. 336, Zhongzheng 3rd St., Yongkang City, Tainan County-71081, Taiwan.
- 4. Questionnaires were sent to the known exporters, known importers/users in India and other interested parties as per the information available, with request to make their views known in writing within 30 days of the Notice of Initiation.
- 5. Requests to consider them as interested parties were received from the following parties and same has been accepted:-

(i) Foreign Nation/Delegation/Embassies

- a. High Commission of Malaysia, Ministry of International Trade and Industry, 50-M, Satya Marg Chanakyapuri, New Delhi.
- b. Delegation of the European Union to India, 65 Golf Links, New Delhi-110003
- c. The Embassy of Japan, 50-G, Shantipath, Chanakya Puri, New Delhi -21.
- d. Embassy of the Arab Republic of Egypt, Commercial Bureau, 1/50 M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-21
- e. China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles, Fl. 7th No.12, Panjiayuan Nanli, Chaoyang Dist. Beijing-100021, China.
- f. Embassy of Russian Federation

(ii) Importers/Users/Users Association

- a. All India Spandex Yarn Importers Association, Krishna Tower, 1st Floor,35 Gajalakshmi Theatre Road, Tirpur-641604
- b. M/s. Narrow Elastic Manufacturers Association, Opp. Excellent Tutorials, Near Portugese Church, Dhuru Bldg., 4th Floor, Gokhale Road (North), Dadar (West), Mumbai-400028
- c. Confederation of Indian Textile Industry, 1508, Maker Chambers V, Nariman Point, Mumbai-400021
- d. Tirupur Exporters' Association, 62, Appachi Nagar, Main Road, Post Box No.:508, Kongu Nagar, Tirupur-641 607
- e. Association of Synthetic Fibre Industry, D-15, F-18-19, NDSE Part-II, New Delhi-110049
- f. Hosiery Manufacturers Association, Delhi, 5126/2, Harphool Singh Building, Clock Tower, Subzi Mandi, Delhi-110007
- g. INVISTA Sales & Service India Pvt. Ltd., 2nd & 3rd Floor, Vatika City point, M.G Road, Sector-25, Gurgoan, Haryana-122002
- h. M/s. Maral Overseas Limited, P.O. Maral Sarovar, Village-Khalbujurg-451660, Tehsil-Kasrawad, Dist. Khargone (Madhya Pradesh)
- i. Sitaram Spinners Pvt. Ltd.,"Rama Towers", 5-4-83, 2nd Floor, TSK Chambers, Opp: Ranigunj Bus Depot, MG Road,Secunderabad 500003.(A.P.)
- M/s. International Bussiness & Trade, 4/15, RBN Compound, Pitchampalayam Pudur, P.N Road, Tirpur-641603.
- k. Kohinoor Elastics Pvt. Ltd., 50-51,60-61 Pologround Industrial Estate, Indore-452015 (M.P.)

- Gimatex Industries Pvt. Ltd., 202, II Floor, Ramji House, 30, Jambulwadi, Kalbadevi Road, Mumbai-400002
- m. Lion Tapes P. Ltd, 283/B Gidc, Chitra Indl. Estate, Bhavnagar, Gujarat
- n. Stretch Bands (Guj.) Pvt. Ltd, 283/A, GIDC Chitra Est., Bhavnagar, Guajarat.
- Chiripal Industries Limited (Fibre Division), Survey No. 199/200, Saijpur-Gopalpur, Pirana Road, Piplaj, Ahmedabad-382405.
- p. Jindal worldwide Ltd., 1st floor "suryarath" panchvati 1st lane, ambawadi, Ahmedabad-380004, Gujarat.
- q. Hemspan Industries LLP, 6 Panchratna Industrial Estate, Sarkhej Bavla Highway Changodar Ahmedabad
- r. Hemlon Synthetics Pvt Ltd., 6 Panchratna Industrial Estate, Sarkhej Bavla Highway Changodar Ahmedabad
- s. M/S. Sunheri Texcraft Pvt Ltd,30,Paschim Enclave,Rohtak Road,Delhi-110087
- t. Associated Chemical corporation.,275/ 277 Samuel Street ,Masjid Bunder . Mumbai. Maharashtra
- u. Unifly Rubber Yarn Ltd.,403, Shivdutta Reddy, Topiwala lane, Goregaon west, Mumbai 400062
- v. Lotus Knits Private Limited, Plot no. C-471, TTC Industrial Area, MIDC, Pawane, Navi Mumbai- 400705
- w. M/S. Gopal Jee Fabrics, F-306, Sector-63, Noida-201301
- Anaadih Vincom Private Ltd., "DIAMOND ARCADE" Unit 413, 68, JESSORE ROAD, KOLKATA-700055
- y. Pioneer Apparels pvt Ltd., b-156 ph-2 ind area Noida
- z. Ginza Industries Ltd., 11, Clive Row, 4th Floor. R.No.1/A/A,Kolkata, West Bengal-700001
- aa. M/s. Elegant Overseas,38th mile stone, Jaipur Highway ,Behram pur Road,Gurgaon.
- bb. M/S. National Synthetics, 4/15-6, RBN Compound, Pitchampalayam Pudur, P.N Road, Tirpur-641603.
- cc. Spica Elastic Private Limited, 22/2, Hadapsar Industrial Estate, Pune 411 013, India
- dd. Cotton Concept (India) Pvt.Ltd., D-66, Sector-63, Noida. 201301 (U.P.)
- ee. Vardhman Textiles Limited, Chandigarh Road, Ludhiana (Punjab) Pin 141010
- ff. Raj exports, B/H. swastik bansidhar engg., N.H.NO. 8, Narol, Ahmedabad 382405.
- gg. Bishnu Texport Pvt. Ltd., B-121, Platinum Heights, Sector- 18B, Dwarka, New Delhi-110078
- hh. M/S. Silversand Agencies, 14, first street, Muthunagar, Kongu Main Road, Tirupur-641607
- ii. M/S. President Clothing Company, 15, first street, Muthunagar, Kongu Main Road, Tirupur-641607
- jj. M/S. Jinzun Synthetics 2/625(2/556), Third Street, Hare Rama Hare Krishna Nagar, Manglam Road Andipalayam Tirupur-641687
- kk. M/S. Loyal Textiles,83, R.A. Puram First Main Road, Chennai 600 028, India.
- II. BNT Innovations Private Limited, 11a, Kuthuspuram 3rd Street, P.N Palayam Road, Tirupur 641 607.
- mm. Zeon Internaional 167, Union Mill Road, Sangeetha Theater (opp) Tiruppur, India 641601.
- nn. M/s. Albion, 26/b222 layakram complex, Badarpur, New Dehi-110044
- oo. Zenith Fibress, 16/44, Andavar Bleaching Compound, Alangadu, Aruvampalayam, Tirupur / Tamil Nadu PIN-641604
- pp. M/S. Shivalik Prints Ltd , Plot No. 7, Sector -6 , Faridabad (H.R.) ,Pin-121006
- qq. Enfield Apparels Ltd ,"Paridhan Garment Park" Module 301-302, 19, Canal South Road, SDF-1/A, Kolkata- 700015. India
- rr. P.K.P.N. Spinning Mills P.Ltd., No.6, Bye-pass Road, Pallipalayam, Erode 638 006, Tamilnadu
- ss. Kiran Texpro Pvt. Ltd., Shed No.20,21,22,Sai Leela Industrial Estate,Near Old Petrol Pump,Udhna, Surat .GUJRAT-394210
- tt. Konika Industries, A/12/22, Road no 6, Udhana, Surat, Gujarat
- uu. Aarvee Denims & Exports Limited,191, Shahwadi, Near Old Octroi Naka, Narol, Sarkhej Highway, Narol, Ahmedabad 382 405
- vv. Bhaskar' industries Pvt Ltd., Plot No 15-16 Sector D. Industrial Area Mandideep-462046
- ww.M/S. Spando Impex, E-105, Veena Nagar C.H.S,S. V. Road, Malad (West), Mumbai 400 064
- xx. Ginza industries limited, 501-a, lotus corporate park, off western express highway, goregoan east, Mumbai -400 093
- yy. Mafatlal Industries Limited Denim Division, Vejalpore Road, NAVSARI 396445
- zz. Welspun Syntex Ltd., Trade World, 'B' Wing, 9th Floor, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai 400 013.

- aaa. Sogo Fashions pvt. Ltd. Plot No. D-1, D-2, Site-B, UPSIDC Industrial Area, Surajpur, Greater Noida, U.P. 201307
- bbb.J. M. Commodities Limited, 701, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai- 400021
- ccc. R. K. Brothers, E-105, Veena Nagar C.H.S,S. V. Road, Malad (West), Mumbai 400 064
- ddd.Arunachala Gounder Textile Mills P Ltd.,No.05, Bye-Pass Road, Pallipalayam, Erode 638 006, Tamil Nadu
- eee. Rajasthan International, 1402, Aggarwal Corporate Heights, A-7, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi 110 034.
- fff. M/S. Moscot Exports, -Above Kapoor Dental Clinic, Shivpuri Road, Ludhiana, Punjab-141007

ggg. Arvind Limited, Naroda Road, Ahmedabad, Gujarat, Pin: 380 025

- hhh.Birla Century,826, GIDC Jhagadia, Bharuch, Gujrat. iii. OswalWoollen Mills Ltd., G.T Road, Sherpur, Ludhiana.
- jij. Raymonds UCO Denim Pvt Ltd., Jekegram, Pokhran Road No.1, Thane(W), Mumbai.
- kkk. Denim Manufacturers Association, 40-41, Community Center, New Friends Colony, New Delhi
- lll. Gima Manufacturing Pvt. Ltd., Ram Mandir, Ward-Hinganghat, Dist.-Wardha(MS)

mmm. TEXPROCIL, 5th Floor, 9 Mathew Road, Mumbai.

- nnn. Unicharm India Pvt. Ltd.,2nd Floor, No.222,244.246 & 247, Centrum Plaza Building, Golf Course Road, Sector-53, Gurgoan-122002.
- ooo. Nandan Denim Ltd., Survey No. 198/1 & 203 Saijpur-Gopalpur, Piprana Road, Piplej, Ahmedabad.

(iii)Foreign Producers/Exporters

- a. Tk chemical corp, 3F, Yeonu Bldg, 416-8, Chimsan-dong, Buk-du, Daegu 702-713, Korea
- b. INVISTA Singapore Fibers Pvt. Ltd.,39,Tuas Crescent, Singapore-638726
- c. Hyosung spandex (jiaxing) co., Ltd., Bei Hai Road, Jiaxing Economic Development Zone, Zhejiang Province, China-314001
- d. Thai Asahi Kasei spandex co., ltd.919 Moo. 11, Tambol Nongkhaam, Amphur Sriracha, Chonburi 20230, Thailand
- e. Toray Opelontex Co.,Ltd. 3-3-3 Nakanoshima kita-ku Osaka-shi, Japan.
- f. AsahiKasei Fibers Corporation, 3-3-23, Nakanoshima, Kita-ku, Osaka, Japan 530-8205
- g. Korea Federation of Textile Industries (KOFOTI), Textile Center 16F, Daechi 3-dong, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
- h. Korea Chemical Fibers Association,9th FL, Chockson Hyundai Bldg,130, Sajik-RO, Chongno-gu,Seoul-110-756, Korea
- i. Vietnam Cotton and Spinning Association (VCOSA),10F1., Vinatex Tai Nguyen Bldg., 10 Nguyen Hue Str, Ben Nghe Ward, District 1, Hochirninh City, Vietnam.
- j. Taekwang Industrial Co., Ltd., Dongho-ro, jung-gu, seoul-100855, Korea
- k. Taekwang Synthetic Fiber(Changshu) Co., Ltd. Block-D,Tonggang Industrial Park, Changshu, Jiangsu, China.
- 1. ASAHI KASEI Spandex Europe GmbH, Germany
- 6. Requests for an extension of time to submit their replies received from the following parties which were allowed:
 - a. M/S. Hyosung Corporation, Korea.
 - b. Hyosung Spandex (jiaxing) Co.,Ltd., China .
 - c. Hyosung Vietnam Co. Ltd., Vietnam.
 - d. TK Chemical Corp., Korea.
 - e. China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles.
- 7. Following Interested Parties filed Questionnaire response/Submissions in response to the Notice of Initiation:
 - (i) Domestic Industry
 - M/S. Indorama Industries Ltd. (Domestic Industry)

(ii) Importers/Users/Users associations

- a. Unifly Rubber Yarn Ltd
- b. Maral Overseas Ltd
- c. Jinzun Synthetics

- d. Silversand agencies
- e. President Clothing Company
- f. Confederation of Indian Textile Industry (CITI)
- g. The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council
- h. Tirupur Exporters Association
- i. B.B.N. Industries Association
- j. The southern India Mills Association
- k. Associated Chemical Corporation
- 1. PKPN Spinning Mills (P) Ltd
- m. Ginza Industries Limited
- n. SachmamFabrics Pvt. Ltd
- o. Arvind Limited
- p. AGT Mills
- q. Zenon International
- r. Narrow Elastic Manufacturer Association
- s. National Synthetics
- t. International Business & Trade
- u. All India Spandex Yarn Importers Association
- v. Sitaram Spinners Pvt. Ltd
- w. INVISTA Sales & Service India Private Limited
- x. BishnuTexport Pvt. Ltd
- y. Vardhman Industries Ltd.
- z. Zenith Fibress
- aa. Chiripal Industries Ltd
- bb. KiranTexproPvt.Ltd
- cc. Gimatex Industries Pvt. Ltd.
- dd. BNT INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
- ee. Association of Synthetic Fibre Industry
- ff. Aarvee Denims and Exports Ltd.
- gg. Bhaskar Industries Pvt. Ltd.
- hh. Jindal WorlwIde Ltd.
- ii. Mafatlal Industries Ltd.
- jj. WelspunSyntex Ltd.
- kk. Birla Century
- ll. OswalWoollen Mills Ltd.
- mm. Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd.
- nn. Gima Manufacturing Pvt. Ltd.
- oo. TEXPROCIL
- pp. Denim Manufacturers Association
- qq. Unicharm India Pvt. Ltd.
- rr. Confederation of Indian Textile Industry
- ss. Vardhman Textiles Limited

(iii) Foreign Nation/Delegation/Embassies

- a. Taipei Economic and Cultural Center in India
- b. Embassy of the Arab Republic of Egypt
- c. Embassy of Russian Federation

(iv) Foreign Producers/Exporters

- a. Asahi Kasei Fibers Corporation, Japan
- b. Thai Asahi Kasei Spandex Co., Ltd., Thailand
- c. Tk chemical corp, Korea
- d. Taekwang Industrial Co., Ltd., Korea
- e. Taekwang Synthetic Fiber(Changshu) Co.,.Ltd., China
- f. HYOSUNG SPANDEX (JIAXING) CO., LTD., China
- g. Hyosung Vietnam Co, Vietnam

- h. Hyosung Corporation, Korea
- i. INVISTA Singapore Fibers Pvt. Ltd
- j. ASAHI KASEI Spandex Europe GmbH, Germany
- 8. All the views expressed by the interested parties have been taken into account in making appropriate determination. The non confidential information received or acquired has been kept in the public file.

II. Views of the Interested Parties (Post Notice of Initiation):

A. Ministry of Industry and trade of Russian Federation

Taking in to account that during the period of investigation from 2012 to 2013, the import of goods falling under sub-heading 54024400 and 54041100 of Custom Tariff Act,1975 and importing from the Russian Federation to India did not exceed three percent and hence the Russian Federation export should be excluded from the Safeguard measure in accordance with the Safeguard provision under the Customs Tariff Act, 1975 (Section 8B) and the article 9 of WTO Agreement on safeguards.

B. Taipei Economic and Cultural Center in India

- a. The market share of importation did not substantially increase.
- b. The percentage of import volume to domestic production volume on the notice of initiation of a safeguard investigation published by India's Directorate General of Safeguards did not show a consistent upward trend. Therefore, importation of the products under investigation did not meet the requirement for increased quantities of imports under Article 2.1 of the Agreement of Safeguards.
- c. In recent years, domestic demand for the subject products under the investigation has exceeded domestic production. If safeguard measures are adopted, this will restrict India's producers from obtaining the subject products which will be more competitive, and consequently, adversely affect India's overall economic development.

C. Arab Republic of Egypt:

According to Indian Statistics , there are no Egyptian export of the concerned product to India during investigation period and hence Egyptian export should be excluded from the Safeguard measure according to article 9.1 of Agreement on safeguards.

- D. M/S. DGS Advocates filed submissions on behalf of M/S. Hyosung Corporation, (Korea),T.K. Chemicals Corp. (TKC), Korea,Taekwang Industrial Co., Ltd., Korea,Hyosung Vietnam Co., Ltd., Vietnam, Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd., China, and Taekwang Synthetic Fiber (Changshu) Co., Ltd., China.
 - a. In the instant investigation the Applicant has not filed the Questionnaire for Domestic Producers and hence has failed to fully cooperate with the Investigating Authority.
 - b. In the instant case the Domestic Industry has not submitted any justified reason for claiming unforeseen development.
 - c. The domestic producer must establish that there is an increased imports and the Domestic producer needs
 time and plan to adjust themselves to meet the situation of competition offered by such increased imports.
 As there is no increase in imports, accordingly, no new situation has emerged due to any increased
 imports. Imports in absolute, as well as relative, terms have not increased.
 - d. Claim of the Domestic Industry that the prices of imports of the subject goods have not increased is totally incorrect and erroneous and not based on facts. The Domestic Industry has calculated landed value by not taking into consideration impact of landing charges and Education Cess on Customs Duty.

- e. There is no price undercutting/ Price underselling.
- f. The increase of imports of the subject goods is not sudden enough, sharp enough and significant enough, and there are no relatively increased imports of the subject goods necessitating imposition of safeguard duty.
- g. The alleged injury suffered by the Complainants neither meets the requirements under WTO Rules nor justifies the application of safeguard measures so, the increase in import if any have not caused any serious injury to the Indian domestic industry necessitating imposition of safeguard duty. The following facts submitted to the DG (Safeguards) would explain that the domestic industry has not suffered injury by import.
 - i. Capacity has been maintained constant level 5000MT.
 - ii. Production has increased during the period of investigation. More specifically, production increased from 2365.9MT in 2012-13 to 4,797.0MT in 2013-14(Annualized) an increase of 103%.
 - iii. Capacity utilization was doubled between 2012-13 and 2013-14(up to Sept.).
 - iv. Domestic sales have sharply increased from 1,679 in 2012-13 to 3,646 in 2013-14(Annualized)-an increase of 117%.
 - v. Total domestic consumption also have rapidly increased from 11,020 in 2012-13 to 13,632 in 2013-14(Annualized)-an increase of 23.7%.
 - vi. Analyzing domestic market share by quarterly is not appropriate, because it is very severe indicator so it is not enough to reflect market trends. Therefore, domestic market share should examine on the basis of annual analysis. the domestic market share have increased from 15% in 2012-13 to 25% in 2013-14, on the other hand, import market share have decreased from 85% in 2012-13 to 75% in 2013-14.
 - vii. Average employment has increased during the period of investigation.
 - viii. Inventory has increased during the period of investigation. But inventories balance to the production has decreased dramatically since 2012-13(Q4). Therefore, increase of inventory is result from increase of India domestic production.
 - ix. Profitability shows that the complainant has suffered injurious financial condition. But more recently, the indicator of Profit/loss and related financial situation of complainant is getting better.
- h. According to above evidence, there is no significant overall impairment in the position of domestic producers, so the alleged injury suffered by the complainants neither meet the requirements under WTO Rules nor justify the application of safeguard measures.
- i. The domestic industry has failed to establish a positive causal link that the increased imports caused serious injury to the domestic industry. At the same time, they have also failed to establish that other factors have not caused injury to the domestic industry.

E. M/S. J. Sagar Associates filed submissions on behalf of INVISTA Singapore Fibres Pte. Ltd & INVISTA Sales & Service India (P) Ltd.

 Indorama is not facing any serious injury due to increased imports of PUC from the Subject Countries during POI.

b. Domestic production:-

- (i) Data provided in annexure 5A to the Application provides that in spite of capacity being the same at 5,000 MT per annum since 2011-12 to September 2013 production has shown many fold increase from 18.1 MT in 2011-12 to 2398.5 MT till September 2013.
- (ii) Domestic Industry has also exported the Subject Goods out of India during POI, which show a scenario of surplus production and not fall.

c. Capacity Utilisation:-

(i) Despite of the installed capacity being the same i.e. 1250 MT for every quarter throughout POI, capacity utilisation has increased to 99.8% in quarter 1 of 2013-14 marginally dropping to 90.2% in quarter 3 thereof.

- (ii) The Domestic Industry cannot claim serious injury or threat thereof on the face of reaching 94% capacity utilisation in less than two years of commencing production of a new plant.
- d. <u>Domestic Sales:</u> As per table at para 5 of Section 4 to the Application the domestic sales during POI has considerably increased from 1866.5 MT in 2012-13 to 2249 MT in 2013-14 (*up till September 2013*) in six months period, which is clear indicator of exponential growth of the Domestic Industry contrary to claims of serious injury which is far from facts mentioned in the Application itself.
- e. <u>Inventory:-</u> There is no drastic increase in inventory throughout POI, which is in line with growth in production and capacity utilisation of new plant of Indorama. In 2012-13 (Q1) inventory (MT) was 477 and in 2013-14 (Q3) it is at 601 which is not a major change. Further even in 2013-14 from Q1 to Q3 inventory has gone down from 646 to 601.
- f. Productivity and Employment:-During POI there has been increase in the level of employment from average employment of 221 in 2012-13 (Q1) to 256 2013-14 (Q3). Further productivity per employee (MT) as also stated in the Initiation Notification has been on a rise from 3.0 in Q1 2012-13 to 4.4 in Q3 2013-14.
- g. **Import and market share:-** The Domestic Industry started commercial production in March 2012 and in less than two years i.e. till September 2013, admittedly has achieved 94% of capacity utilisation and captured nearly 30% of market share in the indigenous market. In view of the data and submissions of Indorama it is apparent that during POI, total imports although increased marginally, have actually shown negative trend when compared to rate in growth of local demand. Thus there has been no such significant increase in imports so as to cause impairment of the Domestic Industry.
- h. <u>Investment in surplus capacity:-</u>Domestic Industry in Annexure 6 to the Application has claimed that in order make positive adjustment of competition offered by imports, Indorama is increasing the capacity of their plant from present 5,000MT to 10,000 MT in March 2015. Thus, it is surprising that on one hand the Domestic Industry claims that alleged capacity surplus set up by the Exporters are suppressing domestic prices hence leading to serious injury or threat thereof and hampering growth of the Domestic Industry and on the other hand, Indorama itself is making confirming further investments to double existing production capacity of their plant.
- i. <u>Price undercutting:</u>-In view of table showing prices of the imported PUC in page 13 of the Application of the Domestic Industry it is clear that price of imported PUC has gone up gradually and there has been no price undercutting as claimed in the Application.
- j. In terms of Section 8B of the Customs Tariff, no impairment to the Domestic Industry has been caused due to serious injury or threat of serious injury firstly because there has been no sudden increase in imports of PUC so as to cause serious injury to the Domestic Industry.
- k. The whole proceedings are anti competitive:- The anti-competitive desires of the Domestic Industry is evident from their grievance of not able to increase price of PUC as stated in page 16 para f) of the Application.
- F. M/S. Unifly Rubber Yarn Ltd submitted as under:
 - a. The quality of the yarn produced by the said company does not matches the standard of the Koreans and Japanese. and no company will be willing to compromise in its finished products.
 - b Since this is the only company manufacturing Spandex in India, it will force all other companies to rely on it in the future which will increase the rates substantially without any reasons.
- **G.** M/S. Maral Overseas Ltd. submitted that they are manufacturing of Cotton Knitted Fabric with Lycra Spandex. They are Importing Lycra Spandex & Elaspan Spandex (Invista) from Singapore & Creora Spandex from Hyosung, Vietnam. Their monthly consumption of Lycra Spandex is approx. 10 MT. Earlier, they have used Inviya Spandex of Indorma and faced quality problem.

H. M/S. Jinzun Synthetics, Silversand Agencies & President Clothing Company: They are importers of Teflon Korean brand Spandex yarn and selling Spandex yarn to various exporters, fabric manufacturers and job workers. The manufacturing capacity of Indorarna synthetics is about 30% of the total Indian market requirement and hence is insufficient to feed the total market. If the price of spandex yarn is increased, it will cause a burden on the finished garment cost there by reducing the competitiveness of Indian garment industry in the international market.

I. Confederation of Indian Textile Industry, M/S. Arvind Ltd and M/S. Vardhaman Industries Ltd filed their injury submission through their Advocate M/S. Lakshmi Kumaran&Sridharan:-

- a. The applicant in this case has not presented any credible basis to demonstrate the existence of unforeseen developments.
- b. The applicant has stated that it was unable to foresee some of the developments arising as a result of operation in Himachal Pradesh. The alleged development identified by the applicant relates to a development that the applicant, rather than the negotiators, was not able to foresee. Furthermore, the alleged developments were unforeseen in March, 2012 when the applicant commenced commercial production rather than in 1995 when the negotiators undertook relevant concessions. Therefore, as a matter of law, the submission of the applicant is untenable.
- c. The applicant claims that it was unable to avail the backward area benefit that it had expected. The applicant has not offered reasons as to why it was unable to avail such a benefit. There may be possible reasons for this. Either the applicant has failed to meet the legal requirements set by the government or the government has changed its policy
- d. To the extent, the applicant has failed to meet the legal requirements set by the government, the applicant should have been able to foresee that if it failed to meet the relevant requirements it would be denied the said benefits.
- e. Furthermore, factors such as transportation of raw materials and finished products and high costs of logistics in the terrain area should have been completely obvious to an applicant that was setting up unit in Himachal Pradesh.
- f. The important obligation is that the unforeseen developments in issue must have resulted in surged imports. The imports in 2012-2013 when the applicant started production was 9341 compared to 9986 in 2013-14 (Annualized), a minor increase of 645 units. In fact, this increase was only because of increased market demand in India and imports in relation to demand actually decreased in 2013-14. While imports increased by 7%, demand actually increased by 24%. Therefore, the applicant was the biggest beneficiary of the increased demand in India. In such a circumstance, it is highly disingenuous to suggest that developments that the applicant could not foresee at the time it set up operations in Himachal Pradesh resulted in surged imports.
- g. The rate of customs duty was 5% when the applicant commenced commercial production. Since the applicant started operations in March 2012, it was already aware of the rate of the customs duty. Therefore, it cannot possibly argue that it could not foresee that the import duty would stand at 5% since the duty was already 5% when it commenced operations.
- h. In the present case, the imports are not recent, sudden, sharp and significant, for reason of which the threshold criteria specified in the legal texts are not met.
- i. The DG, Safeguards may appreciate that in contrast to the LAB case where the market share of imports continued to increase till the most recent year, the market share of imports in domestic demand, in the present case, is actually coming down. Therefore, there is even more reason, to conclude that there is no

suddenness in growth of imports. instead of a sharp increase, there has been a sharp decline in imports in relation to demand. Therefore, there is no sudden, recent, sharp and significant increase in imports.

- j. The position of the domestic industry is consistently improving and their market share is consistently increasing. Therefore, the current trend does not indicate a possibility of enhanced imports but in fact shows that imports are continuously decreasing. For such reason, there is no import in increased quantities within the meaning of Section 8B(1) read with Article 2.1 of the WTO Safeguards Agreement and Article XIX of GATT.
- k. The Initiation Notification indicates, the DG, Safeguards seems to have been influenced by the decline in domestic sales in Q3 of 2013-14. It is important to note that as per page 29 of the application, the total sales (export + domestic) in Q3 were the highest of the previous three quarters. The low sales in the domestic market were for the sole reason that the applicant exported more in Q3 than in any of the previous quarters.
- 1. It is highly unfair to blame end users in India because of the applicant's own decision to devote its resources to exports rather than the domestic market.
- m. In 2013-14 and most prominently in Q3 of 2013-14, the rupee depreciated significantly against the United States Dollar. Resultantly, the cost of borrowing for industries reliant on External Commercial Borrowings (ECB) has also increased significantly. The applicant is completely silent on this issue. The injury, if any, may be attributable to the unique financial structure of the applicant industry.
- n. The applicant has presented no time bound adjustment plan but has only presented unsubstantiated claims of expanding capacity.

J. The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council

- a. "Bare Elastomeric Filament Yarn" is widely used in the manufacture of Man-Made blended Fabrics whose exports from India have been increasing over the years. There is only one Indian Manufacturer of this item, M/s. Indorama Industries
- b. The domestic manufacturer will always price the item on the basis of import parity price which will include the Safeguard Duty. This will make the "Bare Elastomeric Filament Yarn" more expensive. Cost of the export product will increase to the extent of Safeguard Duty. Most of the exporters of Man-made fabrics use the Drawback route and this does not neutralize the Safeguard Duty. Thus the exporter will become less competitive.
- c. Safeguard investigation should be termination in the overall interest of the Indian textile industry and exports.

K. Association of Synthetic Ibre Industry

- a. Spandex Yarn is an important yarn for the domestic apparel and fabric production and is available at competitive prices in China and Korea.
- b. The imports are linked to exports of fabrics and apparels from India. Any duty on this kind of yarn will adversely impact the exports and domestic industry.
- c. The domestic industry works on Duty Drawback route for calculating their exports prices to remain competitive. The safeguard and ADD are not factored in duty drawback calculations.
- d. The domestic industry has earlier approached Ministry of Textiles to increase the import duty on this yarn so that being monopoly producer it can earn windfall profits since it sells this yarn at import parity in India
- e. If the domestic industry suffers any injury from imports, it should approach DGAD for specific remedy rather than blocking the entire imports from all over the world by levy of safeguard duty.

L. <u>Tirpur Exporters Association</u>

- a. Knitwear garment exporting units from Tirupur consume about 25% of total consumption of Bare Elastomeric Filament Yarn in India.
- b. The garment exporters could sustain in the competitive international market only when they supply desired quality garments apart from price and even a small deviation in the quality will trigger the quality conscious buyers to switch over to other competing countries.
- c. The capacity utilization of M/s. Indorama Industries Ltd., was steadily increasing and in a year itself it got increased from 54.6% in 2012 -13 (Q1) to 99.8% in 2013- 14 (Q1), which indicates that the garment industry was purchasing their yarn in the domestic market and also preferring to source the yarn form domestic product.
- d. The market share of domestic manufacturer had increased from just 9% in 2012-13 (Q1) to 39% in 2012-13 (Q4), within nine months itself and more or less maintained 38% in 2013- 14 (Q1). The decline has been observed only in 2013 -2014 (Q2) and (Q3) quarters.
- e. Imposition of safeguard measure would be no way helpful to increase the domestic consumption of knitwear garment exporting units and moreover, as a chain reaction, the duty imposed will affect all knitwear stakeholders of Tirupur and the people employed with them.

M. B.B.N. Industries Association

- a. Plant Capacity of M/s. Indorama is 5000 MT/year and it is operating at more than 90% utilization from last one year (within one year of its installation).
- b. M/s. Indorama is producing only limited product range of Elastomeric Filament Yarn and is exporting some of its goods.
- Domestic manufacturer capacity is only 30% of domestic demand at current consumption rate and this
 demand is rapidly increasing.
- d. Many of its users / customers are having quality issue with the existing product range. If manufacturer can address the quality issue, they must be able to sell the products easily with good amount of profit.

N. The Southern India Mills' Association

- a. The Association (SIMA) is 80 years old and it is the single largest employers' organization representing the entire textile value chain right from cotton research and development to garments/ made-ups /technical textiles in the country and plays a lead role in all policy making committees at State and Central level pertaining to the textile industry.
- b. Some of their member mills import Bare Elastomeric /Spandex yarn and produce value added materials like core spun yarn, stretch fabrics (knitted, woven including denim fabrics) to meet the demands in both domestic and international markets.
- c. The Association strongly objected any safeguard duty on the spandex yarn which would curtail the growth of manufacturing such products and also foreign exchange earnings.
- d. Quality of spandex yarn manufactured by M/s. Indo Rama Synthetics (the monopoly manufacturer in India) is far inferior when compared to the imported spandex yarn in many quality parameters.
- e. The domestic manufacturer is already having advantage to the tune of 19 to 20% protection by way of 3% basic customs duty, 4% special additional duty, 12% countervailing duty and applicable education cess, whereas India's competing countries like Pakistan has no import duty and even countries like Italy has only 4% duty on spandex yarn. China, the world's largest producer of spandex yarn, has no import duty.

f. The quantity produced by M/s. Indo Rama Synthetics caters only to the 20% of the users and for the rest; the elastomeric yarns have to necessarily depend on imports.

O. Associated Chemical corporation.

- a. The applicant has not provided their sales and production data in detail with specific Denier and quality and hence it will be in appropriate to consider the case on the data submitting by the applicant. There are many qualities and Denier in spandex and hence case has to be studied with proper data.
- b. There are many qualities and denier which is not produce by the local manufacturer and hence imposing any safeguard duty on overall product line is unjustified. The price of the product depends on the quality and denier of the product and hence this application is improper and unfit.
- c. There is only one manufacturer in India and imposing a Safeguard duty on the product will lead to monopoly by the manufacturer in this field. This will be also contradictory to Indian Act of MRTP.
- d. Indian textile manufacturer manufacture the spandex Knitted/woven/Narrow fabric for export and local premium brand, mostly they use the imported spandex because local spandex manufacturer's quality is still not up to international standard and their spandex is being used by cost conscious textile manufacturer for lower end market. Hence, the consumer of the said product has to buy the imported standard products by either importing it directly or buying the same through the importers.
- e. The production and sales data in annexure 5A submitted by the applicant indicates that the local sale price is much lower as compare to the sales price of international standard products. The export data, submitted is showing that the sales price realized by the local applicant is much lower than the international prices.
- f. Selling the goods at much lower price may be due to getting a favour in imposing safeguard duty. The applicant could not sale the product as per the international prices due to inferior quality.
- g. Local manufacturer after exporting about 40-45% from its overall production per month, left with about 200 MT/month to cater the Indian spandex user and at the moment the Indian market size for spandex consumption is about 1100 to 1200 MT /month, hence Indian user has no option left except importing of spandex.
- h. There will be unemployment generated which will be at least 20 times higher than the employment given by the applicant. Apart from unemployment, there will be a loss of export revenue due to non competitive prices of the products manufactured in India by using higher rates of spandex due to safe guard duty.
- i. The current import prices offered by their principal are much higher than that mentioned by the applicant
- j. The price offered by the local manufacturer is very much lower than the price of the imported product sold. The lower price is may be due to quality issue or due to planning for making the application for the safe guard duty
- k. Local manufacturer's claim about imported pricing is somehow partial and half revealed as spandex yarn prices varies as per denier. Finer the denier higher the pricing, local manufacturer has not given the clear picture of imported spandex as per denier.
- 1. The applicant is charging only 1% CST (sales tax) in comparison they are charging 5% VAT. There is concessional rate of sales tax offered to the applicant. The applicant claims that importing spandex is cheaper but in actual it is costlier than local spandex manufacturer.
- m. The applicant does not have specialty product of spandex as overseas spandex manufacturer have it example: black spandex/low heat set spandex/chlorine resistance spandex/spandex for diaper application/spandex applicable for warp knitting etc.

- n. The loss shown by the applicant should not be considered as the same is due to low production capacity and higher cost of production. All the international manufacturers are selling their product with comfortable market prices and are not showing the loss as claimed by the local manufacturer. This low price selling and high cost of production has resulted into loss.
- o. If safeguard duty is imposed then the textile manufacturer who are manufacturing the quality spandex fabric will be in trouble due to unnecessary cost increase which will further affect the Indian textile export due to cost increase. By that cost increase, Indian exporter cannot compete with Bangladesh, Pakistan, Vietnam & Chinese competitors etc.

P. PKPN Spinning Mills (P) Ltd, Chiripal Industries Limited & Gimatex Industries pvt. Ltd

- a. Indorama spandex manufacturer quality is not up to mark to meet the international standard level
- b. Indoarma's production capacity is not enough to cater entire Indian market.
- c. Indorama is selling it spandex at cheaper price than imported spandex due to its inferior quality spandex.
- d. Spandex contain in any textile or apparel is about 2-8% and hence manufacture has to use the quality assured spandex because in any textile stretch fabric the major cost involved is of other textile fiber like cotton/polyester etc, spandex cost is not major in textile fabric or apparel. Hence quality of the spandex is most important.
- e. Indorama not manufacturing black spandex/low heat set spandex/chlorine resistance spandex.
- f. Indorama's claim about imported spandex pricing is not true, the imported spandex is costlier as importer has to pay the duty about 19-20% on CIF price.
- g. India has good foreign revenue generation because of its exporting of good quality textile stretch yarn or fabric and import of quality spandex is important for manufacturer to produce the international standard stretch textile fabric.
- h. In case if safeguard duty is imposed then the textile manufacturer who are manufacturing the quality spandex fabric will be in trouble due to unnecessary cost increase which will further affect the Indian textile export due to cost increase. By that cost increase, Indian exporter cannot compete with Bangladesh, Pakistan& Chinese competitors.

Q. Ginza Industries Ltd.

- a. The spandex manufacturer's quality is still not up to international standard and final fabric produced using this local spandex is rejected by Buyer.
- b. Local manufacturer has spandex manufacturing capacity of about 500 MT per month, but in actual, they are manufacturing only 350/400 MT/month. Around 40% of this qty is being exported by them as downgrade material because of poor quality. Now left with about 200 MT to cater the Indian spandex requirement of around 800 MT. So Indian user has no option left except importing of spandex.
- c. Local spandex manufacturer claims that importing spandex is cheaper but in actual it is costlier than local spandex manufacturer and they, as a user are paying high cost for imported spandex due to quality of imported spandex which is of international standard and assure them to manufacture the quality textile final product.

R. Sachmam Fabrics Pvt. Ltd

- a. The quality of the product being manufactured and supplied by the said Indorama is not up to the mark.
- b. They themselves are not able to make regular and timely supply of the products.

- c. The total market size of the said material is about 1200 MT per month whereas the actual production of the Indorama is not even able to service the 1/4th market demand.
- d. There is only one manufacturer in India and imposing a safeguard duty on the product will lead to monopoly by the manufacturer in this field.
- e. The costs of imported goods are higher than the price being charged by the said Indorama.
- f. India is having only one spandex manufacturer whose capacity is small and is not able to cater Indian spandex demand which is about 1100 ton per month.

S. AGT Mills and Gima Manufacturing Pvt. Ltd

- a. Indorama spandex manufacture quality is not up to mark.
- b. Indorama's production capacity is not enough to cater entire Indian marker.
- c. Indorama is selling it spandex at cheaper price than imported spandex due to its inferior quality.
- d. Indorama spandex manufacturer has the small capacity of spandex production which could be one of the reasons for its break even cost to make the profit.
- e. Indorama's claim about imported spandex pricing is not true, the imported spandex is costlier as well importer has to pay the duty about 19-20% on price.

T. Zeon International

- a. Creating Monopoly: If safeguard duty is levied, it will create a monopoly like situation where textile manufacturers will be left with no choice but to buy spandex yarn from Indorama who is the only manufacturer of spandex yarn in India.
- b. **Not enough capacity:** As indicated in the notice the present market demand of spandex yarn in India is about 3500 tons per quarter. The installed capacity of Indorama is only 1250 tons per quarter, which cater only 1/3 of the market demand.
- c. **Indorama's Business is flourishing.** In less than two years of setting up their business they have been able to achieve an efficiency of over 90-99 % in capacity utilisation and have been able to sell 98% of its production in the last three quarters of the year 2013-14. This proves that their business has been thriving, oral flourishing unthreatened by imports.
- d. **No substantial increase in Imports to indicate threat;** Para six of notice of initiation shows that imports have decreased from 2488 MT in Q1 of 2012-13 to 2111 MT in Q4 of 2012-13 and the only in Q3 of 2013-14 there has been a slight increase to 1682 MT which is increase from 229% to 238% of imports in respect to production. In absolute terms it is only an increase of 3.9%. An increase of 4 % in one single quarter is certainly not substantial. Moreover it could have been due to seasonal factors, fashion trends etc. In the same sense if Q3 of 2012-13 is to he compared with Q3 of 2013-14 the percentage of imports (with respect to production) has decline from 582% to 238% which clearly indicates that imports have decreased significantly.
- e. Lower Quality standards: Spandex has various applications in the Textile industry: the main applications are in Circular knitting, Core spinning, air covering and Narrow fabrics. Out of this only air covering is the only application that does not require very high quality standards and only price competitive spandex is sought by these customers. The performance of Indorama in these segments are as under:-.

Market Segment	% of total spandex demand	% of Indorama's Share in segment	Indorama's Acceptability
Core spinning	35	15	poor
Circular knitting	30	15	Poor
air covering	20	60	Good
Narrow fabrics	15	10	Poor

- f. Losses due to cheaper pricing in Domestic and export markets: The loss for indorama in the first 3 quarters of 2012-13 is 3.65 crs, where as in the same period of 2013-14 is only 2.65 crs. Also in the 2013-14 periods, the imports have also marginally increased as claimed by Indorama. So it is very clear that their loss have been decreased by 27% even though the imports have increased in the above period.
- g. **Increase in export resulting in lower domestic market share**: The principal reason for the drop is a substantial increase on Export volume from 106 MT in Q4 (2012-13) to 532MT in Q3 (2013-14). It is clear that slight drop in domestic market share is only because of increase in Exports by Indorama and not due to increase of imported Spandex yarn.

U. Aarvee Denims and Exports Ltd.

- a. The quality of spandex filament being made by the Indo-Rama has till now not as per international standards.
- b. The price of the imported spandex yarn after the current import duty comes at 510/kg whereas the price of the Indian spandex being produced is around 500/kg., which means the price of the Indian spandex is less than the imported because of their poor quality.
- c. Further the supply from the Indian manufacturer is very much less as compared to the total Indian demand.

V. All India Spandex Yarn Importers Association

- a. Indorama's product quality is not supporting it to gain market share.
- b. Indorama at full capacity, provided it does not export material, can only supply 30% of the market requirement.

W. M/S. International Business Trade, Tirupur & M/S. National Synthetics

- a. The data submitted in no way supports the case of M/s. Indorama Industries Ltd. as there has been an abnormal increase in the imports of Bare Elastomeric Filament Yarn.
- b. M/s. Indorama Industries Ltd. established in March 2012 and since from the day it has started production, it has not only been able to achieve 99.8% of its capacity utilization but also able to sell 98% of its production during the year 2013-14.
- c. There has been a constant increase, both in production as well as sales.
- d. The sales figures including exports have shot up to 3453 MT which amounts to 98% of the total production during the year.2013-14 (upto December 2013)
- e. The imports have decreased from 2488 MT in Q-1 of 2012-13 to 2111 MT in Q-4 of 2012-13 and the only ground on which the injury is said to have been caused is slight increase in imports in the Q-3 of 2013-14 wherein it increased from 229% to 238% which amounts to 3.9% in absolute terms. An increase of 3.9% in just one quarter cannot be considered as a sudden and sharp increase in imports especially when there is an overall decline in the imports during the year as compared to previous corresponding year.
- f. For any industry, the demand and supply cannot be measured on a quarter to quarter basis as there may be seasonal variations on account of various factors and only an in-depth study can bring out such factors.
- g. The quality of yarn required by the domestic manufacturers was not being manufactured by M/s. Indorama Industries Ltd., and therefore, there might have been some increase in the quantum of imports.
- h. Factors like production, capacity utilization, market share in domestic demand, change in level of sales, profit/loss, productivity and employment enumerated in para 7 of notice do not support M/s. Indorama Industries Ltd's claim of any injury being either caused or there being any threat of injury.

- i. The nominal decline of 2.1% in domestic share in any particular quarter can never be a cause of concern and can be said to have caused an injury to the domestic market.
- j. The decline in the domestic market is not on account of less sales but on account of exports, as M/s. Indorama Industries Ltd. found exports to be more profitable.
- k. Spandex finds its use in production of stretch fabric. The main markets segments in India are core spinning, circular knitting, air covering, narrow fabric, diapers, etc. Of these segments, M/s. Indorama Industries Ltd's product has found acceptance only in the price sensitive air covering segment.
- 1. Even if it is assumed that there is increase in imports, the losses have come down instead of going up. Thus, the loss is not on account of increase in imports but may be on account of commercial reasons like long gestation period where the cost of production cannot be recovered in the very first year of production. It also depends on management control, efficiency, technology employed and various other factors.
- m. As regards productivity and employment, the production per employee has increased from 2.6% in the year 2012-13 to 4.7% in the year 2013-14. Thus, no injury can be said to have been caused to the domestic industry on the basis of productivity and employment. As regards, inventory, the same has also come down from 94 days of production in 2012-13 to 49 days in 2013-14 which is a very significant improvement.
- n. The import price has gone up substantially much in contradiction to M/s. Indorama Industries Ltd's claim of low import price.
- o. There has been no price undercutting or cause for price depression on account of imports and on the contrary the gap had been widening. Yet there was a drop in domestic sales in 2013-14-Q2 which clearly demonstrates that there is no causal link between imports and performance of domestic industry.
- p. Even with full capacity utilization, M/s. Indorama Industries Ltd. at best can meet only one third of market requirement. Hence safeguard duty will not be in public interest.
- q. The quality of spandex filament being made by the Indo-Rama is not as per users requirements.
- r. The applicant has not proposed an adjustment plan, but only an expansion plan.
- s. There is only one manufacturer in India and imposing a safe guard duty on the product will lead to monopoly by the manufacturer in this field.

X. Narrow Elastic Manufacturers' Association

- a. The product quality in the instant case is yet to settle. In fact, it is sub-standard.
- **b.** Imports took place because of the gap between the demand and domestic availability.

Y. Bishnu Texport Pvt. Ltd.

- a. No customer is satisfied with quality of INDORAMA Spandex yarn.
- b. Domestic product is cheaper than imported spandex

Z. Zenith Fibress & Jindal Worldwide Ltd.

a. Local manufacturer has spandex manufacturing capacity about 500 MT per month and effectively they are manufacturing about 350~400 MT/month and out of it they are exporting about 40–45% at low pricing due to its quality level.

- b. Local manufacturer after exporting about 40~45% from its overall production per month, left with about 200 MT/month to cater the Indian spandex user and at the moment the Indian market size for spandex consumption is about 1000 MT/month, hence Indian user has no option left except importing of spandex.
- c. Spandex basically is used with other companion textile fiber like cotton/polyester/nylon etc to make the textile fabric or apparel and in finished fabric stage the spandex content is about 2–8% mostly and remaining about 90–98% is other companion textile fiber, hence spandex quality decides the future of textile fabric and apparel. If anything goes wrong with spandex quality then user or textile manufacturer can have the big financial loss due to major cost of other companion textile fiber.
- d. Local spandex manufacturer claims that importing spandex is cheaper but in actual it is costlier than local spandex.
- e. If safeguard duty is imposed then M/s. Indorama Industries Ltd will become the Monopoly supplier and will charge abnormal prices and that will cause price increase in fabric which will directly affect the cost of living of common men.

AA. Kiran Texpro Pvt. Ltd.

- a. Local manufacturer's Quality is not up to the standard and have many problems like unwinding, Sticking, Shrinkage, Stretch etc.
- b. Spandex used in Elastic tape is 13% to 15% and Nylon is appx. 85%. Nylon yarn is also costly yarn, so by using poor quality spandex yarn , three types of losses occurred (1) production loss,(2) wastage and (3)business loss.
- c. The capacity is not enough to fulfill Domestic requirement and there is only one manufacturer in India and imposing a safeguard duty on the product will lead to monopoly by the manufacturer in this field. This will also contradictory to Indian Act of MRTP.
- BB.M/S. TPM Consultants filed submissions on behalf of interested parties (1)Association of Synthetic Fibre Industry, (2)Aarvee Denims and Exports Ltd., (3)Bhaskar Industries Pvt. Ltd., (4)Jindal Woriwide Ltd., (5)Mafatlal Industries Ltd.and(6)WelspunSyntex Ltd., (7)Denim Manufacturer Association, (8) Birla Century, (9)Oswal Woollan Mills Ltd. (10)Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd.
 - a. As per the trade Notice issued by the Director General of Safeguards the information is required for a minimum of three years and any longer period may be considered.
 - b. The petition should not be entertained as the petitioner has suppressed vital facts from the Director General (Safeguards). The petitioner had filed a petition seeking imposition of anti dumping duty. The Designated Authority however rejected the petition for the reason that the petitioner had claimed that 'dumped imports' of the product under consideration were retarding establishment of domestic industry in India.
 - c. The petitioner does not produce the product under consideration of above 80 denier therefore, product under consideration of denier above 80mm should be excluded from any safeguard duty.
 - d. The local manufacturer doesn't have beaming facility. Since the domestic industry does not produce and supply yams on beams, yam on beams should be excluded from the scope of the product under consideration, present investigations and proposed measures.
 - e. Imports have not shown such sudden, significant, sharp and recent increase as to constitute increased imports within the meaning of safeguards law. Imports increased in Q2 of 2012-13 from Q1 of 2012-13 and thereafter declined marginally up to Q4 of 2012-13.
 - f. Quarterly analysis of imports in relation to production of the domestic industry shows that imports in relation to production increased in Q2 of 2012-13 as compared to Q1, the same has however, declined in the recent period.

- g. 'Unforeseen development' is a necessary factor for imposing safeguard measures and the petitioner fails to make its claims on any unforeseen development that may have caused any increase in imports.
- h. As per petitioner, total demand of the product under consideration in India was 3352 MT per quarter (based on Q3 of 2013-14), whereas the installed capacity of M/s. indorama, the only producer in the Country, is only 1250 MT/Quarter i.e. 37% of the total requirement of the country. Hence, to meet the balance requirement of the country, there is no other alternative but to Import approx. 63% of the total domestic demand.
- i. Article 4 1(b) of the Safeguard Agreement stipulates that serious injury should mean a significant overall impairment in the position of a domestic industry. However, factors that indicate the situation of the domestic industry do not prove this in the petition. Performance of the company has also improved in respect of various parameters in the recent period.
- j. The petitioner has contended that the import prices are suppressing the domestic selling price and not allowing the petitioner to recover costs resulting in severe losses. The statement cannot however be factually correct. This gets established by the quarterly profits claimed by the domestic industry. Further, the pattern of quarterly profitability also makes it evident that the losses suffered by the domestic Industry have significantly reduced in 2013-14 as compared to preceding year.
- k. It is also pointed out that the Indian Producer is selling the product under consideration at a price lower than import price because the quality of the product under consideration produced by Indian producer has not yet been fully established.
- Under the Rules, injury suffered by the domestic industry, if any, on account of other factors cannot be attributed to increased imports. In the instant case, the petitioner is suffering injury on account of other factors, such as start up operations and cost incurred by the petitioner.
- m. Petitioner being a new and sole producer of the product, imposition of duties would lead to a situation of monopoly by the domestic producer.

CC. TEXPROCIL submitted as under:-

- a. The domestic demand for Bare Elastomeric Filament Yarn is around 3400 MT p.a whereas the production capacity of the applicant is only around 1130 MT p.a. Thus there is a huge gap between the domestic demand and domestic supply of Bare Elastomeric Yarn and therefore there is no justification in imposing any Safeguard measure on this product.
- b. The applicant unit manufacturing Spandex Yarn in Himachal Pradesh already enjoys exemption from Central Excise duty. If Safeguard duties are imposed, it will make imports costlier resulting into an increase in the domestic price as there is monopolistic production of Spandex Yarn in India. This is, therefore, not in the interest of the domestic industry and apparel exporters.
- c. There is only one manufacturing plant in India which enjoys monopolistic situation. Imposition of Safeguard duties will provide further protection to this unit thereby creating further monopolistic situation.

DD. <u>Unicharm India Pvt. Ltd.</u>

- a. Unicharm is engaged in the manufacture of baby diapers and sanitary napkins for which the imported raw material used is "String" with Elastic properties made from Polyurethane. These strings are finished products of specific size and grade and are different from the product under consideration in the present investigation, which is the raw form used by the garment industry, though these Strings fall under the same tariff heading as the product under consideration.
- b. In the initiation notification dated 28.02.2014, the period of investigation has been identified and selected is 2012-13 to 2013-14. For any manufacturing unit initial phase of two to three years are crucial and it takes time to achieve the optimum level of production and profitability. These issues could be:

- i Labor adjustment and training
- ii settlement of raw material supply chain
- iii completion of supply and distribution chain of final product
- iv initial quality of raw material and finished product and quality
- v assurance etc.
- c. From third quarter of 2012-13 onwards, the production and sales of the Applicant picked up dramatically and it almost touched the optimum level of production i.e. 1250 MT. The Applicant being new in the production of product under consideration, present investigation and proceedings for the period 2012-13 & 2013-14 is pre-mature and deserved to be dropped on this ground only.
- d. If the domestic industry (Applicant) achieves the optimum production level or doubles its production to 2500 MT, it cannot meet the total demand of product under consideration in India.
- e. It can be seen that the domestic production of the product under consideration has increased in almost same proportion with the total imports and the total demand of the said product in India. Therefore, the increase in imports has no adverse effect on the domestic production of the said product.
- f. Interestingly, the domestic industry and the imports put together are also not meeting the 100% demand of the product under consideration in India. Therefore, any safeguard measures against the import of product under consideration would adversely affect the garment industry in the country, which plays a crucial role in adding to the export proceeds and generation of foreign exchange for the country.
- g. During 2012-13 and 2013-14 (Q1 toQ3), the average capacity utilization had increased from 47.32% to 94%, which is exactly the double within a span of one year. Even the market share of the domestic industry has increased from 15% to 26% in last one year.
- **h.** The Applicant has pointed various other reasons for losses such as increase in the landed price of the raw material, depreciation of Rupee, inventory etc., which cannot be attributed to the imports of like product into India.

EE. M/S. Nandan Denim Ltd., M/S. Chiripal Industries Ltd and M/S. Deepak Impex (P.) Ltd.

- a. The term "Domestic Industry" has also be defined in the Section 8B(6)(b) of The Customs Tariff Act, 1975 which provides that "domestic industry" means the producers (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or (ii)whose collective output of the, like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India. Thus, the provision is referring to the "domestic. industry" as the "producers' is not a singular producer but is plural in nature and it refers to more than one such producer. However, the present applicant namely M/S. Indorarna Industries Ltd., have claimed that they are the only producer in India who are producing Bare Elastomeric filament Yam in India and hence they account for 100% of total domestic production and therefore they being the single entity have no such standing to file the subject present petition.
- b. Applicant is not in a position to meet the requirements of Indian market, even if they are able to utilize 100 % production capacity. Therefore, this investigation is not warranted in the interests of justice to the other importers.
- c. Applicant has not prove their case that they have any danger of such "threat of serious injury" as explained in 8B(6)(d) of the Customs Tariff Act, 1975.
- d. Market share of Applicant has increased and during same period market share of import has decreased. There is no justification for imposition of safeguard measures as proposed by the Applicant.

e. The sales of the Applicant increased up to Q 1 of 2013-14, it declined from 931 MT in Q1 of 2013-14 to 670 MT in Q3 of 2013-14. These figures does not show/prove that the applicant has suffered serious losses in sales in recent past or it has caused any serious injury or threat to any such serious injury.

FF. J.M Commodities: M/S. J.M Commodities vide their letter dated 16/6/2014 submitted as under:

- a. Production of INDORAMA (INVIYA) is not sufficient to cater the needs of theIndian market.
- b. If the Safeguard applied, there will be monopoly sales of its spandex yarn in future and they will charge higher prices and sell as a premium product to the customers.
- c. QUALITY of INVIYA is not up-to the mark or not equivalent with the imported spandex.

III. PUBLIC HEARING

9. A public hearing was held on 19th June, 2014, notice for which was sent on 6th May, 2014 to the all Interested Parties. Following interested parties presented their views during the public hearing:-

1	Indorama Industries Ltd. (Domestic Industry)
2	Embassy of Japan
3	Embassy of Vietnam
4	Aarvee Denims and Exports Ltd.
5	Association of Synthetic Fibre Industry
6	Bhaskar Industries Pvt. Ltd.
7	Jindal Woriwide Ltd.
8	Mafatlal Industries Ltd.
9	Welspun Syntex Ltd.
10	Denim Manufacturer Association
11	Birla Century
12	Oswal Woollan Mills Ltd.
13	Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd.
14	Chiripal Industries Ltd.
15	Nandan Denim Ltd.
16	All India Spandex Yarn Importers Association
17	Asahi Kasei Fibers Corporation & Thai Asahi Kasei Spandex Co.
18	Association of Synthetic Fibre Industry(ASFI)
19	Arvind Ltd.
20	Vardhman Textiles Ltd.
21	Confederation of Indian Textile Industry

22	Associated Chemical Corporation
23	Enfield Apparels Ltd.
24	Hyosung Corporation, Korea
25	Hyosung Spandex (jiaxing) Co., Ltd., China,
26	Hyosung Vietnam Co. Ltd., Vietnam,
27	TK Chemical Corp., Korea,
28	Taekwang China PR
29	Taekwang Korea
30	INVISTA Sales & Service India Pvt. Ltd.
31	Invista Singapore Fibers Pvt. Ltd.
32	TEXPROCIL
33	The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council
34	Unicharm India Pvt. Ltd.
35	Albion
36	Bishnu Texport Pvt. Ltd.
37	Kiran Texpro Pvt. Ltd.
38	President Clothing Company
39	Zenith Fibress
40	Zeon International
41	Narrow Elastic Manufacturers Association

10. All Interested Parties who participate in the public hearing are required to file a written submission of the views presented orally in terms of Sub Rule (6) of Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997. Thereafter, copy of written submissions filed by an Interested Party is made available to all other Interested Parties. Interested Parties are also given an opportunity to file rejoinders, if any, to the written submissions of other interested parties. Following interested parties submitted written submissions in terms of above said rules.

1	Indorama Industries Ltd. (Domestic Industry)
2	Embassy of Japan
3	Embassy of Vietnam
4	Aarvee Denims and Exports Ltd.
5	Association of Synthetic Fibre Industry
6	Bhaskar Industries Pvt. Ltd.
7	Jindal Woriwide Ltd.
8	Mafatlal Industries Ltd.

9	WelspunSyntex Ltd.
10	Denim Manufacturer Association
11	Birla Century
12	Oswal Woollan Mills Ltd.
13	Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd.
14	Chiripal Industries Ltd.
15	Nandan Denim Ltd.
16	Arvind Ltd.
17	Vardhman Textiles Ltd.
18	Confederation of Indian Textile Industry
19	Associated Chemical Corporation
20	Enfield Apparels Ltd.
21	Hyosung Corporation, Korea
22	Hyosung Spandex (jiaxing) Co.,Ltd., China,
23	Hyosung Vietnam Co. Ltd., Vietnam,
24	TK Chemical Corp., Korea,
25	Taekwang China PR
26	Taekwang Korea
27	INVISTA Sales & Service India Pvt. Ltd.
28	Invista Singapore Fibers Pte. Ltd.
29	Unicharm India Pvt. Ltd.
30	Zeon International
31	Narrow Elastic Manufacturers Association

11. The brief summary of the written submissions filed by various interested parties after public hearing are as under:

A. M/S. APJ-SLG Law Offices filed written submission on behalf of M/S. Indorama Industries Ltd. (Domestic Industry)

- a. All the responding associations including the following cannot be considered as interested parties in terms of Rule 2(d):
 - (i) Conferdation of Indain Textile Industry (CITI)
 - (ii) The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council (SRTEPC)
 - (iii) Association of Synthetic Fibre Industry (ASFI)
 - (iv) Tripur Exporters' Association (TEA)
 - (v) BBN Industries Association (Regd.)
 - (vi) The Southern India Mills Association
 - (vii) Narrow Elastic Manufacturers Association

- (viii) All India Spandex yarn Importers Association
- (ix) Sitaram Spinners Association
- (x) Denim Manufacturers Association
- b. The status of the responding associations as interested parties should only be confirmed after proper presentation of their case along with reasons by such parties.
- c. The associations do not qualify as interested parties in terms of Rule 2 (d) or Rule 6(5).
- d. Certain parties (As listed) should provide information about approaching DGAD for the same product, as claimed by them.
- e. The DG should verify the information submitted by the said parties. The DG should reject their submissions as they are misleading.
- f. The claim that domestic industries is still facing quality issues till March 2014 is misleading.
- g. Denim Manufacturers Association mislead the the DG by comparing the prices of China, Vietnam, Singapore etc which have no bearing on the prices to India.
- h. The present case is not an issue of forum shopping.
- i. The applicant is eligible to be Domestic Industry. (Section 8B(6)(b)(i), chapeau to 8B(6)(b), Section 13 of General Clauses Act)
- j. Sole producer of subject goods is legally and logically eligible domestic industry. (Rule 5(1))
- k. The domestic industry is entitled to file application before DG. The DG Safeguards has initiated with full knowledge that Domestic Industry had started its commercial operations from March 25, 2012. There is nothing to suggest that it is requirement that Domestic Industry is not entitled to file an application before the DG as it has been in existence for a period of less than three years. (Trade Notice SG/TN/1/97, dated 06.09.1997, Rule-5, Rule-4)
- 1. There is no general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. (Custom Tariff Act, Safeguard Rules). It is up to the discretion of the investigating authority of the importing Member. (Panel Findings in US-Line Pipe Case against Korea), (DG in the case of PX-13 Final Findings dated 06.06.2011, and Methyl Acetoacetate Final Findings dated 08.10.2011).
- m. The Age of Industry does not affect its eligibility to file an application.
- n. The DG in the case of PX-13 Final Findings dated 6.06.2011 and in the case of Methyl Acetoacetate Final Findings dated 8.10.2011based on examination of WTO jurisprudence i.e., US- Circular Welded Carbon Quality Line Pipe From Korea, concluded that it is up to the discretion of the DG (Safeguards) to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown" as Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation.
- o. The imports increased from 4006MT in the year 2011-2012 to 9066MT in 2013-14, which is an increase of 5060MT within a period of two years. This increase is 2.26 times or 126% over the base year.
- p. The average quarter-wise imports from 2010-11 is on the increasing trend for all the quarters of the period of investigation as compared to the preceding years' quarters.
- q. After the domestic industry came into production i.e., from March, 2012, the average monthly imports of Elastomeric Filament yarn increased by 224 MT per month and 388 MT per month as compared to the immediately preceding year and the base year respectively which is an increase of over 42% and by 99% respectively.
- r. The DG may like to appreciate that in the instant case, all the injury parameters will prima facie show improvement as the comparison is being made from zero level or from a stage when the Domestic Industry has just established. Any analysis with base year in a mechanical manner will provide distorted figures and lead to erroneous conclusions. The basic fact that needs to be appreciated is that despite achieving high capacity utilization, Domestic Industry continues to suffer losses.

- s. Domestic Industry only seeking protection for interim period of three years so that they can install full capacity as scheduled to be installed originally. This will help Domestic Industry to reduce its cost, so that they can realize margins that will be sufficient to recover cost and also enough to survive in the market.
- t. The capacity issue and restructuring plan needs to be analyzed simultaneously. This combined analysis is important because Domestic Industry has not been able to fully implement its capacity as per the original schedule due to circumstances not in control of the Domestic Industry. In this context, the Domestic Industry submits as under:
 - (i) The plant has been set up with annual capacity of 15000 MT to cater to the increased demand in India, to be installed in three phases of 5000 MT each
 - (ii) The plans of Domestic Industry has concrete plan which will lead to restructuring of the industry. As per the original project plan, the 2nd phase expansion of 5000MT was to start in ***** and to be complete by ****. However it got delayed with unforeseen circumstances and surge in imports etc.
 - (iii) The additional capacity of 5000 MT will be operational by ***** and next addition of 5000 MT will be operational by **** provided the industry is given the necessary support by way of safeguard duties for a short period of three years.
 - (iv) The reason as to why Domestic Industry has not been able to expand as per their initial expansion plans is excessive imports.
 - (v) The issue of limited capacity of the Domestic Industry will also be addressed appropriately once Domestic Industry installs its full capacity.
- u. The statement given by certain interested parties that the Domestic Industry is selling its products below the landed value of imports is not correct as if a proper analysis is made on a denier- to-denier and monthto-month basis.
- v. Following are the unforeseen circumstances which Domestic Industry could not foresee at the time of conceiving the project way back in 2008 or by the negotiators of Indo-ASEAN FTA.
 - (i) The Domestic Industry did not anticipate nor could it have predicted that the prices of the subject goods will reduce significantly despite the increase in raw material prices world-wide. Further, this price reduction of subject goods has also reduced the capability of Domestic Industry to negotiate better price with the customers.
 - (ii) The Domestic Industry could not have anticipated the drop in duties under the Indo-ASEAN FTA at the time of conceptualizing the project. It is not feasible for any industry to roll back its plans if unforeseen developments take place during the implementation stages.

w. Quality Issues:

- (i) The quality per se is not an issue in any safeguard or anti-dumping investigation. There were some teething problems in the initial period after commercial production but that was fully resolved by November 2012. However, it is equally important to note that almost the entire the quantity which was alleged to be deficient in quality was also bought by other consumers who could use it with appropriate adjustments in their machinery.
- (ii) The domestic industry is currently supplying to almost 850 customers including key members of Denim Manufacturers Association, Association of Synthetic Fibre Industry, etc. This fact clearly demolishes the argument of the Opposite Parties that they are currently not buying the material from Domestic Industry because of quality issues.
- (iii) It is a matter of record that between November 2012 and March 2014, the returns were 3% of the total sales, which is the industry norm. For the financial year 2013-2014, this percentage came down to a mere 1.9% which further dropped to just about 1% during the period January-March 2014.

- x. Domestic Industry is selling its production throughout India to customers ranging from big cooperate houses to small weavers. Currently Domestic Industry is serving more than 850 customers in India. The imposition of the proposed safeguard duty shall be in public interest for the reasons explained below.
 - (i) <u>Producers' Interest</u>: The imposition of safeguard duty on imports of subject goods would be in the interest of domestic industry of subject goods. The measure would prevent further injury and give time to install its capacities which could not be materialized on account of losses due to increased imports.
 - (ii) <u>Consumer's Interest</u>: It would be in the interest of domestic consumers of subject goods to have an Indian domestic industry capable of competing with foreign producers. This is possible when the domestic industry is able to recover from the injury suffered due to the sudden increased imports.
 - (iii) <u>Interest of the Public at Large</u>: It is in the interest of the public at large to have a strong, competitive Indian domestic industry. This will not be possible if injury to the domestic industry as a result of increased imports is allowed to be continued. Moreover, the impact of duties on the public at large is negligible. The same can be seen from the table below:

Details		Pair of Socks	Stretch Denim (Fabric)	Suiting Fabrics	Ladies Brassiere	T-Shirts	Jeans	Leggings
Approximate Wholesale Price of Branded Product		Rs.100 per pair	Rs 200 per linear mtr	Rs.250 per linear metre	Rs250 Per Pc	Rs. 800 per Pc.	Rs. 1000 per Pc	Rs. 500 per Pc.
Total Weight	Gms/ UOM	40	520	375	50	300	600	300
Cost of Spandex in the Product	Rs./Pc	1.05	6.93	5	2.21	7.91	7.99	6.62
Avg Retail Price	Lowest-Rs.	100	200	250	250	800	1,000	500
Spandex % cost of Total Price	% of Price	1.10%	3.50%	2.00%	0.90%	1.00%	0.80%	1.30%
Likely Delivered price on Safeguard Duty	@25.00%	658	555	555	550	658	555	550
Likely cost of	Rs./Pc	1.32	8.66	6.24	2.75	9.87	9.99	8.25
Spandex in Product	% of Price	1.30%	4.30%	2.50%	1.10%	1.20%	1.00%	1.70%
	Rs./Pc	0.26	1.73	1.25	0.55	1.97	2	1.64
Impact of Increase of Spandex Duty	% of Price	0.26%	0.87%	0.50%	0.22%	0.25%	0.20%	0.33%

B. Written Submission filed by Embassy of Japan

a. Product involved:

- The Japanese company, Unicharm India Pvt. Ltd., manufactures Baby Diapers and Sanitary Napkins by using the imported raw material with Elastic properties made from Polyurethane. This material falls under the same tariff heading as the product under this investigation, but the purpose of the product use is totally different, and limited to manufacturing of Baby Diapers and Sanitary Napkins, and this material of special use has a totally different purpose from the product under the present investigation.
- The domestic industry does not manufacture this material or similar products for Baby Diapers and Sanitary Napkins.

- The applicant started commercial production of Elastomeric Filament Yarn in March 2012, only
 two years ago. Any manufacturing unit takes time to achieve the optimum level of production and
 profitability, because of other issues than increased imports, which includes labor training,
 settlement of supply chain, improvement of quality, and so on.
- b. **Period of Investigation (POI):**The applicant faced some problems in achieving the optimum production and sales of their product in the initial phase (Q1 to Q3 of 2012-13); but this situation was dramatically improved, and it almost reached the optimum level of production from Q4 of 2012-13 onwards. Therefore, the present investigation for the two-year period 2012-13 & 2013-14 is pre-mature.
- c. **Increased imports:-**Comparing the figures of Q1 to Q3 of 2012-13 with figures of Q1 to Q3 of 2013-14, it can be clearly seen that the total demand increased by 25.6%, although total imports increased by only 6.1%. In the same way, the domestic sales almost tripled, and all domestic production has more than doubled. This implies that the increase in imports causes no serious injury to the domestic production of the said product.
- d. **Injury to domestic industry:** No causal link is visible between the increase in imports and the injury caused to the domestic industry. The applicant started the commercial production of Elastomeric Filament Yarn in March 2012, only two years ago, and it is natural that losses of the applicant are attributed to various other reasons, such as operational instability, which is typical for the early phase of any establishment/company, and external instability, such as the change of supply and demand of Elastomeric Filament Yarn, owing to excessive production capacity, especially in China.

C. Written Submission filed by Embassy of Vietnam

- a. Vietnam did not export the subject product under CN code 54041100 to India. Thus, Vietnam respectfully requests that the Directorate General of Safeguards exclude Vietnam from the safeguards measure regarding the product under CN code 54041100.
- b. The Notification of initiation does not show a significant increase of imports of the subject product during the POI.
- c. The analysis on the situation of the domestic industry does not show clear evidence of serious injury. Most of the indicators show big improvement from the beginning of 2012-2013 (Q1) to the beginning of 2013-2014 (Q1) and slight decline afterwards. With regard to this argument, following are the factors:-
 - Domestic production increased.
 - Capacity utilization increased
 - Market share of imports has decreased whereas the market share of DI increased.
 - Domestic sales increased
 - Productivity Increased
 - In terms of *inventory*, there is a decline in inventory as percentage to total production.
- d. **Causal link:** The Notification to the WTO and the Notice of initiation do not contain any explanation on the causal link between increased imports and the serious injury.
- e. **Unforeseen Developments**: the Notification is silent about any development that might have led to a surge in imports which was unforeseen and unexpected.
- **f. Restructuring Plan:** Government of Vietnam could not find such a restructuring plan in the available documents.
- **g. Public Interests:** As the petitioner is the only producer in the domestic market, there is a high likelihood that it would dominate the market and would create barriers for market entry, which is harmful to the competitive environment and healthy development of the industry of India. Besides, the imposition of the

safeguards measure (if any) would unnecessarily cut the source of regular supply of the subject product and would cause negative impacts on the public interests of India.

D. M/S. DGS Advocates filed written submissions on behalf of M/S. Hyosung Corporation, (Korea), T.K. Chemicals Corp. (TKC), Korea, Taekwang Industrial Co., Ltd., Korea, Hyosung Vietnam Co., Ltd., Vietnam, Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd., China, and Taekwang Synthetic Fiber (Changshu) Co., Ltd., China.

a. Initiation of the Investigation lacks factual basis.

- (i) The Hon'ble Authority cannot initiate an investigation pursuant to an application made under sub rule (1) without examining the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfying himself that there is sufficient evidence regarding increased imports; serious injury or threat of serious injury and a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury. A complete lack of evidence. leave alone "sufficient evidence" is palpable in the application submitted by the domestic industry and the question of its accuracy or adequacy does not arise.
- (ii) The domestic industry has further failed to satisfy the express requirements of the Trade Notice No SG/TN/1/97 dated 06.09.1997, which has been issued pursuant to Rule 5(2) of the Safeguard Rules. The Trade Notice requires the Applicant to furnish information for the most recent period of three years (or longer). There is no provision in the Trade Notice that allows furnishing of information for a period less than three years. In the instant case, the domestic industry having come into existence only in March 2012 fails to fulfill this requirement. In view of the same the application merits dismissal summarily.
- b. The Applicant has not fully cooperated with this Hon' ble Authority: Applicant has failed to file the Questionnaire for Domestic Producers in the prescribed format. Applicant also failed to furnish a viable Adjustment Plan.
- **c.** The Applicant started its commercial production only in March 2012, but claims that domestic industry has suffered from 2010. It does not make sense that serious injury to the Indian industry is caused by the import products that domestic producers, including the Applicant, cannot produce.
- d. The Applicant has failed to demonstrate existence of unforeseen developments resulting in increased imports:
 - (i) In Argentina Footwear 'EC), 2 the Appellate Body pronounced on the meaning of the phrase "as a result of unforeseen developments" and held that the developments, which led to a product being imported in such increased quantities are under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'.
 - (ii) The Applicant claims that its plant was located in Himachal Pradesh, with the expectation of availing the backward area benefit, which it is unable to avail and on the other hand it has had to bear additional burden on account of many factors such as transportation of raw materials and finished products and high cost of logistics in the terrain area. It further claims that the import duty on Elastomeric (Spandex) Filament Yarn falling under 5402.44.00 and 5404.11.00, currently being 5% is one of the lowest globally.
 - (iii) The primary reasons for the Applicant establishing its plant in Himachal Pradesh are (1)Stable power supply; and (2) Tax benefits (tax exemption for 5 years, then after 30% reduction in income tax for 3 years). Therefore, the Applicant was fully aware that the place where it established the plant was a depressed area, and notwithstanding the same it established the plant in order to take advantage of tax benefits. In view of this conscious business decision, albeit impractical, the Applicant cannot be heard to argue that the above circumstances are "unforeseen developments", as envisaged in law.

- (iv) The Applicant has not submitted any justified reason for claiming unforeseen developments, especially since there is a decline in imports during the period of investigation.
- e. There has been no surge in imports of the subject goods necessitating imposition of safeguard duty
 - (i) As per Rule2 of the Safeguard Rules the "Increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production.
 - (ii) According to WTO Appellate Body's ruling on *Argentina-Safeguard Measures on Imports of Footwear*, in Article 2.1 and 4.2 of the Agreement on Safeguards, the Appellate Body clarified that "the increased imports must have been recent enough, sudden enough, sharp enough and significant enough, both quantitatively and qualitatively, to cause or threaten to cause serious injury."
 - (iii) The Applicant has merely made a bald statement that the imports into India have increased suddenly, sharply and significantly without adducing any evidence in support of the same. Applicant has based its analysis on the import data available till Sept 2013. In case of import data for the whole year 2013-14, there is a decline in imports as compared to 2012-13 and hence the Applicant's claim of increase in imports is totally wrong and baseless.
 - (iv) There is decline in imports over the period of investigation despite increase in demand as well as sales of the Applicant, which cannot possibly be termed to have caused serious injury to the Applicant. It can also be observed from the table below that there is no increase in the import of the subject goods in recent times.

Year	Domestic Sales	Imports	Total Domestic consumption	Share of Domestic Sales in total consumption
2010-11	0	4683	4683	0%
2011-12	3	7186	7189	0.10%
2012-13	1679	9341	11020	15.20%
2013-14	3646	9294	12940	28.18%
Comparison between 2012-13 and 2013-14		0.50%	17.43%	

- f. Even if there is an increase in imports, it cannot cause a 'serious injury' to the Applicant necessitating imposition of safeguard duty
 - (i) The alleged injury suffered by the Applicant neither meets the requirements under WTO Rules nor justifies the application of safeguard measures as the increase in import, if any, has not caused any serious injury to the Applicant, which is the sole constituent of the Indian domestic industry, necessitating imposition of safeguard duty.
 - (ii) Except from the period of 2010-11, 2011-12, a close examination of the data reveals the following:
 - Capacity has been maintained at a constant level 5000MT.
 - Production has increased during the period of investigation.
 - Capacity utilization was doubled between 2012-13 and 2013-14(up to Sept.).
 - Domestic sales have sharply increased from 1,679 in 2012-13 to 3,646 in 2013-14(Annualized) an increase of 117%.

- As can be seen from the import data published by GOI, quantity has decreased from 9,341 in 2012-13 to 9,294 in 2013-14, so the growth rate of the import is negative. On the contrary, total domestic consumption has increased from 11,020 in 2012-13 to 12940 in 2013-14, showing a growth rate of the total domestic consumption by 28.18%. Indian market is growing rapidly, yet the growth rate of import is negative.
- Therefore, there is no increase and serious injury prejudicially impacting the domestic industry.
- the Applicant's share has increased from 15% in 2012-13 to 25% in 2013-14, while the import market share has decreased from 85% in 2012-13 to 75% in 2013-14.
- Average employment has increased during the period of investigation. Generally Productivity per employee has increased too.
- Contrary to the Applicant's averments, the inventories balance to the production has decreased dramatically since 2012-13(Q4). Therefore, increase of inventory is result from increase of India domestic production.
- Profitability shows that the Applicant has suffered injurious financial condition. But more recently, the indicator of Profit/loss and related financial situation of the Applicant is getting better.
- The landed value is about 21% higher than the sales realization of the Applicant during the period of investigation. This shows that there is no price depression/suppression and price undercutting by imports.
- (iii) Above facts clearly demonstrate that there is no significant, overall impairment in the position of the Applicant and the alleged injury suffered by the Applicant neither meets the requirements under WTO Rules nor justify the application of safeguard measures.
- g. There is no increase in imports hence there cannot be a 'threat of serious injury' to the Applicant due to increased imports necessitating imposition of safeguard duty.
- h. There has been no price undercutting or cause for price depression on account of imports and on the contrary the gap had been widening. Further, and more importantly, the import price has had little effect on the Applicant's performance. Thus, there is no causal link between imports and the Applicant's performance.

E. M/S. J. Sagar Associates filed submissions on behalf of INVISTA Singapore Fibres Pte. Ltd & INVISTA Sales & Service India (P) Ltd.

- a. The domestic industry which has maximum production, maximum sales, maximum capacity utilization and has been undertaking capacity expansion during the entire PUC as cannot be said to be in position of significant overall impairment in the present case.
- b. There is no unforeseen development within the meaning of Article XIX of GATT.
- c. During the period of investigation, there has been no export of the Subject goods in an increased quantity by INVISTA India.
- d. Domestic industry has admittedly achieved 94% capacity utilization since March 2012. However, it is not able to meet the requirements of the indigenous market. Thus, the gap of demand and supply in Indian market is fed by imports.
- e. There is no "serious injury" caused to the domestic industry.
- f. Indorama is the only producer of PUC in India and holding 30% of the domestic market share.
- g. The domestic industry has constantly increased its production and quantity of exports. Thus there is no injury whatsoever for claiming levy of safeguards duty on import of PUC.

- h. Out of the various economic parameters mentioned by the Domestic Industry in the Application, production, sales, market share, employment, capacity utilization has been on a constant rise, imports have been declining, thus showing a positive trend. The losses also show a positive trend.
- The domestic industry has incurred losses not because of increased imports or price undercutting by exporters of PUC but on account of huge investment incurred by Indorama and loan taken from its overseas sister company.
- j. The manufacture of fibre such as PUC is a capital intensive project. The production of such projects needs time to stabilize. A chemical formulation industry such as Indorama takes time to give higher or desired level of yield. Therefore, it is not correct on part of the Domestic Industry to claim injury within 18 months of starting production.
- k. Domestic industry in the Application has not provided comparative data which can be aligned with the financials of Indorama available on public domain. Therefore, Indorama has not suffered "serious injury".
- Safeguards duty is not imposable when other factors causing alleged injury. Injury might be attributed to
 the location of Indorama in terrain area where transportation of raw materials and finished products results
 in high costs of logistics. Other reasons maybe that the domestic industry is at nascent stage, reasons
 attributable to External Commercial Borrowings (ECB), low quality PUC produced by the Domestic
 Industry.
- m. The PUC manufactured by the INVISTA are of much more higher quality manufactured with different patented technologies which Indorama cannot manufacture. INVISTA and the Domestic Industry cater to a different market segment, import of the PUC manufactured by INVISTA is not causing any injury whatsoever and hence investigations initiated vide the Initiation Notification are liable to be dropped on this ground alone.
- F. M/S. TPM Consultants filed submissions on behalf of (1)Association of Synthetic Fibre Industry,(2)Aarvee Denims and Exports Ltd.,(3)Bhaskar Industries Pvt. Ltd., (4),Jindal Woriwide Ltd., (5)Mafatlal Industries Ltd.and(6)WelspunSyntex Ltd., (7)Denim Manufacturer Association ,(8) Birla Century, (9)Oswal Woollan Mills Ltd. (10)Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd (11) Chiripal Industries Limited (12)Nandan Denim
 - a. The petitioner is the sole producer. The petitioner has not established how imports are causing serious injury.
 - b. The Indian consumers are paying very high prices for the product under consideration when prices prevailing in China are compared with prices from Singapore and Vietnam.
 - c. Injury to new industry cannot be examined under Safeguard Law.
 - d. Petitioner has suppressed vital facts from the DG Safeguards. It has filed petition under anti dumping law.
 - e. The existence of industry is too short to justify consideration of safeguard duty. (Trade Notice; Many previous investigations of DG Safeguards)
 - f. The petitioner is the sole producer in India but can meet only 39% of the total requirement of the country. Thus there is a demand supply gap. Even after enhancement of capacities, the petitioner would not be able to meet the demand of the product in the country. The domestic industry is not entitled to protection unless the domestic industry can meet the demand for the product in the country. (6 PPD Rubber Chemicals Case DG Safeguards)
 - g. Petitioner's products are of poor quality and do not conform to requirements.
 - h. All those product types which are being imported and which are not being produced by the domestic industry should be excluded from the scope of the product under consideration.
 - i. Imports have not shown such sudden, significant, sharp and recent increase so as to constitute increased imports within the meaning of safeguards law.

- j. Imports in relation to production and consumption have declined as shown in the quarterly analysis.
 Imports have declined on an annual basis also,
- k. Unforeseen development is not established. Increased import at low prices is not an unforeseen development. (Argentina Preserved Peaches). Backward area benefits cannot fall in the category of unforeseen development in the present case. (Argentina- Footwear case). Indo Asean Treaty has been entered into much prior to establishment of the domestic industry, and thus is not an unforeseen development.
- 1. The performance of the domestic industry has shown improvement in a number of parameters. Thus, evidently, it has not suffered serious injury as a result of increased imports. Annual analysis and quarterly analysis of the production of the domestic industry shows significant increase. The sales have also shown similar behavior. The domestic industry has been able to achieve 95% capacity utilization in merely second year of its existence. The domestic industry has been able to capture a significant 26.8% of the market share with its limited capacity. There is no injury caused to the petitioner, in fact the performance of the petitioner has improved significantly.
- m. Any injury suffered by the domestic industry cannot be attributed to increased imports. It is due to inability of the petitioner to get a price comparable to the imports, petitioner not being able to sell to all Major Consumers of the product in the country, petitioner not able to establish its product so far and is still at a stage of trials with various companies, or start up operations and cost incurred by the petitioner reason for losses.
- n. Producers' interest alone cannot constitute public interest.
- o. Safeguard duty will have significant adverse effect on the consumers.
- p. The obligation to give a concrete adjustment plan by the domestic industry has not been fulfilled.
- q. With regard to the argument of two periods to be considered for impact analysis and injury analysis, it is submitted that it is denied, the DG cannot consider two different periods for increased imports and serious injury to the domestic industry. (WTO Panel in the matter of United States- Definitive Safeguard Measures on Imports of Circular Welded Carbon Quality Line Pipe from Korea)
- r. With regard to the argument of imports surging in 2012-13, it is submitted that in the present case import surge is to be seen between 2012-13 and 2013-14.
- s. With regard to the argument raised about doing injury analysis differently in case of a new industry, it is submitted that Safeguard rules do not envisage the injury suffered by new industry, thus it is out of jurisdiction of the Director General (Safeguards).
- t. The claim with regard to curtailed expansion due to significant injury is strongly refuted, as the petitioner has already reached 100% capacity utilization, and therefore there is no question of curtailment.

G. M/S. Lakshmi Kumaran & Sridharan filed written submissions on behalf of CONFEDERATION OF INDIAN TEXTILE INDUSTRY, M/S. Arvind Ltd and M/S. Vardhaman Industries Ltd.

- a. Due to safeguard duty imposition, the end users will suffer immensely due to less production of stretch yarns and increased cost of the subject product. It will have major impact on cost of yarn, adverse affect on competitiveness of Indian industry in domestic and export market.
- b. Yarn export business will be at loss and may shift countries.
- c. The application contains less than two years' data, which is inconsistent with the requirements under Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997 issued by DG safeguards.
- d. Application was not updated after repeated reminders and following information was not provided to the interested parties:
 - (i) Import statistics for the entire period of 2013-14;
 - (ii) Injury parameters updated to reflect the entire period of 2013-14;
 - (iii) Annual reports for the periods 2012-13 and 2013-14;
 - (iv) Information on price undercutting for the entire period of 2013-14;

- (v) Information on price depression for the entire period of 2013-14
- (vi) Information on prevention of price-rise information for the entire period of 2013-14; and
- (vii) Amended application to reflect Applicant's position up to March 2014.
- e. Annexure- 5A which provides the production and sales data, does not mention the units for quantity and value for any of the parameters.
- f. Applicant has exercised excessive confidentiality. Applicant has claimed confidentiality on its annual audited accounts, not provided any indexed figures for parameters claimed confidential. Profit and loss figures are not indexed and many parameters that could have been indexed have been kept confidential.
- g. Present case does not meet the criteria of increased imports under Section 8-B(1) of the Act nor under Article 2.1 of the AoS.
- h. Import data fails to satisfy the requirement of sudden surge in such increased quantities so as to cause serious injury or threat thereof.
- i. There is no serious injury to the domestic industry. Applicant has withheld a crucial injury information on a number of factors.
- j. With regard to Volume parameters the import volumes are declining in POI. Applicant's capacity utilization is improving, sales are showing significant improvement, share of imports in demand is declining, productivity and employment are improving,
- k. With regard to price parameters, there is no price undercutting, no price depression, import prices are rising commensurate to increase in raw material prices. Further, the applicant's losses are declining over time. The losses are least in 2013-14 (Q3) when imports are maximum, which breaks the causal link between losses and rising imports.
- 1. There is no causal link between alleged increased imports and any serious injury or threat thereof. There is no injury on volume parameters and price parameters. Any injury due to intrinsic factors to the Applicant cannot be attributed to imports. Any injury claimed is due to non-availment of backward area benefit and other tax benefits, logistical issues it faces and cost of external commercial borrowings made by commercial borrowings made by the Applicant cannot be attributed to imports.
- m. The Application does not identify any unforeseen development within the meaning of Article XIX(1)(a) of GATT that resulted in sudden surge in imports. (China specific safeguards initiated on Hot Rolled Flat products of Stainless Steel of 304 grade; DS 177-178 US- Lamb; AB Report in DS 98 Korea- Dairy Products; AB Report in DS 121 Argentina-Footwear; and Panel Report in DS 415-418 Dominican Republic Polypropylene Bags; DS 238 Argentina- Preserved Peaches)
- n. The factors such as transportation of raw materials and finished products and high costs of logistics in the terrain area should have been obvious as it was a matter of proper due diligence.
- o. The applicant was already aware of the rate of the custom duty when it commenced operations.
- p. There is no correlation between the identified unforeseen development and supposed surged imports.
- q. India's obligations under the India-ASEAN Agreement are not relevant in examining the issue of unforeseen development. The argument has no factual basis as the timetable specifying the rate of reduction of anti-dumping duty was publicly available soon after the conclusion of the India-ASEAN FTA on 1st January 2010.
- r. The application does not identify any obligation incurred by India including tariff concessions for the subject product under GATT that resulted in sudden surge in imports.
- s. The adjustment plan is not time-bound, is too generic and does not show concrete steps for positive adjustment (DG Safeguard investigation Methyl Acetoacetate Final Findings dated 8th October, 2013).
- t. A safeguard duty will not be in public interest in this case. (a) There is a huge demand-supply gap. Textile industry depends on imports of the subject product for a variety of reasons. It would be highly detrimental to the Indian textiles industry and the consumers of stretchable fabrics in India. (b) it would make Indian exports of finished products uncompetitive in international market; (c) Applicant intends to create monopoly in Indian market by blocking imports and creating demand for its new capacities.

H. Written Submissions of Unicharm India (P) Ltd.

- a. The initiation of investigation is contrary to the Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997.
- b. There is no import 'in such increased quantity' and there are no "such conditions" as well as there is no injury or threat of injury requiring initiation of safeguard proceedings.

- It is mis-declaration that Domestic industry is a manufacturer of all varieties and all deniers of Elastomeric Filament Yarn.
- d. The importer is importing the said product having more than 67 decitex i.e. a variety which is not being manufactured by Domestic Industry.
- e. The application should be rejected on the ground that misleading position claimed by Domestic industry in respect with imports of Filament/Yarn more than 67 decitex.
- f. All products which are more than 67 decitex shall be excluded from the scope of PUC as domestic industry has admitted that their product is less than 67 decitex.
- g. Indorama spandex cannot be used for hygiene products due to weak creep resistance. (R&D lab test report)
- h. Domestic industry intends to gain monopoly over the PUC market.
- i. The product imported by the importer is not usable by textile industry rather it is used by products of hygiene manufacturers. Therefore, the product imported by the importer is neither similar/identical/like/inter-changeable with the product manufactured by the Domestic industry.
- j. The domestic industry is using its manufacturing facility to optimum capacity in 2013-14. There is no injury or even threat of injury.
- k. The reduced profitability of the company is not due to cheaper imports, but due to high interest cost and high depreciation which increase the cost of manufacture and in turn, reduce the profitability.
- 1. Domestic industry even at optimum capacity utilization, could not meet domestic requirement.
- m. The quantum of imports is stable whereas the domestic requirement has gone up.
- n. The comparison with large manufacturer outside India is itself misleading as there cannot be a cost comparison between the manufacturer having capacity of 5000 MT and a manufacturer having 1 lakh MT and a cost of small manufacturer is bound to be higher and the manufacturers manufacture at huge numbers.
- o. The allegation that manufacturers are deploying their excess capacity to deluge Indian market is incorrect, the domestic industry is trying to gain monopoly over the Indian market.
- p. The safeguard duty proceedings initiated is against national interest as any contrary action will result in irreparable loss and damage to the domestic users including Unicharm India Pvt. Ltd.

I. Written submission of M/S. Associated Chemical Corporation-

- a. The applicants should not be allowed for application of safeguard duty since they have not even completed their three years of manufacturing the goods.
- b. The duty imposition will encourage monopoly practices.
- c. The applicant has given incorrect statement by saying that they are producing all deniers and all varieties of Spandex.
- d. The usage of spandex stated is incorrect and incomplete. Applying Safeguard duty over all spandex is not justified.
- e. Misleading picture has been given about import duty on elastomeric yarn by not mentioning 0% duty in Pakistan and 4% duty in Italy.
- f. The import prices of Spandex are going up.
- g. The share of the applicant has increased and the contribution in the sale by the domestic industry is also very good and hence clearly, there is no threat/serious injury to the domestic industry from the imports.
- h. The major manufacturers outside India do not have sufficient quantities of Spandex and thus have not put up plants for surplus capacities.

- i. The applicant is not in a position to fulfill the requirement of the Indian Industries.
- j. There are various types of Spandex which are not manufactured by applicant, this imposing duty on overall Spandex yarn will be unjustified.
- k. There is no threat/injury to the applicant for selling the goods in Indian market. The main cause of making their loss is due to inferior quality and not producing the required specific elastomeric yarn which can get them international prices.
- 1. There is no serious injury. The applicants are forced to sell at a lesser price in the international market.
- m. There has been no increase in the raw material prices in the international market.
- n. The applicant's performance is improving as the losses incurred are decreasing.
- That the landed price of the imported spandex yarn is very low as compared to their sale price is an incorrect statement.
- p. There is no threat to profitability due to the import of spandex.
- q. The application for anti dumping duty has already been rejected. Therefore it is not possible that there would be serious injuries to the applicant due to the import of spandex.

J. Written submission of M/S. Enfield Apparels Ltd.

- a. Section 8(B) defines the Domestic Industry as "Producers", which means more than one producer. The applicant very smartly seeking backdoor benefits and trying to attain a Monopolistic type of situation where they can increase prices solely for the reasons that imports will be more costly.
- b. The applicant has generalized the Elastomeric yarn as a product and cleverly concealed that they do not manufacture all types of deniers which are offered in world market. They do not offer chlorine resistant spandex, do not offer dope dyed spandex, do not offer dye able with other fiber varieties, do not have any product for Hygiene Industry, do not have low heat setter spandex type which saves environment and will be mostly used in future, and in public hearing the learned counsel declared that they are not seeking for what they are not manufacturing.
- c. The domestic producers started their production only in March 12 and it is only around 2 years of existence, so far production is concerned, and is very small duration for the quality and production of sensitive product like spandex to stabilize. Further, the Trade notice no. SG/TN/1/97 dtd. 6.09.1997 in order to investigate and justify any increase in imports seeks mandatorily the detailed information regarding the imports of the said product in terms of quantity and value year wise for the last three years (or longer).
- d. The imports data which can be taken from government agencies are in actual showing slight decrease in imports of total elastomeric yarn during the period of investigation. It will be further down if we remove the types which they are not manufacturing and are not seeking safeguard duty on them, which logically should be the case, hence there is no case of safeguard duty imposition.
- e. They do not have any prima facie case for relief under safe guard, Just increase in import do not mean injury as it may be due to increase in demand and in that situation the domestic producer will also be at advantage to sell more quantities and even at better price. They are unable to prove any injury leave aside serious injury or prospect of serious injury.
- f. From the data provided by the domestic industry, it is evident that losses have come down substantially and capacity utilisation is increasing year to year basis. It is good sign and going by the trend they can come out in profit within next reasonable period.
- g. Domestic industry have export obligation and selling same product at much cheaper rates then the imported price.

K. Written submission of M/S. Narrow Elastic Manufacturers Association.

- a. Members of the Narrow Elastic Manufacturers' Association manufacture elastic tapes in which Elastomeric yarn is a crucial input. Therefore the quality of the tape depends on a good quality elastomeric yarn.
- b. The demand for garments and thus demand for tapes and elastomeric yarn is increasing. This can be fully utilized only when the quality is comparable with international standards. The tape manufacturers are disappointed with poor quality of the petitioner's product elastomeric yarn.
- c. The supply of faulty spandex yarn causes damage not only to Narrow Elastic Fibre Manufacturers, but also to manufacturers of fabrics and garments and ultimately the national economy.
- d. The size of the Indian market for elastomeric yarn increased, but the capacity of the petitioner is not enough to meet the demand, even when it is enjoying a monopoly position.
- e. Imposition of safeguard duty will make elastomeric yarn costlier. Most of the exporters of elastic tape prefer the drawback route, which does not neutralize the incidence of Safeguard duty. Thus, the exports will lose its competitive edge and a large chunk of the tape manufacturers which is small scale and medium scale will suffer.
- f. The statement of the petitioner 'moreover, landed value of the subject goods has not increased in proportion to the increase in raw material and overall costs', is without a proper study or justification.
- g. It is incorrect to take into account data for 2010-11 because petitioner was not a manufacturer of the product in that year. The allegation of price undercutting is baseless. The tape manufacturer has to make payment in rupees for the items imported by it.
- h. The petitioner would have made profits had it sold elastomeric yarn at landed cost. But it could not do so because of poor quality.
- i. Petitioners allege that due to continued losses 400 workers and staff of tape manufacturing units will lose jobs. However, if the safeguard duty is imposed more than 4,000 workers and staff of tape manufacturing units will lose jobs.

L. Written submissions of National Synthetics

- a. There is no abnormal increase in the imports of Bare Elastomeric Yarn.
- b. There is neither any injury nor any threat of injury to M/s. Indorama Industries Ltd. on account of any increase in imports as is being projected.
- c. There is no sudden and sharp increase in imports. For an objective study, a comparison should be done to see if domestic manufacturer is able to manufacture the quality and the yarn of specification required by the domestic consumer or not. This is not dealt with in data provided by M/s. Indorama Industries Ltd.
- d. The domestic production has been constantly increasing and so is the capacity utilization. The decline in the domestic market is not on account of less sales but on account of exports, which was found to be more profitable by the domestic industry than before on account of depreciation in rupee value.
- e. Indorama does not meet quality specifications in many quality critical sectors. Imports cannot be held responsible for fall in their sale. M/s. Indorama Industries is trying to get monopoly in spandex market at the cost of domestic consumers.
- f. The losses may be on account of other reasons, commercial reasons like long gestation period where the cost of production cannot be recovered in the very first year of production. It also depends on management control, efficiency, technology employed and various other factors.
- g. Injury cannot be said to have been caused to the domestic industry on the basis of productivity and employment. The inventory is also not abnormal.
- h. The price of imported spandex into India in dollar terms has been more or less stable to an upward trend throughout 2012-13 and then 2013-14 in line with the International market. Thus the import price has gone up substantially.
- i. M/s. Indorama Industries Ltd's business is flourishing by all standards. However, even with full capacity utilization, M/s. Indorama Industries ltd at best can meet only a third of market requirement and any safeguard duty would only be punishing the domestic textile industry for which spandex yarn is a raw material. Imposition of safeguard duty is thus not in public interest.

M. M/S. JSL filed written submission on behalf of All India Spandax Yarn Importers Association

- a. There can be no investigation for spandex yarn as there exists no Domestic Industry for Spandex Yarn in India.
- b. There is no three year data available for the domestic production of Spandex Yarn.
- c. There exists no increase in import of Spandex from the data available on record.
- d. There can be no extrapolation of data done by the Director General Safeguards. The DGS extrapolated import data Q3 of 2013-14 and has considered the same for the period of investigation.
- e. There is no existence of "serious injury" or "threat of serious injury".
- f. There is no causative link between lack of profitability of the domestic producer and the import of Spandex yarn happening in India.
- g. There has been no causation established between 'increased imports' and 'serious injury'.
- h. The public interest will be negatively affected if Safeguard Duty is imposed.
- i. The applicant's repeated reference to price undercutting is invalid and bad in law.

N. Written submission filed by M/S. Zeon International

- a. Levying of safeguard duty on elastomeric yarn will be detrimental to the Indian Textile Industry.
- b. Indorama will create a monopoly and thereby dominate the market and manipulate prices to their advantage. This will make Indian garments made with spandex, uncompetitive in the global market.
- c. Indorama does not have enough capacity to meet the demands of the country. Therefore, levy of safeguard duty will penalize the customers who still have to import the spandex yarn.
- d. Indorama's business has been thriving and flourishing unthreatened by imports.
- e. There is no substantial increase in imports to indicate threat.
- f. Spandex has various applications and Indorama has lower and limited quality standards.
- g. The losses incurred by Indorama are due to cheaper pricing in Domestic and export markets.
- h. The substantial increase in export has resulted in lower domestic market share.
- i. The consumption of Spandex in India is set to grow by 15-20% every year as per the international trends. Therefore, levying additional duty on spandex yarn at this time would be detrimental to the nascent growth of the value added garment industry in India and in the long term India will be unable to compete and grow as value added garment manufacturing base.

12. Following interested parties submitted rejoinders, to the written submissions of other interested parties

1	Indorama Industries Ltd. (Domestic Industry)
2	Aarvee Denims and Exports Ltd.
3	Association of Synthetic Fibre Industry
4	Bhaskar Industries Pvt. Ltd,
5	Jindal Woriwide Ltd
6	Mafatlal Industries Ltd.
7	WelspunSyntex Ltd
8	Denim Manufacturer Association

9	Birla Century
10	Oswal Woollan Mills Ltd
11	Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd
12	Chiripal Industries Ltd.
13	Nandan Denim Ltd.
14	Arvind Ltd.,
15	Vardhman Textiles Ltd
16	Confederation of Indian Textile Industry
17	Hyosung Corporation, Korea
18	Hyosung Spandex (jiaxing) Co.,Ltd., China,
19	Hyosung Vietnam Co. Ltd., Vietnam,
20	TK Chemical Corp., Korea,
21	Taekwang China PR
22	Taekwang Korea
23	INVISTA Sales & Service India Pvt. Ltd
24	Invista Singapore Fibers Pte. Ltd.

13. The brief summary of the rejoinder filed by above interested parties to the written submissions of other interested parties are as under:

A. <u>Brief of rejoinder filed by M/S. APJ-SLG Law Offices on behalf of M/S. Indorama Industries Ltd.</u> (Domestic Industry)

- a. The domestic industry has duly provided the non-confidential version of the petition.
- b. TPM Consultants has given unsatisfactory clarification about relying upon information which is not available in public domain. The source of information relating to the number of times the application have been filed and the grounds of rejection by the Designated Authority is unexplained. The opposite parties should be put to strict proof as to the source of such information so that the rules and procedures are not flouted blatantly.
- c. None of the associations have fulfilled their obligation in terms of their Rule 2 (d), the Director General is requested to reject the responses filed by them.
- d. The definition of domestic industry does not exclude from its scope industries that are in existence for less than three years. Rule 5(1) does not prescribe as to who can file the application as long as it has information relating to the domestic industry. The negative clause 5(3) also does not mandate that DG (Safeguards) can initiate only when evidence of serious injury is more than three years. The opposite parties are not entitled to raise this issue at this stage.
- e. It would not be permissible to read the said Trade Notice to mean that only those producers who have been in existence for more than three years can file the application would tantamount to overruling the specific mandate of the statute by way of a 'Trade Notice'.
- f. There is no specific definition of the period of investigation.
- g. In the instant case the evaluation of the increase in imports during the period of investigation has to be evaluated in terms of the past data. It is completely irrelevant whether or not the Domestic Industry has

- started its commercial production in the period used for benchmarking and to examine whether there is an increase in imports or not.
- h. Imports have increased significantly in the period of investigation. Even if imports had shown marginal decline in March 2014, then also, it had no implication on the conclusion of the DG about increase in the imports. There is sufficient proof to conclude
- i. The Hon'ble DG only needs to analyze and conclude that the imports are causing injury to Domestic Industry and it is one of the grounds which are affecting Domestic Industry's performance. The injury suffered by the domestic industry however is primarily because of increase in imports.
- j. Domestic Industry is suffering from serious injury.
- k. There is no specific requirement in the Safeguard law or Agreement on Safeguards to provide price undercutting. Further, imports are significantly depressing the selling price.
- 1. There is no material price difference between the domestic produced subject goods and that imported into India when price comparison is made denier-wise and on a month to month basis.
- m. The claims of the interested parties to exclude certain products are misplaced and wrong.
- n. Domestic industry is forced to export more than 30% of its production at lower prices.
- o. The subject goods with capacity issue and restructuring plan needs to be analyzed simultaneously. This combined analysis is important because the domestic industry has not been able to fully implement its capacity as per the original schedule due to circumstances not in control of the domestic industry.
- p. There were unforeseen circumstances which domestic industry could not foresee at the time of conceiving the project way back in 2008 or by negotiators of Indo-ASEAN FTA.
- q. The quality issue is a bogey.
- r. The imposition of Safeguard duty is in public interest. If the protection will not be provided to the Domestic Industry at this stage, there is danger that domestic industry cannot sustain its business in the long run and eventually decides to either close down operations or diversify from current operations. In that situation the exporters will again increase their prices.

B. Brief of rejoinder filed by M/S. DGS Advocates on behalf of M/S. Hyosung Corporation, (Korea), T.K. Chemicals Corp. (TKC), Korea, Taekwang Industrial Co. Ltd., Korea, Hyosung Vietnam Co. Ltd., Vietnam, Hyosung Spandex (Jiaxing) Co. Ltd., China, and Taekwang Synthetic Fiber (Changshu) Co. Ltd., China.

- a. The domestic industry has shown in the annexure to their petition responding associations as concerned trade associations and users. Therefore they should not be allowed to change their stand now as per convenience.
- b. The government of India has already established and concluded that there is no "material injury", the Government of India cannot now conclude that "serious injury" has been caused to the Domestic Industry due to the same imports.
- c. Any reference to trends of imports prior to 2012-13 is not correct.
- d. The claim of domestic industry that commencement of period of trend analysis should be from 2010-11 is totally incorrect and should not be accepted. In the current investigation, the Hon'ble authority has specifically adopted injury period as 2012-13 and 2013-14, hence all injury analysis, including trends of imports should be restricted to injury period specified in the Initiation Notification.
- e. DGCI&S data should be taken as it is considered most authentic in case imports are reported under dedicated classification.
- f. There is no decline in prices of imported subject goods.
- g. There were no unforeseen developments.
- h. The participation of hundreds of end users against any imposition of safeguards Duty and highlighting various issues before this Hon'ble Authority is a clear indication that any move on the part of this Hon'ble Authority to impose Safeguards duty on Bare Elastomeric Yarn would not be in Public Interest.

- C. Brief of rejoinder filed by M/S. TPM Consultants on behalf of (1)Association of Synthetic Fibre Industry,(2)Aarvee Denims and Exports Ltd.,(3)Bhaskar Industries Pvt. Ltd., (4)Jindal Woriwide Ltd., (5)Mafatlal Industries Ltd.and(6)WelspunSyntex Ltd., (7)Denim Manufacturer Association ,(8) Birla Century, (9)Oswal Woollan Mills Ltd. (10)Raymonds UCO Denim Pvt. Ltd (11) Chiripal Industries Limited (12)Nandan Denim
 - a. The Director General is requested to consider DGCI&S data for the present purposes and proposed determination.
 - b. The objection of domestic industry on various associations being considered as interested parties is delayed. Denim Manufacturers Association had made known its status at the time of initiation and the Authority had granted the status of interested party to it.
 - c. These associations represent consumers who are importers of the product and thus constitute interested party.
 - d. The information provided by interested parties is on the basis of that which is publicly available. The petitioner has suppressed vital information from the Director General (Safeguards).
 - e. The petitioner's product has not been accepted by all consumers and applications so far.
 - f. Comparison of import price from China, Vietnam, Singapore etc. has a direct bearing on the case.
 - g. The Domestic industry has tried to hide that it had filed an anti dumping application. Subsequently it has tampered the application proforma by deleting the relevant part of prescribed questionnaire with regard to filing of petition.
 - h. With regard to eligibility as domestic industry, it is submitted that the sole domestic producer is a new company, selling materially below import price and not having sufficient history to enable the Director General (Safeguards) to determine increased imports and serious injury, and yet pleading injury from imports.
 - i. The DG Safeguards cannot consider different period for increased imports and serious injury to the domestic industry. A history of 3 years therefore, is minimum.
 - j. A time period of more than two years is necessary in order to objectively determine the question of increased imports and serious injury to the domestic industry.
 - k. The age of Industry is important for determining increased Imports and serious injury in such cases.
 - The DG Safeguards cannot consider a longer period for increased imports and a shorter period for serious injury.
 - m. The imports have not increased at all. The DGCI&S data should be referred instead of IBIS data.
 - n. Imports have actually showed a decline in relation to production and consumption.
 - o. The Domestic industry is admittedly benchmarking its prices to the lowest price of imports. The losses being suffered by the domestic industry are on account of factors internal to the company. Nothing prevents a company from charging a price comparable to the import price.
 - p. The difficulties of the petitioner are with regard to technical acceptability of the product and its failure to charge a price comparable to the import price.
 - q. The petitioner has repeatedly stated in the petition that it is forced to sell the product at a price below the import price and it is forced to benchmark its prices to the lowest import price.
 - r. Factors identified by the petitioner do not constitute unforeseen development.
 - s. Quality is an important issue. Thus petitioner's product is not accepted by a large number of consumers. It is evident from the fact that consumers are importing the product materially higher than the prices at which petitioner is selling the product in the market.
 - t. Only those consumers are buying the product of the petitioner who can compromise on the quality of the end product.
 - Petitioner will have to make a lot of efforts in order to meet the standards of foreign producers and that are required by consumers.
 - v. Consumers may use a lower quality specification product for producing an eventual product with inferior specifications.
 - w. The purpose of the proposed safeguard duty is to increase the price of the product without protecting the domestic industry.

D. Brief of rejoinder filed by M/S. Lakshmi Kumaran & Sridharan on behalf of CONFEDERATION OF INDIAN TEXTILE INDUSTRY, M/S. Arvind Ltd and M/S. Vardhaman Industries Ltd

- a. The applicant's submission on associations being not eligible to register as interested parties is totally unacceptable in view of various Rules under Safeguard Law.
- b. The applicant cannot now state that information on landed price provided by the Respondents is misleading. The argument of the Applicant regarding misleading information on landed prices is also untenable.
- c. The DG Safeguards is requested to examine the aspect eligibility and standing of the Applicant.
- d. The DG Safeguards is urged to examine the aspect of unavailability of data for a minimum period of three years in the application and the Applicant's failure to follow this legal requirement.
- e. The data available in all submissions of the Applicant have not been updated to reflect the Applicant's position till March 2014. Further, several parameters have been kept confidential and no meaningful summary of the same have been provided by the Applicant to all the interested parties. Thus, the Applicant's assertions on the DG Safeguards powers to select the period of investigation serve no purpose.
- f. It is an incorrect statement that import volumes prior to the period of investigation are also to be considered for trend analysis.
- g. The contents of the letter dated 22.04.2014 should not be considered by the DG Safeguards for reaching a decision in this case. The Applicant's data on import statistics from a completely different source (IBIS) should be rejected.
- h. The present investigation should be terminated as it is based on an application that is supported by incorrect import statistics, incomplete and inadequate data and misquoted legal precedents.
- i. The applicant's assertions on adequate capacity and adjustment/restructuring plan should be rejected outright. The Applicant's adjustment plan is too generic, and in the nature of proposals and does not show any concrete steps that the Applicants would take to adjust positively.
- j. With regard to unforeseen development, it is submitted that the Applicant's claim on decrease in prices of subject goods despite increase in raw material prices is incorrect and not supported by the data presented in its application. Further, concessions under an FTA cannot be considerd an unforeseen development under GATT provisions.
- k. The quality of the product of the Applicant does not meet the international standards. The injury to the Applicant is not due to alleged increase of imports but due to inherent issues with the Applicant including poor quality of its goods.
- Larger public interest would be served if the present investigation is immediately terminated as the data in
 the application and all subsequent submissions of the Applicant does not warrant imposition of a safeguard
 duty in this case.
- 14. M/S. J. Sagar Associates on behalf of M/S. Invista Singapore Pte Ltd & M/S. Invista Sales and Service India Pvt. Ltd vide letter dated 14/07/2014 submitted that vide Notification No.12/2014-Cus dated11/07/2014 the basic customs duty on raw materials used for manufacture of Spandex is reduced from 5% ad valorem to Nil. Accordingly price of Spandex manufactured by the domestic industry will be affected.

IV. **EXAMINATION & FINDINGS:**

- 15. I have carefully gone through the case records, the replies filed by the domestic producer, user/importers, exporters and exporting nations. The written submissions and the rejoinder submissions made by them have also been considered appropriately. The submissions made by various parties and the issues arising there from are dealt with at appropriate places in the findings below:
- 16. Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 deals with imposition of Safeguard Duty on imports. Its sub-section (1) provides for imposition of Safeguard duty by the Central Government on an article if the article is being imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the Domestic Industry.
- 17. The Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 provides the manner and principles governing investigation.
- 18. The investigation has been conducted in accordance with the said rules and the Final Findings are recorded through this notification.

A. The Product Under Consideration (PUC):

19. The product under consideration (hereinafter referred to as PUC) in the present case is "Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties" classified under Customs Tariff sub-heading nos. 54024400 and 54041100 of Chapter 54 of the Customs Tariff Act, 1975. The product is also commonly referred to as "Spandex" or "Elastane". Elastomeric filament Yarn is manufactured from two main raw materials, namely Poly Tera Methylene Ether Glycol and Mono Diphenyl Methane Diisocynate and is used in various applications such as denim jeans, Sportswear, T-Shirts, Suitings Socks & other garments. Some of the interested parties have raised the issue that all those product types which are being imported and which are not being produced by the domestic industry should be excluded from the scope of the product under consideration. None of the interested parties have filed any material evidence to substantiate their claim for exclusion from the product scope and hence claims or issues merely based on conjectures cannot be accepted. Therefore, it is confirmed that the product under investigation is "Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties" falling under Custom Tariff Heading 54024400 and 54041100 of Chapter 54 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. Accordingly, it is also held that domestically produced Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties falls under the ambit of like or directly competitive article in all respects to the imported product under investigation and that the domestically produced Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties is a like article to the imported Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties within the meaning of Rule 2(e) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

B. Domestic Industry (DI):

- 20. Section 8B(6)(b) of the Customs Tariff Act 1975 defines Domestic Industry as follows:
 - "(b) "Domestic Industry" means the producers -
 - (i) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or
 - (ii) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India;"
- 21. Some of the interested parties have raised the issue that the provision under Sec 8B(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act,1975 referring to the "domestic. industry" as the "producers' is not a singular producer but is plural in nature and it refers to more than one such producers and hence M/S. Indorarna Industries Ltd., being the single entity, have no such standing to file the subject present petition. This view does not seem to be correct. In this regard, the Section 13 of the General Clauses Act 1897 reads as under:
 - "13. Gender and number.- In all (Central Acts) and Regulations, unless there is anything repugnant in the subject or context.- Words importing the masculine gender shall be taken to include females, and words in the singular shall include the plural, and vice versa."
- 22. In view of the language contained in Section 13 of the General Clauses Act 1897, the use of the word "producers" in Section 8B(6)(b) of Customs Tariff Act,1975 shall automatically include its singular form i.e., "producer" and hence M/S. Indorama Industries Ltd., being a sole producer of the product under consideration have the standing to file the present petition (hereinafter referred as DI).
- 23. In view of above and as output of M/S. Indorama Industries Ltd. constituted 100% share of the total production of bare elastomeric filament yarn in India, it is held that the applicant domestic producer constitutes and represents the Domestic Industry (DI) within the meaning required and defined under Sec 8B(6)(b)(ii) of the Customs Tariff Act, 1975.
- 24. <u>Injury to new industry cannot be examined under Safeguard law</u>: Some of the interested party contended that Injury to new industry cannot be examined under Safeguard law. This contention is not correct as section 8(B) of Custom Tariff Act, Safeguard Rules and even the Agreement on Safeguards do not envisage such a situation where injury to new industry cannot be examined under Safeguard law. Hence the contention of interested party is not acceptable.

C. Status of Associations as Interested Parties:

25. Claim of the Domestic Industry that the responding associations cannot be considered as interested parties in terms of Rule 2(d) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 is contrary

to its submission in the application. As per Annexure 4 to the application filed by the Domestic Industry, most of the Associations have been shown as concerned trade associations and users' associations. Now claim of the Domestic Industry that Associations, which have participated in the instant Investigation and raised voice against any imposition of Safeguards duty on the subject goods are not interested parties is contrary to its submission. Further Rule 2(d) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 clearly indicate that interested party include trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like articles or directly competitive article in India. In view of above, it is decided to include all associations, who filed their submissions, as interested parties.

D. Source of information:

- 26. The product under investigation is imported into India under Custom Tariff Heading 54024400 and 54041100 of Chapter 54 of First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975. The Safeguard investigation was initiated on the basis of import data of DGCI&S, Kolkata till October, 2013. The data on various economic parameters was submitted by the Domestic Industry in their application till December, 2013 and same has been verified by this Directorate on the basis of central excise records of the domestic industry to the extent possible. The import data from Nov, 2013 to March, 2014 has also been taken from the records of DGCI&S, Kolkata. The domestic data from Jan,14 to March, 14 in respect of various economic parameters has been taken as furnished by the applicant, in their written submissions/rejoinder, in order to arrive at quarterly as well as yearly consolidated data for the year 2013-14 for injury analysis. The non-confidential version of the verification report has been placed in the public file for all concerned.
- 27. Anti-dumping application by the DI: Some of the interested party contended that The DI has suppressed vital facts from the Director General (Safeguards) that they had filed a petition seeking imposition of anti dumping duty and the Designated Authority however rejected the petition. With regard to the submission made by the Domestic Industry that the interested Parties have attempted to produce and rely upon information which is not available in public domain, none of the interested parties has brought clear evidence on record to support their claim in this regard.

E. Period of Investigation (POI):

28. Neither the Customs Tariff Act, 1975, nor the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997, specifically define 'Period of investigation' or the minimum period to be considered for a Safeguard investigation. The WTO Agreement on Safeguards does not contain any general or specific provision or guidelines for choosing the investigation period. However the issue of period of investigation has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea (Para 7.196,7.199 and 7.201). The Panel in this case ruled that it is up to the discretion of the investigating authority of the importing Country to decide the "length of the period of investigation" and its "breakdown".

"We note that the Agreement contains no requirements as to how long the period of investigation in a safeguards investigation should be, nor how the period should be broken down for purposes of analysis. Thus, the period of investigation and its breakdown is left to the discretion of the investigating authorities. In the case before us the period selected by the ITC was five years and six months, which is a period similar in length to the one used by the Argentine investigating authority in Argentina — Footwear Safeguard. However, we note that the Appellate Body, in the findings relied upon by Korea to argue the question of the length of the period of investigation, emphasized not the length of the period per se, but that there should be a focus on recent imports and not simply trends over the period examined. In the case of the line pipe investigation the ITC did not merely compare end points, or look at the overall trend over the period of investigation (as Argentina had done in the investigation at issue in Argentina — Footwear Safeguard). It analyzed the data regarding imports on a yearto-year basis for the 5 complete years, and also considered whether there was an increase in interim 1999 as compared with interim 1998. We are of the view that by choosing a period of investigation that extends over 5 years and six months, the ITC did not act inconsistently with Article 2.1 and Article XIX. This conclusion is based on the following considerations: first, the Agreement contains no specific rules as to the length of the period of investigation; second, the period selected by the ITC allows it to focus on the recent imports; and third, the period selected by the ITC is sufficiently long to allow conclusions to be drawn regarding the existence of increased imports." (paras. 7.196, 7.199 and 7.201)⁴

⁴WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

29. Commencement of period of trend analysis: The domestic industry argues that the import volumes prior to the period of investigation are also to be considered for trend analysis. It is felt that this kind of interpretation is completely illogical. First of all, the domestic industry did not even exist before March, 2012. Secondly, the POI has already been selected and notified through Notice of Initiation considering that the domestic industry commenced production only in March, 2012. Thirdly, the injury to the DI cannot be ascertained prior to the commercial production of the product under consideration as relevant domestic data like production, sales, selling price, cost of production etc are not available for analysis vis-à-vis import volume & landed value of import. However the issue of trend analysis has been dealt in detail in Panel findings in US-Line Pipe Case against Korea (Para 7.209). The Panel in this case ruled that the period for examination of increased import trends to be same as that for the examination of the serious injury to the DI.:-

"In a safeguard investigation, the period of investigation for examination of the increased imports tends to be the same as that for the examination of the serious injury to the Domestic Industry. This contrasts with the situation in an anti-dumping or countervailing duty investigation where the period for evaluating the existence of dumping or subsidization is usually shorter than the period of investigation for a finding of material injury. We are of the view that one of the reasons behind this difference is that, as found by the Appellate Body in Argentina – Footwear Safeguard, "the determination of whether the requirement of imports "in such increased quantities" is met is not a merely mathematical or technical determination." The Appellate Body noted that when it comes to a determination of increased imports "the competent authorities are required to consider the trends in imports over the period of investigation". The evaluation of trends in imports, as with the evaluation of trends in the factors relevant for determination of serious injury to the Domestic Industry, can only be carried out over a period of time. Therefore, we conclude that the considerations that the Appellate Body has expressed with respect to the period relevant to an injury determination also apply to an increased imports determination." (Para 7.209)⁵

- 30. Further in view of the above findings of the WTO panel to the effect that the period of examination of the increased imports should be same as that for examination of serious injury to the DI, it would be incorrect to consider any period prior to the selected period of investigation. The Panel has further stated that the position of law in this regard is different in anti-dumping/countervailing duty investigations. Therefore, reliance on anti-dumping cases for this purpose is also not correct. Further, anti-dumping is a different kind of trade remedy which is available in entirely different situation, Therefore, it would not be appropriate to apply the ratio of decisions of anti-dumping law in this case.
- 31. Some of the interested parties have raised objection that application contains less than two years' data, which is inconsistent with the requirements under Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997 issued by DG safeguards. In this regard it is observed that para 5(1) of the Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997 prescribes that the applicant is bound to submit only that information that is in existence. Further it is felt that Trade Notice is not a law but is a creation of executive instructions. It merely provides for the procedure to be followed by the Director General, Domestic Industry and other interested parties in process of determination of levy of Safeguard Duty. The contents of the trade notice cannot lead to a situation where the Director General becomes a helpless creature and the statutory duties cannot be fulfilled. There is no provision in law relating to levy of Safeguard duty which bars the Director General from considering the application of domestic industry merely because the production data for three year or longer has not been furnished. This is all the more relevant in the present situation as the domestic industry came into existence only in March, 2012.
- 32. In view of above, considering these facts, and source of information stated above, it is considered appropriate to adopt data for the period 2012-13 to 2013-14 for the purpose of the present investigations. It has also been considered appropriate to break down the data on quarterly basis for the purpose of comparison and consequent assessment of serious injury.

F. Confidentiality of information submitted:

33. Rule 7 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguards Duty), Rules, 1997 and Article. 3.2 of WTO Agreement on Safeguards provides for confidentiality treatment to certain information. The rules

⁵ WT/DS202/R DT, 29.10.2001 Panel report in US-Line Pipe case

- provide that an Interested Party is not required to disclose such information on actual basis which is confidential information of the company and disclosure of which can cause serious prejudice to the business interests of such party, which is not in public domain and which the petitioner has not disclosed before public at large in the past.
- 34. The Domestic Industry has provided some information on confidential basis and sought confidentiality on the information /data submitted. The Domestic Industry provided nonconfidential version of the application for safeguard measure as per the provisions of Safeguard Rules 1997 and Trade Notice No. SG/TN/1/97 dated 06.09.1997. Further, the Domestic Industry has submitted reasons for seeking confidentiality at the time of filing the application, which appears to be reasonable and, therefore, has been accepted, whenever claimed.

G. Increased Imports:

- 35. Section 8B of Customs Tariff Act, 1975 deals with the power of the Central Government to impose safeguard duty and provides as follows:
 - "(1) If the Central Government, after conducting such enquiry as it deems fit, is satisfied that any article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to Domestic Industry, then, it may, by Notification in the Official Gazette, impose a safeguard duty on that article:"
- 36. The Rules mandate increase in imports as a basic prerequisite for the application of a safeguard measure. Thus, to determine whether imports of the product under consideration have "increased in such quantities" for purposes of applying a safeguard measure, the rules require an analysis of the increase in imports, in absolute terms or in relation to domestic production.
- 37. Rule 2 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 defines 'increased quantity' as follows:
 - "(c) "increased quantity" includes increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production."

a) Increased Import in absolute terms:

38. The analysis of the trend in imports of Bare elastomeric filament yarn in the light of the above mentioned provisions has been done. Bare elastomeric filament yarn is imported into India from a number of countries, and primarily from Vietnam, Korea, China, Singapore, Taiwan and Thailand. The quantum of imports of Bare elastomeric filament yarn during 2012-13 to 2013-14 are as under:

Period	Import (MT)	Production (MT)
2012-13(Q1)	2488	683
2012-13(Q2)	2628	400
2012-13(Q3)	2114	363
2012-13(Q4)	2111	921
2012-13	9341	2367
2013-14(Q1)	2428	1247
2013-14(Q2)	2565	1152
2013-14(Q3)	2214	1127
2013-14(Q4)	2086	1217
2013-14	9293	4743

- 39. It is apparent from the data in the table above that there is no surge in import in absolute terms. The imports have decreased from 2488 MT in 2012-13(Q1) to 2086 MT in 2013-14 (Q4), which shows a decrease of 16%. Further Imports decreased from 9341 MT in 2012-13 to 9293 MT in 2013-14, which shows a decrease of 0.5%.
 - b) Import in relation to Production:
- 40. The imports of product under consideration in India during the POI have also decreased in relation to production of the Domestic Industry when compared with the base quarter/year. The import with respect to total

production decreased from 364% in 2012-13 (Q1) to 171% in 2013-14 (Q4). Further Imports in relation to production decreased from 395% in 2012-13 to 196% in 2013-14.

			% of import with respect to
Period	Import (MT)	Production (MT)	production
2012-13(Q1)	2488	683	364
2012-13(Q2)	2628	400	657
2012-13(Q3)	2114	363	582
2012-13(Q4)	2111	921	229
2012-13	9341	2367	395
2013-14(Q1)	2428	1247	195
2013-14(Q2)	2565	1152	223
2013-14(Q3)	2214	1127	196
2013-14(Q4)	2086	1217	171
2013-14	9293	4743	196

41. It is apparent from the above that there is no surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production.

H. <u>Determination of Serious Injury and Threat of Serious Injury:</u>

42. Section 8B subsection 6(c) of Customs Tariff Act provides as follows:

"Serious injury" means an injury causing overall impairment in the position of a Domestic Industry;

43. Section 8B sub-section 6(d) of Customs Tariff Act provides as follows:

"threat of serious injury" means a clear and imminent danger of serious injury.

44. The Paragraph 1 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 provides as follows:

"In the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Director General shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular, the rate and amount of the increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilization, profits and losses, and employment."

45. Accordingly, in analyzing serious injury or threat of serious injury all factors, which are mentioned in the Rules as well as other factors which are relevant for determination of serious injury or threat of serious injury, have been considered. The determination of serious injury or threat of serious injury is based on evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of that industry.

a. **Production**: The production of the Domestic Industry increased from 683 MT in 2012-13 (Q1) to 1217 MT in 2013-14 (Q4). Further in yearly analysis the production of the applicant increased from 2367 MT in 2012-13 to 4743 MT in 2013-14.

Financial	Total Imports	Production	Domestic Sales	Total Demand		
Year/quarter	(MT)	(MT)	(MT)	(MT)	Market	Share
					Import	DI
2012-13(Q1)	2488	683	220	2708	92	8
2012-13(Q2)	2628	400	293	2921	90	10
2012-13(Q3)	2114	363	351	2465	86	14
2012-13(Q4)	2111	921	815	2926	72	28
2012-13	9341	2367	1679	11020	85	15
2013-14(Q1)	2428	1247	931	3359	72	28
2013-14(Q2)	2565	1152	892	3457	74	26
2013-14(Q3)	2214	1127	670	2884	77	23
2013-14(Q4)	2086	1217	918	3004	69	31
2013-14	9293	4743	3411	12704	73	27

- b. **Changes in the level of Sales**: The sales of the Domestic Industry increased from 220 MT in 2012-13(Q1) to 918 MT in 2013-14(Q4). Further in yearly analysis sales also increased from 1679 MT in 2012-13 to 3411 MT in 2013-14.
- **c. Market Share:** Market share of domestic producer has increased as compared to imports. Domestic industry had a market share of 8% in 2012-13(Q1) which rise to 31% during 2013-14(Q4) whereas the market share of import decreases from 92% in 2012-13(Q1) to 69% in 2013-14(Q4). Further in yearly analysis the market share of the domestic producer increased from 15% in 2012-13 to 27% in 2013-14 and market share of import decreases from 85% in 2012-13 to 73% in 2013-14.
- d. **Capacity Utilisation**: Capacity utilization of the Domestic Industry has increased significantly from 55% in 2012-13(Q1) to 97% in 2013-14(Q4). Further in yearly analysis the capacity utilisation of the applicant increased from 47% in 2012-13 to 95% in 2013-14. However, the total capacity of domestic industry to produce the product under consideration is not sufficient to cater the total demand in India.

Financial			
Year/Quarter	All India Production (MT)	Installed Capacity (MT)	Capacity Utilization
2012-13(Q1)	683	1250	55
2012-13(Q2)	400	1250	32
2012-13(Q3)	363	1250	29
2012-13(Q4)	921	1250	74
2012-13	2367	5000	47
2013-14(Q1)	1247	1250	100
2013-14(Q2)	1152	1250	92
2013-14(Q3)	1127	1250	90
2013-14(Q4)	1217	1250	97
2013-14	4743	5000	95

e.	Employment & Productiv	tv: The emplo	yment and the	productivity	over the injur	y period increased.
----	-----------------------------------	---------------	---------------	--------------	----------------	---------------------

Financial		
Year/quarter	Productivity(MT/day)	Employment(Nos)
2012-13(Q1)	8	221
2012-13(Q2)	4	230
2012-13(Q3)	4	227
2012-13(Q4)	10	236
2012-13	26	229
2013-14(Q1)	14	249
2013-14(Q2)	13	252
2013-14(Q3)	13	256
2013-14(Q4)	14	260
2013-14	53	255

f. **Profit & Loss:** The profitability & returns on investments of the Domestic Industry has improved during period of investigation. This is evident from the table below:-

Financial Year	Profitability (Rs. In lacs) Indexed	Return on capital employed(%) (Indexed)
2012-13	-100	-100
2013-14	-76	-46

g. Other Important Factors:-

(i) Import in relation to Demand: It is noticed in the table below that in quarter wise analysis, the import with respect to demand decreased from 92% in 2012-13(Q1) to 69% in 2013-14(Q4), i.e., by 23%. Further in yearly analysis import with respect to demand decreased from 85% in 2012-13 to 73% in 2013-14 i.e., by 14%. This shows that the DI is able to grab its space quickly in the local market.

			% of import with respect to Demand	Inventory (MT)
Period	Import(MT)	Demand(MT)	respect to Beniana	
2012-13(Q1)	2488	2708	92	477
2012-13(Q2)	2628	2921	90	584
2012-13(Q3)	2114	2465	86	521
2012-13(Q4)	2111	2926	72	528
2012-13	9341	11020	85	528
2013-14(Q1)	2428	3359	72	646
2013-14(Q2)	2565	3457	74	675
2013-14(Q3)	2214	2884	77	601
2013-14(Q4)	2086	3004	69	398
2013-14	9293	12704	73	398

- (ii) Inventories: With decrease in imports and increase in domestic sales, the Domestic Industry has not been forced to accumulate inventories. Inventories have decreased from 477MT in 2012-13(Q1) to 398MT in 2013-14(Q4). Further in yearly analysis inventories also decreased from 528MT in 2012-13 to 398MT in 2013-14.
- (iii) Price undercutting, suppression/depression: It is observed that the average landed price of the imports of Bare elastomeric filament yarn of all varieties is significantly higher than the selling price of the Domestic Industry. There is a significant price difference between the domestic and imported product. The variation of landed prices of imports, cost of production, selling price ,export price and raw material price are as under:-

Financial Year	2012-13 (Indexed)	2013-14 (Indexed)
Landed Value of Import(Rs./Kg)	100	118
Cost of Production(Rs./Kg)	100	83
sales price(Rs./Kg)	100	113
Export Price (Rs./Kg)	100	114
Raw material Prices(Rs./Kg)	100	110
Price Under cutting	-100	-148

- 46. It is seen from the above table that the cost of production decreased and the selling price increased during the period. The increase in the selling price by the DI in 2013-14 over 2012-13 was 13%, much lower than the rise in landed value of imports (18%) as against sharp decline in cost of production (by 17%). The imports were thus not suppressing the Domestic Industry prices in the market and the undercutting is also negative. Further there is no price depression as the selling price increases during POI. It is seen that the prices of raw material increased over the period (by 10%) but there is decline in cost of production showing that the Domestic Industry was not prevented from raising its prices. Moreover decreasing cost of production means that DI is improving and becoming more competitive.
- 47. **Export**: It is noticed from the table below that in quarter wise analysis, the export with respect to production increased from 0.06% in 2012-13(Q1) to 41% in 2013-14(Q4), i.e., by 40%. Further in yearly analysis export with respect to production increased from 8% in 2012-13 to 31% in 2013-14 i.e., by 23%. Further export sale prices are less than domestic sale prices. Hence more export at lower prices could be one of reason for losses.

Financial Year/quarter	Production (MT)	Export (MT)	% of export with respect to production
2012-13(Q1)	683	0.39	0.06
2012-13(Q2)	400	10	3
2012-13(Q3)	363	70	19
2012-13(Q4)	921	106	12
2012-13	2367	187	8
2013-14(Q1)	1247	200	16
2013-14(Q2)	1152	226	20
2013-14(Q3)	1127	532	47
2013-14(Q4)	1217	501	41
2013-14	4743	1460	31

48. From the above analysis, it is seen that the imports of the product under consideration have not increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. Since the performance of the domestic industry has shown improvement in a number of parameters, it is evident that the domestic industry has not suffered serious injury as a result of imports. In the present case, performance of the domestic industry has shown improvement in all the injury parameters listed under the Rules, as demonstrated above. Market share, production, domestic sales, capacity utilization, productivity, profitability, and return on investment have improved during POI. Inventories with the Domestic Industry have decreased during the injury period. Price undercutting was negative throughout the period. Further, the imports are not preventing the price increase by the Domestic Industry in proportion to increase in cost.

- 49. In the instant case, the imports have not caused the alleged injury to the domestic industry and therefore there exists no causal link between the imports and alleged injury suffered by the domestic industry. The DI has contended that they have incurred loss despite high capacity utilization. Mere loss or continuation of loss per se does not mean serious injury. The DI has generated losses due to various reasons listed below including high fixed costs. In my view there is monitory loss but no injury in the legal sense. Injury if any is attributed merely to factors other than the alleged low priced imports, as stated and admitted by the domestic industry in their application/submissions,
 - (a). The plant was located in Himachal Pradesh with the expectation of availing the backward area benefit which they were not able to avail.
 - (b). They had to bear costs on account of many factors such as transportation of raw materials and finished products and high cost of logistics in the terrain area. This added about 3% extra cost on the finished product besides attracting 1% CST on sales to customers who were all located outside Himachal Pradesh.
 - (c). Inability of the domestic industry to get a price comparable to the import price.
 - (d). Also from analysis, it is noticed that 31% of the total production of PUC has been exported by the domestic industry during 2013-14 at prices lower than domestic sale prices which could be one of the reason for losses.
- 50. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, shows a significant improvement in their position. It is thus concluded that, there exists no serious Injury or threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation.

I. Causal Link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury:

51. As per Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, The Director General(Safeguards) is obligated to "determine serious injury or threat thereof of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the principles laid down in Annex to the these rules". Further, paragraph 2 of the Annex requires establishment of causal link between alleged increased imports and serious injury or threat thereof. The Paragraph 2 of Annex to Rule 8 provides as follows:

The determination referred to in paragraph (1) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the article concerned and serious injury or threat thereof. When factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports.

52. The Panel on Korea — Dairy set forth the basic approach for determining "causation":

"In performing its causal link assessment, it is our view that the national authority needs to analyse and determine whether developments in the industry, considered by the national authority to demonstrate serious injury, have been caused by the increased imports. In its causation assessment, the national authority is obliged to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry. In addition, if the national authority has identified factors other than increased imports which have caused injury to the domestic industry, it shall ensure that any injury caused by such factors is not considered to have been caused by the increased imports.

To establish a causal link, Korea has to demonstrate that the injury to its domestic industry results from increased imports. In other words, Korea has to demonstrate that the imports of SMPP cause injury to the domestic industry producing milk powder and raw milk. In addition, having analyzed the situation of the

- domestic industry, the Korean authority has the obligation not to attribute to the increased imports any injury caused by other factors." ⁶
- 53. For the purpose of determining causation, all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry have been evaluated. First of all there is no surge in import and the factors like production, domestic sales, capacity utilization, productivity have improved during the period of investigation. Secondly the landed price of imports is higher than the selling prices of the domestic industry during POI. The imports were thus not suppressing the Domestic Industry prices in the market and price undercutting is negative. It is seen that during POI the cost of production for the product under consideration decreased and the selling price increased. Thus, there are indications that the Domestic Industry is not suffering on account of import prices. The profitability & returns on investments of the Domestic Industry has improved during period of investigation. The market share of DI increased and that of import decreased during the POI. Since increased imports have not taken place and further there is no serious injury caused by imports as narrated in para above, there appears no need for evaluation of causal link between Increased Import and Serious Injury or Threat of Serious Injury.

J. Adjustment Plan:

- 54. Rule 5(2)(b) of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 requires submission of a statement on "efforts being taken or planned to be taken or both to make positive adjustment to import competition". Further Article 7.1 of WTO Agreement on Safeguard provides that a member shall apply safeguard measure only to the extent necessary to prevent or remedy serious injury and facilitate adjustment.
- 55. The purpose of definitive safeguard measure is to provide the domestic producers with a limited period of time in which to restructure so as to more effectively compete with the imports. Section 8B (4) of Customs Tariff Act 1975 and Rule 16(2) of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997 prohibits any possible extension of measure if there is no evidence that the domestic producers are adjusting.
- 56. The domestic producers in this case have laid down following adjustment plan:
 - (i) The domestic industry envisages expanding its production capacity by 5,000 MT per annum by investing further Rs. 300 Crores within a span of next 1 year.
 - (ii) And further increase its capacity by another 5000MT per annum by further investing Rs. 300 Crores by Mar 2017
 - (iii) This will also facilitate in reducing its cost of production by lowering the fixed costs which will contribute towards profit.
- 57. The Applicant submitted that in the adjustment process they have short listed two major Technology Suppliers & have received formal offer from these two major Technology Suppliers with their price quotations and project cost estimates. They are in the process of implementing high quality standards with SIX Sigma methods and eliminate waste and down gradation. They are working on the break up for process equipments and utilities & have obtained the price quote for plan equipment from OEMs or estimated price from other sources. They further submitted that Supplier team have visited site for detailed technical discussions in Aug-13 and they are now in the process of negotiating cost estimates based on OEM prices. As submitted, the Applicant hopes for big potential in reducing cost by buying in bulk and installation material locally. Accordingly, the applicant has requested safeguard duty for a period of three years for better position to face the import competition.
- 58. It is further clarified by the applicant that owing to the above adjustment plan, the company would be in fair position to (i) reduce its cost significantly leading to better margins & (ii) increase the sales realization. In view of the above, it appears that the applicant has provided a viable adjustment plan which focuses on cost reduction, optimum utilization of production capacities to cater the growing demand of bare elastomeric filament yarn.

⁶ Panel Report on *Korea – Dairy*, paras. 7.89-7.90

- 59. Some of the interested parties have contended that the adjustment plan submitted by DI is too generic and shows no concrete steps that the DI is committed to take in a time-bound manner.
- 60. In this regard, it is noted that the DI has provided an adjustment plan spread over a period of 2-3 years. As contended by the Interested Parties, no concrete time-bound plan for positive adjustments has been envisaged by the DI. The DI in their submissions dated 30.06.2014 has accepted that 2nd phase of expansion of 5000 MTs which was to start in July, 2013 has got delayed due to unforeseen circumstances and surge in imports. No further evidence has been provided by the DI regarding expansion. In my view, the DI has not produced viable adjustment plan to become competitive to meet the challenge of imported PUC.

K. Unforeseen developments:

- 61. It has been contended by the domestic industry that there is no express obligation/requirement on the Director General (Safeguards) to analyse unforeseen circumstances as there is no specific requirement in the Indian Law and even in the GATT or the WTO Agreement on Safeguards, there is no specific guidelines or methodology that should be followed for analysing unforeseen developments. In this regard, I find that Article XIX of GATT,94 provides that serious injury has to be as a result of unforeseen developments.
- 62. Article XIX of GATT 1994 states as follows:
 - 1.(a)If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession.
- 63. The Appellate Body in Argentina Footwear (EC case) held that the phrase "Unforeseen Developments" means the developments which were unexpected. 'Unforeseen developments' requires that the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected'. The Appellate Body in Korea-Dairy case held that unforeseen developments are developments not foreseen or expected when the member incurred that obligation.
- 64. The Appellate Body, in Argentina Footwear (EC), then held that the requirement of "unforeseen developments" did not establish a separate "condition" for the imposition of safeguard measures, but described a certain set of "circumstances".
- 65. The domestic industry has submitted the following as unforeseen developments:
 - a) Increased imports at low price: Increased import at low price does not become an unforeseen development. The Panel in Argentina Preserved Peaches emphasized that increased quantities of imports should not be equated with unforeseen developments. This is neither unforeseen, nor a development. Thus, low priced imports per se cannot constitute unforeseen developments. Above all, the claim of the domestic industry with regard to low priced imports is incorrect as the data submitted by the domestic industry indicates that the import prices are higher than the domestic selling prices. Thus, imports do not constitutes low priced imports.
 - b) Backward area benefit: The fact that petitioner had envisaged backward area benefits which have not been granted does not become an unforeseen development within the meaning of safeguard law. Unforeseen development implies the developments which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been 'unexpected' as held by the WTO in the matter of Argentina Footwear case. It is a circumstance whose existence must be demonstrated as a matter of fact. While this fact might have been an unforeseen development for serious injury, this fact cannot be an unforeseen development for increased imports. In view of the same, backward area benefits cannot fall in the category of unforeseen development relevant for the present case.
 - c) Indo ASEAN treaty allowing duty free imports: ASEAN Treaty does not become unforeseen development for the reasons that the treaty has been entered into much prior to the establishment of the domestic industry. While the domestic industry commenced commercial production in March, 2012, the

treaty was signed in 2010. The domestic industry was therefore very well aware of the likely customs duty on the product under consideration. Hence this development can't be termed as "unforeseen".

d) It is thus seen that in the instant case, the arguments put forth by the domestic industry as the reason for increase in imports cannot be termed as 'unforeseen development'. In fact surge in imports has not been noticed.

L. Public Interest:

- 66. Interest of domestic producers alone cannot be seen as public interest. Even if it is admitted that imposition of safeguard duty on the product under consideration shall protect the domestic producers, the same cannot be termed as public interest. The demand of PUC in India is about 2.5 times of the total production of the DI who is the sole producer of the PUC in India and as the adjustment plan to increase its capacity is in the nature of proposals and not time-bound, the demand supply gap will increase over the time about next two years till DI actually expand the proposed capacity. Further, domestic industry is also exporting more than 30% of its product, which reduces the quantity available with the domestic industry to meet domestic demand. In view of the huge demand-supply gap and inability of DI to expand its capacity to the extent to meet the total Indian demand within about next two years, this will severely hamper the legitimate interest of the user industries. Hence, in these circumstances imposition of Safeguard Duty will not be in public interest at large.
- 67. Quality Issue: Quality of product under consideration is important due to the high cost of other textile fabrics in which it is used. Some of the interested party—submitted that downstream industry is ready to pay more provided the quality of subject goods provided by DI is good. In this context DI—submitted that there is no material price difference between the domestic produced subject goods and that imported into India. DI submitted that quality is not a parameter required to be analysed in a safeguard investigation. In this regard some of the interested party contended that paragraph 2 of Annex to Rule 8 of the Customs Tariff(Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules' 1997, states that "when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased imports." In this case, quality issues in the DI's goods is the reason that the DI is unable to command a good price for its goods both in domestic and international markets. The DI in his submission admitted that between November,12 and March,14 the sales returns were 3% of total sales and the total compensation paid by the DI so far is about 0.15% of total turnover. Also during analysis it is noted that there is significant difference in the price offered by the DI for domestic goods as well as for export goods and that of imported goods. These facts show that there may be some quality issues which have been compelling DI to keep their selling prices of the PUC at the lower levels when compared landed prices of PUC.

M. Examination of Post POI data:

68. In the given circumstances, an attempt was made to analyse the trend in the period after the POI i.e. 1st quarter of 2014-15 to draw a clear inference about the possibility of accentuation of the injury to the domestic industry. The domestic industry vide their letter dated 14th August, 2014 submitted the data pertaining to certain economic parameters for the subject "product under consideration" imported into India.

	2012-13			2013-14				2014-15	
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1
Total Imports (MT)	2488	2628	2114	2111	2428	2565	2214	2086	2543
Production (MT)	683	400	363	921	1247	1152	1127	1217	1204
Domestic Sales(MT)	220	293	351	815	931	892	670	918	965
Total Demand(MT)	2708	2921	2465	2926	3359	3457	2884	3004	3508
Market Share of Import(%)	92	90	86	72	72	74	77	69	72
Market Share of DI(%)	8	10	14	28	28	26	23	31	28
Inventory(MT)	477	584	521	528	646	675	601	398	333

Profitability(Rs. In								
lacs)(Indexed)	-100	-127	-138	-96.3	-89.3	-122	-54	-45

69. On scrutiny of the said data it is noted that during the post POI quarter, there is a increase in the imports so much so that the market share of imports have increased by about 3% as against the corresponding decline of the market share of the domestic industry by about 3%. Although there is a slight decline about 1% in production during post POI quarter as compared to previous quarter, the domestic sales increased by about 5% and inventories decreased by 16%. Also there is a rise in profitability for the domestic industry when the trend of import is increasing during post POI quarter. This indicates that the increased import during post POI quarter, is not responsible for any injury to domestic industry. Further the protection has been provided recently by the Govt. of India by reducing Custom duty on raw material required for manufacture of bare elastomeric filament Yarn from 5% to Nil vide Notification. No. 12/2014-Cus dated 11/07/2014. As a result the production cost will come down and profitability will further improve.

N. Conclusion:

- 70. The imports of the product under consideration have decreased in absolute terms and in relation to production and consumption in India. The volume of imports of bare elastomeric filament yarn decreased during the period of investigation. It is thus concluded that there is no surge in imports during the Period of Investigation, both in absolute terms as well as in relation to domestic production.
- 71. Market share, production, domestic sales, capacity utilization, productivity, profitability, and return on investment have improved during the period of investigation. Inventories with the Domestic Industry have decreased throughout the injury period. Price undercutting was negative throughout the period. Thus, an evaluation of the overall position of the Domestic Industry, in the light of all the relevant factors having a bearing on the situation of the Domestic Industry, it is observed that the position of the domestic industry has improved on account of factors of market share, production, sales, export, inventory and profitability. Even the imports have declined. Thus there exists no serious Injury or threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation.
- 72. Even analysis of post POI data indicate that increased import is not the reason for injury to domestic industry as sales increased and losses declined with increase in imports. This clearly indicates that the evidence of causal link between imports and serious injury does not exists. Also DI has not produced viable adjustment plan to become competitive to meet the challenge of imported PUC.
- 73. Thus, there exists no serious Injury or threat of serious injury to the domestic industry in the period of investigation and even in post POI (Q1 of 2014-15) to the extent that no protection is required. Moreover, recently the Govt. of India, by reducing Custom duty, on raw material required for manufacture of bare elastomeric filament Yarn, from 5% to Nil vide Notification. No. 12/2014-Cus dated 11/07/2014 has already provided a relief to the DI, which will improve their position further.

O. Recommendations:

74. In view of the discussions detailed above and the conclusions reached, safeguard duty on the imports of the "Bare Elastomeric Filament Yarn of all deniers and varieties" is hereby not recommended and the investigation in this case is terminated.

[F. No. D-22011/23/2013]

R. K. SINGH, Director General